



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



International Institute
for Educational Planning

प्रतिच्छाया शिक्षा प्रणाली को एक चुनौती

किस प्राइवेट ट्यूशन के लिए
क्या सरकारी नीतियाँ हों?



मार्क ब्रे

प्रतिच्छाया शिक्षा प्रणाली को एक चुनौती

किस प्राईवेट द्यूशन के लिए क्या सरकारी नीतियाँ हों?

प्रतिच्छाया शिक्षा प्रणाली को एक चुनौती

किस प्राइवेट ट्यूशन के लिए
क्या सरकारी नीतियाँ हों?

मार्क ब्रे



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



International Institute
for Educational Planning

इस पुस्तक में व्यक्त विचार और राय लेखक के हैं और यह जरूरी नहीं कि ये यूनेस्को या आईआईईपी के भी विचारों को अभिव्यक्त करते हों। इसमें दिए गए पदनाम और इस संपूर्ण पुस्तक में प्रस्तुत सामग्री यूनेस्को और आईआईईपी की ओर से किसी राय, जो कोई भी हो, को अभिव्यक्त नहीं करती, जो किसी देश, प्रदेश, नगर या क्षेत्र या उसके प्राधिकारियों, या उसकी सरहद या सीमाओं के तहत आने वाले कानून से संबंधित हो।

इस अध्ययन की प्रकाशन लागत को यूनेस्को द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान तथा यूनेस्को के अनेक सदस्य देशों द्वारा दिए गए स्वैच्छिक अंशदान से पूरा किया गया है, जिनकी सूची इस पुस्तक के अंत में दी गई है।

प्रकाशन:

अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान

7-9 रू ईयूजेन डेलाक्रोईक्स, 75116 पैरिस, फ्रांस

info@iiep.unesco.org

www.iiep.unesco.org

आवरण डिजाइन: आईआईईपी

टाइपसेटिंग: लीनेआले प्रोडक्शन

आईआईईपी की प्रिंटशॉप में मुद्रित

आईएसबीएन: 978-92-803-1333-8

© यूनेस्को 2009 नई दिल्ली में मुद्रित

विषय सूची

आभार	6
संक्षिप्तियों का सार	7
सारणियों की सूची	9
बॉक्सों की सूची	10
1. प्रस्तावना	11
प्रतिच्छाया का रूपक	13
पुस्तक की संरचना	14
2. निदान	17
मात्रा, तीव्रता और पद्धति	17
आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक प्रभाव	30
तीन मामलों का अध्ययन	47
3. नीति प्रक्रिया	71
प्रतिचित्रण संदर्भ, उद्देश्य और संरचना	71
ट्यूशन की मांग से निपटना	75
ट्यूशन की आपूर्ति से निपटना	79
बाजार का उपयोग करना	84
नियंत्रक ढांचे में सुधार करना	87
4. निगरानी एवं मूल्यांकन	93
राष्ट्रीय एवं स्थानीय फीडबैक लूप	93
अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्किंग	97
5. निष्कर्ष	101
रुझानों का पता लगाना	101
प्रतिच्छाया शिक्षा प्रणाली से सबक	104
संदर्भ	109
प्रतिच्छाया शिक्षा	127

आभार

इस प्रकाशन तथा इससे जुड़ी गतिविधियों में कई लोगों ने अपना योगदान दिया है। इसमें सबसे अधिक योगदान आईआईईपी पॉलिसी फोरम के भागीदारों का रहा है - जिसकी बैठक 5-6 जुलाई 2007 को पैरिस में बुलाई गई थी - जिसकी सामग्री पर यह पुस्तक आधारित है। इस कार्यक्रम ने विविध पृष्ठभूमि वाले 37 भागीदारों को एक मंच पर ला दिया जिन्होंने बहुत उपयोगी विश्लेषण और चर्चा की। इस कार्यक्रम को आईआईईपी के एक दल द्वारा समर्थन दिया गया जिसमें फ्लोरंस अप्पेरे और ईम्मैन्युएल सुसो का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है और उन्हें धन्यवाद दिया जाता है। इस पुस्तक में अन्य बहुमूल्य योगदान अनेक देशों के योजनाकारों, नीति-निर्माताओं, और शोधकर्ताओं का रहा है जो काफी लम्बे समय तक इससे जुड़े रहे। इस पाण्डुलिपी में विशेष टिप्पणी करने और अन्य सहायता देने के लिए कार्ल हेईन्ज गुबेर, ओरा क्वो, ईजुमी मोरी, स्टेवन ओबीगाडू, अर्मूगम परसुरामेन, लौरा पैविओट, नेविले पोस्टलेथवाईट, ईवेता सिलोवा, शिन'इची सूजुकी, और अलेक्जेंडर वेनतुरा का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया जाता है।

संक्षिप्तियों का सार

एडीईए	अफ्रीका में शिक्षा विकास संघ
सीएलएपी	सामुदायिक शिक्षा सहायक परियोजना
सीपीई	प्राथमिक शिक्षा प्रमाणपत्र
सीपीएस	शिकागो पब्लिक स्कूल
सीएसएटी	कॉलेज शैक्षिक योग्यता परीक्षा
डीएसटी	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
जीसीएसई	सामान्य माध्यमिक शिक्षा प्रमाणपत्र
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीएनपी	सकल राष्ट्रीय उत्पाद
जीपीए	ग्रेड प्वाइंट औसत
आईईए	अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्राप्ति मूल्यांकन संघ
आईआईईपी	अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा योजना संस्थान
आईएनआरपी	इंस्टीटूट नेशनल डे रीचर्च पेडागोगिक्यू
आईसीटी	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
एचसीईसी	हौत काउंसेल ए ला' ईवेल्यूएशन डे ला'ईकोले
मेंडाकी	माले/मुस्लिम शिक्षा परिषद
एनसीएलबी	नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड
एनजीओ	गैर - सरकारी संगठन
ओईसीडी	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
ओएसआई	ओपन सोसायटी इंस्टीट्यूट
पीआईएसए	योग्य शिक्षा स्थिति
एसएसीएमईक्यू	दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका निगरानी शैक्षणिक गुणवत्ता परिसंघ
एसईएस	सामाजिक - आर्थिक स्थिति

एसआईएनडीए	सिंगापुर भारतीय विकास संघ
एसपीएच	विशेष प्रयोजन हाई स्कूल
एसपीएल	स्कूल पॉयलट लीडर
टीआईएमएसएस	तृतीय अंतर्राष्ट्रीय गणित और विज्ञान अध्ययन/अंतर्राष्ट्रीय गणित और विज्ञान अध्ययन में रुझान
यूनेस्को	संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन
यूनिसेफ	संयुक्त राष्ट्र बाल कोष
यूएसए	संयुक्त राष्ट्र अमेरीका
जेडईपी	जोन डी'एजुकेशन प्राईरोटायर

सारणियों की सूची

सारणी 1.	प्राइवेट ट्यूशन के लिए परस्पर राष्ट्रों के संकेतक	18
सारणी 2.	पूर्वी यूरोप और एशिया के चयनित देशों में प्राइवेट ट्यूशन की मात्रा	20
सारणी 3.	1995 और 2000 में पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में पूरक ट्यूशन लेने वाले छठी कक्षा के छात्रों का प्रतिशत	21
सारणी 4.	ग्रेड आधार पर भारत के चार राज्यों में प्राइवेट ट्यूशन लेने वाले छात्रों का प्रतिशत	21
सारणी 5.	वर्ष 2005 - 2006 में पुर्तगाल के चार स्कूलों में 12वीं कक्षा के छात्रों द्वारा ट्यूशन लेने वालों की तीव्रता	25
सारणी 6.	भारत में वर्ष 2005 में विभिन्न विषयों में ट्यूशन लेने वाले छात्रों का प्रतिशत	26
सारणी 7.	भारत में वर्ष 2005 विभिन्न विषयों में ट्यूशन लेने वाले उच्च माध्यमिक छात्रों का प्रतिशत	26
सारणी 8.	पूर्वी यूरोप और एशिया में प्राइवेट ट्यूशन लेने वाले ग्रामीण और शहरी छात्रों में अंतर (%)	37
सारणी 9.	भारत के चार राज्यों के ग्रामीण और शहरी इलाकों में निम्न माध्यमिक स्तर पर प्राइवेट ट्यूशन प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत	37
सारणी 10.	मुख्य स्कूली शिक्षा पर प्राइवेट ट्यूशन का प्रभाव	45
सारणी 11.	कोरिया में 1980 - 2007 के बीच प्राइवेट ट्यूशन लेने वाले छात्रों का प्रतिशत	53
सारणी 12.	फ्रांस के प्रमुख प्राइवेट ट्यूशन उद्योग	68
सारणी 13.	प्राइवेट ट्यूशन के वर्गीकरण करने का तरीका	73
सारणी 14.	इंग्लैंड की 'मेकिंग गुड प्रोग्रेस' योजना में विचारणीय प्राइवेट ट्यूशन के मॉडल	82
सारणी 15.	यूरोप और एशिया के छः देशों में प्राइवेट ट्यूशन को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढांचा	87
सारणी 16.	'मेकिंग गुड प्रोग्रेस' पॉयलट के लिए मूल्यांकन पद्धति	96

बॉक्सों की सूची

बॉक्स 1.	प्राइवेट ट्यूशन की पद्धतियों का वर्गीकरण	24
बॉक्स 2.	मूल्यांकन आधारित निर्णय लेना	30
बॉक्स 3.	दबाव से निपटना	54
बॉक्स 4.	आखिर मॉरीशस में प्राइवेट ट्यूशन इतनी सशक्त क्यों है?	64
बॉक्स 5.	फ्रांस में प्राइवेट ट्यूशन का वित्तीय गणित	69
बॉक्स 6.	जापन में जुकू के प्रकारों में अंतर	74
बॉक्स 7..	मिस्र का एक मास्टर ट्यूटर	78
बॉक्स 8.	एकाधिकार + स्वनिर्णय - जवाबदेही	80

1. प्रस्तावना

पूरी दुनिया में शिक्षा योजनाकारों और नीति निर्माताओं का पूरा ध्यान किंडरगार्डन, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा की औपचारिक प्रणाली पर ही रहता है। जिन संस्थान में ये शैक्षिक प्रणालियां मौजूद हैं वे काफी अधिक संसाधनों का उपयोग करते हैं और उनकी समाज में व्यापक सामाजिक और आर्थिक भूमिका है जहां वे कार्य करते हैं।

इस पुस्तक में प्रमुख शैक्षिक प्रणालियों के समानांतर निजी पूरक शिक्षा की एक प्रतिच्छाया शिक्षा प्रणाली का उल्लेख किया गया है जिसका स्वरूप लगातार बढ़ता जा रहा है। इस प्रतिच्छाया प्रणाली की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है, यद्यपि इसका प्रमुख सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ता है। इस पुस्तक में यह तर्क दिया गया है कि प्रतिच्छाया शिक्षा प्रणाली की ओर शैक्षिक योजनाकारों और नीति निर्माताओं द्वारा काफी अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। दुनिया के कुछ भागों, विशेषकर जापान और पूर्वी एशिया के अन्य भागों में प्रतिच्छाया शिक्षा प्रणाली काफी लंबे समय से विद्यमान है। हाल के वर्षों में हर कहीं काफी विकास हुआ है किंतु साथ ही निजी शिक्षा का विकास और प्रभाव भी बढ़ा है। इसके अलावा, निजी शिक्षा ने मात्र पृथक औपचारिक कार्यकलाप की बजाय इन प्रणालियों में अपनी पैठ बनाई है। निजी शिक्षा उद्यम एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं और कुछ तो विदेशों में भी कार्यरत हैं।

1999 में यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना संस्थान (आईआईपी) ने पूरी दुनिया में निजी शिक्षा पर पहला महत्वपूर्ण अध्ययन प्रकाशित किया जिसे मौजूदा लेखक (ब्रे, 1999ए) द्वारा किया गया था। इस पुस्तक को शैक्षणिक और व्यावसायिक साहित्य जगत में काफी सराहा गया। इसके अलावा, पुस्तक में इन विषयों पर आगे और छानबीन करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है (पृष्ठ 87)।

1999 में इस कार्य के प्रकाशन के बाद की अवधि में इस विषय पर वास्तव में आगे और जांच की गई। आईआईपी ने इस श्रृंखला में नीति-शास्त्र और भ्रष्टाचार पर एक और पुस्तक का प्रकाशन किया (ब्रे, 2003); कुछ दूसरे लेखकों ने भी इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए जिनके नाम इस पुस्तक की संदर्भ सूची में दिए गए हैं और आईआईपी कार्य के विशिष्ट संदर्भ सहित यह विषय अनेक बहुपक्षीय एजेंसियों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा उदाहरण के लिए विश्व बैंक, 2004, 2005; ओईसीडी, 2006ए; एडीईए, 2008, ओपन सोसाइटी इंस्टीट्यूट 2008; यूनेस्को, 2004, 2007, 2008; यूनेस्को 2007; ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, 2009) द्वारा नीति-उन्मुख दस्तावेजों में शामिल

किया गया है। इन बढ़ते विश्लेषणों में इस घटना के महत्व के बारे में बढ़ती जागरूकता को दर्शाया गया है जो आंशिक रूप से अपने आप में निजी शिक्षा की मौजूदगी के विस्तार को दर्शाता है।

इस ओर बढ़ते रुझान से यह प्रश्न उठा है कि नीति निर्माता और योजनाकार निजी शिक्षा के अस्तित्व और विस्तार पर क्या रूख अपनाएंगे। इस विषय पर 1999 में प्रकाशित पुस्तक में उल्लेख किया गया था (ब्रे, 1999ए, पृष्ठ 74 - 77) कि दुनिया भर में इस घटना की अनदेखी करने और इस पर रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा था। पुस्तक में यह भी नोट किया गया कि विभिन्न स्थितियों में और अलग-अलग समय में विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया उपयुक्त होगी, और इस अनुभव से सीखने के लिए लगातार निगरानी और विश्लेषण करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद से बदलती परिस्थितियों ने गहन जांच करने की जरूरत पर और अधिक जोर दिया है।

2007 में आईआईईपी ने पेरिस में आईआईईपी के मुख्यालय में आयोजित एक पॉलिसी फोरम बनाते हुए इस विषय पर फिर से चर्चा की। यह मौजूदा अंक पॉलिसी फोरम में प्रस्तुत पेपर तथा इस दो दिवसीय कार्यक्रम में हुई चर्चा के मुख्य आधार थे। पॉलिसी फोरम का शीर्षक इस पुस्तक का शीर्षक ही था। भागीदारों ने विभिन्न व्यवस्थाओं में निजी शिक्षा के विभिन्न प्रकारों की पहचान की और उन नीतियों पर चर्चा की जो उपयुक्त थे। वे इस बात से भली-भांति परिचित थे कि यह विषय स्पष्ट नहीं है और इसकी नीति पर सिफारिशें सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए। इसके बावजूद चर्चा ने नई अवधारणा स्थापित की और इसीलिए इसका काफी महत्व था।

आईआईईपी परंपरा में, पॉलिसी फोरम में उन विषयों पर ध्यान केन्द्रित किया गया जिनका उत्तर और दक्षिण तथा पूर्व और पश्चिम के देशों में महत्व था। निजी पूरक शिक्षा निश्चित रूप से इस मानदण्ड में सही बैठती है, और इस कार्यक्रम ने आस्ट्रेलिया, बोलिबिया, फ्रांस और कोरिया गणराज्य जैसे दूर-दराज़ के देशों में मौजूद प्रणालियों की अत्यधिक निर्देशात्मक तुलना की। आईआईईपी पॉलिसी फोरम का उद्देश्य योजनाकारों, नीति निर्माताओं और व्यावसायिकों तथा शोधकर्ताओं को भी एक मंच पर लाना था। निजी शिक्षा पर पॉलिसी फोरम कोई अपवाद नहीं था और इसने समूहों के बीच महत्वपूर्ण जानकारी का आदान-प्रदान किया। इसका एक अन्य खास पहलू यह था कि इसमें कई भागीदार स्वयं माता-पिता थे जो इस पशोपेश में थे कि वे अपने बच्चों के लिए निजी शिक्षक लगाएं अथवा नहीं। मौजूदा अंक पॉलिसी फोरम के उन पेपरों और चर्चाओं, साहित्य में अतिरिक्त सामग्रियों और विभिन्न व्यावसायिक और शैक्षणिक बैठकों में हुई अनुवर्ती चर्चाओं पर आधारित है।

प्रतिच्छाया का रूपक

2007 की नीति के शीर्षक में इस रूपक का 1999 में प्रकाशित पुस्तक (ब्रे 1999ए) में प्रयोग किया गया था। इस रूपक का मारीमुथु सिंह, और अन्य (1991), स्टेवेम्सन और बैकर (1992) और जार्ज (1992) द्वारा अपने लेखन में व्यापक तौर पर प्रयोग किया गया है। जैसा कि 1999 की पुस्तक (पृष्ठ 17) में उल्लेख किया गया है, प्रतिच्छाया रूपक कई अर्थों में बिलकुल सटीक बैठता है। पहला, निजी पूरक द्यूशन का वजूद केवल इसीलिए है क्योंकि मुख्य शिक्षा प्रणाली मौजूद है; दूसरा जैसे-जैसे मुख्य प्रणाली का आकार और स्वरूप बदलता है, उसी तरह पूरक द्यूशन का आकार और स्वरूप भी बदलता है; और चौथा, प्रतिच्छाया प्रणाली की विशेषताओं में मुख्य प्रणाली की तुलना में अधिक अंतर नहीं होता। पुस्तक में आगे यह भी कहा गया है (पृष्ठ 17-18) कि:

प्रतिच्छाया शिक्षा प्रणाली निस्संदेह उपयोगी हो सकती है। जिस तरह सूर्य-घड़ी पर पड़ने वाली परछाई समय बता सकती है, उसी तरह शिक्षा प्रणाली का प्रतिबिम्ब भी समाज में होने वाले बदलाव को बता सकता है। हालांकि कुछ देशों में माता-पिता, शिक्षा और राजनीतिज्ञ प्राइवेट द्यूशन के घोर विरोधी हैं, जिस तरह इसने परिवारों और लोगों पर राज करना शुरू कर दिया है। द्यूशन शिक्षा प्रणाली ने सामाज में ऊँच-नीच पैदा कर दी है, और इसमें काफी अधिक मानव शक्ति और पूंजी खर्च हो रही है जिसका संभवतः अन्य कार्यकलापों में अधिक उचित तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। आलोचकों का कहना है कि प्राइवेट द्यूशन मुख्य शिक्षा प्रणाली के पाठ्यक्रम को विकृत कर सकती है, मुख्य शिक्षकों के नियोजित शिक्षा के क्रम को अस्त-व्यस्त कर सकती है और कक्षा के माहौल को खराब बना सकती है। इस तरह से, दूसरी परछाइयों से भिन्न प्राइवेट पूरक द्यूशन न केवल दबे पांव घुसपैठ कर रही है बल्कि यह उस शरीर पर भी बुरा असर डाल सकती है जिसकी यह प्रतिच्छाया है।

इस पुस्तक का नाम *प्रतिच्छाया शिक्षा प्रणाली - एक चुनौती* रखा गया है क्योंकि इसमें यह तर्क दिया गया है कि प्राइवेट पूरक द्यूशन से जुड़े मद्दों से निपटे जाने की आवश्यकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्राइवेट द्यूशन के सभी पहलू नकारात्मक हैं। प्राइवेट द्यूशन बच्चों को सीखने में मदद करती है और इस प्रकार, वे अच्छे नागरिक बनते हैं और अंततः आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। इसका सामाजिक कार्यों में भी महत्व होता है, जो बच्चों और युवाओं को बुद्धिजीवियों और अन्य लोगों के साथ बातचीत करने का रचनात्मक अवसर प्रदान करती है। प्राइवेट द्यूशन पढ़ाने से द्यूटर्स को आमदनी भी होती है; और द्यूशन मुख्य शिक्षकों को भी बच्चों को पाठ समझाने में मदद कर सकती है जो पाठ को इतने अच्छे से नहीं समझ पाते। इसके बावजूद, द्यूशन के व्यापक नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। इससे आम तौर पर सामाजिक और आर्थिक असमानता पैदा होती है; यह बच्चों के जीवन को प्रभावित करती है और

उनके मौज-मस्ती के समय को कम कर देती है जो मानसिक और शिक्षा की दृष्टि से अच्छी बात नहीं है; और यही नहीं, यह कुछ हद तक भ्रष्टाचार का रूप भी ले सकती है जिससे सामाजिक आस्था छिन्न-भिन्न होती है।

अधिकांश देशों में इन सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का मिला-जुला रूप जटिल परिदृश्य उत्पन्न करता है; और कुछ देशों में इन मुद्दों से निपटने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली मौजूद है। अनेक नीति-निर्माता और नियोजक इस घटनाक्रम को नजरअंदाज करते हुए कठोर निर्णय लेने से बचने का मार्ग अपनाना पसंद करते हैं और इसे बाजार पर छोड़ देना चाहते हैं। किंतु कुछ व्यवस्थाओं में सरकार द्वारा हस्तक्षेप न करने की नीति से समस्याएं पैदा होती हैं और इसलिए शिक्षा प्रणाली की प्रतिच्छाया से निश्चित रूप से निपटा जाना चाहिए। उपयुक्त कार्रवाई पर निर्णय लेना कठिन हो सकता है; लेकिन नीति-निर्माताओं और नियोजकों को कम से कम यह समझना चाहिए कि निजी पूरक ट्यूशन का अस्तित्व है और इसका व्यापक प्रभाव है। इसके अलावा, इस पुस्तक में दुनिया भर में हुए अनेक अनुभवों का उल्लेख किया गया है जो नीति-निर्माताओं और नियोजकों को अपनी निजी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त उपायों की पहचान करने में मदद कर सकते हैं।

पुस्तक की संरचना

किसी घटना के नीतिगत प्रभाव का पता लगाने का कोई प्रयास संबंधित घटना के विवरण से ही शुरू होना चाहिए और इसके आयामों की पहचान करने के लिए नीति पर ध्यान देने की जरूरत होती है। इसे ध्यान में रखते हुए पुस्तक के पहले भाग में निजी पूरक शिक्षा (ट्यूशन) के आकार और रूपरेखा का वर्णन किया गया है। इसमें विभिन्न देशों में मौजूद पद्धतियों और शिक्षा के विभिन्न स्तरों में अंतर का उल्लेख किया गया है। पुस्तक में ट्यूशन के विविध प्रकारों का भी उल्लेख किया गया है। ट्यूटोरियल का आकार छात्रों और ट्यूटोरों के बीच अलग-अलग सत्रों के आधार पर तय होता है जिसमें विशाल लेक्चर थियेटर बने होते हैं। ट्यूशन शिक्षक-छात्रों के आमने-सामने बैठकर, दूरस्थ पाठ्यक्रम, टेलिफोन पर या इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकती है। इसकी परीक्षाओं के दिनों में अधिक मांग रहती है, और यह लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों के रोजमर्रा के जीवन का अभिन्न हिस्सा होती है।

इस घटना का वर्णन करने के बाद, पुस्तक में आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक प्रभाव का उल्लेख किया गया है। ट्यूशन इन वर्गों में प्रत्येक के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन इसकी प्रकृति और मात्रा के कारण यह समस्या भी पैदा कर सकती है। सरकारी नीतियों के तहत कमजोर छात्रों को जो ट्यूशन दी जाती है, वह बाजार आधारित ट्यूशन से काफी अलग होती है, जो मुख्यतः प्रतिभाशाली छात्रों के लिए होती है। इसी प्रकार, विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा औपचारिक आधार पर दी जाने वाली ट्यूशन

वाणिज्यिक कंपनियों में पेशेवरों द्वारा दी जाने वाली ट्यूशन से काफी भिन्न होती है। कुछ वर्ग के बच्चों पर ट्यूशन लेने का भारी दबाव रहता है क्योंकि उनके सभी सहपाठी ट्यूशन ले रहे होते हैं, और उनके स्कूल के प्रमुख अध्यापक भी उन पर ट्यूशन लेने के लिए दबाव डालते हैं, और/या उनका परिवार शैक्षिक तथा आर्थिक उन्नति के लिए ट्यूशन को एक प्रमुख अवसर मानता है। व्यापक स्तर पर काफी कुछ संबंधित समाज की संस्कृतियों पर भी निर्भर करता है। ये संस्कृतियां परिवर्तन ला सकती हैं, जो यह बताने में सहायता कर सकती हैं कि आखिर कुछ देशों में ट्यूशन इतनी अधिक लोकप्रिय क्यों हो गई है।

इसका मूल्यांकन करने से यह प्रश्न उठता है कि नीति-निर्माता और नियोजक प्रतीच्छाया शिक्षा प्रणाली से निपटने के लिए क्या कर सकते हैं और उन्हें क्या करना चाहिए। पुस्तक में यह सुझाव दिया गया है कि उन्हें संदर्भ, उद्देश्य और रूपरेखा का जायजा लेना प्रारंभ करना चाहिए। तत्पश्चात् वे मांग और/या आपूर्ति के आधार पर समस्या का समाधान कर सकते हैं। नीति-निर्माता और नियोजक बाजार के उतार-चढ़ाव को देखते हुए तरीके निकाल सकते हैं, और इसके द्वारा वे विनियामक ढांचों में सुधार कर सकते हैं। ऐसी स्थितियों में जहां मुख्य अध्यापक अपने ही छात्रों पर स्कूल में पढ़ाए जाने वाले मुख्य विषयों के लिए उन्हीं अध्यापकों से अतिरिक्त कक्षाएं लेने के लिए दबाव डालते हैं जो स्कूलों द्वारा अलग से दी जाने वाली ट्यूशन से काफी भिन्न होती हैं। इसका कोई समाधान निकालना इस बात पर निर्भर करेगा कि नीति निर्माता इन नीतियों को लागू करने के लिए वित्तीय, मानवीय या अन्य बाधाओं के कारण खुद को किस हद तक लाचार महसूस करते हैं, जो अन्यथा सांस्कृतिक, प्रशासनिक और अन्य तथ्यों को प्रभावित करेंगे। नीति-निर्माता और नियोजकों को निगरानी और मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रणालियों की जरूरत होती है जिससे वे समय के साथ-साथ बदलती पद्धति पर नज़र रख सकें।

अंत में, सबसे पहले यह आवश्यक है कि इस पुस्तक की कुछ अवधारणा संबंधी सीमाओं को पहचाना जाए। पहली, यह केवल प्रशासनिक और माध्यमिक स्कूली शिक्षा के स्तर पर लोगों की निजी अनुपूरक ट्यूशन से संबंधित है, लेकिन इसकी विशेषताएं भिन्न हैं और इसमें विभिन्न मुद्दों को उठाया गया है। दूसरे, यह पुस्तक भुगतान करके ट्यूशन दिलाने के मुद्दे से संबंधित है: इसमें वह ट्यूशन शामिल नहीं है जो रिश्तेदारों, अध्यापकों या अन्य लोगों द्वारा मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। यह ट्यूशन नीति-निर्माताओं और नियोजकों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन ऐसी संभावना है कि इस ट्यूशन का स्वरूप विविध होगा और इससे विभिन्न मुद्दे उठेंगे, जैसे यह शुल्क देने पर ही दी जाएगी। तीसरे, यह पुस्तक केवल मुख्य स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले शैक्षिक विषयों की ट्यूशन से ही संबंधित है। इस प्रकार, उदाहरण के लिए यह बैलेट कक्षाओं, फुटबाल, धार्मिक शिक्षा या कोई अल्पसंख्यक भाषा सीखने से संबंधित नहीं है जो स्कूली छात्रों को नहीं पढ़ाई जाती। ये विषय भी महत्वपूर्ण समझे जाते हैं, लेकिन इन पर इस पुस्तक की रूपरेखा के अलावा, अलग से विचार किए जाने की जरूरत है।

2. निदान

मात्रा, तीव्रता और पद्धति

प्राइवेट पूरक ट्यूशन के आकार और स्वरूप पर सही-सही आंकड़े प्राप्त करना कठिन है। ऐसा ट्यूशन लेने और देने वालों से संबंधित कई कारणों से है:

- **प्रायः ट्यूशन देने वाले इस ओर ध्यान नहीं देते** क्योंकि उनमें से अनेक लोग ट्यूशन को अनौपचारिक रूप में लेते हैं, और ऐसी आय अर्जित करते हैं जिस पर कर नहीं लगता।
- **छात्र भी इस ओर ध्यान नहीं देते** क्योंकि उन्हें भी यह डर लगता है कि यह अनुचित लाभ लेने जैसा समझा जाएगा और/या इससे मुख्य शिक्षा प्रणाली के प्रति अविश्वास पैदा होगा, या यह लगेगा कि उनके बच्चे बेवकूफ समझे जाएंगे।
- **माता-पिता भी इस ओर ध्यान नहीं देंगे** क्योंकि उन्हें भी यह डर लगेगा कि ऐसा करना अनुचित लाभ लेने और/या मुख्य शिक्षा प्रणाली में आस्था न होने जैसा माना जाएगा, या ऐसा भी लगेगा कि कहीं उनके बच्चे बेवकूफ न समझे जाएंगे।

ट्यूशन का जायजा लेना भी मुश्किल होता है क्योंकि इसके विविध रूप, अवधि और तीव्रता विभिन्न मौसमों में अलग-अलग होती है। प्रायः ट्यूशन आमने-सामने बैठकर दी जाती है, लेकिन यह व्यक्तिगत से लेकर बड़ी कक्षाओं के रूप में हो सकती है। इसमें पत्राचार पाठ्यक्रम या बड़े पैमाने पर इंटरनेट शामिल हो सकता है। इसके अलावा, कुछ छात्र लम्बी अवधि तक नियमित रूप से कई विषयों में ट्यूशन प्राप्त करते रहते हैं, जबकि दूसरे छात्र केवल कुछ विषयों में ट्यूशन लेते हैं और रुक-रुककर लेते हैं। इसके बावजूद इसकी व्यापक रूपरेखा का जायजा लेने के लिए पर्याप्त अध्ययन कराए गए हैं। इसके कारण यह रूपरेखा अधिक व्यापक बन गई है क्योंकि प्राइवेट ट्यूशन के सामाजिक और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता काफी बढ़ गई है, और स्वतंत्र शोधकर्ताओं और पेशेवर निकायों दोनों इस बारे में अधिक जानना चाहते हैं।

मात्रा में भिन्नता

तालिका-1 में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। यह आंकड़ों को मानकीकृत फॉर्मेट में प्रस्तुत नहीं करता क्योंकि अध्ययनों का दृष्टिकोण भिन्न था, लेकिन इससे प्रमुख पद्धतियों का अवश्य पता चलता है। सबसे अहम बात यह पता चलती है कि ट्यूशन दुनिया के कई हिस्सों में पाई जाती है। इसमें कम आय वाले देश जैसे कंबोडिया और केन्या, तथा उच्च आय वाले देश जैसे कनाडा और जापान भी शामिल हैं। ट्यूशन ग्रामीण इलाकों की तुलना में शहरों में अधिक पाई जाती है, और कुछ संस्कृतियों में यह लड़कियों के मुकाबले लड़कों द्वारा अधिक ली जाती है।

सारणी 1. प्राइवेट द्यूशन के लिए परस्पर राष्ट्रों के संकेतक

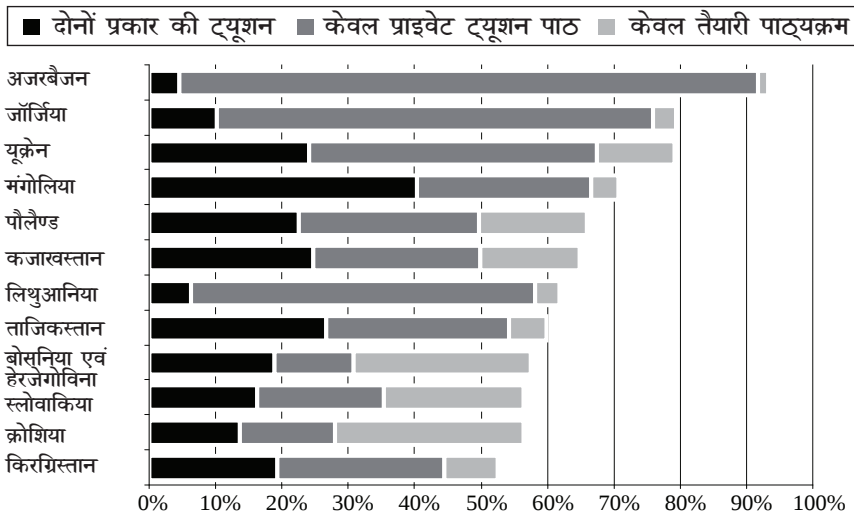
स्थान	पद्धति
बांग्लादेश	वर्ष 2005 में 16,400 परिवारों से लिए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षण आंकड़ों की वर्ष 1998 में 33,229 परिवारों से लिए गए इसी प्रकार के आंकड़ों से तुलना की गई थी। आंकड़ों से पता चलता है कि द्यूशन का स्वरूप विद्यमान था, और इस अवधि के दौरान इसका विस्तार हुआ था। वर्ष 2005 में, प्राथमिक विद्यालय के 31.0% छात्र द्यूशन प्राप्त कर रहे थे (ग्रामीण क्षेत्रों में 28.2%; शहरी क्षेत्रों में 51.7%) लेकिन 1998 में 21.4% बच्चे द्यूशन प्राप्त कर रहे थे (18.1% ग्रामीण, 44.3% शहरी)।
कंबोडिया	1997/1998 में सर्वेक्षण किए गए 77 प्राथमिक विद्यालयों के 31.2% प्रतिवादियों ने बताया कि छात्र द्यूशन ले रहे थे, जो प्राथमिक शिक्षा की कुल लागत का 6.6% था। इसके बाद 2004 में किए गए अध्ययन से पता चला कि इसकी लागत माध्यमिक स्तर पर काफी बढ़ गई थी। निम्न माध्यमिक स्कूली शिक्षा के सबसे ऊंचे ग्रेड में द्यूशन लेने वाले परिवारों की औसत पारिवारिक लागत प्राथमिक स्कूलों के सबसे ऊंचे ग्रेड में द्यूशन की तुलना में चार गुणा अधिक थी।
कनाडा	1997 के राष्ट्रीय दूरभाष सर्वेक्षण में स्कूल जाने वाले बच्चों सहित 501 वयस्कों के 9.4% प्रतिवादियों से पता चला कि उनके बच्चे स्कूल के घंटों के बाद प्राइवेट द्यूशन ले रहे थे, और 8.4% प्रतिवादियों ने बताया कि उनके बच्चे पिछले कुछ सालों से ऐसा कर रहे थे।
चीन	2004 शहरी घरेलू शिक्षा और रोजगार सर्वेक्षण में 4,773 परिवारों को शामिल किया गया था। इससे पता चला कि द्यूशन 73.8% प्राथमिक, 65.6% निम्न माध्यमिक और 57.5% ऊपरी माध्यमिक माध्यमिक छात्रों द्वारा ली जा रही थी।
साइप्रस	1,120 कॉलेज छात्रों का 2003 में किए गए एक अध्ययन से पता चला कि 86.4% छात्रों ने माध्यमिक स्कूल में प्राइवेट द्यूशन प्राप्त की थी।
मिश्र	2004 में कराए गए अध्ययन से यह पता चला कि परिवार शिक्षा व्यय का 61.0% प्राइवेट द्यूशन पर खर्च कर रहे थे। सन् 1997 में कराए गए अध्ययन से पता चला कि स्कूल के सभी स्तरों पर द्यूशन पारिवारिक व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 1.6% था। 1994 में 4,729 परिवारों के सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि शहरी इलाकों में 64.0% और ग्रामीण इलाकों में 52.0% प्राथमिक विद्यालय के बच्चे द्यूशन ले रहे थे।
हांगकांग	सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2006 में 34% प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के छात्र द्यूशन ले रहे थे। वर्ष 2004-2005 में 13,600 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें यह पाया गया कि 36.0% प्राथमिक स्तर पर, 28.0% निम्न माध्यमिक, 33.6% मिडल माध्यमिक में, तथा 48.1% ऊपरी माध्यमिक में द्यूशन ले रहे थे।
जापान	2007 में कराए गए सर्वेक्षण से पता चला कि जुकु के रूप में जाने जाने वाले द्यूशन स्कूल द्वारा 15.9% प्राथमिक-। कक्षा के बच्चों को द्यूशन दे रहा था, और यह अनुपात बाद के ग्रेडों में लगातार बढ़ता गया और यह क्रमिक माध्यमिक 3 में बढ़कर 65.2% हो गया। इसके अलावा, कनिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 3 बच्चे घर पर शिक्षा ले रहे थे, 6.8% और 15.0% पत्राचार पाठ्यक्रम से द्यूशन ले रहे थे।

स्थान	पद्धति
केन्या	1997 में छठी कक्षा के 3,233 बच्चों का राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि 68.6% बच्चे प्राइवेट ट्यूशन ले रहे थे जिनकी संख्या पूर्वोत्तर प्रांत में 39.0% और नयांजा प्रांत में 74.4% थी। तीन भौगोलिक रूप से पृथक जिलों में कराए गए समानांतर सर्वेक्षण से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में, और लड़कियों के मुकाबले लड़कों में ट्यूशन अधिक लोकप्रिय थी।
वियतनाम	वर्ष 2001 में 3,639 प्राथमिक विद्यालयों में पांचवीं कक्षा के 72,660 बच्चों का नमूना सर्वेक्षण किया गया जिसमें 38% छात्रों ने बताया कि वे ट्यूशन प्राप्त कर रहे थे। सन् 2002 में ट्यूशन पर पारिवारिक शिक्षा व्यय का लगभग 20% स्वर्च किया जा रहा था। यह आंकड़ा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सर्वाधिक 29% था, और यह विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों और सेन्ट्रल हाईलैण्ड और दक्षिण-पूर्व क्षेत्रों में अधिक था।

स्रोत: विभिन्न अध्ययनों में सूचना दी गई है (2006 पृष्ठ 517-518)। नाथ में बांग्लादेश पर अद्यतन रिपोर्ट (2008, पृष्ठ 57); विश्व बैंक में मिस्र (2008 पृष्ठ 190); कवोक में हांगकांग (2009, पृष्ठ 106) तथा एनजी (2009 पृष्ठ 1); जापान में शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और खेल मंत्रालय (2008 पृष्ठ 13); जू और डिंग में चीनी आंकड़े (2009, पृष्ठ 119); विश्व बैंक में 2001 सर्वेक्षण पर वियतनाम आंकड़े (2004, पृष्ठ 81)।

वर्ष 2007 की आईआईईपी नीति के दौरान प्रस्तुत आंकड़ों में आगे उदाहरण दिए गए हैं। सिलोवा (2007) ने पूर्वी यूरोप और एशिया के 12 देशों में प्राइवेट ट्यूशन पर आंकड़े उपलब्ध कराए जिनके सोवियत संघ से साझा ऐतिहासिक संपर्क थे (सारणी-2)। उन्होंने टिप्पणी की (पृष्ठ 4) कि हालांकि 1009 के दशक की शुरुआत में प्राइवेट ट्यूशन मामूली रही थी, किंतु इसके बाद यह “एक व्यापक उद्यम” बन गई। उन्होंने अपने आंकड़े वर्ष 2004-2005 तथा 2005-2006 में ओपन सोसायटी संस्थान द्वारा प्रायोजित दोहरे अध्ययन से लिए हैं (सिलोवा, बुडीन और ब्रे 2006; सिलोवा, 2009 भी देखें)। जांचकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष के छात्रों को लक्षित किया और उनसे माध्यमिक स्कूली शिक्षा के अंतिम वर्ष के दौरान अपने ट्यूशन अनुभवों को बताने के लिए कहा गया। अजरबैजान, जॉर्जिया और क्रोशिया में शोधकर्ताओं ने माध्यमिक स्कूली छात्रों का एक अतिरिक्त सर्वेक्षण कराया, और इस प्रकार प्रतिवादियों के पूल और अध्ययन के दायरे का विस्तार किया। सर्वेक्षण में कुल मिलाकर प्रथम अध्ययन के अंतर्गत 8,713 और दूसरे अध्ययन में 3,101 प्रतिवादियों को लक्षित किया गया। शोध से ट्यूशन के दो प्रकार के स्वरूप का पता चला : व्यक्तिगत रूप से दिए जा रहे पाठ, और विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए संस्थाओं द्वारा दिए जा रहे तैयारी पाठ्यक्रम। प्राइवेट पाठ मंगोलिया और भूतपूर्व सोवियत संघ (विशेषकर अजरबैजान, जॉर्जिया और लिथुनिया) में अधिक प्रचलन में थे, जबकि तैयारी पाठ्यक्रम भूतपूर्व युगोस्लाविया (क्रोशिया, स्लोवाकिया, और बोसनिया तथा हेरजेगोविना) में अधिक प्रचलन में थे, जो अधिक विकसित और सुदृढ़ बाजार थे। सबसे अभूतपूर्व आंकड़े अजरबैजान के थे, जहां 90 प्रतिशत से अधिक विश्वविद्यालय के छात्रों ने सूचित किया कि उन्होंने माध्यमिक स्कूल की अंतिम कक्षा में निजी पूरक ट्यूशन प्राप्त की थी।

सारणी 2. पूर्वी यूरोप और एशिया के चयनित देशों में प्राइवेट ट्यूशन की मात्रा



स्रोत: सिलोवा (2007), पृष्ठ 5

पैवियट (2007) ने एक अलग संदर्भ में 15 शिक्षा मंत्रालयों की सहभागिता से दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका निगरानी शिक्षा गुणवत्ता परिसंघ (एसएसीएमईक्यू) के लिए एक प्रश्नावली तैयार की। वर्ष 1995 और 2000 में छठी कक्षा के छात्रों से तुलनात्मक आंकड़ों के सेट तैयार किए गए (सारणी 3)। ये आंकड़े पूरी तरह स्पष्ट नहीं थे क्योंकि इनमें उदाहरण के लिए शिक्षकों और परिवार के सदस्यों द्वारा दी जाने वाली बिना भुगतान वाली ट्यूशन तथा भुगतान करके ली जाने वाली ट्यूशन भी शामिल थी। इसके बावजूद, इससे कुछ देशों में ट्यूशन के विद्यमान होने, और उनमें हुई उल्लेखनीय वृद्धि का पता चलता है। हालांकि छठी कक्षा के औसतन 49.0 प्रतिशत बच्चों ने 1995 में पूरक ट्यूशन लेने की बात स्वीकार की थी, वर्ष 2000 तक यह आंकड़ा बढ़कर 68.3 प्रतिशत हो गया था।

यही टिप्पणी ईलोर (2007) द्वारा यूगांडा में विद्यमान पद्धति के बारे में की गई थी। उन्होंने कक्षाओं के संबंध में आंकड़ों की पुष्टि की कमी की बात स्वीकार की, लेकिन पाया (पृष्ठ 14) कि ट्यूशन व्यवस्था “सभी प्रमुख शहरी केन्द्रों में मौजूद थी और यह एक सामान्य बात थी”। ग्रामीण क्षेत्रों में ट्यूशन केवल उन्हीं कक्षाओं तक सीमित थी जहां बच्चे बड़ी परीक्षाओं में बैठते थे, लेकिन शहरी क्षेत्रों में यह सभी कक्षाओं में एक-समान थी। ईलोर ने कहा (पृष्ठ 14) कि यद्यपि ट्यूशन की तीव्रता विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न थी, लेकिन पिछले दो दशकों में इसमें जबरदस्त वृद्धि हुई और अब यह सभी उप-क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर दिखाई देती है”। छठी कक्षा के 2000 बच्चों का एसएसीएमईक्यू द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चला कि यूगांडा में 81.8 प्रतिशत बच्चे स्कूल के बाद अतिरिक्त

कक्षाएं ले रहे थे, और इनमें से 51.4 प्रतिशत बच्चों ने इन अतिरिक्त कक्षाओं के लिए भुगतान किया था (बयामुगिशा और ससेनबुलया 2005, पृष्ठ 71-72)।

सारणी 3 वर्ष 1995 और 2000 में पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में पूरक द्यूशन लेने वाले छठी कक्षा के छात्रों का प्रतिशत

	एसएसीएचईक्यूआई I (1995)		एसएसीएमईक्यू II (2000)	
	प्रतिशत	नमूने में अंतर	प्रतिशत	नमूने में अंतर
केन्या	68.6	2.53	87.7	1.91
मलावी	22.1	1.96	79.7	3.47
मॉरीशस	77.5	1.44	86.6	1.07
नामीबिया	34.7	2.08	44.7	2.33
जांबिया	44.8	2.35	55.1	3.56
जांजीबार (तंजानिया)	46.1	1.26	55.9	0.95
औसत	49.0	1.94	68.3	2.22

स्रोत: पैवियट, हेईनसोहन और कोर्कमैन (2008) पृष्ठ 152.

एक अन्य प्रकार की व्यवस्था में सुजाता (2007, पृष्ठ 3) ने भारत में चार राज्यों पर ध्यान केन्द्रित किया। 9वीं से 12वीं कक्षा (ग्रेड 9 से 12 तक) में 6,948 बच्चों का सर्वेक्षण करने पर यह बात सामने आई कि राज्यों और ग्रेडों के बीच कुछ अंतर था लेकिन औसतन 41.3 प्रतिशत बच्चे प्राइवेट पूरक द्यूशन ले रहे थे (सारणी 4)। लड़कियों की तुलना में लड़के कहीं अधिक द्यूशन ले रहे थे जिनका प्रतिशत क्रमशः 54.9 और 39.6 प्रतिशत था। ये निष्कर्ष जलालुद्दीन 2007 पृष्ठ 1 द्वारा सूचित शोध कार्य से मेल खाते हैं, जिसमें यह सुझाया गया था कि पश्चिम बंगाल में 70 प्रतिशत परिवार प्राथमिक शिक्षा स्तर पर प्राइवेट द्यूशन पर खर्च कर रहे थे, और पूरे परिवार द्वारा शिक्षा पर किए जा रहे खर्च का एक-तिहाई खर्च द्यूशन पर किया जा रहा था।

सारणी 4. ग्रेड के आधार पर भारत के चार राज्यों में प्राइवेट द्यूशन लेने वाले छात्रों का प्रतिशत

	IX	X	IX-X	XI	XII	XI-XII	IX-XII
आंध्र प्रदेश	11.3	52.7	32.3	-	-	-	-
केरल	43.0	71.6	55.0	31.5	36.0	33.5	43.7
महाराष्ट्र	43.2	56.0	49.3	41.0	38.5	40.0	44.7
उत्तर प्रदेश	31.4	62.0	45.7	31.4	38.6	34.9	40.7
औसत	32.0	58.8	44.6	36.0	53.8	36.8	41.3

टिप्पणी: आंध्र प्रदेश से लिए गए नमूने केवल 9वीं और 10वीं कक्षा के थे।

एन= कक्षा IX-X : 4,031; कक्षा XI-XII: 2,917.

स्रोत: सुजाता (2007) पृष्ठ 3

तुर्की में भी भागीदारी दर काफी अधिक पाई गई; और इसका तेजी से विस्तार हो रहा था। तनसेल और बिर्कन (2007, पृष्ठ 5-6) द्वारा द्यूशन की तीन प्रमुख श्रेणियों का पता लगाया गया था। एक श्रेणी निजी तौर पर तय मूल्य पर संबंधित विषयों पर आमने-सामने बैठकर द्यूशन लेना था। दूसरी श्रेणी स्कूल परिसर में स्कूल के अध्यापकों द्वारा द्यूशन देना था लेकिन स्कूल के बाद के घण्टों के लिए भुगतान किया जाना था। प्राथमिक स्तर के इन पाठ्यक्रमों को स्कूल बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय की अनुमति से और मंत्रालय द्वारा निर्धारित दरों पर आयोजित किया गया था। तीसरी श्रेणी प्राइवेट द्यूशन केन्द्र थे जिन्हें डेरसेन कहा जाता था और ये प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालय के छात्रों, दोनों को शिक्षा देते थे और पब्लिक सर्विस में प्रवेश के लिए पाठ्यक्रम भी उपलब्ध कराते थे। प्राइवेट द्यूशन केन्द्र 1960 के दशक के शुरू में उभरे और उन्हें 1965 में एक कानूनी ढांचे के अंतर्गत लाया गया। उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय में पंजीकरण कराना होता था; और अपनी आय पर कर का भुगतान करना होता था। वर्ष 1975-1976 में तुर्की में ऐसे 157 मान्यताप्राप्त द्यूशन केन्द्र थे। दो दशक बाद इनकी संख्या, 1,292 और 2005-2006 तक 3,986 हो गई - जो कुल माध्यमिक स्कूलों की संख्या (3,406) से अधिक थी। द्यूशन केन्द्रों में 2,076,000 माध्यमिक छात्रों (तनसेल और बिर्कन 2007, पृष्ठ 16-17) की तुलना में 1,072,000 प्राथमिक छात्र थे।

आस्ट्रिया में शिक्षा पद्धति कुछ भिन्न थी। गुबेर (2007, पृष्ठ 3) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार शिक्षा मंत्रालय के पास प्राइवेट पूरक द्यूशन के समग्र राष्ट्रीय आंकड़े, विभिन्न प्रकार की द्यूशन देने वालों के सापेक्ष महत्व, इसके उपयोग के कारणों या अलग-अलग स्कूलों द्वारा द्यूशन से निपटे जाने संबंधी कोई लेखा-जोखा नहीं था। आस्ट्रियाई कर्मचारी चेम्बर की उपभोक्ता सुरक्षा इकाई, जो द्यूशन की लागत का प्रायः सर्वेक्षण करती रहती थी, ने 2006 में अनुमान लगाया कि प्राइवेट द्यूशन पर राष्ट्र का वार्षिक व्यय €140 मिलियन था। आस्ट्रियाई कर्मचारी चेम्बर द्वारा की गई गणना विना विश्वविद्यालय द्वारा शुरू की गई अनुसंधान परियोजना के अनुरूप थी, जिसमें अनुमान लगाया गया था कि 20 प्रतिशत आस्ट्रियाई माध्यमिक स्कूल की आबादी किसी न किसी प्रकार की द्यूशन प्राप्त कर रही थी (वागेनर और अन्य, 2003 गुबेर 2007 पृष्ठ 3)।

अन्य आंकड़ों से पता चलता है कि प्राइवेट द्यूशन पश्चिमी यूरोप में अपनी महत्वपूर्ण पैठ बना चुकी है। इंग्लैंड में 1,500 माता-पिता पर 2008 में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला कि प्राथमिक विद्यालय के 12 प्रतिशत तथा माध्यमिक विद्यालय के 8 प्रतिशत छात्र प्राइवेट द्यूशन ले रहे थे (पीटर्स कारपेंटर, और अन्य, 2009, पृष्ठ 2)। फ्रांस में, 1992 में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि एक क्षेत्र में लगभग 25 प्रतिशत छात्र द्यूशन ले रहे थे (ग्लासमैन, 2007, पृष्ठ 1)। बाद के दशकों में फ्रांसिसी सरकार के प्रयासों से इस क्षेत्र का व्यापक विस्तार हुआ (मेलोत, 2007; अंगलाडे, 2008)। यूक्रेन में, वर्ष 2000

में विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष के छात्रों के सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि लगभग 30 प्रतिशत छात्रों ने *प्रॉटिसिटोरियो* नामक गहन “रट्टा लगवाने” की तैयारी कराने वाले स्कूलों में भाग लिया था, 50 प्रतिशत ने व्यक्तिगत प्राइवेट ट्यूशन ली थी, और एक तिहाई ने सामूहिक और प्राइवेट ट्यूशन ली थीं (पसाचारोपोउलस और पपाकोनस्तानटिनोऊ, 2005, पृष्ठ 105)। और आयरलैण्ड में 1,496 छात्रों; जिन्होंने वर्ष 2003 में उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी की थी, का सर्वेक्षण करने पर पता चला कि 45 प्रतिशत छात्रों ने अपने स्कूल के अंतिम वर्ष के दौरान प्राइवेट ट्यूशन पर खर्च किया था। यह वर्ष 1994 में समान आयु वर्ष में 32 प्रतिशत की काफी अधिक वृद्धि हुई थी (स्मिथ, 2009, पृष्ठ 9)।

आस्ट्रेलिया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका (यूएसए) और कनाडा की शिक्षा पद्धति पश्चिमी यूरोप में मौजूद पद्धति के अनुरूप थीं। वाटसन (2007) ने सूचित किया कि प्राइवेट ट्यूशन पर आस्ट्रेलिया में कम ध्यान दिया जाता था, लेकिन 2004 में संघीय सरकार ने उन छात्रों को प्राइवेट ट्यूशन देने के लिए एक प्रायोगिक वाउचर योजना शुरू की थी, जो तीसरे वर्ष में मुख्यधारा से पिछड़ गए थे। इस योजना से 2005 के दौरान 6,200 छात्रों को फायदा हुआ जो पात्र सहयोगियों का एक-तिहाई थे। इसके अलावा, सरकार द्वारा प्रायोजित योजना से प्राइवेट प्रयासों की संख्या बढ़ रही थी। इसी तरह की घटनाएं अमेरिका में हुई विशेषकर इन्हें नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड (एसीसीबी) कानून बनने के परिणामस्वरूप लागू हुई जो 2002 में अस्तित्व में आया था और इसने प्राइवेट ट्यूशन देने वालों के लिए सरकारी संसाधन उपलब्ध कराए हैं (असचेर 2006, बुर्च, दोनोवैन, और स्टेनवर्ग 2006; वेरगारी 2007)। कनाडा में कोई समानांतर सरकारी कानून नहीं था लेकिन इसमें भी ट्यूशन शिक्षा प्रणाली का व्यापक विकास देखने में आया। डैविस और औरिनी (2006, पृष्ठ 123) ने सूचित किया कि अपने शोध स्थलों में औपचारिक ट्यूशन संस्थानों की संख्या पिछले 30 वर्षों के दौरान 200 से 500 प्रतिशत के बीच बढ़ गई। ओनटारियो में स्कूल जाने वाले लगभग 24 प्रतिशत बच्चों ने हाल में ट्यूटर्स की सेवाएं ली थीं, और कनाडा के 50 प्रतिशत माता-पिताओं ने दावा किया कि वे ट्यूटर की सेवाएं तभी लेगे जब वे उनका खर्च उठा सकते होंगे।

लेटिन अमेरिका में अनुसंधान कम हुआ है, लेकिन क्षेत्र के कुछ भागों में विशेषकर शहरी क्षेत्रों और उच्च माध्यमिक स्तर में ट्यूशन का चलन भी देखने में आया है। उदाहरण के लिए ब्राजील में मैटोस (2007) ने रियो डे जैनेरियो और बार्रोस (2008) में ट्यूटर्स के प्रचालनों की प्रणाली की जांच की है और बाहिया में इस घटना पर विचार किया है।

बॉक्स 1. प्राइवेट ट्यूशन की पद्धतियों का वर्गीकरण

दुनिया भर में पद्धतियों की समीक्षा करने से ऐसे तरीके सामने आए हैं जिनके आधार पर देश प्राइवेट ट्यूशन की मात्रा और प्रकृति के अनुसार समूह बना सकते हैं। समूह बनाने की ऐसी प्रक्रिया सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर ट्यूशन के एक महत्वपूर्ण कार्यकलाप के रूप में उभरने पर ऐतिहासिक आंकड़ों पर आधारित होगी, जो ट्यूशन तथा प्रतिच्छाया प्रणाली और सरकारी शिक्षा नीतियों के बीच संबंधों की प्रकृति को प्रोत्साहित या सीमित करेंगे।

- *पूर्वी एशियाई देशों* जैसे जापान, हांगकांग, कोरिया और ताईवान में ट्यूशन प्रणाली एक महत्वपूर्ण गतिविधि है और यह संस्कृति में गहराई से रची-बसी है। इसका कुछ भाग कनफ्यूशियन परंपराओं से मिलता है जो शिक्षा को महत्व देती हैं और परिश्रम करने पर जोर देती हैं। ट्यूशन विशेष रूप से उच्च अंक पाने में मदद करती है।
- *भूतपूर्व सोवियत देशों और पूर्वी यूरोप* में, प्राइवेट ट्यूशन का स्वरूप 1990 के दशक के शुरू तक मामूली था, लेकिन अर्थव्यवस्था के ढहने के बाद इसमें व्यापक विस्तार हुआ और शिक्षकों को गरीबी की रेखा से ऊपर ठहरने के लिए ट्यूशन के जरिए अतिरिक्त आमदनी करने के लिए बाध्य होना पड़ा था इसमें शैक्षिक योग्यता रखने वाले छात्रों को शामिल किया जाना चाहिए।
- *पश्चिमी यूरोप में उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलेशिया* में ट्यूशन का स्वरूप पूर्वी एशिया और भूतपूर्व सोवियत देशों की तुलना में मामूली था लेकिन इसमें व्यापक विस्तार हुआ है और अब यह अधिक देखने में आता है क्योंकि नीति निर्माताओं ने स्कूलों में प्रतिस्पर्धा पर जोर दिया है और माता-पिताओं को प्राइवेट ट्यूशन में किए गए निवेश का प्रतिफल दिखने लगा है। कुछ सरकारों ने ट्यूशन को कम अंक पाने वाले बच्चों की मदद करने के रूप में प्रोत्साहित किया है।
- *अफ्रीका* में ट्यूशन का प्रचलन भी अधिक दिखाई देने लगा है। कुछ भागों में यह रुझान शिक्षा प्रणाली से आमदनी करने के अवसरों के प्रति शिक्षकों की जागरूकता दर्शाता है, जिसमें जवाबदेही और पर्यवेक्षण की कोई सुदृढ़ प्रणाली नहीं होती। इस संबंध में, अफ्रीकी शिक्षा प्रणाली दक्षिण एशिया की तरह लगती है, जहां ट्यूशन विशेषकर शहरी क्षेत्रों में रोजमर्रा की जिन्दगी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। जैसा कि भूतपूर्व सोवियत देशों में होता था, शिक्षक ट्यूशन को अपनी आमदनी बढ़ाने का जरिया समझते थे।
- *लेटिन अमेरिका* में, ट्यूशन उच्च माध्यमिक स्तर को छोड़कर अपेक्षाकृत नाममात्र की होती है। यह शिक्षा पद्धति में परंपराओं को दर्शाती है - लेकिन इसमें परिवर्तन हो सकता है, जैसा कि पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेल एशिया में हुआ है।

ये विभिन्न श्रेणियां काफी उपयोगी हैं क्योंकि ये विभिन्न नीतिगत आवश्यकताओं पर सुझाव देती हैं। इससे नियोजकों को यह नहीं समझ लेना चाहिए कि यदि ट्यूशन नाममात्र की होती है तो कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। इसके ठीक उलट यही सही समय है जब कार्रवाई किए जाने की जरूरत है क्योंकि समस्या के निदान से सावधानी बरतना कहीं बेहतर उपाय है।

तीव्रता में अंतर

आईआईईपी के पॉलिसी फोरम के दौरान प्रस्तुत आंकड़े विभिन्न प्रकार की पद्धतियों और प्राइवेट ट्यूशन की तीव्रता में प्रमुख उतार-चढ़ाव को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए नेटो-मेडेस

और कोस्टा (2007) में तीन वर्ष की अवधि के दौरान पुर्तगाली शहर में चार माध्यमिक विद्यालयों पर अपने अध्ययन की सूचना दी। इन स्कूलों की 12वीं कक्षा से आंकड़े एकत्र किए गए थे। सारणी-5 में चार स्कूलों के वर्ष 2005-2006 के आंकड़े दर्शाए गए हैं जिनमें एकरूपता बनाए रखने के लिए रंगों के आधार पर नाम रखा गया है। 52 से 65% बच्चे ट्यूशन ले रहे थे। अधिकांश बच्चे एक सप्ताह में 1 से 3 घंटों तक, लेकिन बहुत से बच्चे एक सप्ताह में 4 से 10 घंटों तक और कुछ बच्चे सप्ताह में 10 से अधिक घंटों तक प्राइवेट ट्यूशन ले रहे थे। स्वाभाविक है ये अवधियां लागत से संबंधित थीं।

सारणी 5. वर्ष 2005-2006 में पुर्तगाल के चार स्कूलों में 12वीं कक्षा के छात्रों द्वारा ट्यूशन लेने वालों की अवधि

स्कूल	छात्रों की संख्या	ट्यूशन प्राप्त करने का %	- ट्यूशन में व्यतीत घंटे/सप्ताह -				- मासिक लागत (€) -			
			1-3	4-10	10+	एनए	70	71-210	210+	एनए
ब्लू स्कूल	161	65%	54%	42%	2%	2%	31%	56%	7%	6%
येलो स्कूल	97	52%	56%	36%	4%	4%	46%	50%	-	4%
ग्रीन स्कूल	122	52%	59%	38%	-	3%	38%	53%	3%	6%
पिंक स्कूल	167	63%	54%	45%	1%	-	24%	66%	8%	2%

एन.ए. = कोई उत्तर नहीं

स्रोत: नेटो-मंडेस और कोस्टा (2007), पृष्ठ 7

पुर्तगाल के बारे में आंकड़े शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2005 में कराए गए सर्वेक्षण से प्राप्त हुए थे जिसमें राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षाओं के 31,035 उम्मीदवारों को शामिल किया गया था (कोस्टा, नेटो-मंडेस और वेनतुरा, 2008)। सर्वेक्षण से पता चला कि उनमें से 54.7 प्रतिशत छात्रों ने 10वीं और 12वीं कक्षा में प्राइवेट ट्यूशन ली थी। निस्संदेह यह ट्यूशन प्राप्त करने का सबसे अहम चरण है क्योंकि केवल 7.7 प्रतिशत प्रतिवादियों ने ही 7वीं से 9वीं कक्षा में और मात्र 15 प्रतिशत ने 5वीं और 6वीं कक्षा में ट्यूशन ली थी। जिन छात्रों ने ट्यूशन ली थी, उनमें से 55.9 प्रतिशत सर्वेक्षण पूरे शैक्षिक वर्ष के दौरान नियमित रूप से ट्यूशन ले रहे थे। इसके अलावा, 27.5 प्रतिशत छात्रों ने वर्ष के दौरान जबकि 16.6 प्रतिशत ने केवल परीक्षा से पहले ट्यूशन ली थी।

परीक्षाओं से ठीक पहले ट्यूशन लेने की बढ़ती प्रवृत्ति यूरोप देशों में भी देखी गई है। उदाहरण के लिए, मॉरोशस में प्राथमिक विद्यालय की समाप्ति पर तथा निम्न और उच्च माध्यमिक विद्यालय में महत्वपूर्ण परीक्षाएं होती हैं जिसके दौरान प्राइवेट ट्यूशन अपने चरम पर होती है। (ओबीगाडू, 2007)। नामिबिया में, 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं से पहले ट्यूशन की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी दिखाई देती है (नगहीयोमानए, 2007)। वियतनाम और सिंगापुर में ट्यूशन में बढ़ोतरी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के अंतिम वर्षों में तुलनात्मक स्तर पर होती है (डैंग, 2007; टैन, 2009)।

सारणी-6 में चार भारतीय राज्यों के आंकड़े दर्शाए गए हैं जो छात्रों द्वारा ली जाने वाली द्यूशन की अवधि और विषयों की संख्या दर्शाते हैं। निम्न माध्यमिक स्तर पर केरल में प्राइवेट द्यूशन लेने की प्रवृत्ति सबसे अधिक है (देखें उपर्युक्त सारणी 4) जबकि आंध्र प्रदेश में यह प्रवृत्ति सबसे कम है। उच्च माध्यमिक स्तर पर छात्रों द्वारा आंशिक रूप से अनेक विषयों में द्यूशन लेने की संभावना कम थी, क्योंकि पाठ्यक्रम में मातृभाषा, अंग्रेजी, हिन्दी, गणित, सामान्य विज्ञान और सामाजिक शास्त्र जैसे मुख्य विषय शामिल थे। सर्वेक्षण के अंतर्गत 90 प्रतिशत से अधिक छात्रों ने गणित विषय में द्यूशन ली, इसके बाद सबसे आम विषय विज्ञान और अंग्रेजी थे (सुजाता 2007, पृष्ठ 12)। केरल में, 98.8 प्रतिशत छात्रों ने गणित में द्यूशन ली थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में यह अनुपात केवल 73.0 प्रतिशत था क्योंकि उस राज्य में गणित अनिवार्य नहीं है। उच्च माध्यमिक स्तर पर विज्ञान और गणित विषय के छात्रों द्वारा अन्य विषय के छात्रों की तुलना में अधिक द्यूशन लिए जाने की संभावना थी (सारणी)।

सारणी 6. भारत में वर्ष 2005 में विभिन्न विषयों में द्यूशन लेने वाले छात्रों का प्रतिशत

राज्य	निम्न माध्यमिक				उच्च माध्यमिक			
	1 विषय	2 विषय	3 विषय	सभी विषय	1 विषय	2 विषय	3 विषय	सभी विषय
आंध्र प्रदेश	58.1	36.7	3.4	1.7	-	-	-	-
केरल	7.0	12.9	12.4	67.6	18.8	47.4	13.1	20.7
महाराष्ट्र	12.0	21.8	55.3	10.9	38.0	55.9	6.1	0.0
उत्तर प्रदेश	7.8	21.0	46.8	24.3	35.1	40.6	21.7	2.6
औसत	13.3	20.7	39.1	27.0	33.0	49.5	12.4	5.1

स्रोत: सुजाता (2007), पृष्ठ 11.

सारणी 7. भारत में वर्ष 2005 में विभिन्न विषयों में द्यूशन लेने वाले उच्च माध्यमिक छात्रों का प्रतिशत

विषय	केरल	महाराष्ट्र	उत्तर प्रदेश	योग
विज्ञान और गणित	45.4	55.7	52.1	52.3
कला	23.4	19.4	15.0	17.5
वाणिज्य	20.1	17.8	47.4	19.8
अन्य	0.0	1.6	10.0	4.3

स्रोत: सुजाता (2007) पृष्ठ 13

जब द्यूशन के घंटों को स्कूल के घंटों में जोड़ा जाता है तो शिक्षा की अवधि बहुत लंबी हो जाती है। यह तथ्य सोउ (2007, पृष्ठ 5) द्वारा मैकाओ, चीन के संदर्भ में उजागर किया गया था। प्राथमिक छात्रों के लिए सरकारी शिक्षण समय साढ़े पांच घंटे था लेकिन

छात्र सामान्यतः और दो से चार घंटे ट्यूशन प्राप्त कर रहे थे, जिससे पूरे दिन में शिक्षण समय 7.5 से 9.5 घंटे हो गया था। माध्यमिक स्तर पर सरकारी शिक्षण दिवस 7 घंटे तक था लेकिन छात्र आमतौर पर दो से तीन घंटे और पढ़ रहे थे जिससे कुल समय 9 से 10 घंटे हो गया। सोउ ने टिप्पणी की (पृष्ठ 5) कि ट्यूशन के घंटों की वृद्धि ने “समय के सामान्य आबंटन के अनुपात का गंभीर रूप से उल्लंघन किया है”।

प्रणाली में अंतर

ट्यूशन कई प्रणालियों के माध्यम से दी जा सकती है जो नई प्रौद्योगिकियों के आने से विकसित हो रही है। अधिकांश ट्यूशन व्यक्तिगत रूप से दी जाती है, लेकिन कुछ ट्यूशन फोन पर, दूरदर्शन और इंटरनेट से भी दी जाती है। इससे पहले काफी ट्यूशन पत्राचार पाठ्यक्रम के रूप में दी जाती थी लेकिन अब इसका स्थान वेबसाइटों और ई-मेल ने ले लिया है।

व्यक्तिगत ट्यूशन का स्वरूप भी काफी भिन्न हो सकता है। अच्छी आय वाले परिवार अपने बच्चों के लिए ट्यूटर लगा सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, छात्र ट्यूशन को छोटे समूहों, बड़े समूहों और बड़े आकार वाले लेक्चर हॉल में ले सकते हैं जहां अनेक कक्षाओं में वीडियो लिंक होते हैं। इन विभिन्न प्रणालियों का अध्ययन, प्रयोक्ता की लागत और सरकारी नीतियों पर विभिन्न प्रभाव पड़ता है।

कुछ देशों में स्कूल के अध्यापकों द्वारा प्राइवेट पूरक ट्यूशन दी जाती है और उन पर अपने बच्चों की भी जिम्मेदारी होती है। हालांकि पहली नज़र में यह अध्यापकों के लिए फायदेमंद दिखाई देता है कि वे उन छात्रों को और अधिक सहायता दे सकेंगे जिन्हें वे जानते हैं। किंतु यह व्यवस्था बड़ी समस्याएं भी पैदा कर सकती है। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह हो सकता है कि इसमें ब्लैकमेल की भी गुंजाइश रहेगी। अध्यापक स्कूल में पाठ पढ़ाने के दौरान पाठ्यक्रम छोड़ सकते हैं जिससे स्कूल के घंटों के बाद प्राइवेट ट्यूशन के बाजार का विस्तार किया जा सके। चूंकि अनेक शिक्षा प्रणालियों में अध्यापक यह निर्णय करते हैं कि कौन से छात्रों को अगली कक्षा में भेजा जाए, अतः माता-पिता ट्यूशन के इस मकड़जाल में फंस जाएंगे और उन्हें उसके लिए भुगतान करना होगा, क्योंकि वे भली-भांति जानते हैं कि ऐसा न करना अंततः उन्हें महंगा पड़ेगा, और उनके बच्चों को उसी कक्षा में एक साल और गुज़ारना पड़ेगा।

ट्यूशन कार्यक्रमों का प्रसारण करने के लिए दूरदर्शन का प्रयोग अलग-अलग देशों में भिन्न-भिन्न हो सकता है जैसा कि कोरिया और दक्षिण कोरिया में है। दक्षिण अफ्रीका में कार्यक्रम पब्लिक और पे-टू-व्यू चैनल दोनों पर उपलब्ध होते हैं (रेड्डी, 2007, पृष्ठ 14)। ट्यूटर विषय निर्धारित कर सकता है और उसे स्कूल से जोड़ सकता है, जहां से छात्र अपने प्रश्न भेजते हैं और ट्यूटर उन्हें उदाहरण देकर समझाता है। लेकिन इस प्रणाली में प्रायः बच्चों और ट्यूटर में अधिक बातचीत नहीं हो सकती और इसमें शायद ही कभी कोई

व्यक्तिगत संबंध कायम हो पाता है। प्रसारण से ट्यूटर और छात्रों के बीच की दूरी कम होती है, लेकिन ये प्रायः राष्ट्रीय सीमाओं तक ही सीमित रहते हैं।

इंटरनेट ट्यूशन की दूरी को अधिक कारगर ढंग से कम करता है, और इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार भी उपलब्ध कराया जा सकता है (वेनतुरा 2008ए)। ई-मेल, इंटरनेट टेलिफोन, और वेब कैमरों से विशिष्ट ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सेवा दी जा सकती है। ऐसे ट्यूटर जो अपने छात्रों से सीधे मिलते हैं, को घनी आबादी में अपना कारोबार खोलना पड़ता है ताकि उन्हें पर्याप्त संख्या में छात्र मिलते रहें, और उनका यह स्थान प्रायः परिवहन से जुड़ा होता है। इंटरनेट द्वारा ट्यूशन शहरी क्षेत्रों के अलावा दूर-दराज में बसने वाली जनता को भी दी जा सकती है और इसे किसी भी सुविधाजनक भाषा में दिया जा सकता है। इस प्रकार, उदाहरण के लिए भारत में ट्यूटर, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से अमेरिका में अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान कर सकते हैं; और चीन के ट्यूटर हांगकांग, मलेशिया या सिंगापुर में चीनी भाषा के माध्यम से अपने ग्राहकों को सेवा प्रदान कर सकते हैं।

इस टिप्पणियों से पता चलता है कि ट्यूशन का स्वरूप ट्यूशन पढ़ाने और पढ़ने वाले दोनों से तय होता है। माध्यमिक स्कूल के छात्रों के अधिकांश ट्यूटर विश्वविद्यालय के छात्र होते हैं जो अतिरिक्त आय कमाना चाहते हैं; और इसी प्रकार कुछ प्राथमिक छात्रों को माध्यमिक स्कूल के छात्रों द्वारा ट्यूशन दी जाती है। माध्यमिक स्कूल के छात्रों की तरह ही विश्वविद्यालय के छात्रों में शायद ही कोई पेशेवर अध्यापक की योग्यता होती है। तथापि वे छात्रों के साथ बेहतर तालमेल बना सकते हैं क्योंकि वे समान आयु वर्ग के होते हैं।

दूसरी ओर सेवा-निवृत्त कर्मचारी भी हैं जो समाज में योगदान देना चाहते हैं और अतिरिक्त आय कमाना चाहते हैं। चूंकि वे पुरानी पीढ़ी के होते हैं अतः सेवा-निवृत्त अध्यापकों के पढ़ाने की शैली भी भिन्न होती है और उनके कंप्यूटर आधारित ज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) में दक्ष होने की संभावना कम होती है। इनमें से कुछ सेवा-निवृत्त अध्यापक स्कूल प्रणाली में पूर्णकालिक अध्यापक होते हैं जिन्हें विनियमों द्वारा बाध्य होकर सेवा-निवृत्त कर दिया जाता है। ट्यूशन के बाजार में सरकारी सेवा-निवृत्ति जैसे कोई उम्र नहीं होती और यह मूल्य तथा दी जाने वाली सेवा के बीच संतुलन पर अधिक निर्भर करती है।

प्राइवेट ट्यूशन हमेशा से ही अनौपचारिक रूप से प्रचलन में रही है, यह क्षेत्र लगातार संगठित और कर्मशायल होता जा रहा है। इस बात के भी संकेत मिले हैं कि शिक्षा प्रणाली में ट्यूशन एक परछाई की तरह निरंतर दी जा रही है। इसके लिए कंपनियां स्थापित हो चुकी हैं जो छोटी और स्थानीय, या बड़ी और बहुराष्ट्रीय स्तर की हैं। एक जानी-मानी बहुराष्ट्रीय फर्म कुमोन है, जो जापान में 1954 में अस्तित्व में आई थी, जब इसके संस्थापक

तोरू कमोन (1914-1995) ने अपने पुत्र के गणित विषय में सुधार करने का तरीका निकाला था। आधी सदी बाद कुमोन फ्रैंचाइज़ी प्रणाली के जरिए प्रचालन करते हुए 45 देशों में 4 मिलियन छात्रों को गणित और भाषाओं, दोनों में सेवाएं प्रदान कर रहा था (कुमोन, 2008)। अन्य द्यूशन फ्रैंचाइज़ में सिलवन, द अकेडमी फॉर मेथेमेटिक्स एंड साइंस, और द ओक्सफोर्ड लर्निंग सेंटर शामिल हैं। डैविएस एंड औरिनी (2006, पृष्ठ 124) ने नोट किया कि व्यवसाय में वृद्धि होती है, और इसने कनाडा में द्यूशन फ्रैंचाइज़ के विकास में नाटकीय भूमिका निभाई।

प्रौद्योगिकी भी विविध अवसर प्रदान करती है। इसका एक उदाहरण स्कूल सिटी है। यह जापानी जुकु नामक एक नई शैली है जो छात्रों को पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क (सुजुकी, 2009) के जरिए घर या क्षेत्रीय केन्द्रों में छात्रों को पढ़ने का अवसर प्रदान करती है। नेट-स्कूल द्वारा उपलब्ध कराए गए पाठ्यक्रमों के तीन मॉड्यूल हैं: (i) टीवी कांफ्रेंसिंग और पाठ; (ii) वेबसाइट द्वारा स्वाध्ययन, और (iii) मुद्रित सामग्री द्वारा अध्ययन। स्कूलसिटी का अपना निजी संगठनात्मक ढांचा है, और यह उन तरीकों को अभिव्यक्त करता है जिसमें द्यूशन का अपना निजी स्वरूप हो सकता है, और ये मुख्य शिक्षा प्रणाली की मात्र नकल नहीं होती। स्कूलसिटी जिन “शहरों” में संचालन करता है उनके अपने पाठ्यक्रम और ग्राहक हैं, जो व्यापक भौगोलिक क्षेत्रों को कवर करते हैं। स्कूलसिटी की सहायक कंपनियां भी हैं जो विज्ञापन, सॉफ्टवेयर, मूल्यांकन प्रणालियों और व्याख्या पर ध्यान केन्द्रित करती हैं।

यहां प्रणाली में उल्लिखित विविधता नीति-निर्माताओं और योजनाकारों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है जो यह तय करना चाहते हैं कि “किस प्राइवेट द्यूशन के लिए क्या सरकारी नीतियां” होनी चाहिए? इसलिए:

- पूरी तरह बाजार पर आधारित द्यूशन को सरकारी प्रोत्साहन द्वारा पूर्णतया या आंशिक रूप से दी जाने वाली द्यूशन से बिल्कुल अलग माना जाना चाहिए; जिस तरह अमेरिका में *नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड* कानून के अंतर्गत उल्लेख किया गया है।
- दूसरे देशों से इंटरनेट द्वारा द्यूशन लेने की नीति का प्रभाव आवासीय क्षेत्रों में खुली दुकानों द्वारा पंजीकृत द्यूशन देने वाले व्यक्ति से काफी भिन्न होता है।
- ऐसे अध्यापक, जिन पर छात्रों को स्कूल में पढ़ाने का दायित्व है, द्वारा अनिवार्य आधार पर द्यूशन पढ़ाना कोचिंग से काफी अलग होता है जिसे माता-पिता अपने निजी प्रयासों से सक्रिय रूप से ढूंढते रहते हैं।
- अप्रशिक्षित माध्यमिक स्कूल या विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा दी जाने वाली द्यूशन प्रशिक्षित पेशेवरों द्वारा दी जाने वाली द्यूशन से काफी अलग होती है।
- आमने-सामने बैठकर दी जाने वाली द्यूशन विशाल वीडियो स्क्रीन वाले बड़े व्याख्यान थियेटर्स से काफी भिन्न होती है।

अब जबकि इन सभी विभिन्न प्रकारों का वर्गीकरण किया जा चुका है, नीति-निर्माता और योजनाकार आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाएंगे। तदनुसार, इन आयामों पर इस पुस्तक के अगले अध्याय में ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

बॉक्स 2. मूल्यांकन आधारित निर्णय करना

“स्पष्ट है कि प्राइवेट ट्यूशन अपने आप में न तो अच्छी है और न ही बुरी। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कैसे, और किन परिस्थितियों में दिया जाता है। क्या इसे स्कूल के अध्यापकों, बाहरी ट्यूटोरों, या प्राइवेट सेंटर द्वारा दिया जाता है? क्या अध्यापक ट्यूशन पाठ अपने छात्रों या दूसरे छात्रों को पढ़ा रहे हैं? क्या प्राइवेट ट्यूशन नियमित स्कूली शिक्षा की पूरक है? क्या यह स्कूली शिक्षा प्रणाली को अलग तरह से विकृत करती है?” (पॉइसन, 2007, पृष्ठ 4)

आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक प्रभाव

पिछले अध्यायों से पता चलता है कि ट्यूशन की मात्रा, तीव्रता और प्रणालियां विविध हैं। ये तथ्य आर्थिक प्रणाली, संस्कृति और अन्य परिवर्तकों के साथ मिलकर ट्यूशन व्यवस्था के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक प्रभाव का पता लगाने के लिए चुनौती उत्पन्न करते हैं। इसके बावजूद, तुलनात्मक विश्लेषण से काफी कुछ सीखा जा सकता है।

आर्थिक प्रभाव

इसमें कोई सदेह नहीं कि प्राइवेट ट्यूशन दुनिया के कुछ हिस्सों में एक बड़ा व्यवसाय है। अन्य देशों की तुलना में कहीं भी यह बात स्पष्ट दिखाई नहीं देती जहां प्राइवेट ट्यूशन पर 2006 में अनुमानित कुल घरेलू व्यय 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर, या सकल घरेलू उत्पाद का 2.8 प्रतिशत था (किम और ली, 2008, पृष्ठ 3)। कोरियाई ट्यूशन उद्योग ट्यूटोरों और उनसे जुड़े कर्मचारियों की आय का स्रोत है, जिनकी व्यय पद्धति का व्यापक आर्थिक प्रभाव पड़ा है। प्राइवेट ट्यूशन पर परिवार द्वारा किए जाने वाले खर्च के अन्य उदाहरण हैं:-

- *फ्रांस* में, इस क्षेत्र का अनुमानित मूल्य 2006 में लगभग € 2.21 बिलियन था, और यह प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा था (मेलोत, 2007, पृष्ठ 50)।
- *यूक्रेन* में, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर क्लैम स्कूलों द्वारा 2000 में € 1.1 बिलियन खर्च किया जा रहा था, जो उस स्तर पर सरकार द्वारा शिक्षा पर किए जा रहे खर्च से अधिक था (पसाचारोपोउलोस और तासोउलास, 2004, पृष्ठ 247)।
- *तुर्की* में, वर्ष 2004 में ट्यूशन केन्द्रों की अनुमानित लागत 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 0.96 प्रतिशत बैठती है-यद्यपि अन्य अनुमान कम थे। (तैनसेई और बिरकन, 2007, पृष्ठ 14)।

- *मिस्र* में, वर्ष 2002 में परिवारों द्वारा विश्वविद्यालय-पूर्व स्तर पर ट्यूशन पर प्रतिवर्ष 8 मिलियन मिस्रियाई पाउण्ड (लगभग 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर) खर्च किए जाने का अनुमान था, जो सकल घरेलू उत्पाद के 1.6 प्रतिशत के बराबर था (विश्व बैंक, 2002, पृष्ठ 26)।

इसके अलावा, निस्सदेह ट्यूशन की आर्थिक भूमिका कहीं अधिक मामूली है। लेकिन यह उन अध्यापकों की आय में आज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है जिनका वेतन कम है और जिन्हें अपने परिवार के लिए पर्याप्त आय सुनिश्चित करने हेतु ट्यूशन का सहारा लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। उदाहरण के लिए श्रीलंका में वर्ष 2007 में एक स्नातक सरकारी रोजगार-प्राप्त अध्यापक का मासिक वेतन 108 से 135 अमेरिकी डॉलर के बीच था (सामथ, 2007, पृष्ठ 1)। यह वेतन कारपोरेट क्षेत्र की तुलना में बहुत कम था लेकिन कोलंबो स्कूल का एक गणित अध्यापक प्राइवेट ट्यूशन के द्वारा प्रति घंटा 10 अमेरिकी डॉलर तक कमा सकता था - जो 3 से 4 दिन के सरकारी वेतन के बराबर था। ताजिकस्तान में, वर्ष 2006 में अध्यापक अपने सरकारी वेतन से औसतन प्रतिमाह 24 डॉलर कमाते थे, जबकि प्राइवेट ट्यूशन से वे प्रतिघंटा 1 से 2 डॉलर प्रतिघंटा कमाते थे (कोडिरोव और अमोनोव, 2009, पृष्ठ 144) विश्वविद्यालय छात्र, जो पार्ट टाइम ट्यूशन करते हैं, द्वारा अर्जित की जाने वाली आय भी उन्हें आर्थिक लाभ दिला सकती है क्योंकि इस आय से छात्र अपने अध्ययन को जारी रख सकते हैं और ऐसी दक्षता प्राप्त कर सकते हैं जो आर्थिक विकास में योगदान करती है।

ट्यूटर्स की आय से हटकर हम छात्रों की पढ़ाई पर ध्यान केन्द्रित करने संबंधी आर्थिक सिद्धांत यह सुझाते हैं कि गणित और भाषा में दक्षता अर्जित करना मानव पूंजी का एक महत्वपूर्ण रूप हो सकती है जो आर्थिक विकास में योगदान दे सकती है। निस्सदेह या पूछा जाना आवश्यक होगा कि यदि व्यक्ति पढ़ नहीं रहा होता तो वह क्या कर रहा होता, और इस प्रकार अवसर की लागत का जायजा लिया जा सकता है; लेकिन स्कूल प्रणाली में युवाओं के लिए आर्थिक दृष्टि से अवसर लागत अपेक्षाकृत कम होंगे क्योंकि वे अभी आर्थिक रूप से उत्पादक नहीं बनना चाहेंगे।

इसके साथ-साथ कुछ परिस्थितियों में ट्यूशन चयन प्रणाली की अपनी भूमिका के जरिए संसाधनों के आबंटन में कुछ अदक्षता को प्रोत्साहित कर सकती है। किम और ली (2008, पृष्ठ 31) ने पाया कि कोरिया में:

इस बात को देखते हुए कि वित्तीय बाजार सही नहीं है, अतः गरीब माता-पिता के अत्यधिक योग्य बच्चों के विश्वविद्यालय स्तर पर कम अंक आएंगे, क्योंकि वह प्राइवेट ट्यूशन का बिल चुकाने की स्थिति में नहीं होते। प्राइवेट ट्यूशन के इस असमान वितरण से मामूली परिवारों में योग्यता के साथ न्याय एक जैसा नहीं होगा।

अन्य पर्यवेक्षकों ने भी यह तर्क देते हुए अदक्षता का उल्लेख किया है कि ट्यूशन अन्य उत्पादक प्रयोक्ताओं से संसाधनों को अपवर्तित करती है। इसमें समस्या वहां उत्पन्न

होती है जहां अध्यापक स्कूल में जानबूझकर न पढ़ाकर पूरक ट्यूशन की मांग को बढ़ाने के लिए पूरी निष्ठा से नहीं पढ़ाते। उदाहरण के लिए सुजाता (2007, पृष्ठ 20) ने टिप्पणी की कि भारत में:

... प्राइवेट ट्यूशन करने वाले अध्यापक कक्षा में पूरी निष्ठा से नहीं पढ़ाते और छात्रों को बार-बार उनसे या किसी कोचिंग सेंटर से ट्यूशन लेने के लिए मजबूर करते हैं। इस प्रकार, स्कूल अध्यापकों और प्राइवेट ट्यूशन केन्द्रों के बीच आपसी रिश्ता होता है।

एक अन्य आर्थिक पहलू कर से जुड़ा है। अधिकांश ट्यूशन अनौपचारिक रूप से दी जाती है और यह सरकारी कर ग्रहणकर्ता के दायरे से बाहर होती है। सरकारी प्राधिकारियों को ऐसा लगता है कि जिन लोगों को कर देना चाहिए, वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। और इसके विपरीत वास्तविकता यह है कि कर से होने वाली आय बहुत कम होती है जिसे सरकारें अपने निजी आर्थिक या सामाजिक कल्याण उद्देश्यों को पूरा करने के लिए खर्च नहीं कर सकतीं।

सामाजिक प्रभाव

प्राइवेट ट्यूशन के अनेक रूप सामाजिक असमानता को बढ़ावा देते हैं क्योंकि अधिक आय वाले परिवार कम आय वाले परिवारों की तुलना में अधिक और बेहतर ट्यूशन की व्यवस्था कर सकते हैं। इस पद्धति का मुख्य उत्पाद सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं हैं जैसे अमेरिका में *नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड* परियोजना, जिसमें प्राधिकारी कम अंक प्राप्त करने वालों को संसाधन उपलब्ध कराते हैं जिनकी अपेक्षाकृत कम आय होती है ताकि वे ट्यूशन में निवेश कर सकें।

परिवार का दबाव और सामाजिक स्थल

ट्यूशन उन परिस्थितियों का हिस्सा हो सकती है जिसमें परिवारों पर सामाजिक दबाव रहता है। किम (2007, पृष्ठ 11) द्वारा रिकार्ड की गई एक कोरियाई माँ के शब्दों में माँ-बाप द्वारा अपने बच्चों को ट्यूशन भेजने का एक बड़ा कारण उनकी चिंता है: “यदि बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है और किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में नहीं जाता तो लोग कहेंगे या तो उसकी माँ पागल है या गरीब है।” ट्यूशन का विस्तार परिवार के ढांचे में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है (किम 2007, पृष्ठ 12):

कोरियाई परिवार में एक या दो बच्चे होते हैं। उनके माँ-बाप के समय में तीन से पाँच बच्चे हुआ करते थे। परिवार में बच्चों की घटती संख्या और अच्छे कॉलेज की साख, व्यक्तिगत पहचान बनाने के महत्व को ध्यान में रखते हुए युवा माता-पिता पिछली पीढ़ी के माता-पिता की तुलना में अपने बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि पर व्यक्तिगत रूप से अधिक ध्यान देना चाहते हैं। युवा माता-पिताओं के लिए स्कूल

उनकी मांग को उचित प्रकार से पूरा नहीं करता: स्कूल छात्रों का एक समूह के रूप में ध्यान रखते हैं न कि व्यक्तिगत रूप से।

इसी प्रकार की एक टिप्पणी फ्रांस के बारे में की जा सकती है, जहां परिवार पिछली पीढ़ी की तुलना में अधिक छोटे हैं, और माता-पिता तथा बच्चों के अपने दादा-दादी के पास रहने की कम संभावना रहती है और इस प्रकार उनसे कम मदद मिलने की उम्मीद होती है। ग्लैसमैन (2007, पृष्ठ 1) ने आगे बताया कि जो माता-पिता ट्यूशन का बोझ उठा सकते हैं, उनके लिए प्राइवेट ट्यूशन परिवार में सुख-शांति बनाए रखने का एक तरीका है। गृहकार्य. . .

. . . कुछ परिवारों में माता पिता और उनके बच्चों (विशेषकर जब वे किशोरावस्था में होते हैं) के बीच “तनाव का कारण” होता है। परिणामस्वरूप, बच्चे को किसी प्राइवेट ट्यूशन सेंटर- या किसी तीसरी पार्टी के पास उसके स्कूल कार्य या स्कूल प्रशिक्षण में मदद करने के लिए भेजना तनाव को दूर करना है जिससे परिवार के सदस्यों में सौहार्दपूर्ण संबंध बना रहता है। माता-पिता के लिए बच्चों को गृहकार्य कराना मुश्किल काम होता है विशेषकर जब उनके बच्चे काम न करना चाहते हों। कोई किशोर, जिसे स्कूल में पाठ्यक्रम का कोई पाठ समझ में न आया हो, को समझाना आसान कार्य नहीं होता, भले ही उसके पिता या माता उसी विषय में अच्छी जानकारी क्यों न रखते हों। इसलिए यह अधिक अच्छा होता है कि यदि समस्याओं का कहीं और समाधान किया जाए।

इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए ग्लैसमैन ने टिप्पणी की कि माता-पिता और बच्चों के बीच स्कूल की तुलना में स्कूल के बाहर किसी संस्था की मदद से शांति बनाए रखना अधिक आसान होता है:

स्कूल के बाहर किसी ढांचे को एक मध्यस्थ स्थल के रूप में देखा जा सकता है जो न तो परिवार (जहां ऊपर उल्लेख किए गए अनुसार उच्च अपेक्षाएं और तनाव होता है), न ही स्कूल (जो मूल्यांकन करता है, अंक देता है, आदि) होता है। ऐसे मध्यस्थ स्थल में छात्र सहज रूप से यह स्वीकार कर सकते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आया या उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आया भले ही ऐसी बात न हो, या उन्होंने वास्तव में तैयारी नहीं की है भले ही उन्होंने की हो, वे कोशिश कर सकते हैं, वे गलत हो सकते हैं और दोबारा प्रयास कर सकते हैं, और धीरे-धीरे वे अधिक से अधिक आत्म-विश्वास पैदा कर सकते हैं, जो उनके परीक्षा परिणाम के ख़ाफ़े से उन्हें निज़ात दिलाता है।

एक अलग पृथक आयाम के रूप में ट्यूशन बच्चों के लिए समाज में अलग स्थान भी बनाता है जो वे स्कूल या परिवार में नहीं पा सकते। उदाहरण के लिए, मित्र में अधिकांश माध्यमिक स्कूल लड़के-लड़कियों के आधार पर अलग-अलग हैं। प्राइवेट शिक्षा छात्रों को दोस्तों से विशेषकर लड़के और लड़कियों को आपस में मिलने का सुअवसर प्रदान

करती है। हार्टमैन (2008, पृष्ठ 58) ने ट्यूशन केन्द्र के एक प्रबंधक के विचारों का उल्लेख किया है: “मैं समझता हूँ कि लगभग 50: छात्र यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं . . . क्योंकि वे वास्तव में कुछ सीखने के लिए आते हैं, जबकि अन्य 50: दोस्तों से मिलने के लिए आते हैं।”

जेंडर आयाम

जेंडर आयाम को देखते हुए ट्यूशन अन्य चीजों के साथ अलग ढंग से पेश आ सकती है। इनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण नामांकन में विसंगतियाँ होना हैं। 2007 के आईआईपी पॉलिसी फोरम में तनसेल और बिर्कन (2007, पृष्ठ 7) ने नोट किया कि विकासशील देशों में लड़कियाँ शिक्षा में लड़कों की तुलना में पिछड़ रही हैं और “तुर्की भी कोई अपवाद नहीं है”। उन्होने आगे कहा कि यद्यपि तुर्की में महिला शिक्षा को मिलने वाले आर्थिक लाभ कहीं अधिक या संभवतः पुरुष की शिक्षा से अधिक थे, फिर भी लड़कों को माता-पिता के बुढ़ापे की लाठी समझा जाता है। तनसेल और बिर्कन ने सूचित किया (पृष्ठ 18) कि वर्ष 2005-2006 में छात्रों में लड़के-लड़कियों में अंतर 5 प्रतिशत था, यानी पूरे नामांकन को 52.5 प्रतिशत लड़कों और 47.5 प्रतिशत लड़कियों में विभाजित किया गया था। हालांकि माध्यमिक स्कूल के स्नातकों को देखते हुए यह अंतर छोटा था जहाँ अंतर 9.2 प्रतिशत था (54.6 प्रतिशत लड़के, 45.4 प्रतिशत लड़कियाँ)। इस संबंध में ट्यूशन केन्द्रों में माध्यमिक स्कूल प्रणाली की तुलना में लड़के-लड़कियों के बीच अंतर कम था। इसका एक स्पष्टीकरण यह हो सकता है कि उच्च आय वाले परिवार लड़कों और लड़कियों, दोनों को ट्यूशन दिलाते हैं, और इस तरह निम्न आय वर्ग के परिवारों की तुलना में लड़के-लड़कियों में कम मतभेद किया जाता है।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सुजाता (2007) द्वारा भारत में लड़के-लड़कियों के बीच असंतुलन पर भी टिप्पणी की गई थी, जहाँ लड़कों को अधिक संख्या में ट्यूशन भेजने का स्पष्टीकरण सांस्कृतिक और आर्थिक दोनों पहलुओं को प्रभावित कर सकता है। अन्य देशों से प्राप्त आंकड़े जिनमें इस पद्धति का समर्थन किया गया है, में निम्नलिखित शामिल हैं:

- *केन्या* में बुचमान (2002, पृष्ठ 142-143) ने प्रमुख शिक्षा प्रणाली में नामांकन की समानता में महत्वपूर्ण प्रगति नोट की गई लेकिन आगे कहा कि नौकरी की संभावना को और घर के काम में बच्चों के संभावित योगदान को देखते हुए लड़का-लड़की में भेद करने का अर्थ है कि “माता-पिता अपनी लड़कियों को अतिरिक्त शिक्षा दिलाने में कम रुचि रखते हैं, विशेषकर ऐसे मामलों में जहाँ परिवार के स्रोत बहुत सीमित हों (अर्थात् गरीब या अधिक बच्चे वाले परिवारों में)।” बुचमान ने बताया कि लड़कों की तुलना में लड़कियाँ, घर का काम अधिक करती हैं और पाया कि इससे प्रतिच्छाया शिक्षा में उनके भाग लेने के अवसर कम हो जाते हैं।

- कोरिया में किम और ली (2008, पृष्ठ 25) द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि प्राइवेट ट्यूशन के लिए मांग आय के आधार पर थी अर्थात् लड़कों के लिए 0.51 और लड़कियों के लिए 0.57. इसका अर्थ है कि लड़कों के लिए प्राइवेट ट्यूशन को अच्छा माना जाता था, जबकि लड़कियों के लिए यह लगजरी के तौर पर अच्छी थी। किम और ली ने नोट किया कि महिलाओं के लिए बलात मजदूरी भागीदारी दर पुरुषों की तुलना में काफी कम थी, और परिणामस्वरूप अनुमानित प्रतिलाभ पुरुषों के लिए अधिक होगा।
- बांग्लादेश में नाथ (2008, पृष्ठ 58) द्वारा प्राथमिक विद्यालय स्तर पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि 28.1 प्रतिशत लड़कियों की तुलना में 33.8 प्रतिशत लड़कों ने प्राइवेट ट्यूशन प्राप्त की थी।

लेकिन ये पद्धतियाँ एक समान नहीं थी। डंग (2007, पृष्ठ 692) के प्राथमिक या माध्यमिक स्तर पर वियतनाम में लड़के-लड़कियों में कोई असमानता दिखाई नहीं दी; और केन्या में एसएसीएमईक्यू के आंकड़े बुचमान (पैवियर और अन्य, 2008 पृष्ठ 153) के निष्कर्षों के अनुरूप नहीं थे। इसी प्रकार, ईलबाडी, अहलबर्ग और अन्य (2006) ने मिस्र में लड़का-लड़की में कोई असमानता नहीं पाई गई। लड़का-लड़की में असमानता प्रमुख शिक्षा प्रणाली में थी और असंधानकर्ताओं ने 1998 मिस्र मजदूर बाजार सर्वेक्षण में ट्यूशन क्षेत्र में अधिक असमानता का पता लगाने की अपेक्षा की थी। उन्होंने महसूस किया कि विवाह के बाजार में शिक्षा की प्रीमियम अधिक था - यानी ऊँची शिक्षा प्राप्त लड़कियों का विवाह अमीर घरानों और/या शिक्षित पतियों के साथ होने की संभावना थी - जो असमानता का कारण हो सकती थी जो अपेक्षा से कम गंभीर बात थी। कहीं भी लड़का-लड़की में असमानता पुरुषों की तुलना में महिलाओं के पक्ष में थी। उदाहरण के लिए, किरगिस्तान में बागडासरोवा और ईवानोव ने पाया कि प्राइवेट ट्यूशन लेने वाले छात्रों में 65.4 प्रतिशत महिलाएँ थीं और 34.6 प्रतिशत पुरुष थे। इसके स्पष्टीकरण में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि लगभग दो-तिहाई छात्र पढ़े-लिखे परिवारों से थे, जबकि 65 से 70 प्रतिशत के माता-पिता में कम से कम एक के पास विश्वविद्यालय की डिग्री थी। इसके बावजूद, इस तथ्य ने कन्याओं के पक्ष में असंतुलन की बजाय जेंडर समानता में योगदान दिया था।

स्ट्री-पुरुष आयाम का एक अन्य पहलू अध्यापकों से संबंधित था। कुछ देशों में ट्यूशन मुख्यतः पुरुष अध्यापकों द्वारा ही दी जाती है। कंबोडिया में किए गए एक अनुसंधान में यह अंतर पाया गया कि किसी विशिष्ट ग्रामीण स्कूल में 1 से 3 कक्षा तक का कोई छात्र ट्यूशन प्राप्त नहीं कर रहा था, लेकिन 4, 5 और 6 कक्षा में यह अनुपात 50, 25 और 90 प्रतिशत था। यह पूछने पर कि कक्षा 5 का अनुपात कक्षा 4 और 6 से इतना कम क्यों था, मुख्य अध्यापक ने बताया कि कक्षा अध्यापक महिला थी जो अपने परिवार में व्यस्त रहती थी और नियमित रूप से ट्यूशन नहीं दे सकती थी (ब्रे, 1999बी, पृष्ठ 60)। इसी प्रकार, हार्टमैन (2008, पृष्ठ 68) ने सूचित किया कि हालांकि मिस्र

के कुछ महिला अध्यापक घर पर प्राइवेट शिक्षा देते थे, किंतु प्राइवेट ट्यूशन केन्द्रों में मुख्यतः पुरुष ही पढ़ाते थे। उन्होंने स्पष्ट किया:

इस बात के स्पष्ट कारण मौजूद हैं कि महिला अध्यापक प्राइवेट ट्यूशन कम क्यों लेती थीं। उनके पास घरेलू जिम्मेदारियों के कारण समय और ऊर्जा कम होती थी, विशेषकर जब उनका परिवार हो। इसके अलावा, महिलाओं, विशेषकर युवतियों के लिए समाज में यह बात कम स्वीकार की जाती थी वे अपनी दोपहर घर के बाहर छात्रों के घर पर या उन्हें अपने घर बुलाकर व्यतीत करें। महिला अध्यापकों की उनके पतियों या परिवारों द्वारा वित्तीय रूप से सहायता की जाती है और इस प्रकार वे अपने पुरुष सहयोगियों की तरह अतिरिक्त आय पर निर्भर नहीं होतीं।

बेशक दुनिया के दूसरे हिस्सों में संस्कृतियां काफी भिन्न हो सकती हैं, लेकिन महिला ट्यूटर्स की तुलना में पुरुष अध्यापकों द्वारा बाजार तलाशने और अपने छात्रों को ट्यूशन लेने पर दबाव डालने की संभावना अधिक रहती है।

ग्रामीण/शहरी स्थल

ऊपर उल्लिखित सामाजिक असमानताओं का एक अन्य पहलू ग्रामीण/शहरी स्थल से संबंधित है। शहरों में ट्यूशन तीन मुख्य कारणों से अधिक लोकप्रिय है। पहला, शहरों में जनसंख्या की आय अधिक होती है, और इसलिए वे ट्यूशन का बोझ अधिक आसानी से उठा सकते हैं; दूसरा, शहरों में प्रतिस्पर्धा अधिक होती है जहां मजदूरी कमाने वाला श्रम बाजार का वर्चस्व होता है जिसके लिए शैक्षिक योग्यता की जरूरत होती है; और तीसरा, यह कि शहरों में जनसंख्या का घनत्व सेवा की आपूर्ति करने के लिए ट्यूटर्स को पर्याप्त बाजार उपलब्ध कराने हेतु प्रोत्साहित करता है।

पॉलिसी फोरम के दौरान प्रस्तुत अनुभव आधारित आंकड़ों में पूर्वी यूरोप और एशिया के आंकड़े भी शामिल थे (सिलोवा, 2007, पृष्ठ 7)। सारणी 8 में दर्शाए गए सभी 12 देशों में ट्यूशन ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरी क्षेत्रों में अधिक थी, कजाखस्तान में यह अंतर सबसे अधिक 24.2 प्रतिशत था। इसके अलावा, सुजाता (2007) द्वारा भारतीय ग्रामीण सर्वेक्षण आंकड़ों से पता चलता है कि औसतन 29 प्रतिशत निम्न माध्यमिक स्कूल के छात्र ट्यूशन ले रहे थे जबकि शहरी छात्रों का प्रतिशत 64 प्रतिशत था (देखें सारणी 9)। ये पद्धतियां परस्पर बाध्यकारी थीं क्योंकि ग्रामीण छात्रों का ट्यूशन के बिना शिक्षा प्रणाली में टिक पाना मुश्किल था और उनके पीछे छूटने की संभावना अधिक थी।

सारणी 8. पूर्वी यूरोप और एशिया में प्राईवेट ट्यूशन लेने वाले ग्रामीण और शहरी छात्रों में अंतर (%)

	ग्रामीण	शहरी
अज़रबैज़न	87.8	95.0
बोसनिया तथा हेरजेगोविना	56.9	57.7
क्रोशिया	50.1	61.6
जार्जिया	76.9	81.2
कजाखिस्तान	56.6	70.1
किर्गीस्तान	37.7	61.9
लिथुआनिया	54.9	69.7
मोंगोलिया	69.8	71.6
पोलैण्ड	59.9	70.1
स्लोवाकिया	54.7	58.2
ताजीकिस्तान	41.0	49.2
यूक्रेन	77.7	82.0

स्रोत: सिलोवा (2007), पृष्ठ 7

सारणी 9. भारत के चार राज्यों के ग्रामीण और शहरी इलाकों में निम्न माध्यमिक स्तर पर प्राईवेट ट्यूशन प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत

	ग्रामीण	शहरी
आंध्र प्रदेश	20.7	38.7
केरल	66.5	70.6
महाराष्ट्र	29.3	72.7
उत्तर प्रदेश	32.0	52.7
योग	29.0	64.0

एन = ग्रामीण, 1,492 : शहरी 2,539

स्रोत : सुजाता (2007), पृष्ठ 5

ये आंकड़े साहित्य की दृष्टि से प्राप्त सूचना से सामंजस्य रखते हैं। उदाहरण के लिए, मिस्र मजदूर बाजार सर्वेक्षण 1998 के आंकड़ों में देश के सभी 27 राज्यों में से 22 में 4,816 परिवारों के सर्वेक्षण से पता चलता है कि शहरी क्षेत्रों में 52.0 प्रतिशत छात्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में 39.6 प्रतिशत छात्र प्राईवेट ट्यूशन ले रहे थे (ईलबाडी और अन्य, 2006, पृष्ठ 16)। प्रति बच्चा वार्षिक औसत खर्च भी अधिक था: शहरी क्षेत्रों में 491.5 मिस्रियाई पाउण्ड की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में 188.9 मिस्रियाई पाउण्ड। इसी प्रकार, नाथ (2008, पृष्ठ 58) द्वारा सूचित बांग्लादेश के आंकड़ों से पता चलता है कि शहरी क्षेत्रों में 43.6 प्रतिशत की तुलना में शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक ग्रेड-1 के छात्रों द्वारा प्राईवेट ट्यूशन लेने

का प्रतिशत 19.6 प्रतिशत था। कक्षा 5 में प्राथमिक शिक्षा के समाप्त होने पर यह अंतर अधिक व्यापक था: शहरी क्षेत्रों में 62.2 प्रतिशत की तुलना में 35.6 प्रतिशत। ये आंकड़े मांग और आपूर्ति दोनों दर्शाते हैं। आपूर्ति के संबंध में आस्ट्रेलिया में वाटसन (2008, पृष्ठ 10) ने टिप्पणी की कि ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में ट्यूटर्स की कमी सरकार की ट्यूशन वाउचर स्कीम के लिए एक बड़ी समस्या थी, और इन इलाकों में छात्रों का मानक परीक्षा में निष्पादन स्तर राष्ट्रीय औसत से लगातार कम था।

प्रजातीयता और नस्ल

समाजिक असमानता का एक अन्य आयाम प्रजातीयता और नस्ल से संबंधित था। उदाहरण के लिए, वियतनाम में किए गए एक अध्ययन से पता चला कि 1997-1998 में प्राथमिक स्तर पर 7.1 % जातिगत अल्पसंख्यक छात्रों की तुलना में 37.0 प्रतिशत जातिगत बहुसंख्यक छात्र ट्यूशन ले रहे थे (डांग, 2007, पृष्ठ 688)। निम्न माध्यमिक स्तर पर संबंधित अनुपात क्रमशः 60.7 और 19.0 प्रतिशत था; और उच्च माध्यमिक स्तर पर यह प्रतिशत क्रमशः 78.0 और 55.9 प्रतिशत था।

तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो अल्पसंख्यक छात्र समूह अधिक ट्यूशन ले रहा था। आयरसन और रशफोर्थ (2005, पृष्ठ 6) ने पाया कि इंग्लैण्ड में बाजार आधारित मांग दक्षिण एशियाई, चीन, और अफ्रीकी-कैरिबीयन मूल के बच्चों (हालांकि लघु सर्वेक्षण द्वारा) में श्वेत यूरोपियनों की तुलना में ट्यूशन लेने की अधिक संभावना दिखाई दी। कनाडा में, वैनकोउवर और टोरोन्टो में अधिकांश ट्यूशन हांगकांग, ताईवान, और मुख्यभूमि चीन से पलायन होकर आए लोगों द्वारा दी जा रही थी। अमेरिका के बिलकुल भिन्न संदर्भ में सरकार द्वारा संचालित *नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड* योजना का लाभ कम अंक पाने वाले अफ्रीकी-अमेरिकी और हिसपैनिक छात्रों (जिम्मेर और अन्य, 2007; मोरी 2009) को मिला।

शैक्षणिक प्रभाव

दूसरी परछाइयों की ही तरह प्रतिच्छाया शिक्षा प्रणाली भी उस शरीर को प्रभावित कर सकती है जिससे यह उत्पन्न होती है। अधिकांश व्यवस्थाओं में ऐसा माना जाता है कि प्राइवेट ट्यूशन स्कूल संबंधित सामग्री को समझने के लिए एक पूरक अवसर के रूप में मदद करती है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में यह मुख्य शिक्षा को प्रभावित करती है। सरकारों द्वारा कम अंक पाने वाले छात्रों के लिए प्रायोजित ट्यूशन योजनाएं बिलकुल अलग श्रेणी की होती हैं जो पूरी तरह से बाजार द्वारा संचालित होती हैं, यद्यपि प्रत्येक श्रेणी में पाठ्यक्रम में व्यापक अंतर होने की संभावना रहती है। पोईसन (2007) ने विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक प्रभाव का उल्लेख किया, जिसमें स्कूल सुविधाओं का प्रयोग, अनुदेशात्मक समय, शैक्षणिक तत्व और अध्यापन, शिक्षक निष्पादन, छात्र की पढ़ाई, और कक्षा सक्रियता शामिल होती है (डांग और रोजर्स, 2008 भी देखें, पृष्ठ 8-14)। उदाहरण अगले खण्ड में दिए गए हैं।

कम अंक पाने वाले छात्रों के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं

आईआईईपी पॉलिसी फोरम के भागीदारों में इंग्लैण्ड के बाल, स्कूल और परिवार विभाग (डीसीएसएफ) का एक स्टॉफ सदस्य भी था, जिन्होंने 2007 में लागू एक प्रमुख प्रायोगिक परियोजना के बारे में सूचित किया (टेलर 2007)। 'मेकिंग गुड प्रोग्रेस' योजना में बच्चों को पढ़ाई में मदद करने के लिए आमने-सामने बैठकर ट्यूशन देने और शिक्षा प्राप्त करने में असमानताओं को कम करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। अपनी तैयारी के भाग के रूप में योजना के निर्माताओं ने इंग्लैण्ड, आस्ट्रेलिया और अमेरिका में प्राइवेट ट्यूशन के प्रभाव का मूल्यांकन किया।

पेपर में इंग्लैण्ड से संबंधित जिन आंकड़ों का उल्लेख किया गया है वे मुख्यतः आयरसन (2004) और आयरसन एवं रशफोर्थ ने पाया (पृष्ठ 4) कि 6, 11 और 13 साल के बच्चों पर किए गए सर्वेक्षण में 27 प्रतिशत प्राइवेट ट्यूशन ले रहे थे। शोधकर्ताओं ने पाया कि सबसे पसंदीदा विषय गणित था जिसके बाद अंग्रेजी (6 साल के बच्चे के लिए पढ़ना और लिखना), और विज्ञान विषय थे। अन्य प्रमुख निष्कर्षों में निम्नलिखित शामिल थे:

- ट्यूशन पढ़ने का मुख्य कारण परीक्षाओं में अच्छा करना और बेहतर अंक लेना था (दो-तिहाई छात्र)।
- माध्यमिक स्कूल के छात्र कभी-कभार ट्यूशन, कार्य को पूरा करने या बीमारी आदि के कारण कक्षा में पिछड़ने को पूरा करने के लिए लेते हैं।
- ट्यूशन को जारी रखना उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है और ट्यूशन कार्यक्रम अपनी प्रभावकारिता से काफी भिन्न होता है।
- ट्यूशन का श्वेत बच्चों के सामान्य माध्यमिक शिक्षा प्रमाणपत्र (जीसीएसई) परिणामों पर नगण्य या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन इसका अश्वेत बच्चों (हालांकि लघु सर्वेक्षण आधार पर) अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। संयुक्त रूप से इसका प्रभाव सकारात्मक था। गणित में जीसीएसई में ट्यूशन लेने से लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक लाभ मिला।

चूंकि प्राइवेट ट्यूशन का स्वरूप काफी विविध है, इसलिए इस पर बहुत कम व्यवस्थित आंकड़े मौजूद थे जिनके आधार पर कैसे और किन परिस्थितियों में कार्य किए जाने की संभावना थी।

आस्ट्रेलिया के संबंध में टेलर (2007, पृष्ठ 5-6) ने उन बच्चों की मदद करने के लिए सरकारी पहल का उल्लेख किया जिन्होंने 2003 में 3 वर्षीय राष्ट्रीय पठन मानक पूरा नहीं किया था। इस योजना में पात्र बच्चों के माता-पिता या संरक्षकों को एक वाउचर दिया गया जिससे वे 700 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर मूल्य की आमने-सामने बैठकर दी जाने वाले ट्यूशन ले सकें (देखें वाटसन, 2007, पृष्ठ 6)। तत्पश्चात् योजना का बाद में

ट्यूशन-पूर्व और उसके उपरांत हुए परिवर्तन के आधार पर ट्यूटर्स और माता-पिता या संरक्षकों के विचारों से संबंधित आंकड़ों का मूल्यांकन किया गया था। वर्ष 2003 में 3 वर्ष के अनुमानित 19,000 छात्र बेंचमार्क (राष्ट्रीय समूह का 7.6 प्रतिशत) तक नहीं पहुंच पाए थे, जिनमें से 6,200 छात्रों ने भाग लिया था और 5,443 छात्रों ने ट्यूशन का पूरा पाठ्यक्रम किया था। मूल्यांकन से पता चला कि योजना ने छात्रों का ध्यान भंग किए बिना सीखने का अवसर दिया जिससे उनकी एकाग्रता और ध्यान केन्द्रित करने में सुधार हुआ। इससे उन्हें बिना परेशानी के सीखने का अवसर मिला, और उनमें आत्म-विश्वास पैदा हुआ। स्कूल और परिवार संबंधी विभिन्न घटक सफलता के लिए महत्वपूर्ण थे जो कुछ राज्यों में पर्याप्त संख्या में थे। उदाहरण के लिए, विक्टोरिया राज्य में 39 प्रतिशत छात्रों के निष्पादन में सुधार हुआ और पढ़ने के कौशल में औसत लाभ लगभग 1.7 वर्ष था। लेकिन यह एक प्रायोगिक योजना थी, जिसका अर्थ है कि किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अभी अधिक अनुभव प्राप्त करने की जरूरत थी। वाटसन (2007, पृष्ठ 9) ने आगे कहा कि शैक्षिक हस्तक्षेप की अन्य प्रणालियों की तुलना में योजना की किफायत को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

टेलर (2007, पृष्ठ 6-7) द्वारा उल्लिखित तीसरी योजना नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड (एनसीएलबी) नीति थी, जिसे शिकागो में लागू किया गया था। वर्ष 2005 में शिकागो पब्लिक स्कूल (सीपीएस) ने 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत पर 343 स्कूलों में 60,000 से अधिक छात्रों को सेवाएं प्रदान करने के लिए 30 प्राइवेट कंपनियों और एजेंसियों से संपर्क किया। ट्यूशन लाभ कमाने और लाभ न कमाने वाली, दोनों एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। सीपीएस ने अपना निजी कार्यक्रम भी प्रायोजित किया जिसमें ट्यूशन दिए जा रहे आधे से अधिक छात्र शामिल थे। मूल्यांकन से पता चला कि ट्यूशन प्राप्त न करने वाले पात्र छात्रों की तुलना में ट्यूशन लेने वाले छात्रों को कुछ फायदा हुआ था। ट्यूशन लेने वाले पात्र छात्र कम अंक पाने वाले छात्रों में से थे। एक वर्ष में ट्यूशन पढ़ने वाले छात्रों को पढ़ाई में औसतन 1.09 वर्ष का तथा गणित में 0.94 वर्ष का लाभ हुआ। यह दर ट्यूशन न लेने वाले पात्र छात्रों की तुलना में अधिक थी, जिन्हें क्रमशः 1.03 और 0.92 का औसत लाभ हुआ था, लेकिन यह क्रमशः 1.06 और 1.01 के नगर-वार औसत लाभ से कम था। टेलर ने शिकागो में प्राप्त अनुभव से चार प्रमुख मुद्दों का पता लगाया:

- ट्यूशन मुफ्त स्कूल भोजन की पात्रता के आधार पर दी गई थी जो मुख्यतः आर्थिक स्थिति से तय होती थी, न कि शैक्षिक आवश्यकता के आधार पर। कुछ छात्रों को ट्यूशन की जरूरत थी, लेकिन उन्हें नहीं मिली। इसी प्रकार, जिन बच्चों को ट्यूशन की जरूरत नहीं थी, उन्हें दी गई। माता-पिता यह तय करते थे कि उनके बच्चे किस विषय में ट्यूशन लेंगे और वह प्रायः यह चयन ठीक से नहीं करते थे। ट्यूशन देने वाली कंपनियां विज्ञापनों और प्रोत्साहन का सहारा लेती थीं। कुछ उच्च स्तर की ट्यूशन का प्रस्ताव देती थीं जो माता-पिता को आकर्षित करती थीं लेकिन वे शैक्षिक रूप से फायदेमंद नहीं थीं।

- ट्यूशन समूहों का आकार भिन्न-भिन्न था। कुछ ट्यूशन आमने-सामने बैठकर दी जाती थी, लेकिन अधिकांश ट्यूशन समूहों में दी जाती थी, जिनमें से कुछ में 20 बच्चे होते थे।
- इसका कोई सार्वभौमिक मूल्यांकन नहीं किया गया था, और ट्यूशन देने वाले की जवाबदेही बहुत कम थी। किसी स्कूल या अन्य किसी संस्था की बजाय किसी ट्यूटर को अंतिम वार्षिक परीक्षा में किसी भी बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र का लाभ मिलता है। बहुत कम कंपनियों ने पाठ का नमूना बनाया था, उनका मूल्यांकन किया, और बहुत कम कंपनियां संबंधित माता-पिता या मुख्य अध्यापक के प्रति जिम्मेदार थीं।
- जिन कंपनियों ने बच्चों के अध्यापकों को ट्यूटर के रूप में भर्ती किया, उनका बच्चों पर अधिक प्रभाव पड़ा था। इनमें से अधिकांश अध्यापकों ने सामान्य सामग्रियों को चुना जिन्हें उन्हें बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार ट्यूशन देने के लिए दिया गया था। ऐसे ट्यूटरों को छात्र रिकार्ड प्रायः अच्छा था। माता-पिता को अच्छी जानकारी दी गई और स्कूलों का विश्वास हासिल था।

इन निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2007 में इंग्लैण्ड में शुरू की गई प्रायोगिक परियोजना कक्षा 2 और 3 के प्रमुख चरणों (बच्चों का आयु वर्ग 7-14 और 11-14) में 10 % बच्चों के लिए एक आमने-सामने बैठकर ट्यूशन देने की पूरी लागत को पूरा करने के लिए तैयार की गई थी। इसमें 10 घंटे की ट्यूशन अवधि तथा अंग्रेजी और/या गणित में प्रति विषय प्रति छात्र स्कूल के दो घंटे ट्यूशन लेना शामिल था।

सिंगापुर में एक इसी तरह की योजना लागू की गई थी (टैन 2009, पृष्ठ 97)। 1980 के दशक के दौरान, सरकार शिक्षा में जातीय असंतुलन, और विशेषकर चीनी और भारतीयों की तुलना में जातीय माल्यों के खराब प्रदर्शन को लेकर चिंतित थी। प्राधिकारियों ने माल्य/मुस्लिम छात्र शिक्षा परिषद (मेंडाकी) को ट्यूशन दिलाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई। सरकार ने परिषद को स्कूल के बाद ट्यूशन के लिए पब्लिक स्कूलों और प्रशिक्षित ट्यूटरों को स्वैच्छिक आधार पर या कम शुल्क पर प्रयोग करने की अनुमति भी प्रदान की। ट्यूटोरियल योजनाओं की सबसे पहले मेंडाकी द्वारा और उसके बाद सिंगापुर इंडियन डेवलपमेंट एसोसिएशन (सिण्डा) द्वारा स्थापना की गई थी जो बहुत सुदृढ़ बन गई और उनका बेहतरीन विज्ञापन दिया गया। (देखें मेंडाकी, 2009, सिंडा, 2009)

रेड्डी (2007) द्वारा आईआईईपी पॉलिसी फोरम में दक्षिण अफ्रीका में एक समानांतर योजना का उल्लेख करना भी उपयुक्त होगा। दक्षिण अफ्रीका के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान विषय में सुधार करने के तरीकों का पता लगाने के लिए ट्यूशन प्रणाली की समीक्षा करने का अनुरोध किया था। समीक्षा से उत्पन्न सिफारिशें प्राप्त होने पर विभाग ने निम्न आय वाले परिवारों पर लक्षित एक योजना चलाने का निर्णय लिया। यह ट्यूशन आमने-सामने बैठकर ट्यूशन देने के छात्र मॉडल

पर आधारित थी और सरकार ने वित्त-पोषण में मदद करने के लिए निजी क्षेत्र से संपर्क किया था। यह योजना सरकार द्वारा प्रायोजित पहल का एक विस्तृत उदाहरण थी जिसमें असमानता को कम करने का प्रयास किया गया था और इसमें कम अंक पाने वाले छात्रों की मदद करके उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने की अपेक्षा की गई थी।

बाजार आधारित द्यूशन

अन्य योजनाएं, जैसा कि इस पुस्तक के पिछले खण्डों से स्पष्ट होगा, केवल बाजार आधारित उद्यमों के रूप में ही विद्यमान थीं। इनसे शैक्षिक फायदे मिलने की संभावना थी, जिनके बिना उनकी मांग घट जाएगी। लेकिन इन प्रयासों के मूल्यांकनों से पता चलता है कि कुछ मांग प्रदर्शन साक्ष्यों की तुलना में प्रभाव और मार्केटिंग पर आधारित थी। बहुत कुछ द्यूशन की प्रकृति और छात्रों द्वारा इससे लाभ उठाने की तैयारी पर निर्भर करता है। इसके अलावा, कुछ व्यवस्थाओं में द्यूशन क्षेत्र का प्रमुख शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

सबसे अधिक समस्या वाले मामले वे हैं जिनमें प्राइवेट द्यूशन प्रमुख शिक्षा का स्थान ले लेती है। विशेषकर बाहरी परीक्षा के दौरान कुछ देशों में स्कूल छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें व्यापक मांग क्षेत्र को पूरा करना होता है और उनका व्यापक सामाजिक और राजनीतिक लक्ष्य होता है। तुर्की में, यह पहलू छात्रों में अपने चरम सीमा तक पहुंच चुका है जो स्कूल से गैर-हाजिर रहने के लिए चिकित्सा प्रमाण-पत्र को पैसे देकर प्राप्त करते हैं। विशेषकर सेमिस्टर के दौरान जब छात्र माध्यमिक और तृतीयक शिक्षा प्रवेश परीक्षाएं देते हैं, वे स्कूल में कक्षाओं में भाग लेने की बजाय प्राइवेट द्यूटोरियल केन्द्र जाते हैं या घर में बैठकर तैयारी करना पसंद करते हैं। तनसेल और बिर्कन (2007, पृष्ठ 8) ने सूचित किया कि इस सत्र के दौरान अधिकांश छात्रों ने बीमारी का झूठा चिकित्सा प्रमाण-पत्र लिया जिससे वे स्कूल की कक्षाओं में गैर-हाजिर रहे और यह “व्यापक तौर पर स्वीकृत और महंगी प्रक्रिया बन गई है”। वर्ष 2005 में तुर्की शिक्षक संघ ने 1,078 वरिष्ठ उच्च स्कूल छात्रों तथा 1,073 उच्च स्कूल स्नातकों का एक सर्वेक्षण कराया था। यह पूछे जाने पर कि छात्रों की उपस्थिति का परीक्षाओं की तैयारी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 55 प्रतिशत वरिष्ठ उच्च स्कूल छात्रों और 49 प्रतिशत उच्च स्कूल स्नातकों ने बताया कि उन्होंने झूठी चिकित्सा रिपोर्टें ली थीं।

इसी तरह के तरीके अज़रबैजान में भी अपनाए गए थे। काजिमजादे (2007) ने बताया कि विशेषकर माध्यमिक स्कूल की अंतिम कक्षा में छात्र स्कूल के घंटों के दौरान प्राइवेट द्यूशन लेने के लिए प्रायः कक्षाओं में भाग नहीं लेते थे (देखें सिलोबा और काजिमजादे, 2006, पृष्ठ 128)। कुछ छात्र स्कूल से गैर-हाजिर रहने के लिए स्कूल प्राधिकारियों को रिश्वत भी देते थे - लेकिन उनकी स्कूल रजिस्ट्रों में उपस्थिति दर्ज होती थी - ताकि वे प्राइवेट द्यूशन में भाग ले सकें। मॉरीशस के संदर्भ में ओबीगाडो (2007)

की टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए काजिमजादे ने टिप्पणी की कि इस सत्र के दौरान स्कूल कक्षाएं वास्तव में खाली रहीं क्योंकि अधिकांश छात्र स्कूल के बाहर ट्यूशन ले रहे थे।

प्राइवेट ट्यूशन की अधिकता निस्संदेह छात्रों की एकाग्रता की अवधि को प्रभावित करेगी। कोरिया में, किम (2007, पृष्ठ 16-17) में विशेष प्रयोजन वाले हाई स्कूलों (एसपीएच) में प्रवेश के लिए ट्यूशन के प्रभाव के बारे में सूचना दी। छात्रों द्वारा ट्यूटोरियल केन्द्रों को प्रशिक्षण देने के रूप में अधिक उपयोगी समझा जाता है। चूंकि ट्यूटोरियल सेंटर की मांग काफी अधिक है अतः छात्र प्रायः स्कूल समय में ही सो जाते थे। बच्चों ने इस बात को स्वयं स्वीकार किया था (किम 2007, पृष्ठ 17):

स्कूल अध्यापकों को एसपीएच उम्मीदवार पसंद नहीं हैं। वे कक्षा में एकाग्र नहीं होते और प्रायः सो जाते हैं। एसपीएच द्वारा तीसरे ग्रेड के दूसरे सेमिस्टर के ग्रेडों को जोड़ा नहीं जाता है। इसलिए अध्यापक उन्हें पसंद नहीं करते क्योंकि ये छात्र कक्षाओं के दौरान व्यवधान उत्पन्न करते हैं. . .

सभी एसपीएच छात्र अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। वे कक्षा में मन लगाकर नहीं पढ़ते। वे कक्षा में व्यवधान उत्पन्न करते हैं. . . वास्तव में इनमें से कई छात्र कक्षा के दौरान सो जाते हैं या प्राइवेट संस्थान का गृहकार्य करते हैं या अन्य विषयों का अध्ययन करते हैं. . . अग्रेजी कक्षा में, इनमें से अधिकांश छात्र (एसपीएच छात्र) सो जाते हैं। हमने पाठ याद कर लिया है। और अध्यापक भी यह बात जानते हैं।

उपर्युक्त टिप्पणियां न केवल एकाग्रता अवधि बल्कि मुख्य कक्षाओं में विविधता के बारे में प्रश्न उठाती हैं। जब ट्यूशन से कम अंक पाने वाले छात्रों को फायदा होता है, तो यह प्रायः विविधता को कम करता है और इस तरह से स्कूल के अध्यापक की मदद करता है। लेकिन बाजार आधारित अधिकांश ट्यूशन उच्च योग्य छात्रों के लिए होती है। जैसा कि मॉरीशस के संदर्भ में स्पष्ट किया गया है (बाह-लालया, 2006, पृष्ठ 75):

जब कुछ छात्र प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं लेकिन अन्य छात्र नहीं लेते तो स्कूल के अध्यापकों को व्यापक असमानताओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि पूरक ट्यूशन प्रणाली मूल पाठ को समझने में मदद करती है, यह स्कूल के सामान्य घंटों के दौरान सीखने और पढ़ने से ध्यान भंग कर सकती है।

इसमें अन्य चुनौतियाँ यह हो सकती हैं कि प्राइवेट ट्यूटर्स का अध्यापन स्कूल के अध्यापकों से भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, ट्यूशन सेंटर में गणित में, छात्र संबंधित गणित सिद्धांतों को समझने की बजाय यांत्रिक रूप से प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। अमेरिका में, *नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड* योजना की कक्षा पाठ्यक्रम के साथ पूरक सेवाओं का सामंजस्य न कर पाने के कारण आलोचना हुई है। आलोचकों का आगे यह भी कहना है कि ट्यूटर्स की कक्षा अध्यापकों के साथ बातचीत नहीं होती, परिणामस्वरूप ट्यूशन सेवाएं

“एक संगत अनुदेश कार्यक्रम विकसित करने के लिए स्कूल की संगठनात्मक क्षमता को कमजोर करती है।” (सुंदरमान, 2006, पृष्ठ 118)।

संभवतः इससे भी अधिक समस्या वाली स्थितियां वे हैं जिनमें अध्यापक स्कूल के छात्रों की इसलिए उपेक्षा कर देते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि छात्र ट्यूशन में पढ़ लेंगे - कई मामलों में ये ट्यूशन अध्यापकों द्वारा स्वयं दी जाती है। हार्टमैन (2008: 52) ने मिश्र में छात्रों के विचारों को दर्ज किया जिनका रसायन विषय का प्राइवेट ट्यूटर उनका स्कूल का अध्यापक ही था:

दीना ने कहा, स्कूल में छात्र कक्षाओं में बात करते हैं या अन्य विषय पढ़ाते हैं।

“कोई भी ध्यान नहीं देता। इसलिए अध्यापक पूरा पाठ पढ़ाने पर ध्यान नहीं देते।

वे विषय को गहराई से न पढ़ाकर मामूली सा ही स्पष्ट करते हैं। उन्हें मालूम है कि

हम सभी प्राइवेट ट्यूशन ले रहे हैं, इसलिए वह क्यों परवाह करेंगे?”

हर्टमान ने यह भी नोट किया (पृष्ठ 67) कि अधिकांश ट्यूटर उनके द्वारा लिखी गई पाठ्य पुस्तकों से भी अतिरिक्त आय कमाते हैं। ये पुस्तकें आम तौर पर बाजार में और पुस्तकों की दुकानों पर उपलब्ध होती हैं, लेकिन इन्हें स्कूलों में लाने की अनुमति नहीं होती क्योंकि इन्हें लाने की सरकारी तौर पर स्वीकृति नहीं दी जाती तथा इनसे पाठ्यक्रम विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत अध्यापन दृष्टिकोण प्रभावित हो सकता है।

ट्यूशन के प्रभाव के अन्य पहलू निम्नलिखित खण्ड में प्रस्तुत तीन मामला अध्ययनों से स्पष्ट हो जाएंगे। इस दौरान, यह प्राइवेट ट्यूशन और स्कूली शिक्षा के बीच संभावित संबंध के बारे में पोईसन का सार दोबारा प्रस्तुत करना भी लाभदायक होगा (सारणी 10)।

सारणी 10. मुख्य स्कूली शिक्षा पर प्राइवेट ट्यूशन का प्रभाव

प्रभाव वाले क्षेत्र	प्रभाव के प्रकार	
	सकारात्मक	नकारात्मक
शिक्षा वित्त - पोषण	● शिक्षा क्षेत्र में विश्व स्तर पर आबंटित अधिक संसाधन	● निधियों का अन्यत्र उपयोग जिनका मुख्य एक्टरों द्वारा अधिक कारगर प्रयोग किया जा सकता है। ● अध्यापकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन के लिए भुगतान करने पर माता-पिता पर दबाव डालना। ● राज्य कर राजस्व प्राप्त न होना।
अध्यापक की आमदनी	● अध्यापकों के लिए अतिरिक्त आय	
अध्यापक प्रबंधन		● प्रबंधन प्रक्रियाओं को तोड़ना-मरोड़ना (कार्य आबंटित करने के लिए दबाव डालना जिससे निश्चित रूप से अधिक धनराशि प्राप्त होगी)।
स्कूल सुविधाओं का लाभ उठाना	● स्कूल के घंटों के बाद स्कूल सुविधाओं का उपयोग करने की बढ़ी हुई दर।	● प्राइवेट हित के लिए सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग।
आदेशात्मक समय	● स्कूल के बाद का बेहतर उपयोग करना (कम निगरानी रखने वाले युवाओं सहित)	● शिक्षण के कुछ घंटों में कमी करना (अध्यापक की अनुपस्थिति)। ● अध्यापकों के चार्ज में सुधार कक्षाएं चलाने की बजाय प्राइवेट ट्यूशन पर ध्यान केन्द्रित करना।
शिक्षण सामग्री और अध्यापन		● सरकारी घंटों के दौरान पाठ्यक्रम का केवल कुछ अंश पढ़ाया गया। ● प्राइवेट ट्यूटर्स द्वारा उपयोग की गई रट्टा लगाने के तरीके को अपनाना।
शिक्षक का निष्पादन	● प्रमुख स्कूली अध्यापकों के कार्यभार में कमी करना।	● अध्यापकों द्वारा कक्षा में कम परिश्रम करना ताकि प्रत्येक छात्र पर्याप्त रूप से तैयार हो सके। ● ट्यूशन पाठ उपलब्ध कराने वाले अध्यापकों की थकान और अदक्षता। ● ट्यूटोरियल कार्य के पक्ष में अध्यापकों द्वारा अपने मुख्य कर्तव्यों की उपेक्षा करना (गैर-हाजिरी)

प्रभाव वाले क्षेत्र	प्रभाव के प्रकार	
	सकारात्मक	नकारात्मक
छात्र शिक्षा	● छात्रों को सामान्य स्कूल दिन के दौरान प्रस्तुत सामग्रियों को समझने में मदद करता है।	● अत्यधिक कार्यभार और छात्रों को थकान होना। ● कक्षा गतिविधियों में रुचि न होना। ● प्राईवेट ट्यूशन पढ़ने के दौरान दिए गए टिप्स का इस्तेमाल करते हुए छात्रों का यंत्रवत कार्य करना। ● छात्रों की गैर-हाजिरी की दर में वृद्धि होना।
कक्षा गतिशीलता	● धीमे सीखने वाले छात्रों को शेष कक्षा के बराबर लाने में मदद करता है।	● प्राईवेट ट्यूशन का गतिशील कक्षा के अनुभव की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होना। ● अध्यापकों द्वारा अध्यापन और शिक्षा दृष्टिकोण का ट्यूशन के साथ मेल न खाना। ● स्कूल के प्रमुख अध्यापकों का सम्मान न करना। ● स्कूल के अध्यापकों द्वारा अपनी कक्षाओं में व्यापक असमानताओं का सामना करना।
मूल्यांकन और चयन प्रक्रियाएं		● ट्यूशन का औचित्य ठहराने के लिए परीक्षाओं की आवश्यकता में वृद्धि की गई। ● विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया से कतराना।
छात्रों की उपलब्धियां	● कम अंक प्राप्त करने वालों का बेहतर परिणाम आना। ● शैक्षिक बाजार में छात्रों की शिक्षा और प्रतिस्पर्धा में सुधार करना।	● छात्रों में सामाजिक असमानता का बढ़ना। ● अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों द्वारा ट्यूशन प्राप्त करने पर अंतर का बढ़ना। ● प्राईवेट ट्यूशन लेने वाले छात्रों का पक्ष लेना। ● प्राईवेट ट्यूशन न लेने वाले छात्रों को दण्डित करना (जानबूझकर फेल करना)।
पाठ्यक्रम लिखना और उसका वितरण	● नई सामग्री बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, जो आसान हो और परीक्षा की तैयारी करने में मददगार हो।	● पाठ्य पुस्तकों की सामग्री के आधार पर रद्द लगाने की नीति लागू करना।

स्रोत: पोईसन (2007), पृष्ठ 14 - 15.

तीन मामलों का अध्ययन

विशिष्ट राष्ट्रीय अनुभवों की जांच करने पर विषय की जटिलता का पता चलता है। मामला अध्ययनों के लिए अनेक देशों को चुना गया है, लेकिन दूरी की वजह से केवल तीन देशों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। कोरिया को इसलिए चुना गया है क्योंकि यहां बड़े पैमाने पर प्राइवेट ट्यूशन का लम्बा इतिहास रहा है; और कई सरकारों द्वारा इस मुद्दे से निपटने के लिए विभिन्न नीतियों को अपनाया गया है - लेकिन इसमें कोई स्वास सफलता नहीं मिली है। मॉरीशस में भी इसी तरह का इतिहास रहा है, लेकिन यह कोरिया की तुलना में निर्देशात्मक है, क्योंकि यहां जनसंख्या कम है और संस्कृति तथा ट्यूशन का वर्चस्व भिन्न प्रकार का है। फ्रांस को इसलिए चुना गया है क्योंकि इसकी सरकार ने प्राइवेट ट्यूशन को प्रोत्साहित करने के लिए आधारभूत ढांचा स्थापित किया है और इसमें हुआ महत्वपूर्ण विकास हाल ही की घटना है।

कोरिया

सेठ (2002, पृष्ठ 1) ने कोरिया में शिक्षा को एक “राष्ट्रीय सनक” की संज्ञा दी है। उनके अध्ययन में कोरियाईयों द्वारा अपनी शिक्षा को “पढ़ाई का बुरा” कहा जाता है जो यह दर्शाता है कि शिक्षा आर्थिक और सामाजिक बदलाव लाने में प्रमुख साधन रही है और 20वीं सदी के मध्य से प्राइवेट ट्यूशन एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। किम (2007, पृष्ठ 1) द्वारा आईआईईपी के पॉलिसी फोरम के दौरान नोट किए गए अनुसार 63.1 प्रतिशत हाई स्कूल के छात्रों द्वारा 2007 में प्राइवेट ट्यूशन ली जा रही थी। जूनियर हाई स्कूल स्तर पर यह अनुपात 78.4 प्रतिशत, और प्राथमिक स्तर पर यह अधिकतम 88.2 प्रतिशत था। कोरियाई ट्यूशन प्रणाली के विविध रूप हैं उदाहरण के लिए, 2007 में मिडल स्कूल स्तर पर 45.5 प्रतिशत छात्र *हाकवोन* नामक प्राइवेट संस्थान में थे, 25.4 प्रतिशत छात्र व्यक्तिगत या समूह में ट्यूशन ले रहे थे, 10.4 प्रतिशत छात्र कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई वर्कशीट की मदद से ट्यूशन ले रहे थे जिन पर परिवार के सदस्यों द्वारा ट्यूटर्स से यदा-कदा प्राप्त सहायता के जरिए नज़र रखी जा रही थी, और 5.0 प्रतिशत छात्र ऑनलाइन ट्यूशन ले रहे थे (किम 2007, पृष्ठ 7)। वर्ष 2006 में ट्यूशन पर कुल परिवार खर्च 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर होने का अनुमान था (किम और ली, 2008, पृष्ठ 3)। यह सकल घरेलू उत्पाद का 2.8 प्रतिशत था, और पब्लिक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर हुए सरकारी खर्च के 80 प्रतिशत के बराबर था।

सरकारी अधिकारियों और आम जनता, दोनों द्वारा इन आंकड़ों को सदेह की दृष्टि से देखा जाता है। किम (2007, पृष्ठ 1) ने बताया कि:

प्राइवेट पूरक शिक्षा कोरिया में . . . सबसे पेचिदा मुद्दों में से एक है। इसे माता-पिता पर आर्थिक बोझ बढ़ाने, अमीर और गरीब के बीच असमानता की खाई को बढ़ाने, स्कूल

पाठ्यक्रम को विकृत करने, स्कूल अध्यापकों के अधिकारियों को कम करने, और छात्रों के संतुलित विकास को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है।

इसके साथ-साथ परिवारों की ट्यूशन संबंधी मांग-व्यापक और स्थिर बनी हुई है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर, जब कोरिया को जापानी उपनिवेश शासन से आजादी मिली थी तो निरक्षरता बहुत अधिक थी और देश बहुत गरीब था। चार दशकों बाद कोरिया में औद्योगिक क्रांति आई और यह 1996 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) का हिस्सा बन गया - जिसे उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों के “अमीर लोगों का क्लब” कहा जाता है (हेनरी, लिंगार्ड, और अन्य, (2009 पृष्ठ 7)। सेठ (2002, पृष्ठ 3) ने पाया कि प्राइवेट ट्यूशन पर बल देने सहित शिक्षा प्रणाली ने इस सफलता में अहम भूमिका निभाई थी, जो कम उपलब्धि नहीं है क्योंकि “अध्यापक वर्ग पर इसका दबाव और कड़ी प्रतिस्पर्धा ने ही अत्यधिक प्रतिस्पर्धी स्कूल प्रवेश परीक्षा का माहौल तैयार करते हुए एक कार्यबल तैयार किया जो अत्यधिक साक्षर और अनुशासित था जिससे देश पूंजीपति औद्योगिक व्यवस्था की प्रतिस्पर्धी विशेषताओं के लिए तैयार हो सका”।

परीक्षा प्रभुत्व और बार-बार किए गए सुधार

जापानी उपनिवेश के अधीन सदियों तक रहने के दौरान कोरिया में सिविल सर्विस परीक्षाओं की एक ठोस परंपरा पनपी जिससे सरकारी पदों पर पहुंच नियंत्रित हुई और कुछ थोड़े लोग ही इन प्रतिष्ठित पदों पर आसीन हो सके जिन्होंने कड़ी परीक्षा द्वारा इसमें प्रवेश पाया था (जेंग, 1999)। यह प्रणाली चीन के मॉडल पर आधारित थी, और यह कनफ्यूशियसवाद की परंपराओं से संबंध रखती थी, जिसमें औपचारिक शिक्षा और छात्रवृत्ति प्रमुख सामाजिक भूमिका निभाती थी। लेकिन परीक्षा की आधुनिक प्रणाली 20वीं सदी जापानी उपनिवेश युग का परिणाम थी और इसे स्वतंत्र कोरिया द्वारा मामूली संशोधन करने के बाद ज्यों का त्यों रखा गया था। 1950 के दशक के दौरान मिडल स्कूलों, हाई स्कूलों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण वॉटरशेड परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। इनमें से शुरुआती परीक्षाएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण थीं, जिन्होंने प्राथमिक स्कूल के छात्रों पर अत्यधिक दबाव डाला। कुछ स्कूलों ने शाम को और सप्ताह के अंत में शुल्क का भुगतान करके विशेष कक्षाओं का आयोजन किया और स्कूल के समय के बाद स्कूलों और अध्यापकों दोनों के लिए रट्टा लगवाने वाले सत्र आय का महत्वपूर्ण स्रोत बन गए।

परीक्षाओं की तैयारी के लिए इस पाठ्येतर प्रक्रिया की व्यापक आलोचना हुई क्योंकि इसने बच्चों पर दबाव बढ़ाया, माता-पिता पर आर्थिक बोझ डाला और इस तरह से समाज में असमानता की खाई को बढ़ाया। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी अनेक निर्देशों के कारण यह प्रथा समाप्त हुई। सन् 1955 में डिगरी अध्यक्ष रही साइनजमैन ने नोट किया कि अनेक स्कूलों और अध्यापकों को छात्रों की संख्या और स्कूल की क्षमता के बीच असंतुलन “से

काफी फायदा हुआ था, और यह घोषणा की गई कि भविष्य में पाठ्येतर कक्षाओं सहित ऐसी प्रक्रिया जारी रखने पर कानून के तहत कड़ा दण्ड दिया जाएगा” (सेठ, 2002, पृष्ठ 143)।

लेकिन इन प्रतिबंधों का कोई खास असर नहीं पड़ा। इसलिए प्राधिकारियों ने शिक्षा के विभिन्न चरण बनाते हुए छात्रों का चयन करने हेतु प्रणाली में सुधारों के माध्यम से पूरक ट्यूशन प्रणाली का दायरा सीमित करने के लिए आगे कदम उठाए। 1969 में सियोल में; 1970 में अन्य प्रमुख शहरों, और शेष देश में 1971 में सबसे महत्वपूर्ण उपायों को लागू करते हुए लॉटरी द्वारा मिडल स्कूल परीक्षा को बदला गया। इन सुधारों का उद्देश्य:

- दबाव को कम करके बच्चों का सामान्य विकास करना;
- मिडल स्कूल परीक्षा की तैयारी के लिए प्राथमिक स्कूलों द्वारा अत्यधिक ध्यान दिए जाने से रोकना;
- प्राइवेट ट्यूशन को हतोत्साहित करना;
- विभिन्न माध्यमिक स्कूलों के बीच के अंतर को न्यूनतम करना;
- परिवारों पर वित्तीय और मानसिक बोझ को कम करना था।

इन उपायों के माध्यम से नामांकन का विस्तार करना था, ताकि सभी छात्रों को नौ वर्षों तक अनिवार्य शिक्षा प्रदान करके राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

ये सुधार कम से कम अल्पावधि के लिए आंशिक रूप से सफल हुए, लेकिन इनसे अन्य समस्याएं उत्पन्न हुईं। स्कूलों ने पाया कि पढ़ाने के स्तर पर उनके पाठ्यक्रम में व्यापक भिन्नता थी, और अध्यापकों को उनके अनुसार अपने पढ़ाने के तरीके में तालमेल बैठाना था। माध्यमिक स्कूल परीक्षा को समाप्त करने और नामांकन का विस्तार करने का अर्थ था कि वॉटरशेड को अगले स्तर में भेज दिया गया था। जिन छात्रों में योग्यता और आकांक्षाएं थी, ने महसूस किया कि उनकी आवश्यकताएं माध्यमिक स्कूलों की मिली-जुली योग्य कक्षाओं से पूरी नहीं हो रही थीं, और उन्होंने हाई स्कूल परीक्षा के लिए स्वयं को तैयार करने के लिए प्राइवेट ट्यूशन का सहारा लिया।

इस पद्धति के उभरने के मद्देनजर 1974 में प्राधिकारियों ने हाई स्कूल में एक अन्य लॉटरी प्रणाली लागू की। 1980 तक सियोल और पुसान में लागू इस नीति को 20 शहरों में लागू किया गया, और 2003 तक इसने सामान्य हाई स्कूल के 73 प्रतिशत छात्रों को कवर कर लिया (किम, 2004, पृष्ठ 9)। विशेष प्रयोजन वाले हाई स्कूलों के असाधारण ट्रैक के लिए 1982 में एक योजना की घोषणा की गई थी ताकि योग्य छात्र विज्ञान, विदेशी भाषाओं, खेलकूद या अन्य क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित कर सकें। इसकी आलोचना हुई क्योंकि लॉटरी प्रणाली से सामान्य योग्यता प्रोत्साहित हो रही थी। वर्ष 2007 में, इन विशेष प्रयोजन हाई स्कूलों ने सभी माध्यमिक स्कूलों के 4.2 प्रतिशत छात्रों की जरूरतों की पूर्ति की (किम 2007, पृष्ठ 3)।

एक बार फिर, हाई स्कूल स्तर पर प्रतिस्पर्धी परीक्षा को समाप्त करने का मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि वॉटरशेड बढ़कर विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा स्तर पर पहुंच गया। वास्तव में, इस स्तर पर परीक्षा इतनी अधिक महत्वपूर्ण हो गई कि इसका निम्न स्तरों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। सेठ (2002, पृष्ठ 157) ने नोट किया कि कॉलेज की तैयारी करने का प्रारंभिक स्तर “निम्न से निम्नतर स्तर पर पहुंचना शुरू हो गया जब तक कि अधिकांश बच्चों ने यदि पहले नहीं तो प्राथमिक स्कूल में स्कूल की कक्षाओं के बाद प्राइवेट ट्यूशन लेना नहीं शुरू कर दिया। माध्यमिक और उच्च स्कूल प्रवेश परीक्षाओं को समाप्त करने का यह अर्थ भी था कि यह पहले की तुलना में प्रतिष्ठित संस्थानों सहित स्कूल डिस्ट्रिक्ट में रहना अधिक महत्वपूर्ण हो गया था। कुछ जिलों में स्कूलों ने कॉलेज प्रवेश परीक्षा में व्यापक सफल दर प्राप्त करने के कारण मान्यता प्राप्त कर ली जिससे संपत्ति के मूल्यों में वृद्धि हो गई। तत्पश्चात् मान्यता को अपने आप हवा मिली क्योंकि जिले समृद्ध परिवारों की कॉलोनियां बन गए जो प्राइवेट ट्यूशन का बोझ आसानी से उठा सकते थे।

प्रतिबंध के लिए नए सिरे से प्रयास

1980 में जब चुन डू-हवान ने नई सैनिक सरकार के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला तो अनुमानित 12.9 प्रतिशत प्राथमिक स्कूल छात्र, 15.3 प्रतिशत माध्यमिक स्कूल छात्र और 26.2 प्रतिशत हाई स्कूल छात्र ट्यूशन प्राप्त कर रहे थे (किम, 2007, पृष्ठ 1)। इस समस्या का कारगर हल निकालने के लिए प्रतिबद्ध राष्ट्रपति चुन ने कॉलेज प्रवेश परीक्षा का नियंत्रण व्यक्तिगत संस्थानों की बजाय नए राज्य नियंत्रित कॉलेज प्रवेश प्राप्ति परीक्षा के हाथों में दे दिया। उन्होंने अतिरिक्त हाई-स्कूल कक्षाओं और शैक्षिक विषयों में प्राइवेट ट्यूशन दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया। यह अब तक का सबसे कड़ा उपाय था। प्राइवेट ट्यूशन की अनुमति केवल खेलकूद, कला, संगीत, रैहकवांडर्ग और फल सज्जा के क्षेत्र के लिए थी।

लेकिन प्रतिबंध का लागू करना बड़ा ही मुश्किल था। सेठ (2002, पृष्ठ 186) ने टिप्पणी की कि:

माता-पिताओं ने प्राइवेट ट्यूशन के खिलाफ विनियम से बचने का भरसक प्रयास किया। कभी-कभी कॉलेज के छात्र हाई स्कूल की वर्दी पहनकर सदेह की कोई गुंजाइश छोड़े बिना अपने छात्रों के अपार्टमेंट में प्रवेश करते थे। कुछ परिवारों ने ट्यूटरों को अपार्टमेंट किराए पर दे दिए ताकि वे अपार्टमेंट के चौकीदारों की नज़र बचाकर एक या अधिक परिवारों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकें। रिसोर्ट और होटल तथा कोनडोस प्रायः गुप्त क्रैम स्कूल चलाते थे। अमीर लोग अपने बच्चों को ट्यूशन के लिए विदेश भेजते थे।

इन जोखिमों से लागत बढ़ गई, और गुप्त ट्यूशन एक फायदेमंद पेशा बन गया।

समझौते की आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने धीरे-धीरे प्रतिबंध में ढील दे दी (यांग, 2001):

- 1984 में सीनियर हाई स्कूल के छात्रों को सर्दी की छुट्टियों के दौरान प्राइवेट विदेशी भाषा संस्थान में भाग लेने की अनुमति दे दी गई। कम अंक पाने वाले छात्रों (न्यूनतम 20 प्रतिशत) को अध्यापकों से स्कूल में अतिरिक्त ट्यूशन लेने की अनुमति दी गई थी।
- 1988 में स्कूलों में प्रत्येक छात्र को अतिरिक्त ट्यूशन लेने की अनुमति दी गई थी जिसे स्कूल के अध्यापक शुल्क का भुगतान करने के आधार पर अपने छात्रों को देते थे।
- 1989 में विश्वविद्यालय के पूर्व-स्नातकों को प्राथमिक और माध्यमिक छात्रों को ट्यूशन देने, अध्ययन-सहायक टेप बनाने, खरीदने और किराए पर देने की अनुमति दी गई थी। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के छात्रों को छुट्टियों के दौरान ट्यूशन लेने के लिए प्राइवेट संस्थानों में भाग लेने की अनुमति दी गई थी।
- 1991 में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के छात्रों को स्कूल समय के दौरान ट्यूशन लेने के लिए प्राइवेट संस्थानों में जाने की अनुमति दी गई थी।
- 1996 में विश्वविद्यालय के स्नातकों को प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के छात्रों को ट्यूशन देने की अनुमति दी गई थी।

इन प्रतिबंधों को हटाने से तीव्र विकास हुआ। वर्ष 1993 में प्राइवेट ट्यूशन पर राष्ट्रव्यापी व्यय अनुमानित 3,410 बिलियन वोन (4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर) था। यह आंकड़ा 1994 में बढ़कर 4,696 बिलियन वोन और 1995 में 9,320 बिलियन वोन हो गया (यून और अन्य, 1997, पृष्ठ 1)। वर्ष 1997 तक प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्कूल छात्रों का औसत वार्षिक ट्यूशन शुल्क अनुमानित 12 से 16 प्रतिशत प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर था, जो जापान के स्तर से तीन से चार गुणा था (कवाक, 1999)। प्राथमिक स्तर पर ट्यूशन सबसे अधिक थी, और यह विशेष रूप से शहरों में थी लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रचलन में थी।

संभवतः इसकी वृद्धि के कारण ही 1997 में इस पर प्रतिबंध लगाने का मुद्दा राजनीतिक एजेडे में फिर से शामिल किया गया। राष्ट्रपति किम-डेई-जंग ने अपने 1998 के उद्घाटन भाषण में यह घोषण की कि वे “युवकों को पाठ्येतर कार्यक्रमों से मुक्त कर देंगे और माता-पिताओं को प्राइवेट ट्यूशन के भारी-भरकम आर्थिक बोझ से मुक्त कर देंगे” (यी 2002 द्वारा उद्धृत, पृष्ठ 2)। सरकार ने 1998 में घोषणा की कि माध्यमिक छात्रों के लिए अतिरिक्त शैक्षिक ट्यूशन पर चरणों में प्रतिबंध लगाया जाएगा: वर्ष 1999 में निम्न माध्यमिक स्कूल छात्रों और प्रथम वर्षीय उच्च स्कूल के छात्रों, तथा 2001 में माध्यमिक स्कूल के प्रत्येक छात्र पर।

लेकिन इस कदम की घोर आलोचना हुई। आलोचकों ने तर्क दिया कि ट्यूशन को महत्वहीन बनाकर यानी-ट्यूशन के जरिए प्राप्त होने वाले प्रतिस्पर्धी फायदों को कम करके,

और स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करके ही इससे निपटा जा सकता है। समाचार-पत्रों में एक संपादकीय लेख में यह सुझाव दिया गया (एशियावीक, 1997, पृष्ठ 20) कि:

कोरियाई प्राधिकारियों के लिए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में अपनी निजी खामियों से निपटने के लिए ट्यूटर्स पर प्रतिबंध लगाना वैसा ही है जैसे लूटपाट को समाप्त करने के लिए पूरी जनसंख्या को ही गरीब बना दिया जाए। एशिया में लगातार बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए इस बात में कोई तर्क नहीं दिखाई देता कि सर्वहारा के पक्ष में कानून बनाया जाए।

प्रतिबंध लगाने का यह नया प्रयास पिछले शासकों द्वारा किए गए उपायों से अधिक दूरी तक नहीं जा सका। वर्ष 2000 में, न्यायालय ने प्रतिबंध को असंवैधानिक घोषित कर दिया और इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन माना।

वैकल्पिक तरीके अपनाने का प्रयास

इस इतिहास के मद्देनज़र, कोरियाई प्राधिकारियों ने व्यापक दृष्टिकोण अपनाने का फैसला लिया और वर्ष 2004 में “सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के पुनरुद्धार के जरिए प्राईवेट ट्यूशन व्यय को कम करने की नीति” नामक एक पहल की शुरुआत की। इसका उद्देश्य यह देखते हुए सभी स्तरों पर राज्य शिक्षा सहित जनता को संतुष्ट करना था कि ट्यूशन पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों ने मूल बीमारी का इलाज करने की बजाय उसके लक्षणों का ही समाधान किया था। इसके लिए दस विशिष्ट उपायों की घोषणा की गई थी (किम, 2004, पृष्ठ 22):

1. ई-शिक्षा कार्यक्रमों के जरिए शिक्षा या शैक्षणिक प्रसारण सेवा टेलिविजन चैनल और इंटरनेट के जरिए तैयारी पाठ्यक्रम;
2. स्कूलों के विद्वतापूर्ण निष्पादन के आधार पर स्कूल के घंटों के बाद पूरक ट्यूशन के विभिन्न स्तरों का आयोजन करने की अनुमति दी गई;
3. पाठ्येतर कार्यकलापों को सशक्त बनाया जाए;
4. युवा प्राथमिक स्कूल के छात्रों के लिए स्कूल के बाद कक्षाएं, जिनके माता-पिता कामकाजी हैं और अपने बच्चों को शिशु देखभाल केन्द्रों में भेजने का खर्च नहीं उठा सकते;
5. पेशेवर अध्यापकों को भर्ती करना और एक विविधकृत शिक्षक मूल्यांकन प्रणाली को अपनाना;
6. शिक्षण और मूल्यांकन पद्धतियों में परिवर्तन करना;
7. छात्रों को उनकी दक्षता के आधार पर विभिन्न कक्षाओं में बांटकर एक अनुदेश प्रणाली बनाकर हाई स्कूल समानता नीति में परिवर्तन करना;
8. सीएसएटी अंकों पर केन्द्रित ध्यान में कमी लाते हुए हाई स्कूल रिकार्डों और पाठ्येतर कार्यकलापों को प्राथमिकता देते हुए कॉलेज प्रवेश प्रणाली में परिवर्तन करना;
9. शिक्षा प्राप्ति का अधिकतम स्तर सुनिश्चित करना;
10. समाज और संस्कृति में सुधार लाना;

इनमें से कुछ उपाय उलट दिए गए या इनसे पिछले सुधारों में पर्याप्त रूप से संशोधन हो गया। स्कूलों की सिफारिशों को महत्व देने के लिए कॉलेज प्रवेश प्रणाली तथा पाठ्यतर कार्यकलापों में सुधार करना केन्द्रीयकृत परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने और मूल्यांकन मापदण्ड को मानकीकृत बनाकर भ्रष्टाचार को कम करने के कहीं भी अपनाए गए उपायों से भिन्न था (गोर्गोडजे, 2007)। स्कूली शिक्षा के लिए प्राइवेट ट्यूशन प्रणाली के कुछ पहलुओं का दावा करने के लिए नई योजना में जाने-माने कैम स्कूल व्याख्यानों को किराए पर लेना शामिल था ताकि उपग्रह दूरदर्शन और इंटरनेट के जरिए प्रमुख विषयों में निःशुल्क ट्यूशन दी जा सके (ली, 2007, पृष्ठ 1228)।

हाई स्कूल समता नीति में परिवर्तन भी महत्वपूर्ण था। 1974 में जब यह नीति लागू की गई थी तो यह तर्कसंगत और आकर्षक दोनों प्रतीत होती थी, और यह ऐसा उपाय था, जो कम से कम पहली नज़र में दूसरे देशों की सरकारों को अपील कर सकती थी। इसलिए किम और ली (2008, पृष्ठ 29) जैसे मूल्यांकनकर्ताओं की टिप्पणियों को पढ़ना व्यंग्यात्मक है। इस नीति को “प्राइवेट ट्यूशन की मांग बढ़ाने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार माना जा सकता है”। हालांकि यह स्पष्ट है कि यह नीति अपने कार्यान्वयन और प्रभाव में खरी नहीं थी।

सारणी 11. कोरिया में 1980 – 2007 के बीच प्राइवेट ट्यूशन लेने वाले छात्रों का प्रतिशत

	प्राथमिक स्कूल	माध्यमिक स्कूल	हाई स्कूल
1980	12.9	15.3	26.2
1997	72.9	56.0	32.0
2007	88.2	78.4	63.1

स्रोत: किम (2007), पृष्ठ 1

10 की सूची में इन विशिष्ट घटकों के विपरीत यह अंतिम घटक “समाज और संस्कृति में सुधार” था, जिसे परिभाषित करने या लागू करना यदि बहुत सामान्य था, तो उतना ही कठिन भी था। कोरिया में शिक्षा के प्रति प्रतिस्पर्धी भावना और सम्मान कहीं गहरे तक जुड़ा है और इसमें तत्काल सुधार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार, ट्यूशन का पिछली सरकारों द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिशों के बावजूद व्यापक विस्तार हुआ है (सारणी 11)। ट्यूशन संस्थानों (हाकवोन्स) की संख्या 1980 में 381 से बढ़कर 2000 में 14,043 और 2007 में 31,000 हो गई थी (किम और ली, 2008, पृष्ठ 9)। प्राइवेट ट्यूशन पर खर्च आय में वृद्धि की तुलना में काफी अधिक तेजी से बढ़ रहा है (किम और ली, 2008, पृष्ठ 3)। इसके बावजूद, कोरियाई प्राधिकारियों ने मामले का ताकत से समाधान करना जारी रखा। ली और जांग (2008, पृष्ठ 15) ने “धैर्य बनाए रखने और समस्या का दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य में समाधान करने का दृष्टिकोण अपनाने” की आवश्यकता की ओर सही संकेत किया है जो एक “बहुआयामी और व्यापक दृष्टिकोण” है।

बॉक्स 3. दबाव से निपटना

कोरियाई सरकार ने विशेष प्रयोजन हाई स्कूलों के एक समूह का सृजन किया है जो स्कूल की समतावादी नीति से मुक्त है। इन स्कूलों में प्रवेश लेने की प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक रूप से काफी तीव्र है, और प्राइवेट ट्यूशन निरपवाद रूप से इसका हिस्सा है। किम (2007) के उन तरीकों का अध्ययन किया कि विभिन्न परिवार दबावों का सामना करते हैं। यहां एक दा-जंग और उसकी मां से हुई बातचीत दर्शाई जा रही है। यह परिच्छेद दा-जंग के जीवन की महत्वपूर्ण अवधि; उस पर पड़ते दबाव, हालांकि औरों की तुलना में जिसकी तीव्रता कम है, को उजागर करता है, जिसका लाखों कोरियाई बच्चों द्वारा अपने पूरे स्कूल करियर में रोज़ाना सामना किया जाता है।

दा-जंग ने विशेष प्रयोजन हाई स्कूल की प्रवेश परीक्षा से दो महीने पहले प्राइवेट संस्थान में दाखिला लिया, और कोरियाई, अंग्रेजी और गणित विषयों का अध्ययन किया। वह स्कूल के बाद प्राइवेट संस्थान में शाम को लगभग 5 बजे जाती थी, और रात 10 बजे तक कक्षा में पढ़ती थी। वह प्रातः 2 बजे तक संस्थान के स्व-अध्ययन कक्ष में रहती थी और फिर घर लौटती थी। वह लगभग 3 बजे सोती थी और प्रातः 6 बजे उठकर स्कूल जाती थी।

दा-जंग की मांग ने याद करते हुए बताया कि वह कितना कम सोती थी।

वह मेरे जागने के साथ ही उठ जाती थी। मुझे उसे जगाने में बहुत बुरा लगता था। जब मैं उसे 6.00 बजे तक नहीं जगाती थी, क्योंकि मुझे उसे उठाना अच्छा नहीं लगता था, वह बेहद नाराज़ हो जाती थी। उसने मुझसे कहा: “आपको सख्त होना पड़ेगा। यदि ऐसा करना आपके लिए मुश्किल है तो भी आपको मुझे जगाना होगा। क्योंकि यह मेरी भलाई के लिए है। आपको मुझे जगाने के लिए हिलाना होगा और ज़रूरत पड़े तो मारना भी होगा।”

हालांकि दा-जंग की मांग यह महसूस करती है कि उनकी बेटी की जिंदगी इस अवधि के दौरान बहुत कठोर रही, फिर भी वे प्राइवेट ट्यूशन को एक निवेश मानती हैं। इस अवधारणा की पुष्टि बच्चों की दूसरी माँओं से मिलकर और उनके बच्चों द्वारा प्राप्त की जाने वाली ट्यूशन के बारे में जानकारी हुई।

दा-जंग के लिए ट्यूशन संस्थान ने उसे अपने दृष्टिकोण का विस्तार करने में सक्षम बनाया। दा-जंग ने यहां प्रतिस्पर्धा से खबरू हुई, और उसने जमकर पढ़ाई की। हालांकि प्राइवेट संस्थान में जाने से उसकी स्कूल की पढ़ाई प्रभावित हुई क्योंकि वह संस्थान में रात 2 बजे तक रहती थी, और वह प्रायः स्कूल में सो जाती थी।

स्रोत: किम (2007), पृष्ठ 7-8

मॉरीशस

कोरिया में अपने सहयोगी देश की तरह मॉरीशस प्राधिकारियों ने भी लम्बे समय से प्राइवेट ट्यूशन की समस्या से निपटने के प्रयास किए थे लेकिन उन्हें मामूली सफलता ही मिली थी। आईआईईपी के पॉलिसी फोरम ने मॉरीशस में दो पूर्व शिक्षा मंत्रियों को एक साथ मंच पर ला दिया, अरमूगम परसुरामेन (1983-1995) और स्टीवेन ओबीगाडू (2000-2005)। राजनीति के क्षेत्र में वे परस्पर विरोधी थे, लेकिन पॉलिसी फोरम के

दौरान वे प्राइवेट ट्यूशन की समस्या का कोई कारगर समाधान निकालने की कठिनाई का घोषणा करने में एक साथ थे। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने जिन चुनौतियों का सामना किया था, उन्हीं चुनौती का उनके उत्तराधिकारियों द्वारा भी सामना किया गया था।

वास्तव में, मॉरीशस में प्राइवेट ट्यूशन की चुनौतियाँ पिछली एक सदी से विद्यमान है। फुनडून (2002, पृष्ठ 488) ने 1901 के एक वक्तव्य को उद्धृत किया जिसे राज्य के एकमात्र बाल माध्यमिक स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा दिया गया था, जिन्होंने ट्यूशन के नकारात्मक आयाम को पहचान लिया था लेकिन इसे रोकने में “अक्षमता जताई”। इसी प्रकार की टिप्पणी मॉरीशस के रॉयल कॉलेज; कुरेपाइप द्वारा 1911 में की गई थी (मॉरीशस में उद्धृत 1994, पृष्ठ 1-2), जिन्होंने शिकायत की कि उनके स्टॉफ के 12 सदस्य प्रति सप्ताह 13 से 33 घंटों की प्राइवेट ट्यूशन दे रहे थे। उन्होंने आगे कहा:

इस प्रथा को रोकना तब तक असंभव था जब तक पर्याप्त मुआवजा नहीं दे दिया जाता, न ही मैं समझता हूँ कि ऐसे उपाय की जरूरत है। लोगों को कॉलेज के घंटों के बाद अपने फुर्सत के क्षणों को जैसा चाहें इस्तेमाल करने का अधिकार है और मैं नहीं समझता कि उन्हें कोई रोक सकता है। मेरे लिए भी उन पर अंकुश लगाना समान रूप से असंभव है। इसे कैसे लागू किया जा सकता है? सदस्य अपनी बात को जोरदार ढंग से कह सकते हैं कि कार्यालय घंटों के बाद उन पर कोई बंदिश नहीं लगाई जा सकती। मैं इसे एक बुराई मानता हूँ, लेकिन मैं इसका कोई संतोषजनक समाधान सुझाने में असमर्थ हूँ।

तीन दशकों के बाद, 1941 शिक्षा रिपोर्ट के लेखक ने तर्क दिया कि यदि अध्यापक सोमवार से शुक्रवार तक प्रत्येक रात को दो अतिरिक्त घंटों तक अध्यापन कर रहे हैं तो वे अपने कार्य में दक्ष नहीं हो सकते। रिपोर्ट (मॉरीशस में उद्धृत, 1944, पृष्ठ 2) में आगे कहा गया है:

यदि... कार्य दिवस अधिक लंबा न हो, तो उसे बढ़ाया जा सकता है। पूरी कक्षा के लिए प्राइवेट कोचिंग की आवश्यकता नहीं है; और कुछेक पिछड़ने वाले लड़कों के लिए आवश्यक प्राइवेट कोचिंग कक्षा के अध्यापक द्वारा उसकी ड्यूटी के भाग के रूप में दी जानी चाहिए जिसके लिए उसे वेतन दिया जाता है।

अरमूगम परसुरामेन नेतृत्व (1983-1995)

अरमूगम परसुरामेन ने प्राइवेट ट्यूशन के बारे में बढ़ती चिंता की अवधि के दौरान पदभार संभाला, और मामले का समाधान करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। उनके कार्यभार के दौरान एक श्वेत पत्र जारी किया गया (मॉरीशस, 1984, पृष्ठ 15), जिसमें कहा गया था कि:

सरकार प्राइवेट ट्यूशन की बुराई के प्रति चिंतित है - विशेषकर प्राथमिक स्कूलों में। जिन परिवारों के बच्चे प्राइवेट ट्यूशन का बोझ नहीं उठा सकते, वे अपने स्कूली जीवन

में शुरू से ही घाटे की स्थिति में होंगे। सरकार प्राइवेट ट्यूशन और स्कूलों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव की संपूर्ण जांच कराने का प्रस्ताव करती है। अध्ययन के परिणामों के आलोक में स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्धारित किए जाएंगे। लेकिन प्राइवेट ट्यूशन के नुकसानदायक प्रभावों के खिलाफ अभियान छेड़ने में मुख्य बल स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना होगा। यदि अध्यापक अपना सामान्य कार्य निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से करते हैं तो प्राथमिक स्कूलों में प्राइवेट ट्यूशन की मांग काफी हद तक कम हो जाएगी।

इसकी मॉरीशस विश्वविद्यालय के एक दल द्वारा जांच की गई थी। यह पाया गया कि 1986 में प्राथमिक स्कूल के बच्चों द्वारा ट्यूशन लेने का प्रतिशत प्राथमिक कक्षा (ग्रेड) I में 11.2 प्रतिशत से बढ़कर कक्षा VI में 72.7 प्रतिशत हो गया था। यह अनुपात माध्यमिक स्तर-I में घटकर 37.3 प्रतिशत रह गया था, लेकिन फोरम VI में बढ़कर 87.2 प्रतिशत हो गया था (जॉयनाथसिंह, मंजूर, और अन्य, 1998 पृष्ठ 31 और पृष्ठ 43)। प्राथमिक स्तर के समाप्त होने पर प्रतिशत का बढ़ना प्राथमिक शिक्षा प्रमाण-पत्र (सीपीई) परीक्षा के महत्व को दर्शाता है, जो माध्यमिक स्कूल प्रणाली का प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार से गुजरने के बाद प्राइवेट ट्यूशन लेने वाले छात्रों का अनुपात तब तक गिरा रहा जब तक स्कूल प्रमाण-पत्र और उच्च स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षाएं नहीं आ गईं। मॉरीशस की माध्यमिक स्कूल प्रणाली में काफी अधिक चरण हैं, और प्राथमिक स्कूल चरण पर प्राइवेट ट्यूशन लेने का जुनून चरम सीमा पर पहुंच जाता है। फूनडून (1992) के शब्दों में यह “फाइव स्टार” माध्यमिक स्कूल में प्रवेश पाने की पागलपन की सीमा तक एक होड़ है। छात्र पढ़ाई में जितना अधिक अच्छे होते हैं, उतना ही अधिक उनके द्वारा प्राइवेट ट्यूशन लेने की संभावना रहती है।

ट्यूशन लेने का स्थान उनके स्तर के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकता है। प्राथमिक स्तर पर अधिकांश ट्यूशन अध्यापकों द्वारा स्वयं स्कूल में ही दी जाती है और छात्रों पर ट्यूशन लेने का काफी दबाव रहता है। माध्यमिक स्तर पर, ट्यूशन प्रायः विषय के विशेषज्ञ द्वारा दी जाती है जो जरूरी नहीं छात्रों के अपने स्कूल का ही अध्यापक हो। ट्यूशन छोटे समूहों के लिए अध्यापक के घर पर या बड़े समूहों के लिए किराए पर लिए गए परिसरों में दी जाती है। मॉरीशस में कोरियाई *हाकवोन* जैसे कुछ ही संस्थान थे।

मॉरीशस विश्वविद्यालय अध्ययन कोई स्पष्ट प्रस्ताव नहीं दे पाया, लेकिन इससे पता चला (जॉयनाथसिंह और अन्य 1998, पृष्ठ 64-66) कि:

- प्राइवेट ट्यूशन का प्रचलन स्वयं को सुदृढ़ करने की प्रणाली का एक हिस्सा थी। इस बात में कोई दो राय नहीं कि कक्षा की पढ़ाई परीक्षा में अच्छा परिणाम हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। लेकिन कई अध्यापकों का मानना था कि उनके जो छात्र ट्यूशन ले रहे थे, उन्हें कक्षा में कम परिश्रम करना पड़ा और इससे प्रत्येक छात्र परीक्षा के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सका था। अतः प्राइवेट ट्यूशन लेने की जरूरत भविष्य के लिए खुद को तैयार करना बन चुकी है।
- प्राइवेट ट्यूशन प्रणाली में एक बार पैर जमाने के बाद सशक्त और निहित स्वार्थी लोग इसे बनाए रखना चाहते हैं। माता-पिता ट्यूशन को अपने बच्चों के सामाजिक और

आर्थिक विकास के रूप में लेते हैं, अध्यापक ट्यूशन को बिना कर वाली आमदनी के रूप में लेते हैं, और आम जनता ट्यूशन को करदाता पर कोई बोझ डाले बिना शिक्षा के स्तर में सुधार के तरीके के रूप में लेती है। इन्हीं सब कारणों से ट्यूशन के दायरे को घटाने के प्रस्ताव के अधिक कारगर होने की संभावना नहीं है, जब तक कि स्कूल में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए आमूल-चूल परिवर्तन न किए जाएं।

- हम उन मापदण्डों में बदलाव लाकर प्राइवेट ट्यूशन की मांग को कम कर सकते हैं जिसके तहत शिक्षा प्रणाली कार्य करती है; उदाहरण के लिए परीक्षाएं ज्ञान प्राप्त करने की बजाय योग्यता के आधार पर ली जाएं, या नियोक्ताओं को मुख्यतः शैक्षिक योग्यता की बजाय अभिरूचि परीक्षा के अनुसार इसे अध्यापकों द्वारा लिए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हालांकि सुधार तभी सफल हो सकते हैं यदि इनका आधार सामाजिक और आर्थिक हो। सुधार माता-पिता और छात्रों की अपेक्षाओं, और बाजार में नौकरी की वास्तविकता के अनुरूप होने चाहिए। इन तथ्यों की अनदेखी करने वाला कोई भी थोपा गया समाधान निश्चित रूप से असफल होगा।

शिक्षा मंत्री परसुरामेन ने संसद का ध्यान मॉरीशस विश्वविद्यालय की अध्ययन प्रणाली की ओर आकृष्ट करने में सफलता हासिल की जहां, 1988 में इस पर व्यापक बहस हुई। परसुरामेन ने बच्चों की पढ़ाई के बढ़ते घण्टों, “कड़ी शारीरिक श्रम स्थितियों” जिसमें ट्यूशन दी जा रही थी, जिसमें अध्यापकों के गैराज और इसी प्रकार के स्थल शामिल थे, तथा निम्न आय वर्ग के परिवारों द्वारा यह दण्ड भोगा जा रहा था, की ओर ध्यान दिलाया। प्रधानमंत्री ने इस विषय को संज्ञान में लेते हुए यह सुझाव दिया कि माता-पिता शिक्षक एसोसिएशन (पीटीए) बच्चों के हित में कहीं अधिक संतुलित दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद कर सकती है। उन्होंने माध्यमिक प्रावधान का विस्तार करके प्राथमिक स्तर के समाप्त होने तक की बाधाओं को कम करने की जरूरत पर भी जोर दिया, और प्रि-प्राइमरी से लेकर कक्षा-III तक के बच्चों के लिए निजी ट्यूशन पर प्रतिबंध लगाने की संभावना पर बल दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि राजनीतिज्ञ अपने बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन के लिए न भेजकर अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं।

सरकार ने आम जनता के लिए प्राइवेट ट्यूशन पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। चूंकि मॉरीशस एक छोटा देश है जिसकी आबादी केवल दस लाख है, फिर भी कार्यशाला में माता-पिता के समूहों और शिक्षक यूनियनों सहित काफी लोगों ने भाग लिया। इससे यह बात उभरकर सामने आई कि ट्यूशन प्रणाली ने अपनी जड़ें किस हद तक जमा ली हैं। इसे देखते हुए 1989 में मंत्री ने यह विनियम (परसुरामेन, 2007) निर्धारित किए कि:

- छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा-III तक ट्यूशन को प्रतिबंधित किया जाए;
- निम्न कक्षाओं के टाइम टेबल की समीक्षा की जाए, विशेषकर नागरिक शास्त्र, रचनात्मक और संचलन शिक्षा, तथा अध्ययन के समय को बढ़ाया जाए;

- कक्षा IV, V और VI के छात्रों को ट्यूशन अध्यापकों के घरों में या किराए पर लिए गए भीड़भाड़ वाले परिसरों में देने की बजाय उचित माहौल वाली कक्षाओं का प्रयोग करने की अनुमति दी जाए;
- प्राइवेट ट्यूशन कक्षा के आकार को अधिकतम 40 छात्रों तक तथा छात्रों के ट्यूशन के समय को प्रति सप्ताह 10 घण्टे तक सीमित किया जाए।

अगला कदम इन विनियमों को कानूनी रूप देना था। वर्ष 1991 में संसद में विधेयक प्रस्तुत करने के दौरान परसुरामेन ने कहा कि शिक्षकों को ऐसे छात्रों को प्रवेश देने के लिए कहा जाएगा जो ट्यूशन शुल्क नहीं दे सकते और उन्होंने इन उपायों को अमल में लाने के लिए नीतिशास्त्र सहिता और शिक्षक परिषद लागू करने की योजना बनाई है। बहस के दौरान विरोधी दल के सदस्यों ने कक्षा IV से VI में शिक्षकों के एक ऐसे वर्ग के उभरने के जोखिम की ओर ध्यान दिलाया जिन्हें ट्यूशन लेने की अनुमति दी गई थी जबकि कक्षा I से III के शिक्षकों को इसकी अनुमति नहीं दी थी। उन्होंने यह भी दलील दी कि कक्षा IV से VI में लगातार ट्यूशन देना “अत्यधिक निंदनीय” था क्योंकि इससे शिक्षा की एक समानांतर प्रणाली बनेगी। किंतु मंत्री महोदय अपने निजी दृष्टिकोण पर दृढ़ रहे और बहस के बाद विधेयक पारित हो गया (परसुरामेन, 2007)।

इसी वर्ष सीपीई परीक्षा में असफलता का विशेष संदर्भ लेते हुए प्राथमिक स्कूल के कार्य-निष्पादन के घटते स्तर पर एक रिपोर्ट जारी की गई (मनराखन, वशिष्ठ और अन्य, 1991)। रिपोर्ट में कहा गया कि हालांकि ट्यूशन दिलाना कई माता-पिताओं के लिए आर्थिक बोझ था, फिर भी कई लोगों ने अच्छे माध्यमिक स्कूलों में स्थान पाने के लिए अपने बच्चों को ट्यूशन दिलाई थी। लगभग 70 प्रतिशत सीपीई उम्मीदवार सप्ताह में 2 दिन से लेकर 5 दिन तक ट्यूशन ले रहे थे। अधिकांश बच्चों (88 प्रतिशत) ने एक ट्यूटर से, 9 प्रतिशत बच्चों ने दो ट्यूटरों से तथा 3 प्रतिशत बच्चों ने तीन ट्यूटरों से मदद ली थी। सीपीई परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले नब्बे प्रतिशत बच्चे प्राइवेट ट्यूशन ले रहे थे, जबकि असफल रहने वाले आधे बच्चे ट्यूशन नहीं ले रहे थे।

इन आंकड़ों से, और मंत्री द्वारा माता-पिता को जागरूक बनाने का समर्थन किए जाने के बाद सरकार ने प्राइवेट ट्यूशन के फायदे और नुकसान विषय पर एक इशतहार जारी किया (मॉरीशस 1994)। इस इशतहार में उन नीतियों को संक्षेप में दर्शाया गया था जो वास्तव में विनियम, सुविधा और अनुरोध का मिला-जुला रूप था। कक्षा I-III में ट्यूशन पर प्रतिबंध लगाना तथा सप्ताह के घण्टों की संख्या को सीमित करना और कक्षा का आकार इस विनियम का हिस्सा थे। सुविधाओं में प्राइवेट ट्यूशन के लिए स्कूल परिसर का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा यह सुनिश्चित किया गया था कि बच्चे शैक्षिक रूप से अनुपयुक्त माहौल में कक्षाएं न लें, इस उपाय से ऐसे स्थान उपलब्ध कराए गए जिन पर प्राधिकारी विनियमों के अनुरूप अनुपालन करने पर नजर रख सकते हैं। नीति में शिक्षकों से निम्न आय स्तर के छात्रों से भेदभाव न बरतने की अपील की गई थी।

पूरक उपायों के रूप में प्राथमिक और सीपीई परीक्षा के पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया था, और एक ही शिक्षक पर छात्रों की निर्भरता को कम करने के लिए कक्षा IV में विषय आधारित अध्ययन शुरू किया गया था। प्रधानाचार्य और निरीक्षकों को उन शिक्षकों की रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है जो ट्यूशन न लेने वाले छात्रों के साथ भेदभाव बरतते हैं और माध्यमिक स्कूलों के बीच असमानता को कम करने और इस प्रकार 'फाइव स्टार' संस्थानों में प्रवेश पाने की होड़ को कम करने के लिए आगे प्रयास किए गए थे।

विनियम मुख्यतः शिक्षकों को ध्यान में रखकर बनाए गए थे जिन पर प्रमुख कक्षाओं को पढ़ाने की भी जिम्मेदारी थी। तथापि, इस प्रक्रिया पर रोक लगाना ट्यूशन के किसी रूप को रोकने से अधिक आसान है, और कक्षा I से III तक के बच्चों के महत्वाकांक्षी माता-पिता को ट्यूटर्स को स्वतंत्र रूप से नियुक्त करना जारी रखा। इसके अलावा, जैसा कि कुछ सांसदों को आशंका थी, कक्षा I से III में प्रतिबंध लगाए जाने से स्कूल में चरण बन गए क्योंकि मॉरीशस समाचार पत्र (*ला' एक्सप्रेस* 20 जून 1993 में फूनडून, 202 पृष्ठ 506 द्वारा उद्धृत) के शब्दों में निम्न श्रेणी के शिक्षकों को "प्राइवेट ट्यूशन के रसदार केक का हिस्सा खाने से वंचित कर दिया गया था"। इसका परिणाम यह हुआ कि स्कूलों में इस बात पर तेजी से पैरवी होने लगी कि कौन सा शिक्षक उच्च कक्षाएं ले सकता है। 1994 की यूनिसेफ रिपोर्ट में कहा गया है (पृष्ठ 35) कि:

शिक्षक के लिए कक्षा IV के शुरू होने पर माता-पिता को एक नोट भेजते हुए यह घोषणा करना आम बात है कि उनके बच्चे की प्राइवेट ट्यूशन उसके द्वारा ली जाएगी। छात्रवृत्ति देने के रूप में जाने जाने वाले शिक्षकों से प्राइवेट ट्यूशन लेने की मांग अधिक रहती है। स्वाभाविक है कि पैसे वाले माता-पिता बेहतर शिक्कों से व्यक्तिगत प्राइवेट ट्यूशन का बोझ उठा सकते हैं। इस प्रकार, एक लोकतांत्रिक समाज में समतावादी, मुफ्त शिक्षा प्रणाली व्यावहारिक तौर पर एक विशिष्ट वर्ग की प्रणाली बनकर रह गई जिसमें परिणाम और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा कीमत चुकाकर बिकने लगी।

परसुरामेन ने 1995 में शिक्षा मंत्री के रूप में अपने लम्बे करियर को पूरा किया। अपने लगातार प्रयासों के बावजूद उन्होंने दो वर्ष बाद यह टिप्पणी की (परसुरामेन, 1997, पृष्ठ 51) कि "समस्या ज्यों की त्यों है"। वे यह देखना चाहते थे कि उनके उत्तराधिकारी द्वारा "इस जटिल मुद्दे से निपटने के लिए" क्या नए उपाय किए जाएंगे।

कैडरेस आर. चेदुमबारूम पिल्ले ने कार्यभार संभाला (1997-2000)

परसुरामेन के उत्तराधिकारी चेम्स बर्टी डेविड थे। वे कार्यालय में केवल डेढ़ वर्ष के लिए रहे और उन्होंने ट्यूशन के मामले का कोई समाधान नहीं किया। लेकिन उनके उत्तराधिकारी ने ऐसा किया। उनका नाम कैडरेस आर. चेदुमबारूम पिल्ले था, जिन्होंने प्राइवेट ट्यूशन और शिक्षा प्रणाली में चरण बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने

दीर्घावधि ढांचागत सुधार किए जिनमें कुछ संस्थानों को “पांच सितारा स्कूल” समझे जाने में कमी करने का लगातार प्रयास करना था जबकि दूसरे संस्थानों को दूसरा और तीसरा दर्जे के रूप में देखा जाता था। प्राथमिक स्कूलों में असमानताओं को कम करने के लिए समानांतर प्रयास किए गए, ताकि छात्रों को सीपीई परीक्षा में और अधिक समान अवसर प्राप्त हो सकें। इन उपायों पर 1997 में एक श्वेत-पत्र जारी किया गया, जिसमें कहा गया था (मॉरीशस, 1997, पृष्ठ 28) कि प्राइवेट ट्यूशन का जन्म “अत्यधिक प्रतिस्पर्धी शिक्षा प्रणाली, कोई शिक्षक विकास योजना न होने, शिक्षकों की सेवा-शर्तों में प्रतिभाशाली व्यक्तियों को पहचानने की अक्षमता, और किसी गुणवत्ता आश्वासन ढांचे के विद्यमान न होने के कारण हुआ था”। श्वेत पत्र में कोई बड़ा समाधान करने की वकालत नहीं की गई थी, बल्कि इस बात पर विचार किया गया था कि प्राइवेट ट्यूशन की समस्याएं व्यापक शिक्षा सुधारों के बाद समाप्त हो जाएंगी। फिर भी दस्तावेज में यह परिकल्पना की गई थी (पृष्ठ 28-29) कि:

- स्कूल परिसर में प्राइवेट ट्यूशन पर प्रतिबंध लगाया जाए;
- शिक्षकों को ट्यूशन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी जिसमें घंटों की संख्या, छात्रों की संख्या, अवधि, समय और स्थल का उल्लेख किया गया हो;
- सप्ताह के अंत में और सार्वजनिक अवकाश के दौरान ट्यूशन पर प्रतिबंध लगाया जाए;
- स्कूल के घंटों के बाद शिक्षकों से पारिश्रमिक आधार पर सुधार कक्षाएं लगाने की अपेक्षा की जाती है।
- शिक्षकों के पाठ को दोहराने की स्थिति।
- निरीक्षकों द्वारा शिक्षकों के कार्य-निष्पादन की कड़ी निगरानी रखना ताकि लक्ष्यों और मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके।
- मीडिया सामग्री का विकास करना तथा माता-पिताओं की ई-मेल के इस्तेमाल द्वारा कक्षा कार्य को पूरा करने में मदद करना।
- प्राइवेट ट्यूशन के दुष्परिणामों के बारे में माता-पिता और समुदाय को जानकारी देना।
- शिक्षकों की पदोन्नति की संभावनाओं पर विचार करते समय अनुपालन न करने के साक्ष्य जुटाना।
- नए छात्र अधिकार घोषणा-पत्र का सख्ती से पालन करना।

पिछली नीतियों में ट्यूशन के लिए स्कूल के परिसर का इस्तेमाल किया जा सकता था। पिछली व्यवस्था में नीति निर्माताओं ने स्कूलों में ट्यूशन की अनुमति इस आधार पर दी थी कि वह ऐसा व्यवस्थित ढंग से होने देंगे और घरों या अन्य अपर्याप्त परिसरों में आयोजित की जा रही बड़ी कक्षाओं के खतरे को मिटाया जा सकेगा। एक अन्य उद्देश्य छोटे बच्चों द्वारा स्कूल से ट्यूशन स्थल तक पहुंचने के जोखिम को हटाना था। पिल्ले ने इस नीति को यह तर्क देते हुए उलटने का प्रयास किया कि यह सार्वजनिक सुविधाओं का

दुरुपयोग था और इसने इस संभावना को बढ़ाया कि शिक्षक अपने बच्चों पर ट्यूशन लेने के लिए दबाव डालेंगे क्योंकि बच्चों के पास इससे बचने की बहुत कम संभावना होगी।

हालांकि पिल्ले ने पाया कि उनके प्रयासों से सरकार में ही विरोध के स्वर उभर रहे थे। वह अन्य मंत्रियों और वरिष्ठ कार्मिकों की नजर में अलग-थलग पड़ गए जो जनता के दबाव के कारण ट्यूशन का समर्थन कर रहे थे। आखिरकार, उनके सहयोगियों की ही बात मानी गई: पिल्ले को विदेशी दौर पर भेजा गया, और उनकी गैर-हाजिरी में मंत्रिमंडल ने नीति को उलट दिया।

स्टेवेन ओबीगाडू द्वारा नए सिरे से किए गए प्रयास (2000-2005)

स्टेवेन ओबीगाडू के कार्यकाल में उन्हीं बातों पर विचार किया गया जो उनके पूर्व नेताओं की चिंता का विषय रहे थे। इसकी समानता का परिचायक वह जोखिम दस्तावेज था जिसका शीर्षक स्पष्ट था *प्राथमिक शिक्षा में चूहे की दौड़ को समाप्त करना* (मॉरीशस, 2001)। इस दस्तावेज में एक बार फिर स्टार स्कूलों में स्थान सुरक्षित करने की होड़ की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए यह उल्लेख किया गया कि इस प्रणाली से “छात्रों और उनके माता-पिताओं पर भारी मानसिक दबाव पड़ रहा है और साथ ही समाज में स्कूल की कार्य-प्रणाली को विकृत कर रहा है”। सुधारों का एक पैकेज लागू किया गया (ओबीगाडू, 2007, पृष्ठ 4):

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की संख्या को दुगुना कर दिया गया, विशिष्ट माध्यमिक विद्यालयों को VI फार्म कॉलेजों में परिवर्तित किया गया और माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश आवास के आधार पर दिया गया ताकि प्रारंभिक स्कूली शिक्षा के अंत में उच्च स्तरीय परीक्षा से बचा जा सके। इसके साथ-साथ स्कूल के समय को बढ़ाया गया ताकि ट्यूशन के समय को सीमित किया जा सके और सभी शिक्षकों को विशेष वेतन भत्ता दिया गया। इसके अलावा, कम अंक लेने वाले (निर्धनतम) बच्चों के लिए मुफ्त अनुपूरक ट्यूशन के प्रावधान सहित शैक्षिक कार्य क्षेत्रों की स्थापना की गई थी।

हालांकि ऐसा करने में सरकार को इस प्रक्रिया में विरोधी पक्ष का सामना करना पड़ा जो इसे मानने के लिए तैयार नहीं थे। आईआईईपी नीति कोरम के दौरान ओबीगाडू द्वारा दिया गया एक उदाहरण कानूनी प्रणाली से संबंधित था। एक वकील होने के नाते ओबीगाडू कानूनी प्रणाली का प्रयोग करने के लिए उत्सुक थे। उन्हें माता-पिताओं से कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं, और आखिरकार उन्हें एक ऐसा शिकायतकर्ता मिला जो एक दोषी ट्यूटर को न्यायालय में ले जाने के लिए तैयार हो गया था। हालांकि इस मामले में दो वर्ष का समय लगा, और अंत में लोक अभियोजक निदेशक ने यह निर्णय दिया कि मामला नहीं बनता था।

निष्क्रियता का एक अन्य उदाहरण ओबीगाडू के अपने सहयोगी थे। ट्यूशन व्यवस्था को कम करने के लिए एक प्रणाली बनाने के लिए अथक प्रयास करने के बाद वह यह नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर प्रगति इतनी धीमी क्यों थी। अंत में उन्होंने महसूस किया

कि शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय में उनके खुद के सलाहकार स्वयं ट्यूशन दे रहे थे और इस प्रकार प्रणाली से फायदा उठा रहे थे। ये सलाहकार शिक्षक, प्रधानाचार्य और मंत्रालय के अधिकारियों के रूप में प्रणाली से जुड़े थे, और इस वजह से उनकी साख ऐसी थी कि उनकी ट्यूटर के रूप में अच्छी आमदनी हो जाती थी।

आईआईईपी पॉलिसी फोरम के दौरान ओबीगाडू द्वारा एक बिलकुल अलग मामले का उल्लेख किया गया जिसमें एक अध्यापक ट्यूशन इसलिए पढ़ाने का इच्छुक नहीं था क्योंकि उसका मानना था कि वह अपने खाली समय में इससे बेहतर काम कर सकता था। इससे माता-पिता नाराज हो गए क्योंकि वे समझते थे कि उनके बच्चों को ट्यूशन की जरूरत है और शिक्षक ऐसा न करके गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहा था। परिणामस्वरूप, इस शिक्षक का दूसरे स्कूल में स्थानांतरण करना पड़ा था। ओबीगाडू के अनुसार ऐसी घटनाएं सामान्य थीं।

यद्यपि इसका कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं था, फिर भी ओबीगाडू ने यह दावा किया कि इन उपायों से प्राथमिक स्कूलों में ट्यूशन की मांग में कमी आई थी। हालांकि इसकी मांग स्पष्ट रूप से अधिक थी। शिक्षा प्रणाली की समीक्षा में यह रिपोर्ट किया गया (बाह-लालया, 2006 पृष्ठ 75) कि:

साक्षात्कार लिए गए प्रतिवादियों से पता चला कि बच्चे और माता-पिता का मानना था कि यदि उनके बच्चे प्राइवेट ट्यूशन नहीं लेंगे तो वे पाठ्यक्रम में पिछड़ जाएंगे। स्पष्ट था कि अधिक सफल शिक्षक वे थे जिन्होंने अपने ज्ञान को पुस्तकों के रूप में प्रकाशित किया और बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन के भाग के रूप में उन्हें खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया। यह सूचित किया गया कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशनों से अपने वेतन से दुगुना कमा रहे थे और अपनी पुस्तकों पर रॉयल्टी भी ले रहे थे। इसका एक कारण यह था कि मंत्रालय और शिक्षकों के मुखिया का स्कूल के घंटों के बाद शिक्षकों पर आंतरिक, माता-पिता की बैठकों या अन्य संबंधित कार्यकलापों पर बहुत कम या बिलकुल नियंत्रण नहीं था। शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन के उनके समय को प्रभावित करने वाले किसी भी नए विचार या सुधारों का पुरजोर विरोध करते थे। बच्चे स्कूल के बाद की गतिविधियों में भाग नहीं लेना चाहते थे। संक्षेप में, अनुपूरक ट्यूशन व्यर्थ वित्तीय और मानव संसाधनों के जाल में फंस सकती थी जिनका दूसरी जगह बेहतर उपयोग किया जा सकता था।

इन स्पष्ट समस्याओं और स्टीवन ओबीगाडू के प्रयासों के बावजूद निहित स्वार्थी लोगों का दबदबा बना रहा। जैसा कि ओबीगाडू ने आईआईईपी पॉलिसी फोरम के दौरान सूचित किया था, इस युग के सुधार, जो विवादास्पद साबित हुए थे, को बाद में उलट दिया गया था, जिसके कारण प्राइवेट ट्यूशन को फिर से प्रोत्साहन मिला।

अब आगे क्या किया जाए?

सन् 2005 में स्टेवन ओबीगाडू का स्थान धरम गोखूल ने लिया यद्यपि वे दूसरी पार्टी से आए थे और उन्होंने अपने पिछले उत्तराधिकारी की नीतियों को चुनौती दी थी, गोखूल के

पास विकल्प के रूप में कोई रामबाण उपलब्ध नहीं था। ट्यूशन के स्थान के प्रश्न पर शिक्षकों को एक बार फिर स्कूल परिसर का इस्तेमाल करने की अनुमति प्रदान की गई लेकिन उन्हें इस सेवा (बाह-लाल्या, 2006, पृष्ठ 94) के लिए भुगतान करना था। गोखूल ने माना (2006, पृष्ठ 4-5) कि प्राइवेट ट्यूशन “शिक्षा की प्रक्रिया को दूषित करती है” और इससे “शिक्षा का पूरा उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है”। वे पुनः पाठ्यक्रम और विशेषकर सीपीई में सुधार करना चाहते थे, हालांकि कुछ जनप्रतिनिधियों (उदाहरण के लिए महादेव 2008) ने इतिहास का स्मरण करते हुए यह प्रश्न पूछा कि आखिर इस प्रक्रिया में इतना विलंब क्यों हो रहा था, और इस बात पर संदेह व्यक्त किया कि क्या लक्ष्य पूरे किए जा सकेंगे।

इस पुस्तक के विषय से संबंधित एक लेख मॉरीशस की प्रेस में प्रकाशित हुआ जिसमें आईआईईपी के पॉलिसी फोरम के प्रति जागरूकता और संबंधित चिंताओं के प्रति इनके सामंजस्य को दर्शाया गया था (ईटीएन्ने, 2007)। आईआईईपी कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए लेख में यह कहा गया कि “पैरिस में अनेक शिक्षा विशेषज्ञ इस बात पर चर्चा करने के लिए एकजुट हुए हैं कि लोग इस “आवश्यक बुराई (प्राइवेट ट्यूशन) के बारे में क्या सोचते हैं।” पॉलिसी फोरम के विषय पर “विशेषकर मॉरीशस के संदर्भ में “विचार किया गया था, जहां ट्यूशन एक महाविपत्ति का रूप ले चुकी थी जो शिक्षा और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही थी”। लेख में आगे यह भी कहा गया था कि:

मॉरीशस में प्राइवेट ट्यूशन की समस्या का मुख्य कारण यह था कि यह प्राइवेट के अलावा सब कुछ थी। वहां ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां बच्चे छोटे समूहों में यह प्रश्न पूछ सकें कि उन्होंने कक्षा में क्या सीखा था, जबकि यह एक ऐसा स्थान बन चुका था जहां वे अन्य चालीस बच्चों के साथ शिक्षक की गैराज में बैठकर रट्टा लगाया करते थे। प्राइवेट ट्यूशन प्रायः उन बच्चों के लिए होनी चाहिए थी जिन्हें किसी विशिष्ट विषय में कठिनाई थी और वे उसे शिक्षक से फिर से समझना चाहते थे, जिसके पास समय और धैर्य था और जो एक बार में केवल दो या तीन बच्चों को ही पढ़ाते थे। मॉरीशस में, अधिकांश ट्यूशन कक्षाएं इस मॉडल से कोसों दूर हैं . . .

प्राइवेट ट्यूशन के मौजूदा फोरम के स्वरूप को घटाने या इसे समाप्त करने के लिए प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन करना होगा। फिलहाल, यह एक ऐसा दुष्प्रक्र है जिसमें माता-पिता बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन के लिए न भेजने का जोखिम नहीं उठा सकते क्योंकि हर दूसरा माता-पिता अपने बच्चों को ट्यूशन के लिए भेजता था। यदि कोई बच्चा प्राइवेट ट्यूशन के लिए नहीं जाता था तो वह नुकसान में रहेगा। इसके अलावा, कुछ शिक्षक कक्षा में पूरे मन से नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि वे जानते हैं कि छात्र प्राइवेट ट्यूशन सत्रों में तो पढ़ ही लेंगे।

गोखूल के उत्तराधिकारी वसंत बनवारी (मॉरीशस, 2008) ने मंत्री के रूप में इन सुधारों का एक खाका तैयार किया। इस दस्तावेज (पृष्ठ 39) में उस “भयंकर होड़ का उल्लेख किया गया था जो शिक्षा क्षेत्र को परिभाषित करती है” और उन्होंने शिक्षा की प्रकृति और मूल्यांकन की पद्धति में आधारभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता पर बल दिया। रिपोर्ट में “प्राइवेट ट्यूशन की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए धीरे-धीरे

अभियान चलाने की बात कही गई, जिसे एक निश्चित अवधि के प्राथमिक उप-क्षेत्र के तीसरे चक्र (अर्थात् कक्षा V और VI) में लागू करने की अनुमति दी जाएगी। शिक्षा के प्राथमिक क्षेत्रों की प्रणाली जेडईपी के जरिए कुछ उपलब्धियां हासिल हुई थीं, जिनका उद्देश्य सामाजिक असमानता से निपटना था। रिपोर्ट में यह बात स्वीकार की गई कि परीक्षा उत्तीर्ण दर के अनुसार छात्रों की प्रगति धीमी रही थी, लेकिन सामूहिक शिक्षा दृष्टिकोण, स्कूल समुदाय भागीदारी और माता-पिता की सक्रिय भागीदारी काफी अच्छी थी। इन हस्तक्षेपों का उद्देश्य स्कूलों को “शिक्षा के खरे संस्थान” बनाने के लिए ट्यूशन पर से निर्भरता को कम करना, शिक्षकों का पेशेवर विकास करना और पाठ्यक्रम में सुधार करना था (पृष्ठ 85)।

इस दस्तावेज को बनाने के बाद मंत्री बनवारी ने सन् 2009 में यह घोषणा की कि अगले वर्ष से कक्षा IV तक के छात्रों के लिए प्राइवेट ट्यूशन पर प्रतिबंध रहेगा (मीतरभान, 2009)। इस प्रकार इस नीति में 18 वर्ष पूर्व मंत्री परसुरामेन द्वारा किए गए प्रयासों को ही बल दिया गया था। लेकिन शिक्षक संघों ने तत्काल इसका पुरजोर विरोध किया (हिलबर्ट 2009), और आम जनता की प्रतिक्रिया यह रही कि इस नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करना पिछले वर्षों की तरह अमल में लाना आसान काम नहीं होगा। मॉरीशस में प्राइवेट ट्यूशन के लक्ष्यों और कारणों दोनों से निपटने का काफी लम्बा इतिहास रहा है, लेकिन प्रत्येक दशक में नीति निर्माताओं ने यह पाया कि यह संस्कृति में इस कदर घुल-मिल चुकी है कि इसमें परिवर्तन करना आसान नहीं होगा।

बॉक्स 4. आखिर मॉरीशस में प्राइवेट ट्यूशन इतना सशक्त क्यों है?

इतिहास गवाह है कि मॉरीशस की शिक्षा प्रणाली हमेशा से बहुत चुनिंदा और प्रतिस्पर्धी रही है; (i) माध्यमिक स्तर पर उत्कृष्ट स्कूलों में प्रवेश पाना (जो अनंत काल से चलता आ रहा एक मिथक बन गया है) और (ii) विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए राज्य पोषित छात्रवृत्ति प्राप्त करना। समकालीन समय में, ट्यूशन की मांग आज भी इस बात से तय होती है कि शिक्षा चयन की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाती है, जो भारी-भरकम पाठ्यक्रम और उच्च स्तरीय परीक्षाओं पर निर्भर करती है, जिनसे ‘बेहतर’ विश्वविद्यालयों में शिक्षा के उच्च स्तर में प्रवेश तय होता है। इसलिए ट्यूशन कड़ी प्रतिस्पर्धा प्राप्त करने का एक माध्यम है। ट्यूशन की मांग इतनी सशक्त है कि मध्यम-वर्ग के क्षेत्रों में जो शिक्षक ट्यूशन उपलब्ध कराने के इच्छुक नहीं होते, उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

आपूर्ति पक्ष को देखा जाए तो बहुत कम वेतन होने के कारण ट्यूशन की प्रवृत्ति को काफी प्रोत्साहन मिलता है। सन् 2002 में प्राथमिक शिक्षकों को मिलने वाला वेतन प्रति व्यक्ति जीडीपी का 0.8 प्रतिशत के बराबर था। जबकि ओईसीडी देशों में यह औसत 1.7 प्रतिशत था, और मॉरीशस जैसे देशों में यह प्रति व्यक्ति जीडीपी का 20 प्रतिशत था। ट्यूशन के जरिए प्राथमिक शिक्षक अपनी आय को दो गुणा या तीन गुणा कर सकते थे।

स्रोत: ओबीगाडू (2007), पृष्ठ 2

फ्रांस

कोरिया और मॉरीशस के विपरीत, फ्रांस में प्राइवेट ट्यूशन उद्योग केवल सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर ही नहीं चल रहा है बल्कि इसे सरकार का प्रोत्साहन भी प्राप्त है, जिसमें अनुपूरक प्राइवेट ट्यूशन में निवेश करने के लिए परिवारों को कर-निर्धारण में मिलने वाली छूट भी शामिल है। इन प्रोत्साहनों के माध्यम से सरकार स्वयं वित्तीय भार उठाकर शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाना चाहती है।

फ्रांस में प्राइवेट ट्यूशन पर सबसे पहला बड़ा अध्ययन ग्लासमैन और कोलॉज (1944) ने किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था कि देश में प्राइवेट ट्यूशन का इतिहास सम्भवतया पिछली शताब्दी में शुरू हुआ था। किंतु, उनका कथन था, कि शिक्षा प्रणाली का अधिक विस्तार होने और इसमें अनेक विषय शामिल हो जाने से प्राइवेट ट्यूशन की विशेषताओं में काफी परिवर्तन आया है। ग्लासमैन और कोलॉज ने प्राइवेट ट्यूशन की प्रकृति और भूमिका का सामाजिक प्रतिस्पर्द्धा और सामाजिक स्तरों के संदर्भ में विश्लेषण किया है। उनकी पुस्तक रोहने-एल्स क्षेत्र के 12 लिसियों (उच्चतर माध्यमिक स्कूल) के 9,400 छात्रों से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित है। यहां औसतन 15 प्रतिशत छात्र प्राइवेट शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, लगभग 10 प्रतिशत छात्र भविष्य में ट्यूशन लेना चाहते थे, और 36 प्रतिशत छात्रों ने अपनी माध्यमिक कक्षाओं के दौरान कभी-न-कभी प्राइवेट ट्यूशन ली थी (ग्लासमैन और कोलॉज, 1944, पृ. 30)। गणित सबसे अधिक लोकप्रिय विषय (57 प्रतिशत) था, जिसके बाद भौतिक शास्त्र और रासायनिक शास्त्र (20 प्रतिशत), अंग्रेजी (9 प्रतिशत), फ्रेंच (5 प्रतिशत) आते थे। छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहरों के बच्चे अधिक संख्या में प्राइवेट ट्यूशन लेते थे और यह सार्वजनिक स्कूलों की तुलना में निजी स्कूलों के छात्रों में अधिक लोकप्रिय थी।

इस अध्ययन के बाद से प्राइवेट ट्यूशन का चलन काफी बढ़ा और इसमें अधिक विस्तार हुआ। एक दशक बाद, ग्लासमैन (2004) ने नेशनल एजुकेशन मंत्रालय और हायर एजुकेशन एंड रिसर्च मंत्रालय के *हॉत कोसिल ए' ला' इवेल्यूएशन डे ला' इकोल* (हाई काउंसिल फॉर स्कूल इवैल्यूएशन) (एचसीईसी) के तत्वावधान में इसी विषय पर एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में (पृष्ठ 51) यह बताया गया था कि परिवारों को घरेलू कार्यों, बच्चों की देखभाल और प्राइवेट ट्यूशन पर आने वाली लागत पर आयकर में छूट का दावा करने की अनुमति देने के सरकारी निर्णय के प्रभाव पर प्रकाश डाला गया था। यह निर्णय शिक्षा मंत्री का न होकर सोशल कोहिज़न मंत्री का था, जो अकेले अभिभावकों और अन्य लोगों की सहायता करना चाहते थे और कुछ विशेष प्रकार की नौकरियों को भी बढ़ावा देना चाहते थे। इस उपाय ने कुछ ऐसे परिवारों को प्रोत्साहित किया जो अधिक खर्च होने के कारण प्राइवेट ट्यूशन पर खर्च करने से हिचकिचाते थे और जिन्हें कुछ वित्तीय सहायता की आवश्यकता थी, और इसलिए यह ऐसे परिवारों के लिए उपयोगी था जो थोड़ा बहुत त्याग करने के लिए तैयार थे। इस कानून का अनेक उद्यमों ने लाभ उठाया। इसमें अकेडेमिया नामक कंपनी सबसे आगे थी

जो स्टॉक एक्सचेंज में भी सूचीबद्ध थी; इसने अपनी सेवाओं का जोर-शोर से प्रचार किया और कर-निर्धारण में मिलने वाली छूट की ओर भी ध्यान दिलाया।

अगले वर्ष एचसीईसी ने ग्लासमैन की रिपोर्ट पर एक टिप्पणी जारी की (फोरेस्टियर, 2005) और इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली सामाजिक असमानताओं पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए इस पर नज़र रखने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके फलस्वरूप, सरकार ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के क्षेत्र में मिलने वाले असमान अवसरों और प्राइवेट ट्यूशन के प्रभाव पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जिसके समर्थन में एक वृत्तचित्र भी ऑनलाइन प्रसारित किया गया, जिनके आधार पर मार्गदर्शक नीतियां बनाई गईं।

उसी वर्ष, *इंस्टीट्यूट नेशनल डी रिसर्चे पेडागोगीक* (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेडागोगिकल रिसर्च) (आईएनआरपी) की ओर से कैवेट (2006) ने इन ऑनलाइन प्रलेख का व्यापक विश्लेषण किया। इस प्रलेख में विशेष रूप से 2003 के बाद हुए सरकारी सर्वेक्षणों के आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे जिनसे पता चलता था कि छात्र प्रमुख रूप से माध्यमिक कक्षाओं में प्राइवेट ट्यूशन प्राप्त करते थे जिनकी संख्या उच्चतर कक्षाओं में अधिक बढ़ जाती थी। जूनियर हाई स्कूल के छात्र किसी विशेष विषय (विशेष रूप से गणित) को अच्छी तरह समझने के लिए प्राइवेट ट्यूशन का सहारा लेते थे किंतु 25 प्रतिशत छात्र, जो पहले ही अच्छे अंक प्राप्त कर रहे थे, प्राइवेट ट्यूशन को श्रेष्ठता हासिल करने का माध्यम मानते थे (कैवेट, 2006, पृ. 2)। अधिकतर अध्यापक प्राइवेट ट्यूशन के खिलाफ थे। इसके विपरीत अधिकतर माता-पिता या कुछ मामलों में स्वयं छात्र (जूनियर हाई स्कूल के 23 प्रतिशत, सीनियर हाई स्कूल के 40 प्रतिशत) प्राइवेट ट्यूशन पर बल देते थे। प्राइवेट ट्यूशन में र्वर्च करने वाले अधिकांश अभिभावक अपेक्षाकृत धनी वर्ग से संबद्ध थे और समय कम होने के कारण अथवा पाठ्यक्रम को समझ पाने में अक्षम होने के कारण प्राइवेट ट्यूशन का सहारा लेते थे। सामान्य अध्यापक कभी-कभार ही प्राइवेट ट्यूशन देते थे। अक्सर उनके बदले कोई दूसरा छात्र (34 प्रतिशत), कोई अन्य अध्यापक (31 प्रतिशत) या कोई निजी संस्थान (21 प्रतिशत) निजी कक्षाएं लेते थे। कैवेट (पृ. 4) ने ग्लासमैन के साथ लिए एक साक्षात्कार का उल्लेख किया जिसमें उन्होंने कहा था कि कभी-कभी माता-पिता अपने बच्चों द्वारा दिए जाने वाले तनाव से बचने के लिए स्वयं निजी शिक्षक नियुक्त करते थे। उनका कहना था कि बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी बाहर वालों को सौंप देने से परिवारों में अधिक सामंजस्य बना रहता है।

इसके बाद, 2007 में बाजारी विश्लेषण में विशेषज्ञताप्राप्त एक कंपनी ने इस बारे में लिखित प्रमाण प्रस्तुत किए। रिपोर्ट में (मेलोट, 2007, पृ. 104) में प्राइवेट ट्यूशन के क्षेत्र में होने वाली वृद्धि को “विस्फोटक” बताया गया था “जिसमें स्कूली शिक्षा की प्रणाली की कमी के कारण अभिभावकों में मौजूद भय के कारण तेजी आई... इसके अतिरिक्त, आर्थिक वातावरण अत्यधिक अनुकूल होने के कारण, प्राइवेट ट्यूशन में वर्ष 2006 में लगातार छठे वर्ष 15 प्रतिशत से अधिक वृद्धि देखने को मिली।” बाजार के कुल आकार

के बारे में मेलोत के अनुमानों के अनुसार, निम्न माध्यमिक कक्षाओं के 25 प्रतिशत और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के 33 प्रतिशत छात्र, विशेष रूप से गणित में प्राइवेट ट्यूशन प्राप्त कर रहे थे किंतु इसमें क्षेत्रों के अनुसार काफी अंतर मौजूद था। मेलोत का कहना था, कि प्राइवेट ट्यूशन प्राप्त करने वाले छात्रों का अनुपात पेरिस में विशेष रूप से काफी अधिक था, उसने अकेडेमिया के अनुमानों का उल्लेख (पृ. 105) किया कि पेरिस के बड़े लिसियों में 75 प्रतिशत छात्र प्राइवेट ट्यूशन लेते थे। वर्ष 2008 में, देश में अनुमानतः दस लाख से अधिक छात्र प्राइवेट ट्यूशन प्राप्त कर रहे थे।

बाजार में प्रमुख रूप से प्राइवेट ट्यूशन उपलब्ध कराने वाले दो प्रकार के माध्यम मौजूद थे:

- **प्राइवेट अध्यापक जो व्यक्तिगत आधार पर पढ़ाते थे।** अभिभावक और अध्यापक किसी की सिफारिश से या विज्ञापन के माध्यम से और अधिकतर इंटरनेट के माध्यम से एक-दूसरे से सम्पर्क करते थे। सीधे सम्पर्क करने का तरीका सबसे अधिक प्रचलित था। हालांकि लेन-देन को अधिकतर गुप्त रखा जाता था, किंतु कर-निर्धारण में मिलने वाले लाभ ने अध्यापकों को अपने काम को वैध बनाने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि अपने प्रस्तावों से वे अधिक-से-अधिक परिवारों को आकर्षित कर सकें। कुछ अध्यापक अनुभवी थे (या तो वे अभी भी सक्रिय रूप से पढ़ा रहे थे, या सेवानिवृत्त हो चुके थे), किंतु अन्य सभी छात्र या युवा स्नातक थे, जो किसी अच्छी नौकरी की तलाश में थे।
- **स्कूल-के-बाद प्राइवेट ट्यूशन देने वाली कंपनियाँ:** यह कंपनियाँ भिन्न-भिन्न तरीकों से अपना कारोबार चला रही थीं:
 - कंपनी द्वारा शिक्षक को द्वारा छात्र के घर भेजकर पढ़ाने, या छात्रों के एक छोटे समूह को कंपनी के परिसर में पढ़ाने का तरीका सबसे अधिक लोकप्रिय था और इसमें काफी वृद्धि हुई।
 - छुट्टियों के दौरान छोटे समूहों में पढ़ाए जाने वाले *गहन पाठ्यक्रमों* का भी धीरे-धीरे विकास हो रहा था।
 - बच्चों की देखभाल और आराम के साथ पढ़ाई कराने वाले *संयुक्त कार्यक्रम* भी आरंभ होने लगे थे।
 - *ऑनलाइन ट्यूशन* का अभी अधिक विकास नहीं हुआ था किंतु धीरे-धीरे इसमें विस्तार हो रहा था।
 - स्कूली शिक्षा भी उभरने लगी थी, जिसमें अधिक व्यापक क्षेत्रों, जैसे आत्म-विश्वास, प्रेरणा और व्यवस्थापन पर अधिक ध्यान दिया जाता था, किंतु अभी इसका प्रयोग केवल सम्पन्न वर्ग ही करता था।

इन कंपनियों के संचालन के तरीके में अंतर था। कुछ कंपनियाँ अपने परिसरों में समूहों में प्राइवेट ट्यूशन प्रदान करती थीं, जबकि अन्य कंपनियाँ छात्रों को उनके घर में ही पढ़ाने के लिए निजी शिक्षक नियुक्त करती थीं। कुछ कंपनियों को किसी विशेष विषय तथा/अथवा विशेष स्तर की शिक्षा प्रदान करने में विशेषज्ञता प्राप्त थी, जबकि

अन्य अधिक सामान्य प्रकार की शिक्षा प्रदान करती थीं। कंपनियों का एक समूह प्राइवेट ट्यूशन के साथ-साथ अनेक प्रकार की अन्य सेवाएं भी प्रदान करता था, जिनमें बच्चों की देखभाल और अन्य घरेलू सुविधाएं शामिल थीं। सारणी 12 में कुछ प्रमुख ट्यूशन कंपनियों के आंकड़े दिए गए हैं। इनमें से कुछ कंपनियों ने फ्रांस के किसी विशेष भाग को अपना केंद्र बनाया, जबकि अन्य कंपनियां पहले ही सभी प्रमुख शहरों में अपना कारोबार चला रही थीं या वहां अपना कारोबार चलाना चाहती थीं। इनमें से कम-से-कम दो कंपनियां बहुराष्ट्रीय उद्योग के रूप में कारोबार कर रही थीं: 2एमैथ की कनाडा और मोरक्को में भी शाखाएं थीं और कीपस्कूल की शाखाएं जर्मनी और ब्रिटेन तक फैली हुई थीं। इस संदर्भ में, वह सिल्वन की बराबरी पर थीं जिसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमरीका में था और अब वह फ्रांसीसी बाजार में अपनी पैठ बनाना चाहती थी।

सारणी 12. फ्रांस के प्रमुख प्राइवेट ट्यूशन उद्योग

उद्योग का नाम	छात्रों की संख्या	फ्रांस में कार्यालयों की संख्या	कारोबार का घोषित आकार (€ मिलियन)
अकेडोमिया	100,000	97	87
कोर्स लीजेंडरे	30,000	9	16
कम्प्लीच्यूड	23,000	34	23
सिल्वन	अनुपलब्ध	18	8
एनाकोर्स	16,000	50	5
2एमैथ	10,000	72	12
कीपस्कूल	8,000	80	5
डोमीकोर्स	6,500	20	5

स्रोत: मेलोत (2007)

इन निजी संचालकों ने अपनी सेवाएं प्रदान करने के तरीकों को भी उन्नत बनाया है। ग्लासमैन (कैवेट, 2006, पृ. 11 में उल्लिखित) ने विभिन्न दौरों में कंपनियों के नामों में हुए परिवर्तनों का उल्लेख किया है:

- 1960 और 1970 के दशक के दौरान, प्राइवेट ट्यूशन कंपनियां सामान्य रूप से स्वयं को सुधारक (रेमेडिएशन) कहती थीं। कंपनियों के नाम मैथ-असिस्टैंस, मैथ-सिकोर्स और ऑर्थो-मैथ, इत्यादि होते थे।
- 1980वें दशक के मध्य में, इस क्षेत्र ने स्वयं को प्रतिस्पर्द्धा के साथ जोड़ लिया। कंपनियों के नाम इट्यूडीज़ प्लस, परफॉर्मेंस, स्टड अवेनिर और प्रोग्रेस सिस्टम, इत्यादि होने लगे।
- आज की आधुनिक पीढ़ी सामान्य और सीधे-सादे नामों को पसंद करती है। अब डोमीकोर्स, कीपस्कूल, कम्प्लीच्यूड और एप्रिस ला क्लासे जैसे सामान्य नाम रखे जाने लगे हैं।

निजी कंपनियों ने शांति और तनावमुक्ति की जो तस्वीर प्रस्तुत की, वह शायद स्कूली शिक्षा और रोजगार के बाजार से संबंधित चिंताओं को दूर करने में उपयोगी सिद्ध हुई। फ्रांस

की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां कोरिया, मॉरीशस और अन्य स्थानों से काफी भिन्न हैं। फ्रांस में भी सामाजिक-आर्थिक वर्गों और क्षेत्रों (विशेष रूप से बड़े शहरों, छोटे नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में) में काफी अंतर मौजूद है। इस आधार पर, प्राइवेट ट्यूशन को एक विशेष संदर्भ में देखना होगा। इसके अतिरिक्त, प्राइवेट ट्यूशन प्रदान करने वाले उन सभी परिस्थितियों का लाभ उठाते हैं, जिनसे स्कूल में शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा और तनाव बढ़ता हो, जैसे निजीकरण, स्कूलों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा, और स्कूली शिक्षा प्रणाली का पतन।

तथापि, इस क्षेत्र की कई बार आलोचना हुई और प्राइवेट ट्यूशन की गुणवत्ता पर प्रश्न उठाए गए। उदाहरण के लिए, फ्रांसीसी टेलीविज़न द्वारा 2009 में प्रसारित एक डॉक्यूमेंटरी में (बेंडल एवं तूरते, 2009), अनेक निजी शिक्षकों के अनाड़ीपन की ओर ध्यान आकर्षित किया गया और उन्हें नियुक्त करने वाली कंपनियों के विपणन दावों की जांच की गई। मेलोत की एक टिप्पणी (2007, पृ. 99) के अनुसार, यह क्षेत्र अधिकतर “अंडरग्राउंड” गुप्त रूप में काम करता है और प्राइवेट ट्यूशन का बाजार, कुल मिलाकर बिखरा हुआ, अस्थिर और अपारदर्शी है” (पृ. 119)।

बॉक्स 5. फ्रांस में प्राइवेट ट्यूशन का वित्तीय गणित

फ्रांसीसी सरकार ने प्राइवेट ट्यूशन कंपनियों को भुगतान किए जाने वाले मूल्य के 50 प्रतिशत को आयकर देयता से मुक्त रखा है। अकेडोमिया ऐसी ही कंपनियों में से एक है जो इस प्रावधान का लाभ उठा रही है। कंपनी एक ब्रोकर की तरह काम करती है और ट्यूटर्स को अभिभावकों से मिलाती है जो ट्यूटर की फीस का भुगतान करते हैं और कर में छूट का लाभ उठाते हैं। अपने बच्चे के पंजीकरण के लिए अभिभावकों को आरंभिक पंजीकरण शुल्क के रूप में €75 का भुगतान करना पड़ता है जिस पर कर नहीं लगता। उसके बाद, प्राइवेट ट्यूशन के प्रत्येक एक घंटे के लिए वे औसतन €32 का भुगतान करते हैं जिसमें से €14 (कभी-कभी कम भी) अध्यापक को मिलता है, €5 कर्मचारी प्रभार के रूप में और €13 अकेडोमिया को जाता है। इस €32 में से अभिभावकों को केवल €16 पर कर का भुगतान करना पड़ता है। इस प्रकार, अंत में एक घंटे की प्राइवेट ट्यूशन का कुल मूल्य केवल €16 पड़ता है। अध्यापक कुल $14 + 13 = €27$ की आय घोषित करता है, किंतु कर-निर्धारण के समय इसमें से अकेडोमिया को भुगतान किए जाने वाले €13 को खर्च के रूप में काट सकता है।

स्रोत: कैवेट, 2006, पृ. 12

फ्रांसीसी और कोरियाई तथा मॉरीशस की नीतियों में सबसे महत्वपूर्ण अंतर कर-प्रणाली का है जो परिवारों को प्राइवेट ट्यूशन में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। फ्रांसीसी सरकार इस आलोचना पर, कि इस नीति के कारण सामाज में असमानताएं पनपती हैं, द्विपक्षीय प्रतिक्रिया दर्शाती है। उसका पहला उत्तर यह है कि राष्ट्र द्वारा संचालित गृह कार्य में सहयोग देने की प्रणाली, जो निःशुल्क है, उसे विस्तृत बनाया जा सकता है। राष्ट्र द्वारा संचालित यह प्रणाली 1980 आदि के दशक में शुरू हुई, जो चार मंत्रालयों (शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा) के तत्वावधान में काम कर रही है तथा 2,000 संस्थाओं

तथा सार्वजनिक या अर्ध-सार्वजनिक संस्थानों के नेटवर्क पर निर्भर है (कैवेट, 2006, पृ. 4)। दूसरे, सरकार ने इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर स्कूलों के नेटवर्क में प्राइवेट ट्यूशन के विकास की नीतियों की घोषणा की कि ऐसा करने से सभी सामाजिक-आर्थिक वर्गों के छात्रों के लिए सहायता उपलब्ध रहेगी। प्रारंभ में, इस प्रस्ताव को कुछ स्कूलों में अनिवार्य रूप में तथा शेष स्कूलों में ऐच्छिक आधार पर लागू किया गया। इसके बाद, सरकार ने घोषित किया कि इस योजना को सभी स्कूलों को लागू करना होगा जिसमें सप्ताह में चार दिन सायं 4 बजे से लेकर 6 बजे तक गृह कार्य में सहयोग, सांस्कृतिक गतिविधियां एवं खेलकूद, इत्यादि कार्य करने होंगे। सरकार ने यह नीति लागू करने के लिए 1400 लाख यूरो की राशि आबंटित की (वेंचूरा, 2008बी, पृ.9)।

3. नीति प्रक्रिया

पिछले भाग का शीर्षक निदान था, जिसमें प्राइवेट द्यूशन प्रणाली की विशेषताओं और प्रभाव का पता लगाने का प्रयास किया गया था, जिन पर नीति निर्माताओं को कदम उठाने की आवश्यकता है। कुछ नीति प्रक्रियाओं को कोरिया, मॉरीशस और फ्रांस पर प्रस्तुत केस स्टडीज़ में शामिल किया गया है। पुस्तक के इस भाग में उस प्रकार की प्रतिक्रियाओं का विस्तार से उल्लेख किया गया है जिन पर नीति-निर्माता विचार कर सकते हैं। इसमें सफल नीतियों के अतिरिक्त, उन नीतियों का भी उल्लेख किया गया है जो विभिन्न कारणों से असफल रही हैं।

इस प्रस्तुतीकरण का आरंभ प्रतिचित्रण (मैपिंग) के सिद्धांत से कर रहे हैं क्योंकि प्रत्येक स्थान अलग होता है और नीतियां उन विशेष स्थान की परिस्थितियों के अनुसार ही तैयार की जानी चाहिए। इसके बाद इसमें प्राइवेट द्यूशन की मांग और प्राइवेट द्यूशन की सप्लाई का उल्लेख किया गया है। आगे उन तरीकों तथा सम्भावित विनियमन ढांचे का उल्लेख किया गया है जिनके द्वारा नीति-निर्माता व्यापक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बाजारी ताकतों पर लगाम लगा सकते हैं।

प्रतिचित्रण (मैपिंग) – संदर्भ, उद्देश्य और संरचना

नीति निर्माताओं को प्रतिचित्रण या मैपिंग की शुरुआत दो बुनियादी प्रश्नों के साथ करनी होगी:

- प्रतिच्छाया शिक्षा प्रणाली किस सीमा तक समस्या उत्पन्न कर सकती है (या स्वयं समस्या बन सकती है), जो शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को क्षति पहुंचाती है और जिसे नियंत्रित करना ज़रूरी है।
- प्रतिच्छाया शिक्षा प्रणाली किस सीमा तक संभावित सम्पत्ति हो सकती है, जिसका अब तक सम्पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं किया गया है और जिसे प्रोत्साहित किया जा सकता है।

पुस्तक के पिछले भाग में दर्शाया गया है कि अनेक देशों में प्राइवेट द्यूशन को संशय की दृष्टि के साथ देखा जा सकता है। यह सरकार या करदाता पर कोई भार डाले बिना शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है और उन परिवारों के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है जो इसे खरीद सकते हैं और यह महसूस करते हैं कि उन्हें वह सब कुछ नहीं मिल रहा है जो उन्हें मुख्य धारा की शिक्षा से मिलना चाहिए। तथापि, प्राइवेट द्यूशन पूरी तरह बाजारी ताकतों द्वारा संचालित है जो सामाजिक असमानताओं को बढ़ा सकती है और मुख्य धारा की शिक्षा पर अवांछित प्रभाव डाल सकती है। इसके अतिरिक्त, ऐसी सेवाओं के साथ-साथ चलने से संशय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसे एक ओर तो सरकार द्वारा मुफ्त प्रदान किया जाता है और दूसरी ओर निजी क्षेत्र उसी सेवा के लिए उन्हीं ग्राहकों से शुल्क की वसूली करता है।

नीति निर्माताओं को छात्रों के आर्थिक-सामाजिक प्रोफाइल, सांस्कृतिक संदर्भ और अन्य बातों का भी ध्यान रखना होगा। ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमरीका की प्राइवेट ट्यूशन पद्धति, जहाँ सरकार कम अंक पाने वाले छात्रों के लिए प्राइवेट ट्यूशन को प्रोत्साहन देती है, कोरिया और जापान में प्रचलित पद्धति से बहुत भिन्न हैं, जहाँ अधिकतर अंक पाने वाले छात्र ट्यूशन लेते हैं। इसी प्रकार, सिंगापुर में अध्यापकों को मुख्य धारा के उन छात्रों को ट्यूशन देने पर पाबंदी है जिन्हें वह स्कूल में पढ़ाते हैं, इसके विपरीत मॉरीशस में ऐसा करना सामान्य बात है। नीति निर्माताओं को सम्भवतया इस पर विचार करना होगा कि माध्यमिक स्कूलों के छात्रों, विश्वविद्यालयों के छात्रों, सेवानिवृत्त और अन्य लोगों को किस सीमा तक प्राइवेट ट्यूशन देने के लिए प्रोत्साहित या हतोत्साहित करना चाहिए। इसके बाद, प्राइवेट ट्यूशन प्रदान करने के तरीके में भी अंतर होता है। एक अकेले छात्र को पढ़ाना, स्पष्ट रूप से छात्रों को बड़े समूहों में इकट्ठे या बड़े लेक्चर कक्षों में पढ़ाने से भिन्न होता है। और सीधे आग्ने-सामने बैठकर पढ़ाना, स्पष्ट रूप से इंटरनेट पर पढ़ाने से भिन्न होता है।

नीति निर्माताओं को अपने क्षेत्र में इस समय मौजूद प्राइवेट ट्यूशन प्रणाली का वर्गीकरण करना होगा और प्राइवेट ट्यूशन के उस प्रकार का पता लगाना होगा जिसे प्रोत्साहित करने या रोकने की ज़रूरत है। इसके लिए सारणी 13 में दिए गए चार्ट की सहायता ली जा सकती है। इसमें न केवल प्राइवेट ट्यूशन के प्रकार और तरीकों का उल्लेख किया गया है किंतु आम तौर पर इस समय प्रचलित और भविष्य में वांछित प्राइवेट ट्यूशन की सीमा भी दर्शाई गई है। इस सीमा को निम्नलिखित श्रेणियों के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है:

- **आय वर्ग:** क्या प्राइवेट ट्यूशन का कोई ऐसा प्रकार भी है जो प्रमुख रूप से एक विशेष आय वर्ग के लिए ही उपलब्ध होती है, और क्या नीति-निर्माता इसकी पहुंच को अधिक विस्तृत बनाना चाहते हैं?
- **लिंग:** क्या लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम महत्त्व दिया जाता है (या इससे विपरीत), और क्या अधिक समानता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है?
- **प्रजातीयता:** क्या अन्यो की तुलना में किसी विशेष प्रजाति वर्ग (या प्रजाति) में सामान्य रूप से अधिक प्राइवेट ट्यूशन लेने का चलन है और क्या इसे समस्या समझा जाता है?
- **स्थान:** क्या इससे किसी विशेष क्षेत्र तथा ग्रामीण/शहरी क्षेत्र को अधिक फायदा या नुकसान हो रहा है, और क्या भौगोलिक संतुलन को बढ़ावा देना चाहिए।

सारणी को अधिक उपयोगी बनाने के लिए इसमें निम्नलिखित घटकों को जोड़ा जा सकता है:

- **अधिकता:** किन कक्षाओं में, किन मौसमों में तथा किन विषयों में सबसे अधिक ट्यूशन ली जाती हैं?
- **गुणवत्ता:** प्राइवेट ट्यूशन की गुणवत्ता क्या है और न केवल परीक्षाओं की दृष्टि से बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी इससे शिक्षा में कितनी सहायता मिलती है?

- **लागत:** विभिन्न प्रकार के प्राइवेट ट्यूशन का इकाई मूल्य क्या है, और यह लागत परिवारों के लिए किस सीमा तक बोझ हो सकती है?
- **आर्थिक प्रभाव:** उन लोगों के लिए प्राइवेट ट्यूशन किस सीमा तक उपयोगी हो सकती है, जिन्हें रोजगार या पूरक आय की आवश्यकता है? क्या सरकार प्राइवेट ट्यूशन को अधिक सीमा तक कर प्रणाली के दायरे में लाना चाहती है? विभिन्न प्रकार की प्राइवेट ट्यूशन के अन्य आर्थिक प्रभाव क्या हैं?

सारणी 13. प्राइवेट ट्यूशन के वर्गीकरण का तरीका

प्राइवेट ट्यूशन प्रदान करने वाले	माध्यम	अभी यह किस सीमा तक प्रचलित है (सम्भवतया आय वर्ग, लिंग, प्रजाति और स्थान के आधार पर)	भविष्य में यह किस सीमा तक वांछनीय होगी (सम्भवतया आय वर्ग, लिंग, प्रजाति और स्थान के आधार पर ही)
अपने ही छात्रों को	प्रत्येक के लिए अलग		
प्राइवेट ट्यूशन प्रदान करने वाले शिक्षक	छोटे समूहों में बड़े समूहों में		
दूसरे शिक्षकों के छात्रों को	प्रत्येक के लिए अलग		
प्राइवेट ट्यूशन प्रदान करने वाले शिक्षक	छोटे समूहों में बड़े समूहों में		
छात्र (माध्यमिक तथा / अथवा विश्वविद्यालयों के छात्र)	प्रत्येक के लिए अलग छोटे समूहों में बड़े समूहों में		
अन्य (जैसे व्यावसायिक, सेवानिवृत्त लोग, गृहणियाँ)	प्रत्येक के लिए अलग छोटे समूहों में बड़े समूहों में		
प्राइवेट ट्यूशन देने वाली कंपनियाँ (स्थानीय, राष्ट्रीय, फ्रैंचाइज़ी नेटवर्क)	प्रत्येक के लिए अलग छोटे समूहों में बड़े समूहों में लेक्चर थियेटर रटाने वाले		
इंटरनेट पर प्राइवेट ट्यूशन प्रदान करने वाले लोग	सॉफ्टवेयर की सहायता से प्रत्येक के लिए अलग		

प्राइवेट ट्यूशन से संबंधित आंकड़े बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हैं, अतः नीति - निर्माता अपनी निजी समझ के अनुसार तथा अपने देश में या अपने देश के समान अन्य देशों से संकलित आंकड़ों के आधार पर सुविज्ञ निर्णय लेने या अनुमान लगाने को मजबूर हो जाते हैं। आईआईपी के पॉलिसी फोरम और इस पुस्तक में मुख्य रूप से यह सिफारिश दी गई है कि सभी प्रकार के वातावरणों में आंकड़ों के संकलन पर अधिक ध्यान देना होगा।

बॉक्स 6. जापन में जुकु के प्रकारों में अंतर

कुछ समालोचकों ने, विशेष रूप से गैर-जापानी टीकाकारों ने, जुकु संस्था को सामान्य रूप में प्रस्तुत किया है और जुकु शब्द को 'क्रैम स्कूल' के रूप में भाषांतरित किया है तथा वे जुकु के विभिन्न प्रकारों का अंतर बताने में असफल रहे हैं। अधिक सतर्क विश्लेषकों ने जुकु के एक से अधिक प्रकारों का उल्लेख किया है, जिसमें प्रत्येक जुकु का, नीति-निर्माताओं के लिए, एक अलग अर्थ है।

रोसगार्ड (2006, पृ. 32) ने सबसे पहले अकादमिक गाकुशी जुकु और कला, तकनीकी प्रशिक्षण और अंग्रेजी में बातचीत से संबद्ध जुकु में पाए जाने वाले अंतरों का उल्लेख किया है। गाकुशी जुकु के प्रकारों में भी विशेषज्ञता के आधार पर अंतर पाया जाता है। होशू जुकु में सुधारात्मक शिक्षा दी जाती है जबकि फुकुशी जुकु में अनुपूरक शिक्षा और याशु जुकु में किसी परीक्षा की तैयारी के लिए शिक्षा दी जाती है। शिंगाकु जुकु अच्छे अंक प्राप्त करने वाले उन छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करता है जो पहले से अधिक बेहतर अंक पाना चाहते हैं, जबकि डोरीरु जुकु की तुलना में, जिसमें प्रशिक्षण और प्रतियोगिता पर आधारित अभ्यास पर भरोसा किया जाता है, क्योसाई जुकु में काफी लचीली नीति अपनाई जाती है। कुछ प्राइवेट ट्यूशन केंद्र देई नो बा या इदोकारो (मित्रों से मिलने का स्थान) और यहाँ तक कि ताकुजिजो (केयर सेंटर) के रूप में भी संचालित हैं।

इसके बाद रोसगार्ड ने आठ परिवर्तियों के आधार पर एक टाइपोलॉजी का निर्माण किया:

- वातावरण: क्या संस्थान प्रतिस्पर्धात्मक, प्रेरक, तनाव रहित और सहयोगी प्रकार का है।
- पाठ्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य: क्या पाठ्यक्रम नियमित स्कूली शिक्षा पद्धति के पाठ्यक्रम के अनुसार है या इसमें प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जाती है
- स्कूल से संबंध: क्या संस्थान या पाठ्यक्रम से स्कूल की नियमित शिक्षा में सहयोग मिलता है या यह अपने निजी लक्ष्यों को पूरा करता है।
- छात्र: छात्रों का प्रकार और विशेष रूप से उनकी शिक्षा का स्तर क्या है
- पाठ्य सामग्री: स्कूल, व्यावसायिक और घरेलू सामग्रियों का मिश्रण
- आकार: छात्रों की संख्या, और क्या जुकु शिक्षा संस्थानों की एक बड़ी ऋग्ग्वला की एक कड़ी है।
- प्रवेश: क्या छात्रों को प्रवेश परीक्षा में जाँच के बाद भर्ती किया जाता है या संस्थान में जगह खाली होने तक भर्ती प्रक्रिया को जारी रखा जाता है।
- विज्ञापन: क्या छात्रों की भर्ती मौखिक प्रचार के आधार पर की जाती है या व्यावसायिक विज्ञापन दिए जाते हैं, और प्रशिक्षण या विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में सफलता पर बल दिया जाता है।

जुकु के प्रकारों और परिवर्तियों के मेट्रिक्स से एक निर्देशक टाइपोलॉजी तैयार हुई:

	शिंगाकु जुकु	होशु जुकु	क्सोयाई जुकु	दोरीरो जुकु
वातावरण	प्रतिस्पर्धात्मक / प्रेरक	शांत / सहयोगात्मक	शैक्षणिक / सहयोगात्मक	शांत (अक्सर घर पर पढ़ाई)
पाठ्यक्रम का लक्ष्य	प्रवेश परीक्षा	पढ़ाई पूरी करना और स्कूल टेस्ट	बुनियादी शिक्षा	बुनियादी कुशलता
स्कूल से संबंध	कुछ नहीं	स्कूली कक्षाओं की गति के साथ कदम मिलाकर चलना, अक्सर घनिष्ठ संबंध	बहुत कम या कुछ नहीं	कुछ नहीं
छात्र	श्रेष्ठ अंक पाने वाले	औसत अंक पाने वाले	कम अंक पाने वाले	सभी स्तर के
अध्ययन सामग्री	अपनी पाठ्य पुस्तकें	घर पर बनी, व्यावसायिक या स्कूल की पाठ्य पुस्तकें	घर पर बनी, व्यावसायिक या स्कूल की पाठ्य पुस्तकें	अपनी पाठ्य पुस्तकें
संख्या	200 से कम छात्र, कुछ फ्रैंचाइज़	200 से अधिक छात्र	100 से अधिक छात्र	हज़ारों
प्रवेश	प्रवेश परीक्षा	केवल भौतिक सीमाएं	केवल भौतिक सीमाएं	कोई सीमा नहीं
विज्ञापन	व्यावसायिक, विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा पर बल	मौखिक प्रचार, अध्यापन	मौखिक प्रचार, अध्यापन	व्यावसायिक, कुछ मामलों में अध्यापन

ट्यूशन की मांग से निपटना

ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस, सिंगापुर और सं.रा.अमरीका की सरकारों ने अलग-अलग तरीकों से प्राइवेट ट्यूशन की मांग बढ़ाने के प्रयास किए हैं। वर्ष 2004 में ऑस्ट्रेलिया ने *ट्यूटोरियल वाउचर इनीशिएटिव* नाम की योजना आरंभ की जिसके अंतर्गत अपने बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन दिलाने के लिए योग्य अभिभावकों को 700 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 547 अमरीकी डॉलर) तक खर्च करने का अधिकार दिया। वर्ष 2007 में ऑस्ट्रेलियाई संघीय सरकार ने *एन इवेंट स्टार्ट* नामक एक अनुवर्ती योजना के लिए चार वर्ष के लिए निधि आवंटित की (वाटसन, 2008, पृ. 7)। संयुक्त राज्य अमरीका में भी ऐसी ही प्रणाली का प्रयोग किया गया (बर्च और अन्य, 2006) और इसी अमरीकी योजना तथा ऑस्ट्रेलिया की मूल योजना से प्रेरण पाकर इंग्लैंड में एक नई मॉडल योजना शुरू की गई (टेलर, 2007)। सिंगापुर में, सरकार ने समुदायों को अनुदान और अन्य प्रोत्साहन प्रदान किए ताकि कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों में प्राइवेट ट्यूशन की मांग बढ़े (टैन, 2009)। इसके विपरीत, फ्रांस की कर-निर्धारण में प्रोत्साहन देने की प्रणाली न तो विशेष रूप से कम अंक पाने वाले छात्रों के लिए और न ही कम आय वाले परिवारों के लिए बनाई गई है (मेलेत, 2007)।

इन सभी मॉडलों को अलग-अलग प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वाटसन (2007, पृ. 9) का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में प्राइवेट ट्यूशन की सफलता पर तथा विशेष रूप से ग्रामीण और सुदूरवर्ती इलाकों में पर्याप्त संख्या में कुशल अध्यापक मिलने में होने वाली कठिनाई पर अधिक ठोस आंकड़े संकलित करने की आवश्यकता

है। अत्यधिक शहरीकृत सिंगापुर के सामने ऐसी कोई कठिनाई मौजूद न होने के बावजूद, वहाँ कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों में प्राइवेट ट्यूशन की मांग बनाए रखना कठिन होता है जहाँ की बाजारी ताकतें समाज के शीर्ष स्तर को प्राइवेट ट्यूशन प्रदान करके इस अंतर को बढ़ा देती हैं (चियो एवं कुआह, 2005, टैन, 2009)। संयुक्त राज्य अमरीका में, सुंदरमैन ने प्राइवेट ट्यूशन की सफलता का प्रमाण न जुटा पाने के लिए एनसीएलबी के ढांचे की आलोचना करते हुए कहा कि कुछ प्राइवेट ट्यूशन प्रदाता छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए “अनैतिकता” का सहारा लेते हैं, उन्होंने कहा कि वास्तव में देश भर के कुल 20 प्रतिशत योग्य छात्र ही इस में भाग लेते हैं। अन्य देशों के नीति निर्माता योजनाएं बनाते समय इन तथ्यों का लाभ सकते हैं।

अन्य स्थानों में सबसे बड़ा मुद्दा यह होता है कि प्राइवेट ट्यूशन की मांग को, बढ़ाने की तुलना में कम कैसे किया जाए। कोरिया की केस स्टडी से पता चलता है कि यहाँ इसके लिए कई रणनीतियां अपनाई गईं और प्राइवेट ट्यूशन पर पूरी तरह पाबंदी भी लगा दी गई। मॉरीशस की केस स्टडी से पता चलता है कि वहाँ भी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 3 तक प्राइवेट ट्यूशन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया। अन्य देशों, जैसे कम्बोडिया (ब्रे एवं बनली, 2005, पृ. 75), मिस्र (हार्टमैन, 2008, पृ. 48), केन्या (वन्यामा एंड न्जेरू, 2004, पृ. 1), तुर्की (टैन्सल एवं बिकर्न, 2007, पृ. 6), यूगांडा (ईलोर, 2007, पृ. 28), तथा भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य (जलालुद्दीन, 2007, पृ. 2) में भी ऐसी ही नीतियां अपनाई गईं। किंतु, प्रतिबंध की नीति कहीं भी सफल नहीं हुई। उदाहरण के लिए, मिस्र के संदर्भ में हार्टमैन (2008, पृ. 48) ने हरेरा (1992, पृ. 75) की टिप्पणी दोहराते हुए कहा था कि यह प्रतिबंध उतने ही असफल रहते हैं जितने ‘लापरवाही से सड़क पार करने (अर्थात् सड़क को पार करने के लिए निर्धारित स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से पार करना) को गैरकानूनी’ बताने वाले कानून बेकार होते हैं जिसमें कानूनी जोखिम बहुत कम या लगभग नगण्य होने के कारण लोग उन्हें व्यापक रूप से तोड़ते हैं। कोरिया और मॉरीशस में भी प्रतिबंधों का व्यापक प्रचार करने और सरकार द्वारा कड़े प्रयास करने के बावजूद उन्हें लागू कर पाना असम्भव सिद्ध हुआ। स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों पर अपने मुख्य धारा के छात्रों को, जिन्हें कक्षाओं में ही पढ़ाने की जिम्मेदारी होती है, प्राइवेट ट्यूशन पर प्रतिबंध लगाने पर जोर दिया जा सकता है किंतु यह प्रतिबंध प्राइवेट ट्यूशन पर लगाए जाने वाले सम्पूर्ण प्रतिबंध से भिन्न होगा।

अतः, प्राइवेट ट्यूशन की मांग घटाने की नीतियों में इन मांगों के बाहरी कारणों पर ध्यान देने के स्थान पर, इनके मूल कारणों का इलाज करना होगा। अकेले शिक्षा मंत्रालय इनका समाधान नहीं कर सकता क्योंकि इन कारणों में सांस्कृतिक और अर्थव्यवस्था से संबद्ध कारण भी शामिल होते हैं। सांस्कृतिक कारणों में वह सीमा शामिल है जिस सीमा तक समाज शैक्षणिक उपलब्धियों को सम्मान देता है और जिसके लिए त्याग की कामना करता है। आर्थिक कारकों में उच्च स्तरीय शिक्षा से मिलने वाला लाभ और इस प्रकार वह सीमा शामिल है जिस सीमा तक प्राइवेट ट्यूशन उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला लाभकारी निवेश हो। इन पर आर्थिक विकास मंत्रालय और परिवार विकास मंत्रालय

या उसके समकक्ष मंत्रालयों तथा इसके साथ-साथ शिक्षा मंत्रालय को कार्यवाही करनी होगी। ऑस्ट्रिया और कोरिया जैसे एक-दूसरे से पूरी तरह भिन्न देशों में, शिक्षा क्षेत्र के व्यावसायिकों के स्थान पर, सरकार के उच्च अधिकारियों ने कुछ मुख्य कार्यक्रम शुरू किए हैं। सरकारी अधिकारी चाहें तो, नागरिक समितियों के साथ सहयोग स्थापित कर सकते हैं जिनमें धार्मिक संगठन और समाज कल्याण दल भी शामिल हैं।

फिर भी, शिक्षा मंत्रालय के व्यावसायिकों के पास कुछ ऐसे पत्ते हैं जिन्हें वह प्रतिच्छाया शिक्षा प्रणाली का आकार और प्रकार बदलने के लिए खेल सकते हैं। विशेष रूप से, उन्हें निम्नलिखित बातों पर विचार करना होगा:

- **परीक्षाएं:** अनेक देशों में, प्राइवेट ट्यूशन की मांग का प्रमुख आधार परीक्षाओं का प्रकार होता है। अनेक परीक्षाएँ काफी महत्वपूर्ण होती हैं जिनके परिणामों का परीक्षार्थियों को भविष्य में मिलने वाले अवसरों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कभी-कभी परीक्षाओं के प्रारूप के आधार, परीक्षार्थी किसी विषय को मूल रूप से समझने और उसे लम्बे समय तक याद रखने की तुलना में थोड़ी देर तक रटने से ही अच्छे अंक पाने में सफल हो जाते हैं। अतः, परीक्षा अधिकारियों को परीक्षाओं के प्रकार की समीक्षा करनी होगी। किंतु, उन्हें केवल यह नहीं सोच लेना चाहिए कि परीक्षाओं में सुधार आसानी से किया जा सकता है। कोरिया एवं मॉरीशस की केस स्टडी से पता चला है कि इन पर विचार करते समय, सम्भवतया अनेक निहित स्वार्थों और समानताओं पर भी विचार करना होगा।
- **पारगमन दरें:** कुछ देशों में इस जानकारी से भी ट्यूशन की मांग बढ़ जाती है कि शिक्षा के किसी स्तर को आवेदक सीमित संख्या में ही पार कर सकते हैं। प्राइवेट ट्यूशन की मांग घटाने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि इस सीमा को बढ़ा दिया जाए ताकि छात्र अधिक से अधिक संख्या में अगले स्तर तक जा सकें। शायद ऐसा करना भी सरल नहीं होगा। कुछ समाजों में, यह प्रश्न कि कोई छात्र अगले स्तर तक जा सकता है या नहीं, बदल कर यह रूप ले लेता है कि अगले स्तर के लिए किस संस्थान को चुनना चाहिए। जिन देशों में सामाजिक स्तरीकरण होने के कारण कुछ धनसम्पन्न लोगों के लिए उच्चवर्गीय संस्थान होते हैं, वहाँ इन संस्थानों में प्रवेश पाने की होड़ में प्राइवेट ट्यूशन की भी मांग बढ़ जाती है।
- **सामान्य सार्वजनिक आत्मविश्वास:** प्राइवेट ट्यूशन की मांग का एक कारण यह भी है कि माता-पिता को मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली पर अधिक विश्वास नहीं है, वे मानते हैं कि यह समाज की या विशेष रूप से उनके बच्चों की आवश्यकताएँ पूरी कर पाने में सक्षम नहीं है। भले ही स्कूलों को विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने या अन्य कार्य करने वाली अनिवार्य संस्था माना जाता है, किंतु आम धारणा यह भी है कि उन्हें स्कूलों के अनुपूरक की आवश्यकता पड़ती है। विडम्बनापूर्ण रूप में, कुछ स्थानों पर इसका कारण इन स्कूलों का विकास है ताकि पारगमन दरें बढ़ाकर प्राइवेट ट्यूशन की मांग को घटाया जा सके। लेकिन सरकार को यह जानकारी भी होनी चाहिए कि प्राइवेट ट्यूशन का अधिकांश दबाव केवल कम अंक प्राप्त करने वालों की ओर से

नहीं, अपितु अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की ओर से आता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, प्राइवेट ट्यूशन का चलन, उन देशों की तुलना में जहाँ प्रबुद्ध छात्रों की संख्या कम है, जैसे अफ्रीका, की तुलना में उन देशों में अधिक है जहाँ अधिक प्रबुद्ध छात्रों की संख्या अधिक है, जैसे पूर्वी एशिया।

नीति-निर्माताओं और योजनाकारों को उपयोगी तरीके से इस पर भी विचार करना होगा कि विभिन्न प्रकार की प्राइवेट ट्यूशन से क्या अपेक्षा की जाती है। परिवार 110 छात्रों की संयुक्त कक्षाओं पर (बॉक्स 7) खर्च करने के लिए क्यों तैयार रहते हैं जबकि मुफ्त शिक्षा प्रदान करने वाले सार्वजनिक स्कूलों की कक्षाओं में छात्रों की संख्या 35 से अधिक होने पर वे जोर-शोर से शिकायत करते हैं? माता-पिता क्यों सोचते हैं कि छोटे समूहों में तथा अकेले प्राइवेट ट्यूशन लेने पर उनके बच्चों को विशेष लाभ मिलेगा, जो मुख्य धारा की सामान्य शिक्षा में या गृह कार्य में माता-पिता द्वारा मदद देने से प्राप्त नहीं हो सकता? और माध्यमिक कक्षा के छात्र को मुख्य धारा की माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में प्रशिक्षित अध्यापक के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के एक अप्रशिक्षित छात्र से अंशकालिक आधार पर मदद दिलाने से क्या फायदा हो सकता है?

बॉक्स 7. मिस्र का एक मास्टर ट्यूटर

हार्टमैन (2008, पृ. 43) ने मिस्र के एक ट्यूटर का निम्नलिखित वर्णन किया है जिनकी साख और बाजार में मांग काफी अच्छी है। जैसाकि इस वर्णन से पता चलता है, छात्र बड़ी संख्या में उसके पास पढ़ने आते हैं।

मुझे रसायनशास्त्र की इस कक्षा में आने का निमंत्रण मिला, तो मैं कमरे में लड़कियों की सबसे अंतिम पंक्ति में एक सीट पर जा बैठी। पाठ शुरू होने पर मैंने गिना कि कक्षा में 110 छात्र मौजूद थे जिनकी आयु लगभग 14 वर्ष थी। तीन या चार युवा कर्मचारियों ने उन्हें चुप रहने और कक्षा में ध्यान देने के लिए कहा। मि. हिशम के कक्षा में प्रवेश करते ही आवाजें बंद हो गईं और 110 जोड़ी आंखें आशा और अपेक्षा के साथ अपने अध्यापक को देखने लगीं। मि. हिशम लगभग 45 वर्ष आयु के दुबले-पतले आदमी हैं जिनके बाल कम और मूँछें पतली हैं। उनकी पोशाक रूढ़िगत प्रकार की थी और उन्होंने सफेद कमीज, टाई और हल्के पीले रंग की जर्सी पहनी हुई थी, किंतु सामान्य वेशभूषा से उनके बारे में कोई अनुमान लगाना कठिन था।

अगले दो घंटों में पता चला कि मि. हिशम न केवल एक अनुभवी और प्रख्यात अध्यापक थे, बल्कि वह एक प्रतिभाशाली “शो मास्टर” भी थे। मि. हिशम जोश के साथ अपने श्रोताओं के सामने घूम रहे थे, ब्लैक बोर्ड पर फॉर्मूले लिख रहे थे और उन्हें अपने माइक्रोफोन पर लयबद्ध तरीके से दोहराकर समझाते जा रहे थे। समय-समय पर वह कुछ फॉर्मूलों और वाक्यांशों का उच्चारण करते थे जिन्हें छात्र एकसाथ मिलकर कई बार दोहराते थे, जो शायद उनके इशारे को भलीभांति समझते थे। . . . छात्रों ने उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछा, हालांकि उन्हें अपने प्रश्न एक पर्ची पर लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था जिसे कक्षा में मौजूद एक सहायक अध्यापक के पास पहुंचा देता था।

ट्यूशन की आपूर्ति से निपटना

कुछ परिस्थितियों में आपूर्ति की वजह से मांग बढ़ जाती है। इस शीर्षक के अंतर्गत तीन विशेष परिस्थितियों पर विचार किया जा सकता है:

- *अध्यापक अपना बाजार खुद बनाते हैं:* सर्वविदित है कि कुछ देशों में अध्यापकों द्वारा अपने उन छात्रों को अतिरिक्त कक्षाओं में पढ़ाना आम बात है जिन पर पहले ही उन्हें मुख्य धारा की कक्षाओं में पढ़ाने की जिम्मेदारी होती है। समस्या तब जटिल होती है जब अध्यापक स्कूल के सामान्य घंटों में पाठ्यक्रम पूरा नहीं करते और छात्रों से यह कहकर कि उन्हें अच्छे अंक देना उनके ही हाथ में है, उन पर उन्हीं से ट्यूशन लेने का दबाव बनाए रखते हैं। सिलोवा (2007, पृ. 8) के अनुसार, अनिवार्य प्राइवेट ट्यूशनों में:

अध्यापक द्वारा अपने ही छात्रों पर स्कूल के बाद उनसे अनुपूरक प्राइवेट ट्यूशन लेने का दबाव डालना (और कभी-कभी ब्लैकमेल करना) और मना करने पर छात्रों को अक्सर कम अंक देने की धमकी देना शामिल है।

सिलोवा ने जिन क्षेत्रों का अध्ययन किया उनमें यह प्रथा विशेष रूप से मध्य एशिया (कजाखिस्तान, किर्गीस्तान, ताजीकिस्तान, और मंगोलिया) और कौकेशस देश (अज़रबैजान और जॉर्जिया) में व्यापक रूप से फैली हुई है।

- *सहपाठियों का दबाव:* जब प्रत्येक दूसरा छात्र ट्यूशन ले रहा हो, तो छात्रों और उनके परिवारों को लगता है कि यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो वे पिछड़ जाएंगे या उपेक्षित रह जाएंगे। एक माता ने किम (2007, पृ.9) को बताया कि:

जन सम्पर्क के सभी साधनों में यह रिपोर्टें आती हैं कि लोग प्राइवेट ट्यूशन प्राप्त करते हैं और (मेरे बच्चे के) मित्रों की माताएँ कहती हैं कि उनके बच्चे निजी संस्थानों में यह सीखते हैं या वह सीखते हैं.... मैं भी उसका जीवन बेहतर बनाना चाहती हूँ और इसलिए मैंने भी उसे निजी संस्थान में भेजना शुरू किया है और उस पर खर्च कर रही हूँ।

- *ट्यूशन देने वालों द्वारा विज्ञापन:* इस व्यावसायिक वातावरण में निजी शिक्षक अन्य व्यावसायी की तरह काम करते हैं और अपनी सेवाओं की मांग बनाने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग सड़कों पर प्रचार करते हैं, या समाचारपत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करते हैं, सार्वजनिक परिवहनों पर विज्ञापन छपवाते हैं। भले ही उनके अनुभवी होने या उनके काम की गुणवत्ता दर्शाने का कोई प्रामाणिक आधार न हो, किंतु मुख्य धारा के समान, अंक कम आने पर अध्यापक के स्थान पर छात्र को दोष देना आसान होता है। इंटरनेट के विकास ने प्राइवेट ट्यूशन की सप्लाय में आने वाली भौगोलिक बाधाओं को दूर कर दिया है। कुछ देशों में, फ्रैंचाइजिंग द्वारा इसकी पूर्ति की जा रही है। जैसाकि डेविस और औरिनी (2006, पृ. 124) ने उल्लेख किया है:

इस व्यवस्था ने छोटे व्यापारियों को केन्द्रीयकृत नेटवर्क से जोड़ दिया है, किंतु, फ्रैंचाइजर कॉर्पोरेट जगत से इस दृष्टि से भिन्न हैं कि स्थानीय कारोबारियों

की अपनी दुकानें होती हैं और अधिकांश जोखिम वे स्वयं उठाते हैं। स्थानीय दुकानदार का अपना धन दांव पर लगा होता है और इसलिए वे एक वेतनभोगी प्रबंधक की तुलना में फ्रैंचाइज़ी सेवा अधिक कुशलता से प्रदान करने की कोशिश करते हैं। यह छोटे निवेशक किसी प्रतिष्ठित और जाने-माने उत्पाद को बेचने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं और उन्हें कंपनी से उत्पाद की बिक्री में सहायता मिलती है और प्रबंधन प्रशिक्षण तथा उत्पाद-परीक्षण की सामग्री, इत्यादि कंपनी से प्राप्त होते हैं। . . . चाहे वे कॉफी बेच रहे हों या कारें भाड़े पर दे रहे हों या छात्रों को ट्यूशन पढ़ा रहे हों, स्थानीय फ्रैंचाइज़ी के मालिकों के लिए उत्पाद और ग्राहकों का सुस्थापित आधार तत्काल उपलब्ध रहता है।

अध्यापकों द्वारा अपने मौजूदा छात्रों को ट्यूशन पढ़ाने की समस्या को व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के संदर्भ में देखा जा सकता है (हलाक एवं पॉइसन, 2007; पॉइसन, 2007; डौसन, 2009)। *बॉक्स 8* में इस समस्या के निर्धारण करने के लिए क्लिटगार्ड ने एक उपयोगी फॉर्मूला दिया है। इस फॉर्मूले का प्राइवेट ट्यूशन पर प्रयोग करने से पता चलता है कि जब अध्यापकों के पास अपने छात्रों की शिक्षा का एकाधिकार होता है, जब वह स्वयं यह निर्णय लेते हैं कि किसे पास करना है और किसे फेल, और जब शिक्षा प्रणाली के अन्य भागों के लिए उनका उत्तरदायित्व और जवाबदेही बहुत कम या बिल्कुल नगण्य होते हैं, तो उनके भ्रष्ट होने के अवसर और सम्भावनाएं अधिक हो जाते हैं। मॉरीशस में, कक्षा 4-6 में सभी विषयों के लिए एक क्लास टीचर के स्थान पर प्रत्येक विषय के लिए अलग-अलग शिक्षक नियुक्त करने के निर्णय का उद्देश्य अध्यापकों को इसी एकाधिकार को समाप्त करना था। इसके अतिरिक्त उनके स्वनिर्णय के अधिकार को कम करने और स्कूल तथा शिक्षा प्रणाली में जवाबदेही बढ़ाने के तरीके भी अपनाए गए।

बॉक्स 8. एकाधिकार + स्वनिर्णय - जवाबदेही

भ्रष्टाचार के प्रकार और कारणों पर ध्यान देते हुए, क्लिटगार्ड (1988, पृ. 75) ने इन मूल तत्त्वों का प्रयोग करके एक फॉर्मूला तैयार किया:

भ्रष्टाचार = एकाधिकार + स्वनिर्णय - जवाबदेही

उनका सुझाव था कि अवैध और अनुचित व्यवहार केवल तभी पनपता है जब व्यक्ति का अपने ग्राहकों पर एकाधिकार होता है, जब एजेंट्स स्वयं निर्णय लेते हैं, और जब एजेंट की जवाबदेही की प्रणाली कमजोर होती है।

बिस्वाल (1999, पृ. 223) ने दर्शाया कि इस सिद्धांत से पता चलता है कि प्राइवेट ट्यूशन और अन्य प्रकार के भ्रष्टाचारों में कितनी समानता है, विशेष रूप से तब, जब मुख्य धारा के अध्यापक स्वयं अपने ही छात्रों को ट्यूशन देते हों। बिस्वाल का कथन था कि “यह अध्यापक अपने छात्रों को अपनी सेवाएं देने का एकाधिकार अपने हाथ में ले लेते हैं, उन्हें स्वयं यह निर्णय लेने का पूरा अधिकार होता है कि वे कैसी सेवाएं देंगे, और उनसे उनके कामों के लिए शायद ही कोई जवाब मांगा जाता है। इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब अध्यापक स्कूल में अपने काम से जी चुराते हैं और स्कूल से बाहर फीस लेकर प्राइवेट ट्यूशन देकर छात्रों को उपभोक्ता की तरह निचोड़ने का प्रयास करते हैं।”

जॉनसन (2008) ने इस धारणा की व्याख्या करते हुए, इसमें कुछ और कारण जोड़ दिए जिसमें पढ़ाया जाने वाला विषय, छात्रों की आर्थिक-सामाजिक अवस्था, और छात्रों की उपलब्धि का स्तर शामिल था। उन्होंने किर्गीस्तान में किए गए अपने अध्ययन के संदर्भ में बताया, कि (पृ. 213):

भ्रष्टाचार करने वाले और भ्रष्टाचार न करने वाले शिक्षकों की उनके लिंग, जातीयता, आयु या प्रशासनिक भूमिका से पहचान नहीं की जा सकती, बल्कि उनकी पहचान इन तथ्यों से होती है कि उनके छात्र कौन हैं, उनके सहयोगी शिक्षक कौन हैं, उनके स्कूल का निदेशक कौन है, वे कौन सा विषय पढ़ाते हैं और वे किस जिले में रहते हैं।

विशेष रूप से (पृ. 219):

किर्गीस्तान का एक अत्यधिक भ्रष्ट शिक्षक अधिकतर ऐसे विषय पढ़ाता है जिनकी मांग बहुत अधिक है, जैसे गणित, किर्गीज़ भाषा, या इंग्लिश, वह इतिहास जैसे विषय नहीं पढ़ाएगा, जिनकी मांग कम होती है। ऐसे शिक्षक अधिकतर उन छात्रों को पढ़ाते हैं जो उच्च सामाजिक-आर्थिक वर्ग से संबद्ध होते हैं अथवा जिनके अंक जीपीए (ग्रेड पॉइंट एवरेज) की मध्य श्रेणी में आते हैं। वे अक्सर कम विकसित क्षेत्रों में या ऐसे क्षेत्रों में पढ़ाते हैं जहां एक ही प्रजाति के लोग रहते हों, जो शहरी या ग्रामीण क्षेत्र भी हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अत्यधिक भ्रष्ट शिक्षक अक्सर ऐसे स्कूलों में काम करते हैं जहाँ अन्य शिक्षकों की “कड़ाई” और स्कूल के निदेशक की व्यावसायिकता एक-दूसरे के रास्ते में नहीं आते।

अतः, जॉनसन (2008) का कहना था कि क्लिटगार्ड की मूल धारणा वैध है क्योंकि ऐसे अध्यापकों का अत्यधिक मांग वाली शिक्षा पर पूरा एकाधिकार होता है और उन्हें अपनी इच्छा से अनेक निर्णय लेने की छूट होती है। किंतु जॉनसन द्वारा शामिल किए गए परिवर्तियों में छात्रों की मांग, जो उनकी क्रय-शक्ति से संचालित होती है, उनकी योग्यता और किसी विशेष विषय के बारे में उनकी चिंता शामिल हैं। यूं कहें, तो भ्रष्ट अध्यापकों को भी भ्रष्ट छात्रों की आवश्यकता होती है। इसके आधार पर नीति-निर्माताओं को विभिन्न परिस्थितियों में मौजूद विभिन्न स्थितियों पर विचार करना होगा।

इस दृष्टि से, इस तथ्य में कि कुछ शिक्षा प्रणालियां अध्यापकों के स्व-निर्णय को कम करने के स्थान पर बढ़ा रही हैं, उतना विरोधाभास नहीं है, जितना दिखाई देता है। परीक्षाओं के दूरगामी प्रभावों को कम करने का एक तरीका यह भी है कि स्कूल पर आधारित विभिन्न प्रकार के मूल्यांकनों में से, परीक्षाओं को मूल्यांकन का केवल एक घटक बना देना चाहिए। स्कूल-पर-आधारित मूल्यांकन में निश्चित रूप से शिक्षकों की भूमिका बढ़ जाती है और इसके साथ ही उनका स्वयं निर्णय लेने का अधिकार भी बढ़ जाता है। नीति-निर्माताओं के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या स्कूल पर आधारित विस्तृत मूल्यांकन को अधिक व्यापक बना देने से शिक्षा प्रणाली में सुधार होगा या अधिक समस्याएं उत्पन्न होंगी। बड़ी सीमा तक इसका उत्तर शिक्षक वर्ग की व्यावसायिकता और

कुछ सीमा तक आत्म-संयम पर निर्भर करेगा। यह कदम किर्गीज़स्तान के कुछ भागों के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं हुए, किंतु उस देश के अन्य भागों के लिए और अन्य देशों के लिए उपयुक्त हो सकते हैं; विशेष रूप से तब, जब स्वयं प्राइवेट ट्यूशन के लिए या अधिक विश्वव्यापी शिक्षक संहिता के भाग के रूप में प्राइवेट ट्यूशन के लिए एक विशेष संहिता बनाई जाए (पोइसन, 2007, पृ. 17)। यदि शिक्षक यूनियनों से इस मामले में ठोस रुख अपनाने को कहा जाए, तो वे इस प्रयास में महत्वपूर्ण सहयोग दे सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, इंग्लैंड द्वारा 2007 में लागू *मेकिंग गुड प्रोग्रेस* योजना में टेलर (2007, पृ. 17-18) द्वारा प्रस्तुत किए गए मॉडलों पर विचार करना भी समीचीन होगा (सारणी 14)। इस योजना में, सक्रिय रूप से स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापकों द्वारा अपने मौजूदा छात्रों को अतिरिक्त ट्यूशन पढ़ाने की योजना पर विचार किया गया था, जिसे सम्भवतया यह सोचकर आरंभ किया गया था कि ऐसा करने पर निरीक्षण का समुचित ढांचा उपलब्ध होगा (दूसरे शब्दों में पर्याप्त जवाबदेही मौजूद होगी) और कोई नैतिक समस्या उत्पन्न नहीं होगी। इसमें अन्य स्कूलों के अध्यापकों, व्यावसायिक ट्यूटर्स और शिक्षार्थी सलाहकारों को शामिल करने पर भी विचार किया गया, बशर्ते कि उनके पास अर्हताप्राप्त शिक्षक का प्रमाणपत्र (क्यूटीएस) मौजूद हो। विश्वविद्यालय के अयोग्य छात्रों को लेने पर विचार नहीं किया गया और प्रशिक्षु अध्यापकों को केवल अत्यावश्यक परिस्थितियों में, जबकि वे छात्र के स्कूल से पहले ही परिचित हों, नियुक्त करने पर विचार किया गया। यह मॉडल अन्य स्थानों पर भी उपयोगी हो सकते हैं। हालांकि इस मॉडल को ऐसे देश के लिए तैयार किया गया था जिसके वित्तीय संसाधन अत्यधिक मजबूत थे और व्यवसायी अध्यापकों का मजबूत आधार मौजूद था।

सारणी 14 इंग्लैंड की 'मेकिंग गुड प्रोग्रेस' योजना में विचारणीय प्राइवेट ट्यूशन के मॉडल

विकल्प	लाभ	सीमाएँ
क्लास टीचर	• छात्रों को और उनकी आवश्यकताओं को जानता है • अभिभावकों को जानता है • कक्षा में ध्यान रखना आसान होता है • गुणवत्ता आश्वासन अधिक मजबूत होता है	• छात्र अपने क्लास टीचर के प्रति बाहरी ट्यूटर की तरह प्रतिक्रिया दर्शाता है • बच्चे का ध्यान केंद्रित करने के लिए नवीन कार्यप्रणाली / व्यक्ति की आवश्यकता होती है • अध्यापक के वर्तमान कार्य भार से समस्या उत्पन्न हो सकती है • अध्यापक के पास समय सीमित होता है क्योंकि वह स्कूल के बाद के कामों में व्यस्त होता है • निजी कक्षा के बारे में अभिभावकों की राय - निजी शिक्षक क्लास टीचर से भिन्न होना चाहिए

विकल्प	लाभ	सीमाएँ
स्कूल का या स्कूल से संबद्ध कोई अन्य शिक्षक	● शकल-सूरत और शैली भिन्न होती है ● अधिक अनुभवी ● स्कूल की प्रणाली और नीतियों की जानकारी ● मिलकर काम करने का अवसर ● क्लास टीचर और अभिभावकों का आपसी सम्पर्क आसान होता है ● रिकॉर्ड और योजनाएं उपलब्ध रहते हैं ● सम्भवतया माता-पिता और बच्चे उसे पहले ही जानते हैं ● गुणवत्ता आश्वासन अधिक मजबूत होता है	● शिक्षक का परिवर्तन होने पर छात्र असुरक्षित महसूस करते हैं ● शिक्षक बच्चे की आवश्यकताओं से परिचित नहीं होता ● शिक्षकों के वर्तमान कार्य भार से समस्या हो सकती है ● अध्यापक के पास सीमित समय उपलब्ध होता है क्योंकि वह स्कूल को बाद किए जाने वाले कामों में व्यस्त होता है ● निजी कक्षा के बारे में अभिभावकों की राय - निजी शिक्षक अपने परिचित शिक्षक से भिन्न होना चाहिए
क्रॉस-फेज ट्यूशन, जैसे सहभागी स्कूलों के अध्यापक	● नया चेहरा / नए विचार ● शिक्षकों के लिए नया अनुभव ● परिवर्तन से सुधार और मजबूती आती है ● जिले के सभी स्कूल अच्छी पद्धतियां अपनाने हैं	● भिन्न क्रमावस्था के शिक्षक के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता हो सकती है ● बड़ी आयु के छात्रों के लिए उपयुक्त, जो शिक्षक बदलने पर उसे शीघ्र अपना लेते हैं ● शिक्षक को क्रमावस्था से होने वाली अपेक्षाओं की जानकारी नहीं होती ● शिक्षक को बच्चे की आवश्यकताओं की जानकारी नहीं होती ● प्राइवेट ट्यूशन सत्रों के गुणवत्ता आश्वासन पर नज़र रखना अधिक कठिन होता है
कोई भी शिक्षक	● नया चेहरा / नए विचार ● छात्र की आवश्यकताओं के प्रति नवीन दृष्टिकोण ● कार्यक्रम में शिक्षकों की भागेदारी को बढ़ाता है ● अन्य विषय पढ़ाने का अनुभव	● विषय के मुख्य स्तर की जानकारी नहीं होती ● स्कूल प्रणाली की जानकारी नहीं होती ● समय और स्थान में परिवर्तन के कारण क्लास टीचर से सम्पर्क करना कठिन होता है ● चल रहे क्रम से अपेक्षाओं की जानकारी नहीं होती ● बच्चे की आवश्यकताओं की जानकारी नहीं होती ● प्राइवेट ट्यूशन सत्रों के गुणवत्ता आश्वासन पर नज़र रखना अधिक कठिन होता है

विकल्प	लाभ	सीमाएँ
निजी शिक्षण संस्थान	● वह निजी शिक्षकों को नियुक्त करते हैं ● शिक्षकों का बड़ा समूह, जिसमें से शिक्षक भेजे जा सकते हैं ● सभी प्रबंधन कार्य स्थानीय प्राधिकरण के लिए किए जाते हैं ● क्षमता और समय की समस्या नहीं होती ● स्कूल में शिक्षकों का कार्य भार का दबाव कम हो जाता है	● नवीन शिक्षा प्रणालियों की जानकारी का स्तर ● प्राइवेट ट्यूशन के सत्रों की गुणवत्ता पर नज़र रखना कठिन होता है ● निजी शिक्षक की भौगोलिक स्थिति ● छात्रों और अभिभावकों के साथ संबंध बनाने की क्षमता ● स्कूल प्रणाली की समझ, जैसे छात्रों को खोजना और उन्हें भर्ती करना ● कार्यस्थल का मूल्य ● सुरक्षा और विश्वास का मुद्दा
अन्य सुझाव: सलाहकार; प्रमुख शिक्षक; प्रौढ़ शिक्षा प्रदान करने वाले अध्यापक; दोबारा अध्यापन में लौटने वाले; सूचना एवं संचारण प्रौद्योगिकी (आईसीटी), शिक्षक/मुख्य शिक्षक जो प्रयोग में शामिल न हों, खानदानी शिक्षक (अर्हताप्राप्त शिक्षक की हैसियत - क्यूटीएस); अध्ययनरत सलाहकार (अर्हताप्राप्त शिक्षक की हैसियत - क्यूटीएस होनी चाहिए); विशिष्ट परिस्थितियों में प्रशिक्षार्थी अध्यापक, यदि स्कूल को उनकी पूरी जानकारी हो।	● चेहरे और शैली में परिवर्तन ● अधिक अनुभव ● सम्भवतया छात्र और अभिभावकों से पहले ही परिचित हों ● विषय का समुचित ज्ञान होता है	● प्राइवेट ट्यूशन के सत्रों की गुणवत्ता पर नज़र रखना कठिन होता है ● मुख्य अवस्था में नया और सुसंगत अनुभव महत्वपूर्ण हो सकता है ● विषय की मुख्य अवस्था का समुचित ज्ञान न हो, अतिरिक्त प्रशिक्षण और सहयोग की आवश्यकता।

बाजार का उपयोग करना

जो नीति - निर्माता यह मानते हैं कि प्राइवेट ट्यूशन ने पहले ही अपने पांव जमा रखे हैं और सरकार के चाहने पर भी इसे समाप्त नहीं किया जा सकता, तो कम-से-कम उन्हें ऐसे रास्ते खोजने होंगे जिनसे तालमेल बढ़ाने के लिए, प्राइवेट ट्यूशन के बाजार का सही उपयोग हो सके। इसके उदाहरण ऊपर दिए जा चुके हैं। जैसे, मॉरीशस में प्रतिच्छाया प्रणाली को अधिक स्पष्ट रूप में सबके सामने लाने और उस पर कुछ नियंत्रण लगाने के लिए शिक्षकों को स्कूल की कक्षाओं का प्रयोग करने की अनुमति है। इसी प्रकार, जंज़ीबार में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अभिभावकों की सहमति से स्कूल के समय के बाद

ट्यूशन पढ़ाने के लिए थोड़ी फीस लेने की अनुमति दी गई है। एक सरकारी दस्तावेज में कहा गया है (जंजीबार, 1998, पृ. 18):

विवादास्पद होने के बावजूद, इस कार्रवाई से अभिभावकों को स्वेच्छा से शिक्षकों के वेतन में कुछ योगदान देने का अवसर मिलेगा, जिससे शिक्षकों को प्रोत्साहन मिलेगा और उनका दूसरी नौकरी की ओर झुकाव नहीं होगा। इस उपाय का सकारात्मक प्रभाव भी होगा, क्योंकि छात्रों की लगातार बढ़ती संख्या को पढ़ाने के लिए भर्ती किए जाने वाले शिक्षकों की संख्या काफी हद तक स्थिर बनी रहेगी।

इस नीति में कुछ जोखिम भी हैं, क्योंकि संरचना में वांछित परिवर्तनों करने का दबाव कम हो जाएगा, जिसमें अध्यापकों को उनके द्वारा किए गए कार्य के अनुरूप उपयुक्त स्तर पर वेतन दिया जाता है। इसके साथ-साथ, यह नीति अप्रत्यक्ष रूप से निजीकरण का रूप ले लेगी जो स्कूली शिक्षा की संस्कृति को बदल देगी, जिससे वापिस लौटना कठिन होगा। प्राधिकारियों का मानना है कि प्राइवेट ट्यूशन हमेशा मौजूद रहेगी अतः वे इसका मुख्य धारा के साथ तालमेल बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

स्कूली स्तर पर अन्य कदम उठाए जा सकते हैं किंतु उन्हें जिला या उच्च स्तर पर ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। अन्य स्थानों के समान कंबोडिया में, प्राइमरी स्कूल के प्रशासकों ने पाया कि अधिकतर शिक्षक उच्च कक्षाओं में पढ़ाने और केवल प्रमुख विषय पढ़ाने के लिए अधिक उत्सुक रहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से प्राइवेट ट्यूशन के बाजार में उनकी मांग बढ़ जाती है (ब्रे एवं बनली, 2005; डॉसन, 2009)। परिणामस्वरूप, छोटी कक्षाओं और अन्य विषयों की उपेक्षा होने की सम्भावना रहती है। एक दूरदर्शी मुख्याध्यापक ने प्राइवेट ट्यूशन से होने वाली आय को इकट्ठा करके स्कूल के सभी शिक्षकों में बांटने का तरीका अपनाया। हालांकि यह उनका अपना निर्णय था, किंतु यह ऐसा उपाय था किंतु इस उपाय को पूरी शिक्षा-प्रणाली पर लागू किया जा सकता है।

सरकार निजी शिक्षकों को अपने कार्य को व्यावसायिक रूप देने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। उदाहरण के लिए, ताईवान में, प्राइवेट ट्यूशन प्रदान करने वाले शिक्षकों का एक संगठन है जो अपने सदस्यों के शैक्षिक और कारोबारी आयाम पर नज़र रखता है। 1999 में, तेइपेई शहर में प्राइवेट ट्यूशन प्रदान करने वाले स्कूलों की संख्या लगभग 1,150 थी, जिनमें से आधे तेइपेई सिटी एसोसिएशन फॉर प्रोवाइडर्स ऑफ ट्यूटोरियल एजुकेशन के सदस्य थे। यह संगठन सदस्य स्कूलों के खिलाफ जनता की शिकायतें दर्ज करता है, एक सूचना पत्र प्रकाशित करता है, और एक स्व-नियंत्रक समिति के रूप में काम करता है (ब्रे, 2003; पृ.57)। ग्रीस में, हेलेनिक फेडरेशन ऑफ फ्रंटिस्टीरिया टीचर्स एक ऐसी ही संस्था है जिसकी स्थापना 1981 में हुई थी और 2008 तक इसके 3,000 सदस्य प्राइवेट ट्यूशन स्कूलों के मालिक थे और 37,000 सदस्य निजी शिक्षक थे (हेगीटेगास, पृ. 1; हेगीटेगास, 2008बी भी देखें)। सरकार ऐसी व्यावसायिक संस्थाओं के

साथ बातचीत कर सकती है और बच्चों के कल्याण से संबंधित सामान्य हित के विषयों पर बातचीत कर सकती है।

अन्य ट्यूशन कंपनियां गुणवत्ता नियंत्रण मानदंडों का प्रचार करके अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखती हैं। जर्मनी की एक बड़ी ट्यूशन कंपनी शुएरहिल्फे.डी बड़े गर्व से बताती है कि उसने आईएसओ 9001 से गुणवत्ता परीक्षा कराई है और ग्राहक प्रबंधन गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। फ्रांस की कम्पलीट्यूड ने भी इसी प्रकार स्वयं को अपने प्रतिस्पर्द्धियों से अलग रखा है। कंपनियों ने यह कदम स्वयं उठाए हैं, किंतु, यदि उक्त उद्यम स्व-नियंत्रण के लिए कोई कदम न उठाएं तो राष्ट्रीय सरकारें बाहरी नियंत्रण का भय दिखाकर उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं।

सरकार जनता के विशेष वर्ग को अधिक जागरूक बनाने के लिए प्राइवेट ट्यूशन प्रदान करने वाले स्कूलों की विपणन रणनीति का भी प्रयोग कर सकती है। किम (2007, पृ. 14) ने सूचित किया है कि कोरिया में, निजी संस्थानों के शिक्षक, सामान्य रूप से उच्च-मध्य-वर्ग के समुदायों और निम्न-श्रेणी के समुदायों के बीच के अंतर को पहचानते हैं जिससे पता चलता है कि निम्न-श्रेणी के माता-पिता अपने बच्चों पर पढ़ने का कोई दबाव नहीं डालते। क्योंकि प्राइवेट ट्यूशन संस्थान अपना बाजार बढ़ाना चाहते हैं, अतः “वे शिक्षा के माध्यम से लोगों की समाज में आगे बढ़ने की चाह को सक्रिय रूप से उकसाते हैं”। यदि निम्न-श्रेणी के समुदायों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, तो सरकार का उद्देश्य पूरा करने में मदद मिल सकती है।

इसी प्रकार, सरकार गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और नागरिक समितियों के साथ मिलकर प्राइवेट ट्यूशन को बढ़ावा दे सकती है। जलालुद्दीन (2007, पृ. 4) ने बांग्लादेश के कम्युनिटी लर्निंग असिस्टेंट प्रोजेक्ट (सीएलएपी) का उल्लेख किया है जिसे शिक्षा में सुधार के लिए और बच्चों तथा समुदायों को अपनी क्षमताओं का विकास करने में मदद करने के लिए 1998 में शुरू किया गया था। सीएलएपी का एक प्रमुख तत्त्व समुदाय-पर-आधारित शिक्षकों की भर्ती करना है, जो अधिकतर कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्र होते हैं, जिन्हें स्थानीय समुदायों द्वारा चुना जाता है और उनके साथ काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। निजी शिक्षक स्कूल के शिक्षकों के निर्देशन में नहीं, बल्कि उनके साथ घनिष्ठ रूप से मिलजुलकर काम करते हैं।

इसी प्रकार, मिस्र में एक कार्यक्रम लागू किया गया जिसमें प्राधिकारियों ने एक ओर तो प्रतिच्छाया शिक्षा प्रणाली का विरोध किया, किंतु दूसरी ओर हुए धर्मार्थ संस्थानों को निम्न-आय वर्ग के बच्चों को मस्जिदों, गिरजाघरों और अन्य स्थानों पर ट्यूशन देने को प्रोत्साहित किया गया। हार्टमैन (2008, पृ. 41) के कथनानुसार, यह सरकारी और कानूनी प्रकार की ट्यूशन “व्यापक रूप से फैली ट्यूशन की अवैध प्रणाली समाप्त करने के लिए” आरंभ की गई थी। प्राइवेट स्वयंसेवी संगठनों के लिए शिक्षा मंत्रालय के स्थान पर समाज कल्याण मंत्रालय में पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया।

नियंत्रक ढांचे में सुधार करना

सिलोवा (2007) ने अपने शोधपत्र में नियंत्रक ढांचे की अच्छी व्याख्या की है। उनका कहना है (पृ. 9) कि पूर्वी यूरोप और एशिया में प्राइवेट ट्यूशन के विस्तार और इसके प्रतिकूल प्रभावों के बावजूद, उसने जिन 12 देशों का अध्ययन किया उनमें से केवल 6 देशों – कज़ाखिस्तान, लिथुआनिया, मंगोलिया, स्लोवाकिया, ताजिकिस्तान और यूक्रेन में ही नियंत्रक ढांचा मौजूद है (सारणी 15)।

सारणी 15. यूरोप और एशिया के छः देशों में प्राइवेट ट्यूशन को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढांचा

कज़ाखिस्तान	राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुपूरक शिक्षा प्रणाली को 1999 की आज्ञापत्र द्वारा विनियमित किया गया। प्राइवेट ट्यूशन को शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम द्वारा 'निर्धारित समय के अतिरिक्त छात्रों को व्यक्तिगत आधार पर स्कूली विषयों में शिक्षा प्रदान करने' के रूप में परिभाषित किया गया है। इस आज्ञापत्र में यह भी अनुबंधित किया गया है कि स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा मानदंडों के अतिरिक्त, अनुपूरक शिक्षा कार्यक्रमों के रूप में भी प्राइवेट ट्यूशन प्रदान कर सकते हैं।
लिथुआनिया	2003 के शिक्षा कानून में स्वतंत्र अध्यापक की धारणा आरंभ की गई और उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जिसे निजी आधार पर शिक्षा प्रदान करने का लाइसेंस प्राप्त हो। एक स्वतंत्र अध्यापक अनौपचारिक शिक्षा प्रदान कर सकता है या ऐसे प्रोग्राम मॉड्यूल तैयार कर सकता है जिनसे स्कूल-पूर्व पाठ्यक्रम तथा/अथवा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों की पूर्ति हो। स्वतंत्र अध्यापक को अपने व्यक्तिगत कार्यक्रम के अनुसार कार्य करने, शिक्षा कार्य के लिए अपनी निजी प्रणाली और तरीके चुनने और परामर्श तथा नौकरी के दौरान सहायता प्रदान करने का अधिकार है। कानून में स्वतंत्र अध्यापकों के लिए दायित्व निर्धारित किए गए हैं जिनमें नीतियों का पालन करना, छात्रों की सुरक्षा बनाए रखना, पढ़ाने के लिए एक उचित स्थान की व्यवस्था करना, जो स्वच्छ हो, तथा छात्रों की सहमति से शिक्षा का उचित तरीका अपनाना, इत्यादि शामिल हैं। इस कानून में स्वतंत्र अध्यापकों को मुख्यधारा के स्कूलों में पढ़ने वाले अपने निजी छात्रों को प्राइवेट ट्यूशन देने पर पाबंदी लगाई गई है।
मंगोलिया	शिक्षा कानूनों में 2006 में संशोधित और 2007 में लागू किए गए <i>इथिक्स कोड ऑफ प्रीस्कूल, प्राइमरी एंड सेकेण्ड्री स्कूल टीचर्स</i> में शिक्षकों को मुख्यधारा के स्कूलों में पढ़ने वाले अपने ही छात्रों को प्राइवेट ट्यूशन देने पर प्रतिबंध है। विशेष रूप से, इस नैतिक संहिता के अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि "शिक्षक अपने छात्रों पर पुस्तकें, शिक्षा सामग्री या अन्य वस्तुएं खरीदने के लिए दबाव नहीं डाल सकते, ऐसे किसी शुल्क या फीस का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते जिसका कानून में उल्लेख न किया गया हो, और शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन प्राप्त करने के लिए बहकाना नहीं सकते।" इस नैतिक संहिता का उल्लंघन करने वाले शिक्षक पर जुर्माना लगाने या उसके शिक्षण प्रमाणपत्र जब्त करके उसे दंडित करने का प्रावधान है

स्लोवाकिया ट्रेड लाइसेंसिंग ऐक्ट में विदेशी भाषा और कला में प्राइवेट ट्यूशन प्रदान करने की शर्तें निर्धारित की गई हैं। विदेशी भाषा में प्राइवेट ट्यूशन प्रदान करना केवल तभी संभव है जब व्यक्ति के पास उस विषय में डिग्री (विश्वविद्यालय में अध्ययन द्वारा या विदेशी भाषा का प्रमाणपत्र) हो या उस देश में, जहाँ वह भाषा अधिकारिक रूप से बोली जाती है, में 10 वर्ष प्रवास का प्रमाणपत्र हो। कोई व्यक्ति किसी कला क्षेत्र में केवल तभी पढ़ा या प्राइवेट ट्यूशन प्रदान कर सकता है जब उसने कला स्कूल से प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो या उस क्षेत्र में 10 वर्ष पढ़ाने का अनुभव हो। तथापि, स्कूल के अन्य विषयों में प्राइवेट ट्यूशन प्रदान करने के लिए कोई अनिवार्य अर्हता निर्धारित नहीं की गई है और शिक्षकों को स्वयं प्राइवेट ट्यूशन देने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

ताजिकिस्तान 2004 के शिक्षा कानून में निजी शिक्षक की निम्नलिखित परिभाषा दी गई है: “एक शिक्षक जो स्कूल या विश्वविद्यालय के (अधिकृत) कार्य घंटों के अतिरिक्त छात्रों को व्यक्तिगत रूप में या समूहों में प्राइवेट ट्यूशन प्रदान करता है।” अनुच्छेद 24 के अनुसार, अभिभावक या अन्य संरक्षक सरकारी माध्यमिक स्कूलों से फीस लेकर अनुपूरक कक्षाओं का प्रबंध करने का अनुरोध कर सकते हैं। कानून के अनुसार, स्कूल के अधिकृत पाठ्यक्रम के अतिरिक्त निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुपूरक प्राइवेट ट्यूशन प्रदान की जा सकती है: (1) भिन्न कार्यक्रम या विषय, जिन्हें राष्ट्र के शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल न किया गया हो, (2) उन विषयों का गहराई से अध्ययन, जिन्हें शिक्षा संस्थानों द्वारा पढ़ाया न जाता हो, तथा (3) अन्य प्रकार की शिक्षा सेवाएं जो राष्ट्र के शिक्षा मानदंडों के अतिरिक्त हों।

यूक्रेन 2003 में, शिक्षा एवं विज्ञान मंत्रालय ने स्कूल परिसर में प्राइवेट ट्यूशन पर प्रतिबंध लगाने दिया था। अभिभावकों द्वारा ‘अनिवार्य ट्यूशन’ (अर्थात् छात्र के कक्षा अध्यापक द्वारा दी जाने वाली तथा/अनिवार्य बताई जाने वाली निजी शिक्षा) की शिकायत करने पर, मंत्रालय ने 2004 में शिक्षकों को अपने ही छात्रों को प्राइवेट ट्यूशन देने पर प्रतिबंध लगा दिया।

स्रोत: सिलोवा (2007), पृ. 10-11.

इन छः देशों में से, लिथुआनिया का कानूनी ढांचा सबसे अधिक व्यापक है। लिथुआनिया के 2003 के शिक्षा कानून में निजी शिक्षक की विस्तृत परिभाषा दी गई है (जिसे एक ‘स्वतंत्र शिक्षक’ कहा गया है) और पंजीकरण प्रक्रिया का विवरण दिया गया है। इसमें निजी शिक्षक के दायित्व भी निर्धारित किए गए हैं जिनमें शिक्षक के लिए नैतिकता का पालन करना, छात्र की सुरक्षा का ध्यान रखना, और प्राइवेट ट्यूशन के लिए उचित स्थान की व्यवस्था करना शामिल है। लिथुआनिया के कानून में यह उल्लेख किया गया है कि कुछ शिक्षक मुख्य धारा के स्कूलों में काम कर सकते हैं किंतु उन्हें इन स्कूलों में अपने ही छात्रों को प्राइवेट ट्यूशन देने की मनाही है।

इसके विपरीत, स्लोवाकिया में, ट्रेड लाइसेंसिंग ऐक्ट में केवल विदेशी भाषा और कला में प्राइवेट ट्यूशन देने की शर्तें निर्धारित की गई हैं। स्कूल के अन्य विषयों में प्राइवेट ट्यूशन प्रदान करने के लिए किसी विशेष अर्हता की आवश्यकता नहीं है और अधिकांश शिक्षक प्रतिच्छाया अर्थव्यवस्था में ट्रेड लाइसेंस के बिना पढ़ाते हैं और वेतन करमुक्त होता है (कुबानोवा, 2006, पृ. 282 भी देखें)। इसके अतिरिक्त, स्वयं अध्यापकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन देने पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। इस समूह के केवल तीन देशों (लिथुआनिया,

मंगोलिया और यूक्रेन) में शिक्षकों पर मुख्य धारा में अपने ही छात्रों को प्राइवेट ट्यूशन देने पर प्रतिबंध है।

सिलोवा का कथन था (पृ. 11) कि विनियमों का विरले ही पालन किया जाता है। कज़ाखिस्तान और ताजिकिस्तान की कानूनी प्रक्रिया विशेष रूप से जटिल और महंगी है; और लिथुआनिया में भी, जिसका कानूनी ढांचा सबसे अधिक विस्तृत है, मांग के हिसाब से बहुत कम शिक्षकों ने पंजीकरण कराया है। इसके अतिरिक्त, लिथुआनिया के स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर का विचार है कि यह सिद्ध कर पाना लगभग असम्भव होता है कि व्यक्ति ट्यूशन पढ़ा रहा है और अघोषित आय अर्जित कर रहा है। कज़ाखिस्तान और ताजिकिस्तान के कानून में यह अनुबंधित है कि अभिभावकों को अनुपूरक प्राइवेट ट्यूशन का भुगतान शिक्षा संस्थान के बैंक खाते में हस्तांतरित करना होगा, किंतु कज़ाखिस्तान के केवल कुछ पब्लिक स्कूलों का बैंक खाता है और ताजिकिस्तान के किसी भी पब्लिक स्कूलों का, वास्तव में कोई बैंक खाता ही नहीं है। सिलोवा ने कर-निर्धारण में मिलने वाली छूट की कमी पर भी प्रकाश डाला (पृ. 12) है। ताजिकिस्तान के शिक्षा कानून में कहा गया है कि “ताजिकिस्तानी कानून के अनुसार, वैतनिक शिक्षा सेवाओं से होने वाली आय पर अधिकतम कर निर्धारित किया जाएगा।” किंतु सरकार के पास इस कानून को लागू करने की कोई प्रणाली मौजूद नहीं है और निजी शिक्षकों को स्वेच्छा से इसका अनुपालन करने पर कोई छूट नहीं मिलती।

अन्य देशों का कानूनी ढांचा और सिद्धांत भिन्न हैं। यहाँ तक कि, उपनिवेशवाद के दौरान कोरिया की कानून प्रणाली पर जापान का प्रभाव होने के बावजूद, कोरिया और जापान के कानूनी ढांचे में भी काफी अंतर है। किम एवं ली (2008, पृ. 9) का कथन है कि *हकवोन* चलाने वालों के लिए सरकारी परमिट प्राप्त करना ज़रूरी है। इसके शिक्षकों के पास कुछ विशेष शैक्षणिक अर्हताएं होनी और शिक्षा केंद्रों में सुरक्षा मानदंड लागू होना अनिवार्य है। विनियमों में यह भी ज़रूरी है कि प्राइवेट ट्यूशन की फीस स्थानीय शिक्षा प्राधिकरण द्वारा संचालित समितियों द्वारा निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए। किम और ली का कथन है (पृष्ठ 9) कि:

यह सशक्त विनियम जापान में जुकु को दी गई ढील से पूरी तरह विपरीत हैं। जापानी सरकार जुकु को किसी अन्य छोटे कारोबार की तरह मानती है और उसे नियंत्रित नहीं करती। तदनुसार, जुकु, जिसमें अनेक प्रकार की निजी शिक्षाएं शामिल हैं और जिसमें शिक्षा की मांग पूरी करने में लचीलापन बरता जाता है, के विपरीत *हकवोन* में काफी कठोर नियम लागू किए गए हैं और यह अधिकतर स्कूलों के समान है।

डिर्क (2008) और मोरी (2008) ने भी यही टिप्पणियां दोहराई हैं। आईआईईपी पॉलिसी फोरम में प्रस्तुत किए गए अन्य उदाहरणों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- ऑस्ट्रिया में, अधिकांश प्राइवेट ट्यूशन ने अकेले छात्र को पढ़ाने वाले गृह-उद्योग का रूप ले लिया है जिसमें विश्वविद्यालय के छात्र, सेवानिवृत्त लोग, और सक्रिय

शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन प्रदान करते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाए गए कानूनों में अध्यापकों को अपने ही छात्रों को प्राइवेट ट्यूशन देने पर प्रतिबंध है (गुबेर, 2007, पृ. 3; गुबेर 2008 भी देखें)।

- भारत में, प्राइवेट ट्यूशन को नियंत्रित करने की कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है किंतु कुछ राज्यों में विनियम लागू किए गए हैं (सुजाता, 2007, पृ. 29-30) जिनमें से अधिकांश में मुख्य धारा के अध्यापकों पर प्राइवेट ट्यूशन प्रदान करने पर पाबंदी है। कुछ राज्यों में, मुख्य धारा के शिक्षक, यदि अधिक आर्थिक कठिनाई में हों, तो मुख्याध्यापक की अनुमति से सीमित मात्रा में प्राइवेट ट्यूशन प्रदान कर सकते हैं। सुजाता का कथन है (पृ. 29) कि “यह बात सर्वविदित है कि शिक्षक खुलकर ट्यूशन देते हैं।” महाराष्ट्र राज्य में, कोचिंग सेंटers को राज्य के राजस्व विभाग में दूकान अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया जाता है, जबकि घरों में शिक्षक भेजने वाली एजेंसियों को चैरिटी कमीशन अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया जाता है। सिद्धांततः, पंजीकरण का प्रत्येक तीन वर्ष बाद नवीनीकरण कराना ज़रूरी होता है, किंतु संबद्ध विभाग और “सरकार द्वारा दी गई ढील के कारण यह नवीनीकरण नहीं कराया जाता।” (सुजाता, 2007, पृ. 30)।
- नमीबिया में, इस तथ्य के बावजूद कि नमीबिया में प्राइवेट ट्यूशन का चलन बढ़ता जा रहा है, वहाँ “अतिरिक्त प्राइवेट ट्यूशन को मार्गदर्शन करने के लिए कोई विनियम नहीं है,” (नघियून्नानये, 2007, पृ. 2)।
- पुर्तगाल सरकार ने 1999 में शिक्षा के क्षेत्र में “सरकारी कार्यों को निजी गतिविधियों के साथ जोड़ना” विषय पर एक विनियम पारित किया था (नेटो-मेंडीज़ एवं कोस्टा, 2007, पृ. 3)। कार्यों को एक-साथ करने की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है, जब “आवेदक द्वारा किया जाने वाला प्रश्नाधीन निजी कार्य, तथा इसी के समान या ऐसा ही सरकारी कार्य एक ही छात्र {शिक्षक के प्रमुख कार्य} के लिए न किया गया हो। 2005 में, एक अधिक विशेष विनियम में कहा गया था कि सरकारी स्कूल के शिक्षक को कोई निजी कार्य करने की अनुमति नहीं होगी - जिसमें निजी अनुपूरक शिक्षा शामिल है - जबकि इस कार्य में शामिल छात्र उसी स्कूल के हों। तथापि, नेटो-मेंडीज़ एवं कोस्टा ने यह भी कहा कि (2007, पृ. 3):

हम जानते हैं कि कानूनी दस्तावेज द्वारा लगाए गए प्रतिबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसाकि हम जानते हैं: वे समाज को राजनीतिक प्राधिकारी द्वारा दी गई चेतावनी के समान हैं जिसमें सम्भावनाएं और प्रतिबंध निर्धारित किए जाते हैं तथापि, उनकी प्रभावकारिता से अनेक शंकाएं उत्पन्न होती हैं, विशेष रूप से तब जब उनके साथ कोई अतिरिक्त उपाय नहीं दिए हों जो एक ओर उक्त निर्देश का लाभ दर्शाते हैं और दूसरी ओर कानूनी निर्देशों को समर्थन देने और लागू करने के लिए स्पष्ट राजनीतिक सहयोग प्रदान करते हैं।

- *सिंगापुर* में, यदि मुख्यधारा का शिक्षक प्रति सप्ताह छः घंटे से अधिक समय तक प्राइवेट ट्यूशन प्रदान करना चाहता है, तो उसे इसकी अनुमति लेनी होगी, शिक्षकों को अपने स्कूल के छात्रों को प्राइवेट ट्यूशन देने पर प्रतिबंध है जिसमें वे कार्य कर रहे हों। तथापि, इन विनियमों को कठोरता से लागू नहीं किया जाता और किसी भी विनियम में प्राइवेट ट्यूशन की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया है (टैन, 2007; टैन, 2009, पृ. 100 भी देखें)।
- *मकाओ* में, 1998 में अनुमोदित कानून में प्राइवेट ट्यूशन केंद्रों के लिए लाइसेंस प्राप्त करना और ऐसे परिसर में कक्षाएं चलाना अनिवार्य है कि जहां स्वच्छता और सुरक्षा के पूरे मानदंडों का पालन किया जाता हो (सोउ, 2007, पृ. 3)। लाइसेंसधारक के लिए एक प्रमाणपत्र जमा कराना अनिवार्य होता है कि उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं चल रहा है; तथा प्राइवेट ट्यूशन केंद्र के दैनिक प्रबंधन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के पास जूनियर कॉलेज या अधिक स्तर की अर्हताएं मौजूद होनी चाहिए। प्राइमरी, जूनियर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षकों की अर्हताएं क्रमशः जूनियर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और उच्च शिक्षा से कम नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट ट्यूशन केंद्रों के लाइसेंस का प्रतिवर्ष नवीनीकरण कराना ज़रूरी है और सरकार के शिक्षा एवं युवा मामलों के ब्यूरो को लाइसेंस के बिना चलने वाले केंद्रों को बंद करने का अधिकार है। पंजीकरण प्रणाली कठिन है और उसका लाभ भी मिलता है, इसलिए जिन निजी शिक्षकों के पास लाइसेंस होते हैं, वे कभी-कभी लाइसेंस-रहित शिक्षकों का नाम भी सरकार के पास दर्ज करा देते हैं।
- *यूगांडा* में, शिक्षा एवं खेल मंत्रालय के पास 'प्राइवेट ट्यूशन की कोई ठोस नीति नहीं है।' (ईलोर, 2007; पृ. 33)। मंत्रालय ने विभिन्न परिपत्र जारी किए, प्राइवेट ट्यूशन में संदर्भ में अपने दायित्वों का दुरुपयोग करने के लिए मुख्य शिक्षकों और शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी और समय-समय पर अभिभावकों से अपील की कि वे प्राइवेट ट्यूशन को रोकने में सरकार को सहयोग दें। तथापि, "प्राइवेट ट्यूशन का संचालन करने वाले विभिन्न प्रबंधकों की भूमिका के बारे में कोई स्पष्ट कानून न होने के कारण, इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए कोई प्रभावकारी तंत्र मौजूद नहीं है" (ईलोर, 2007; पृ. 33)।

इंग्लैंड की पद्धति का उल्लेख करना भी ज़रूरी है। आयरसन (2007ए, पृ. 5) के अनुसार, बाजार में मिलने वाली अधिकांश प्राइवेट ट्यूशन के लिए "कोई भी व्यक्ति सुसंगत अर्हताओं या अनुभवों के बिना भी निजी शिक्षक बन सकता है।" तथापि, सरकार की 'मेकिंग गुड प्रोग्रेस' योजना में इस बारे में विस्तृत विनियम निर्धारित किए गए हैं कि निजी शिक्षक किसे नियुक्त किया जा सकता है और इस शिक्षक को कितना वेतन देना चाहिए। उदाहरण के लिए, हर्टफोर्डशायर के स्थानीय प्राधिकरण द्वारा साधारण जनता के लिए जारी एक सूचनापत्र (2009) में यह उल्लेख किया गया है कि इस योजना के अंतर्गत

नियुक्त निजी शिक्षक के लिए निम्नलिखित अनिवार्यताओं को पूरा करना जरूरी है:

- उसके पास अर्हताप्राप्त शिक्षक की हैसियत (क्यूटीएस) होनी चाहिए, भले ही वह अध्यापक के रूप में कार्य न कर रहा हो;
- अर्हताप्राप्त शिक्षक की हैसियत (क्यूटीएस) प्राप्त करने से पहले वर्ष वह गैर - क्यूटीएस होना चाहिए;
- इंग्लैंड के स्कूलों में पढ़ने के लिए विदेश में प्रशिक्षित अर्हताप्राप्त शिक्षक होना चाहिए; अथवा
- संबद्ध विषय में अर्हताओं के साथ अतिरिक्त शिक्षा या उच्चतर शिक्षा में प्रशिक्षित शिक्षक होना चाहिए।

इस योजना के अंतर्गत नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों को अपराधी रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा दोषमुक्त प्रमाणित किया गया हो और स्थानीय प्राधिकरण या स्कूल के शासी निकाय द्वारा नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों को विशिष्ट वेतनमान के अनुसार वेतन दिया जाना चाहिए जिनमें पेंशन अधिकार भी शामिल होने चाहिए। शर्मा (2009) का कहना है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत:

देश के निजी शिक्षकों की गुप्त सेना, जिनमें से अनेक अतिरिक्त आय के लिए स्कूल में शिक्षक का काम करते हैं... को सरकार के स्कूलों के लिए निर्धारित 'व्यक्तिगत शिक्षा' लक्ष्य को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा।

तथापि, इसी दौरान टैनर, डे, और अन्य, (2009, पृ. 47) ने सामान्य बाजार में मौजूद 103 प्राइवेट ट्यूशन एजेंसियों के सर्वेक्षण में पाया कि केवल 43 प्रतिशत शिक्षा एजेंसियाँ चाहती थी कि उनके निजी शिक्षकों के पास अनिवार्य अर्हताएं या अर्हताप्राप्त शिक्षक की हैसियत (क्यूटीएस) हो, जबकि 79 प्रतिशत ने बताया कि उन्होंने अपने सभी निजी शिक्षकों की अपराधी रिकॉर्ड ब्यूरो से जाँच कराई थी।

इन सभी नियंत्रक उपायों के वर्णन से पता चलता है कि कुछ सरकारें इस मामले को गंभीरता से लेती हैं किंतु अनेक सरकारों ने कोई भी विनियम लागू नहीं किए हैं, कुछ देशों ने अस्पष्ट विनियम बनाए हैं और कुछ देशों ने स्पष्ट विनियम बनाए हैं किंतु उन्हें कठोरता से लागू नहीं किया गया है। सामान्य रूप में, इस क्षेत्र के लिए अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है, जिसे विभिन्न राष्ट्रों की तुलना करके सुगम बनाया जा सकता है। अधिकांश देशों में, मुख्य धारा के अध्यापकों द्वारा अपने निजी छात्रों को प्राइवेट ट्यूशन देने पर प्रतिबंध लगाने पर बल दिया जा सकता है जिनके शिक्षण की जिम्मेदारी उन पर पहले से है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार प्राइवेट ट्यूशन की योजना बनाई गई है और सरकार द्वारा उसे मंजूरी भी दी गई है; फ्रांस और कुछ अन्य देशों में भी इसकी अनुमति है। किंतु इस प्रकार की प्राइवेट ट्यूशन की अनुमति के विरुद्ध यह तर्क दिया जाता है कि इससे भ्रष्टाचार की सम्भावना बढ़ जाएगी, बशर्ते कि सरकार नियमित शिक्षकों के लिए उचित वेतन निर्धारित करे ताकि उन्हें अतिरिक्त आमदनी के लिए प्राइवेट ट्यूशन देने के लिए मजबूर न होना पड़े।

4. निगरानी एवं मूल्यांकन

नीति निर्माताओं को अपने अधिकार क्षेत्र में शिक्षा के सभी प्रकारों पर नज़र रखनी होगी ताकि शिक्षा में मौजूद नियोजित और अनियोजित परिवर्तनों का पता लगाया जा सके। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट नीति कार्यक्रमों का प्रभाव जानने के लिए एक विशेष मूल्यांकन प्रणाली की आवश्यकता होगी। निम्नलिखित भाग में प्राइवेट ट्यूशन के क्षेत्र में हुए अनेक प्रकार के अनुभवों का सारांश दिया गया है। निश्चित रूप से, प्रत्येक स्तर: व्यक्तिगत स्कूल, जिला, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर आंकड़ों की आवश्यकता होती है। पहले भाग में देश में किए गए मूल्यांकन पर ध्यान दिया गया है, जबकि दूसरे भाग में विभिन्न देशों की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

राष्ट्रीय एवं स्थानीय फीडबैक लूप

इस पुस्तक के 'निदान' भाग के आरंभ में यह कहा गया था कि निजी अनुपूरक ट्यूशन के आकार और विस्तार पर शुद्ध आंकड़े संकलित करना बहुत कठिन है। कई कारणों से निजी शिक्षक, छात्र और अभिभावक यह बताना नहीं चाहते कि वह कितनी और किस प्रकार की प्राइवेट ट्यूशन देते, लेते या खरीदते हैं। इसके अतिरिक्त, सामान्य रूप से, विभिन्न मौसमों में प्राइवेट ट्यूशन की अवधि और मात्रा बदलती रहती है और जब इन्हें प्रभावित करने वाले कई अन्य कारण मौजूद हों, तो इसका प्रभाव निर्धारित करना कठिन हो सकता है।

तब भी, इस पुस्तक में दिए गए अनेक अनुसंधान अध्ययनों से पता चलता है कि प्राइवेट ट्यूशन का निगरानी और मूल्यांकन किया जा सकता है। आयरसन का कथन था (2007ए, पृ. 3) कि सामान्य रूप से, शिक्षा संस्थानों के छात्र सूचनाओं का सबसे अच्छा स्रोत होते हैं क्योंकि उन्हें कक्षा में प्रश्नावली देना अपेक्षाकृत आसान होता है। उन्होंने आगे कहा कि:

छात्र सर्वेक्षण से प्राइवेट ट्यूशन के प्रकार और विस्तार, विभिन्न विषयों में प्राइवेट ट्यूशन की लोकप्रियता, प्राप्त की जाने वाली प्राइवेट ट्यूशन की मात्रा और स्कूल के वर्षों के दौरान प्राइवेट ट्यूशन की पद्धति के बारे में काफी मात्रा में उपयोगी सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं। इन सर्वेक्षणों से अक्सर जनसंख्या के बारे में अतिरिक्त सूचनाएं भी प्राप्त होती हैं जिनमें निजी शिक्षक नियुक्त करने के कारणों और प्राइवेट ट्यूशन के बारे में छात्रों की राय से संबंधित प्रश्न शामिल किए जा सकते हैं।

अनुसंधानकर्ता मात्रात्मक सर्वेक्षणों के साथ, अनुपूरक रूप में साक्षात्कार और अन्य गुणात्मक अन्वेषणों का भी प्रयोग कर सकते हैं। गुणात्मक अन्वेषणों से प्राइवेट ट्यूशन के विभिन्न प्रकारों का पता लगाने और उनका वर्गीकरण करने में मदद मिलेगी। हालांकि नियमित नमूनों से उपयोगी व्याख्यात्मक सूचनाएं प्राप्त होती हैं, किंतु विभिन्न देशों में प्राइवेट ट्यूशन की सीमा या प्रवृत्ति की तुलना के लिए वे अधिक महत्वपूर्ण नहीं होते।

आयरसन (2007ए) का यह भी कहना है कि सर्वेक्षणों में पूछे जाने प्रश्नों में, सामान्यतया, उत्तरदाता की सही याददाश्त, जैसेकि प्राइवेट ट्यूशन की मात्रा और लागत के बारे में उसकी स्मृति पर भरोसा किया जाता है। बीते काल की तुलना में प्राइवेट ट्यूशन की वर्तमान स्थिति के प्रश्नों के उत्तर अधिक परिशुद्ध होते हैं। छात्रों से प्राइवेट ट्यूशन पर आने वाली लागत के बारे में प्रश्न पूछने से विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त नहीं हो पाती क्योंकि अक्सर उन्हें अपने माता-पिता द्वारा किए गए भुगतान की जानकारी नहीं होती। इसके अतिरिक्त, जब छात्र अनेक प्रकार की अतिरिक्त कक्षाओं में पढ़ते हैं या अकेले ट्यूशन लेते हैं तो वे फीस का भुगतान करके और निःशुल्क ली गई ट्यूशन का अंतर नहीं समझ पाते।

ऐसे सभी मामलों में, उपलब्ध विकल्पों की विस्तृत जानकारी की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रश्नों को सही शब्दों का प्रयोग करके सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है जिनके सही उत्तर मिलेंगे। छोटे बच्चों से उन्हीं के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्न तैयार करते समय अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। आयरसन (2007ए, पृ. 5) का कहना है कि:

डायरी विधि से छात्रों के उत्तर अधिक शुद्ध हो सकते हैं, क्योंकि इस विधि में मिलने वाली सूचनाएं बीते समय की याददाश्त की तुलना में वास्तविक समय की सूचनाएं होती हैं। किंतु, डायरी पूरी न होने या खो जाने की सम्भावना भी रहती है, जिससे बीती घटनाओं को याद करना कठिन होता है और इस प्रकार प्राप्त होने वाली सूचनाओं की विश्वसनीयता कम हो जाती है। यह विधि सम्भवतया बड़े सर्वेक्षणों के लिए उपयोगी न हो, किंतु इनसे छात्रों के उत्तरों की शुद्धता की जांच की जा सकती है।

माता-पिता सूचनाओं के वैकल्पिक स्रोत होते हैं। उन्हें स्कूल में छात्रों के विशेष समूहों को दी जाने वाली अतिरिक्त कक्षाओं की जानकारी नहीं होती, किंतु वह प्राइवेट ट्यूशन के बारे में भरोसेमंद सूचनाएं प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर वही अपने बच्चों के लिए प्राइवेट ट्यूशन की व्यवस्था करते हैं और जानते हैं कि इस पर कितना खर्च होता है। इंग्लिश स्कूल माता-पिता के नाम और उनका जारी नहीं करते, इसलिए आयरसन ने अपने अनुसंधान के लिए माता-पिता के पास बच्चों के हाथों प्रश्नावली भेजने की रणनीति अपनाई। इस विधि में काफी अनिश्चितताएं थीं, किंतु आयरसन को इससे अपेक्षाकृत काफी अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई, क्योंकि 6 वर्ष की आयु के बच्चों के 38 प्रतिशत माता-पिताओं ने, 9 से 11 वर्ष की आयु के 29 प्रतिशत माता-पिताओं ने प्रश्नों के उत्तर भिजवाए। अन्य देशों के विनियम इतने अधिक प्रतिबंधकारी नहीं हैं, अतः वहाँ दूसरे तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है जिसमें माता-पिता से सीधे सम्पर्क करना शामिल है।

माता-पिता से सूचनाएं प्राप्त करने का दूसरा तरीका घरेलू सर्वेक्षण है। जनगणना जैसी प्रश्नावली में प्राइवेट ट्यूशन को एक मद के रूप में शामिल किया जा सकता है, जैसे वियतनाम लिविंग स्टैंडर्ड सर्वे में किया गया था (डांग, 2007)। तथापि ऐसे सर्वेक्षणों में अनेक सरकारी मंत्रालय अपने निजी प्रश्न शामिल करने की जी-तोड़ कोशिश करते हैं, और प्राइवेट ट्यूशन को प्राथमिकता नहीं माना जाने के कारण, इनमें केवल अत्यधिक

बुनियादी प्रश्नों को ही जगह मिल पाती है। एक अन्य पद्धति टेलीफोन सर्वेक्षण है, जिसका प्रयोग हॉगकाँग (ब्रे एवं क्वोक, 2003, पृ. 614) और इंग्लैंड (पीटर्स और अन्य, 2009, पृ. 2) में किया जाता है। इसमें भी कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे लोग इसे अपने निजी जीवन में हस्तक्षेप समझते हैं या उन्हें प्राइवेट ट्यूशन पर होने वाला खर्च याद नहीं आता और तत्काल इस बारे में कुछ भी बता पाने में असमर्थ रहते हैं, किंतु तब भी उनसे कुछ उपयोगी सूचनाएं मिल सकती हैं।

प्राइवेट ट्यूशन प्रदान करने वाले स्कूल, निजी शिक्षक और प्राइवेट ट्यूशन एजेंसियां भी सूचनाओं के मूल्यवान स्रोत होते हैं। क्रैम (रटार्ड) स्कूलों और ट्यूशन एजेंसियों का विज्ञापनों और स्थानीय डायरेक्टोरियों के माध्यम से असानी से पता लगाया जा सकता है। यह विज्ञापन भी सूचनाओं का महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं - विशेष रूप से तब जब वे 'गारंटी के साथ' अच्छे परिणाम प्राप्त करने का अत्यधिक विश्वास दिलाते हैं। कुछ विज्ञापन उन कंपनियों के होते हैं जिनकी एक से अधिक शाखाएं होती हैं, जबकि अन्य कंपनियां भौगोलिक दृष्टि से सीमित होती हैं और उनके लिए एक राष्ट्रीय छवि बनाना बहुत कठिन होता है। कभी-कभी निजी शिक्षक भी अपना विज्ञापन देते हैं किंतु वे अक्सर छात्रों को केवल व्यक्तिगत सिफारिश पर दाखिला देते हैं और ऐसे मामलों में वे लगभग अदृश्य बने रहते हैं।

आयरसन का कहना है (2007ए, पृ. 5) कि प्राइवेट ट्यूशन की रिपोर्ट देने वाले पत्रकार अक्सर बड़ी एजेंसियों के निदेशकों या कुछेक स्वतंत्र ट्यूटर्स के साथ किए साक्षात्कारों पर भरोसा करते हैं। इन एजेंसियों को अपने कारोबार की पूरी जानकारी होनी चाहिए, किंतु तब भी सावधानी की आवश्यकता होती है:

सर्वप्रथम, पत्रकारों से बात करने के लिए सहर्ष तैयार हो जाने वाला एजेंसी का निदेशक, सम्भवतया अच्छा कारोबार कर रहा हो और वह इस तथ्य का प्रचार करना चाहता हो। इसके अतिरिक्त, एजेंसियां इस प्रकार के प्रचार को मुफ्त विज्ञापन का स्रोत समझती हैं वे जानती हैं कि माता-पिता, यह सोचकर कि शायद ऐसा होना सामान्य है, निजी शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अतः, इस बात पर ज़ोर देना कि उनके कारोबार का विकास हो रहा है, उनके हित में रहता है।

तब भी, ऐसी एजेंसियां पूरी तरह निष्पक्ष होने के बावजूद, प्राइवेट ट्यूशन का सम्पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करतीं।

निगरानी से मूल्यांकन की ओर रुख करते हुए, टेलर (2007, पृ. 11) इंग्लैंड में 2007 में आरंभ की गई *मेकिंग गुड प्रोग्रैस* योजना की रूपरेखा के बारे में बताती हैं। उनका कहना था कि शिक्षा और शिक्षण की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए प्राइवेट ट्यूशन के सत्रों और प्राइवेट ट्यूशन की योजनाओं के नमूने संकलित किए जाएंगे। सभी स्कूलों से प्राइवेट ट्यूशन की अवधि आरंभ और समाप्त होने पर छात्रों की उपलब्धियों के आंकड़े प्रस्तुत प्राप्त किए जाएंगे। प्राइवेट ट्यूशन के अंत में, क्लास टीचर छात्रों की उपलब्धियों के स्तर का आकलन करेंगे। प्राइवेट ट्यूशन प्राप्त करने वाले छात्रों

की उपलब्धियों पर निरंतर नज़र रखने के लिए विभिन्न परीक्षाएं लेने और अध्यापक द्वारा मूल्यांकन आंकड़े प्रस्तुत करने तथा उनकी प्रगति की दूसरे छात्रों के साथ तुलना करने की योजना बनाई गई है। इसी दौरान इस प्रयोग का मूल्यांकन करने के लिए एक सलाहकार संस्था को ठेके पर नियुक्त किया गया जिसे 10 स्थानीय प्राधिकरणों के 450 प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में आयोजित किया गया था (प्रिंसवॉटरहाउस कूपर्स, 2008)। मूल्यांकनकर्ताओं ने अपना प्राथमिक अध्ययन तीन वर्गों में आयोजित किया गया जिसे सारणी 16 में दर्शाया गया है।

सारणी 16. 'मेकिंग गुड प्रोग्रेस' योजना की मूल्यांकन प्रणाली

स्कूल सैम्पल	गतिविधि
डीप डाइव स्कूल प्रत्येक स्थानीय प्राधि करण का एक स्कूल और कुल 6 प्राथमिक और 4 माध्यमिक स्कूल शामिल थे	• प्रत्येक स्कूल का दौरा करके निम्नलिखित कार्य करना: - प्रमुख स्टाफ का साक्षात्कार लेना, जिसमें मुख्याध्यापक, स्कूल पायलट लीडर (एसपीएल), गणित और इंग्लिश विभाग के अध्यक्ष, एक गवर्नर, स्पेशल एडुकेशन निड्स कोऑर्डिनेटर, एक प्रोग्रेशन ट्यूटर और अन्य शिक्षक शामिल हैं। - माध्यमिक स्कूलों में एक छात्र सर्वेक्षण कराना (100 वर्ष 8 छात्र प्रति स्कूल) या प्राथमिक स्कूलों में समूहों में अध्ययन करना (8-10 वर्ष 5 छात्र प्रति स्कूल); - एक लघु (रेचिछक) शिक्षक सर्वेक्षण कराना; • लगभग 100 छात्रों के अभिभावकों/संरक्षकों का सर्वेक्षण कराना और डीप डाइव स्कूलों की सहायता से उसे हार्ड कॉपी में जारी करना; • यह कार्य 8 माह पहले इसी प्रकार किए गए कार्यों या 4 माह पहले मुख्य अध्यापकों या स्कूल पायलट शिक्षकों के साथ टेलीफोन पर किए गए साक्षात्कारों पर आधारित होगा।
लाइट टच स्कूल प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण के चार स्कूल और कुल मिलाकर 20 प्राथमिक स्कूल और 20 माध्यमिक स्कूल शामिल थे	• प्रत्येक स्कूल के मुख्य अध्यापकों या स्कूल पायलट शिक्षकों के साथ टेलीफोन पर साक्षात्कार; • लगभग 100 छात्रों के अभिभावकों/संरक्षकों का सर्वेक्षण कराना और लाइट टच स्कूलों के माध्यम से उसे हार्ड कॉपी में जारी करना; • यह कार्य 8 माह पहले इसी प्रकार किए गए कार्यों पर आधारित होगा (जिसमें प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण में मुख्य अध्यापकों/एसपीएल के साथ टेलीफोन पर साक्षात्कार के स्थान पर सामूहिक विचार-विमर्श का आयोजन किया जाएगा)।
जनसंख्या अन्य सभी पायलट स्कूलों में	• सभी मुख्य अध्यापकों का ई-सर्वे (8 माह पहले भी जारी करना होगा) • प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण के स्कूलों के शिक्षकों के व्यापक अनुभवों का पता लगाने के लिए स्थानीय प्राधिकरण के 10 पायलट शिक्षकों के साथ साक्षात्कार (जिसे पहले 8 और 4 माह पहले भी लेना होगा)।

स्रोत: प्राइसवाटरहाउस कूपर्स (2008), पृ. 6

अन्य देशों की सरकारों के लिए ऐसी परिष्कृत पद्धतियों का प्रयोग करना शायद सम्भव न हो, क्योंकि उनके पास सम्भवतया कुशल कर्मचारियों तथा/अथवा वित्तीय स्रोतों की कमी हो। तब भी, मौजूदा सरकारी मशीनरी द्वारा बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। पुर्तगाल के शिक्षा मंत्रालय ने 2005 में सीनियर सेकेंडरी के छात्रों को राष्ट्रीय

विश्वविद्यालय में पंजीकरण के समय एक सरल प्रश्नावली देने का निर्णय लिया (कोस्टा और अन्य, 2008)। इसमें प्राइवेट ट्यूशन में पढ़ाए जाने वाले विषयों, प्राइवेट ट्यूशन की लागत और निजी कक्षाओं में बिताए गए समय के बारे में प्रश्न पूछे गए। हालांकि यह एक सीमित प्रयोग था - जिसमें उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के सभी छात्रों के स्थान पर केवल उन्हीं छात्रों को शामिल किया गया था, जो विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते थे - तब भी, इससे काफी सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्रश्नावली को कागज पर या ऑनलाइन भरा जा सकता था। इसकी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई क्योंकि इसमें भाग लेने वाले छात्रों को पहले ही परीक्षाओं के पंजीकरण फॉर्म भरने थे, और सम्भवतया कुछेक छात्रों को लगा कि यह प्रपत्र पंजीकरण की विस्तृत प्रक्रिया का ही भाग था।

सरकार विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के साथ भागेदारी करके भी निगरानी और मूल्यांकन को बढ़ा सकती है। ऊपर दी गई मॉरीशस की केस स्टडी में मॉरीशस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा की गई सरकार के आदेश से एक जाँच करने का उल्लेख किया गया है (जॉयनाथसिंह और अन्य, 1988)। इसी प्रकार, 2007 में मकाओ सरकार ने प्राइवेट ट्यूशन प्रणाली और उस पर अभिभावकों की राय जानने के लिए चाइनीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ हाँगकाँग के शोधकर्ताओं के एक दल का गठन किया था (हो, 2008)। ओपन सोसायटी इंस्टीट्यूट ने स्थानीय नीति विचारकों के साथ मिलकर प्राचीन समाजवादी ब्लॉक में प्राइवेट ट्यूशन का अन्वेषण किया (सिलोवा और अन्य, 2006; सिलोवा, 2009)। सरकार विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए स्वतंत्र अनुसंधानों से, तथा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा किए गए अध्ययनों से भी लाभ उठा सकती है (देवें, यूनेस्को, 2000; वर्ल्ड बैंक, 2004)।

यहाँ यह उल्लेख करना भी ज़रूरी है कि यूगांडा और बोत्सवाना में किए गए आरंभिक अन्वेषण स्वयं आईआईईपी पॉलिसी फोरम से प्रोत्साहित थे। (ईलोर, 2007; मैकगोटी, 2007)। आईआईईपी आगे भी इन कार्यों में सहयोग करने में प्रसन्नता होगी।

अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्किंग

विभिन्न राष्ट्रों में किए गए तुलनात्मक सर्वेक्षणों से राष्ट्रीय नीति निर्माताओं और योजनाकारों को न केवल विभिन्न देशों के विशेष आंकड़े प्राप्त होते हैं, किंतु अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्किंग की सुविधा भी मिलती है। इनमें से चार सर्वेक्षण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ एडुकेशनल अचीवमेंट (आईईए) के तत्वाधान में थर्ड इंटरनेशनल मैथेमैटिक्स एंड साइंस स्टडी (टीआईएमएसएस-टिम्स) और इसके पश्चात् ट्रेन्स इन इंटरनेशनल मैथेमैटिक्स एंड साइंस स्टडी (इसे भी टीआईएमएसएस-टिम्स ही कहा जाता है) आयोजित किए गए। वर्ष 1995 में हुए टिम्स परीक्षण के पहले दौर में 45 देशों के पाँच आयु वर्गों और कक्षाओं के 500,000 छात्रों और उनके शिक्षकों और मुख्य अध्यापकों से आंकड़े संकलित किए गए (मार्टिन, 1996,

पृ. 1-2)। दूसरा दौर 1999 में आयोजित किया गया और इसमें 38 देशों के आठवीं कक्षा के गणित और विज्ञान के छात्रों पर ध्यान दिया गया (रोबिटेल् एवं बीटन, 2002, पृ. 11)। 2003 में आयोजित तीसरे राउंड में 49 देशों के कक्षा 4 और कक्षा 8 के छात्रों से तुलनात्मक आंकड़े संकलित किए गए (मुलिस, मार्टिन, और अन्य, 2005, पृ. 3-4)।

इन अध्ययनों से अन्य बातों के अतिरिक्त प्रतिच्छाया प्रणाली पर बहुत शिक्षाप्रद सूचनाएं प्राप्त हुई (बेकर, अकीबा और अन्य, 2001; वुल्फ, 2002; बेकर एवं लीतेद्रे, 2005)। यह सर्वेक्षण बहुआयामी थे, अतः विश्लेषणकों के लिए विभिन्न परिवर्तियों के बीच परस्पर विविध संबंध स्थापित कर पाना सम्भव था। किंतु, उन्हें कार्य प्रणाली से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वर्ष 1995 के सर्वेक्षण में गणित की निजी कक्षाओं के बारे में कक्षा 7 और 8 के छात्रों से पूछा गया: “सप्ताह के दौरान, स्कूल से पहले और बाद में आप गणित की अतिरिक्त पढ़ाई में/ट्यूशन स्कूल में कितना समय बिताते हैं?” (टिम्स, 1998, पृ. एसक्यू 2-3)। विज्ञान के बारे में भी ऐसा ही प्रश्न पूछा गया। इन प्रश्नों के उत्तरों में स्पष्ट रूप से प्राइवेट ट्यूशन के अतिरिक्त अन्य सूचनाएं भी शामिल थीं, जिसमें शिक्षकों द्वारा अपने सामान्य कार्यभार के एक भाग के रूप में, अवैतनिक आधार पर अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित करना शामिल था। इसके अतिरिक्त, केवल ‘सप्ताह के दौरान’ अतिरिक्त कक्षाओं के बारे में पूछे गए प्रश्न में मौसम के अनुसार होने वाले परिवर्तनों को शामिल नहीं किया गया था। 2003 के सर्वेक्षण में, कक्षा 8 से पूछे गए प्रश्नों को संशोधित करके यह पूछा गया कि: “इस वर्ष स्कूल में आपने निम्नलिखित विषयों में अतिरिक्त कक्षाओं या निजी कक्षाओं में कितनी बार पढ़ाई की, जो आपकी नियमित कक्षाओं में शामिल नहीं थीं” (टिम्स, 2003, पृ. 27)। इसके बाद, छात्रों से गणित, जीव विज्ञान, भू विज्ञान, रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र के बारे में प्रश्न पूछे गए और उन्हें “प्रतिदिन या लगभग प्रतिदिन”, “सप्ताह में एक या दो बार”, “कभी-कभी” तथा “कभी नहीं या लगभग कभी नहीं” के विकल्प दिए गए। पूरे शैक्षणिक वर्ष पर ध्यान देने से, मौसमी परिवर्तनों का आकलन करने की समस्या कम हो गई, किंतु शायद यह पूरी तरह समाप्त नहीं हुई क्योंकि उत्तरदाता छात्रों को अधिकतम और न्यूनतम प्राइवेट ट्यूशन के मौसमों के बीच औसत निकालनी पड़ती, और इन प्रश्नों में निःशुल्क या सःशुल्क प्राइवेट ट्यूशन को अलग नहीं किया जा सकता था।

दूसरा नियमित सर्वेक्षण सदरन एंड ईस्टर्न एफ्रीका कंसोर्टियम फॉर मॉनीटरिंग एडुकेशनल क्वालिटी (सैकमेक) सर्वेक्षण है, जिस पर प्रकाश डालना ज़रूरी है। वर्ष 1995 और 2000 में, सैकमेक ने छः शिक्षा प्रणालियों के प्राइवेट ट्यूशन प्राप्त करने वाले कक्षा 6 के छात्रों द्वारा ली जाने वाली अतिरिक्त कक्षाओं के बारे में डाटा संकलित किया (ऊपर दी गई सारणी 3 देखें)। एक बार फिर, संकलित आंकड़े स्पष्ट नहीं थे क्योंकि कुछ प्रत्यार्थियों ने निःशुल्क कक्षाओं को सःशुल्क ट्यूशनों के साथ शामिल कर लिया था। विश्लेषण को अधिक शुद्ध बनाने के लिए, 2007 के संस्करण की प्रश्नावली में, जिसे 15 देशों में भेजा

गया, अधिक परिशुद्ध और संक्षिप्त प्रश्न पूछे गए जिनकी पहले ही जाँच कर ली गई थी (पेवियट, 2007; 2009)। इस सर्वेक्षण में कुल 13 प्रश्न पूछे गए, जिनका उत्तर देने के लिए एक से अधिक विकल्प दिए गए थे:

1. क्या आपने इस शैक्षणिक वर्ष में, स्कूल के निर्धारित समय के अतिरिक्त, स्कूल में पढ़ाए जाने वाले विषयों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं में भाग लिया?
2. इस शैक्षणिक वर्ष में, आपने स्कूल के निर्धारित समय के अतिरिक्त, किन विषयों में अतिरिक्त कक्षाओं में भाग लिया?
3. इस शैक्षणिक वर्ष में आपने इन अतिरिक्त कक्षाओं में किस समय पढ़ाई की?
4. इस शैक्षणिक वर्ष में आपने कितनी बार अतिरिक्त कक्षाओं में भाग लिया?
5. इस शैक्षणिक वर्ष में अक्सर कितने छात्र (आपको मिलाकर) इन अतिरिक्त कक्षाओं में उपस्थित रहे?
6. इस शैक्षणिक वर्ष के दौरान आपने प्रति सप्ताह लगभग कितने घंटे इन अतिरिक्त कक्षाओं में पढ़ाई की?
7. इस शैक्षणिक वर्ष के दौरान आप इन अतिरिक्त कक्षाओं में क्या करते थे?
8. इस शैक्षणिक वर्ष में आपकी अतिरिक्त कक्षाएं किसने लीं?
9. इस शैक्षणिक वर्ष के दौरान यह अतिरिक्त कक्षाएं कहां होती थीं?
10. आपसे अतिरिक्त कक्षाओं में भाग लेने के लिए किसने कहा?
11. इन अतिरिक्त कक्षाओं में भाग लेने का प्रमुख कारण क्या था?
12. आप इन अतिरिक्त कक्षाओं के बारे में क्या सोचते हैं?
13. क्या आपने अतिरिक्त कक्षाएं लेने वाले व्यक्ति को फीस का भुगतान किया था?

फीस के भुगतान का प्रश्न, और इस आधार पर अतिरिक्त कक्षाओं को, सार्वजनिक या स्वैच्छिक ट्यूशन के स्थान पर प्राइवेट ट्यूशन में वर्गीकृत करने का प्रश्न सबसे अंत में आता है। शोधकर्ता जानते हैं कि ऐसी अस्पष्टता सदैव बनी रहेगी। कक्षा 6 के छात्रों में शायद यह समझ ही नहीं थी कि पढ़ाई के लिए भुगतान करने की आवश्यकता होती है या नहीं; इसलिए उनसे भुगतान की मात्रा के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। जिन छात्रों ने भुगतान के बारे में बताया, उनसे पूछा गया कि “क्या यह भुगतान धन के रूप में किया गया था या किसी अन्य वस्तु के रूप में, या संयुक्त रूप से दोनों में किया गया था।” (पेवियट, 2007, पृ. 15)। तथापि, सैकमेक वैज्ञानिक समिति ने इस विषय पर आगे न बढ़ने का फैसला किया और यह माना कि “भुगतान का प्रश्न बहुत संवेदनशील और विवादास्पद था।” राष्ट्रों के तुलनात्मक अध्ययनों में सबसे बड़ी चुनौती अलग-अलग राष्ट्रों की संवेदनशीलताओं का ध्यान रखने की होती है, अन्यथा इन अध्ययनों का महत्त्व कम हो जाता है।

तीसरा बहु-राष्ट्रीय अध्ययन, जिसका उल्लेख पहले भी किया जा चुका है, ओपन सोसायटी इंस्टीट्यूट (ओएसआई) द्वारा किया गया था। 2004-2005 तक चले इस अध्ययन में 9 देशों को शामिल किया गया था (सिलोवा और अन्य, 2009) और इसके

बाद 2005 - 2006 में, इसी विधि द्वारा किए गए अध्ययन में तीन देशों को शामिल किया गया (सिलोवा)। वर्ष 2007 में, ओएसआई ने इस अवधि में हुए परिवर्तनों का पता लगाने के लिए इस अध्ययन को दोबारा दोहराने का निर्णय लिया। टिम्स एवं सैकमेक अध्ययनों के विपरीत, जिनमें प्राथमिक और निम्न माध्यमिक कक्षाओं पर ध्यान दिया गया था, इन सर्वेक्षणों में विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष के छात्रों से प्रश्न पूछे गए और उनसे माध्यमिक स्कूल में अंतिम वर्ष में अपनी प्राइवेट ट्यूशन के अनुभव बताने को कहा गया। इन छात्रों की आयु अधिक होने के कारण उनके उत्तर अधिक शुद्ध होने की आशा थी। टिम्स अध्ययनों में 12 देशों में से केवल 2 देशों (लिथुआनिया और स्लोवाकिया) को शामिल किया गया, किंतु यहाँ निष्कर्षों की तुलना करना सम्भव था जिससे शिक्षा प्रणाली में शामिल विभिन्न स्थितियों की स्पष्ट तस्वीर उभरकर सामने आ सकती थी।

चौथा बड़ा और उल्लेखनीय बहु-राष्ट्रीय सर्वेक्षण प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट (पीसा) है जिसे ऑर्गनाइज़ेशन फॉर इकोनॉमिक को-ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (ओईसीडी) द्वारा आयोजित किया गया था। पीसा ने विभिन्न शिक्षा प्रणालियों के 15 वर्ष आयु के छात्रों की शिक्षा उपलब्धियों की जांच की (2000 में 43, 2003 में 41, और 2006 में 58)। 2006 के सर्वेक्षण में अभिभावकों की प्रश्नावली में पूरे परिवार की शिक्षा में होने वाले खर्च के आंकड़े शामिल किए गए किंतु प्राइवेट ट्यूशन पर होने वाले खर्च को अन्य मदों के खर्च से अलग नहीं रखा गया और छात्रों की प्रश्नावली में स्कूल के पश्चात् निजी कक्षाओं के बारे में सूचनाएं एकत्र की गई, किंतु इसमें निजी शिक्षकों की कक्षाओं और अन्य कक्षाओं में कोई अंतर नहीं रखा गया (ओईसीडी 2005, 2006बी)। पीसा दल ने अपने भावी सर्वेक्षणों में प्राइवेट ट्यूशन पर अधिक विस्तृत आंकड़े संकलित करने की योजना बनाई, किंतु वैचारिक और तार्किक चुनौतियों का ध्यान रखा।

5. निष्कर्ष

इस अंतिम अध्याय का आरंभ हम इस टिप्पणी के साथ कर रहे हैं कि प्राइवेट द्यूशन पूरी दुनिया में पाई जाती है, जिसमें अलग-अलग देशों के अनुरूप भिन्नता पाई जाती है। हाल ही के दशकों में इसका काफी विस्तार हुआ है और धीरे-धीरे इसने एक स्वत्वाधिकार पद्धति का रूप ले लिया है। इन तथ्यों के कारण इस ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। नीति निर्माताओं और योजनाकारों को प्रतिच्छाया शिक्षा प्रणाली से निपटना होगा ताकि इसे नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त प्रक्रियाओं और अधिक सक्रिय उपायों का पता लगाया जा सके। उनका उद्देश्य केवल इसे नियंत्रित करना और सही मार्ग दिखाना ही नहीं होना चाहिए, अपितु नीति निर्माता और योजनाकार प्रतिच्छाया प्रणाली से काफी कुछ सीख भी सकते हैं।

रुझानों का पता लगाना

2007 आईआईईपी पॉलिसी फोरम के समापन के समय अपने विचार प्रस्तुत करते समय ओबीगाडू (2007, पृ. 6) ने टिप्पणी की थी कि प्राइवेट द्यूशन “का विस्तार सभी देशों और संस्कृतियों में तेजी से फैल रहा है। पूर्व हो या पश्चिम, धनी हों या निर्धन सभी देशों में धीरे-धीरे शिक्षा का बाजारीकरण और निजीकरण अपने पैर पसार रहा है।” अन्य भागीदारों ने भी इन्हीं उद्गारों को दोहराया। कुछ सीमा तक प्राइवेट द्यूशन का कारोबार छिपकर किया जाता था (देखें सिलोवा और अन्य, 2006); किंतु अब यह कारोबार गोपनीय नहीं रहा है। अब, प्राइवेट द्यूशन कारोबार अंधेरे कोने से निकलकर उजाले में आ रहा है।

पश्चिमी यूरोप से लेकर पूर्वी एशिया तक, अनेक संस्कृतियों में प्राइवेट द्यूशन की जड़ें काफी गहराई तक फैली हुई हैं। बीसवीं सदी के दूसरे भाग तक, निजी शिक्षा का प्रसार काफी कम था। इसके बाद, जापान और कोरिया में इसका महत्त्व बढ़ने लगा तथा सदी के अंत तक अज़रबैज़न, कंबोडिया, मॉरीशस और श्रीलंका जैसे देशों में इसने प्रमुख स्थान ले लिया। इक्कीसवीं सदी के आरंभ में, पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में निजी शिक्षा का विस्तार बढ़ने लगा और धीरे-धीरे पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमरीका, ऑस्ट्रेलेशिया और अफ्रीका में भी इसका प्रभाव दिखाई देने लगा।

अलग-अलग स्थानों पर, अलग-अलग परिस्थितियों ने इसकी वृद्धि को बढ़ावा दिया। उदाहरण के लिए, जॉर्जिया, किर्गीस्तान, और तज़ाकिस्तान में इसके प्रसार का मुख्य कारण प्रमुख धारा के शिक्षकों का कम वेतन था जिसने उन्हें अपने परिवारों का लालन-पालन करने के लिए आय के अतिरिक्त स्रोत ढूँढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। इसकी तुलना में हॉंग कांग, कोरिया, जापान और सिंगापुर के शिक्षकों का वेतन अपेक्षाकृत काफी अच्छा था

तथा उन्हें सामाजिक प्रतिस्पर्द्धा और भावी सफलताओं की कामना ने निजी शिक्षा देने के लिए मजबूर किया जिन्हें नई पीढ़ी के लिए निजी शिक्षा में निवेश द्वारा हासिल किया जा सकता था। अमरीका और इंग्लैंड में, कुछ सीमा तक, निजी शिक्षा सरकारी कार्यक्रमों के कारण प्रचलित हुई जिनका उद्देश्य स्कूलों को अधिक प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाना और कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का स्तर ऊंचा उठाना था; तथा यूगांडा और मलावी में प्राईवेट ट्यूशन के प्रसार का कारण यह रहा कि शिक्षा प्रणाली के स्तर में गिरावट आ रही थी।

शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट की एक विडम्बनापूर्ण स्थिति यह भी है कि कुछ स्थानों में सरकार द्वारा निःशुल्क प्राथमिक या निम्न माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने से भी शिक्षा के स्तर में गिरावट आती है। तब होता यह है कि सरकारी तौर पर सार्वजनिक प्रणाली में शिक्षा निःशुल्क होती है किंतु मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली को छिपे तौर पर एक गुप्त निजीकरण का सहारा मिलने लगता है जो सामाजिक असमानताएं बनाए रखता है। आईआईईपी पॉलिसी फोरम के दौरान, कितेव (2007, पृ. 3) ने इस विडम्बना की ओर ध्यान दिलाया। निजी शिक्षा की उत्तरोत्तर वृद्धि से, जिससे पता चलता है कि कम-से-कम कुछ अभिभावक शिक्षा प्रणाली 'निःशुल्क' होने पर भी शिक्षा के लिए खर्च करते हैं और खर्च कर सकते हैं, यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या सभी के लिए मुफ्त शिक्षा का मूल सिद्धांत अभी भी वैध है। बोत्सवाना सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लिया और इस आधार पर माध्यमिक स्तर पर दोबारा फीस लेना शुरू कर दिया कि कम-से-कम कुछ अभिभावक इसका भुगतान कर सकते हैं; और निःशुल्क शिक्षा के संसाधन ऐसे क्षेत्रों में उपलब्ध कराए जिन्हें इसकी अधिक आवश्यकता थी।

ओबीगाडो (2007, पृ. 6) ने निजी शिक्षा की बढ़ती मांग और बढ़ती सप्लाई पर भी टिप्पणी की है। बढ़ती मांग के संदर्भ में, उनका कहना है, कि:

ज्ञान के वर्तमान युग में, विशेष रूप से व्यक्ति को जीवन में मिलने वाले अवसरों और समुदाय की सामाजिक और आर्थिक प्रगति को शिक्षा और शैक्षणिक सफलता से निर्धारित किया जाता है। श्रम बाजारों में परिवर्तन होने से प्रौद्योगिकी पर संचालित अर्थव्यवस्था में विविध कुशलताओं की आवश्यकता होने लगी है, जिसके कारण जनता शिक्षा के विभिन्न अवसरों और मार्गों के तलाश रही है।

साथ ही, निजी शिक्षा में न केवल इसलिए वृद्धि हुई है कि समाज ने इसे स्वीकार कर लिया है अपितु इसका एक कारण बढ़ता हुआ वैश्वीकरण भी है, जिसमें आउटसोर्सिंग को भी मान्यता मिली है (उदाहरण के लिए, देखें नंदा, 2005; मरलांटीज़ एवं सुनोल, 2006; वेंचुरा, 2008ए)। अब, प्रत्यक्ष रूप से इंटरनेट द्वारा दूसरे देशों में भी ट्यूशन प्रदान की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, ओबीगाडो इसके लिए उपभोक्तावाद को भी उत्तरदायी मानते हैं, जो “शिक्षकों में, अपनी व्यावसायिक सफलता को मापने के लिए अधिक धन कमाने की ललक पैदा करता है और शिक्षा व्यवसाय में उद्यम की संस्कृति को बढ़ावा देता है।” निश्चित रूप से, अनेक देशों में शिक्षा व्यवसाय की संस्कृति में बहुत परिवर्तन हुए हैं,

जिसका कारण या तो सरकारी कार्यक्रम हैं जो शिक्षा को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाना चाहते हैं अथवा शिक्षकों और परिवारों के बाजारी संकेतों के प्रति प्रतिक्रिया है।

इन परिस्थितियों में, निजी शिक्षा को समाप्त करना आसान नहीं होगा। कुछ नीति निर्माता और योजनाकार इसे अनदेखा करते रहे हैं, किंतु अब ऐसा करना सम्भव नहीं होगा। इसके कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं की जानकारी के बाद भी विशेष नीतियां तैयार करना आसान नहीं होगा। निजी शिक्षा एक बहुत जटिल प्रक्रिया है जिसमें अनेक कारण और अनेक घटक शामिल हैं जिनमें विभिन्न संस्कृतियों, अर्थव्यवस्थाओं, भौगोलिक क्षेत्रों और सामाजिक वर्गों के अनुरूप काफी अंतर पाया जाता है। इसके अतिरिक्त, यह तथ्य कि कोरिया और मॉरीशस के प्राधिकारी कई दशकों से इस समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें बहुत कम सफलता मिल पाई है, अभिन्नदनीय है। इन मामलों से पता चलता है कि निजी शिक्षा पद्धति का आकार बढ़ने से पहले ही इसे नियंत्रित करने के लिए ठोस नीतियों की आवश्यकता होगी, कहीं ऐसा न हो कि हम नीतियां बनाते रह जाएं और यह समाज में जड़ें जमा ले। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देशों में सचेत रहने की आवश्यकता पर भी बल दिया जहाँ कम अंक पाने वाले छात्रों के लिए निजी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के सरकार के सु-विचारित कार्यक्रम अप्रत्याशित रूप में स्कूली शिक्षा प्रणाली की संस्कृति को बदल सकते हैं।

आईआईईपी पॉलिसी फोरम के दौरान अनेक सहभागी ओबीगाडू (2007, पृ. 6) की इस टिप्पणी से सहमत थे कि जहाँ तक सम्भव हो, निजी शिक्षा में प्रसार की गति को:

औपचारिक शिक्षा प्रणाली में दिखाई देने वाली कमियों और दोषों को दूर करके रोकना और नियंत्रित करना अधिक उपयोगी होगा। राष्ट्रीय संदर्भों और वास्तविकताओं के आधार पर, नीति विकल्पों में प्रतिष्ठा के प्रतीक परीक्षाओं को समाप्त करना, शिक्षा सेवाएं प्रदान करने के बेहतर तरीके अपनाना, शिक्षा के लिए अधिक विकल्प और विविध अवसर उपलब्ध कराना, जिसमें निजी कार्यवाहियों को सुगम बनाना, इत्यादि शामिल है।

शिक्षाप्रद रूप में, यह ज़रूरी नहीं कि सरकार द्वारा शिक्षा पर अधिक खर्च करने से परिवारों द्वारा निजी शिक्षा पर किया जाने वाला खर्च कम हो जाएगा। इसके विपरीत, निश्चित रूप से मुख्य धारा की शिक्षा के सरकारी विस्तार से प्रतिच्छाया प्रणाली का विस्तार होने की सम्भावनाएं बढ़ जाएंगी। अतः बहुत कुछ परिवार की प्रयोज्य आय पर और इससे भी अधिक, सामान्य शिक्षा और विशेष रूप से निजी शिक्षा के बारे में परिवारों के आचरण पर निर्भर करेगा। अनेक परिवार अपने बच्चे को जीवन में आगे बढ़ने के अधिक-से-अधिक अवसर देने के लिए प्रत्येक संभव मार्ग का प्रयोग करना उचित समझते हैं और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ देशों में, गैर-शैक्षिक विषयों, जैसे नृत्य, पियानो बजाने या धार्मिक संबंधी शिक्षा लेने से अधिक सफलता हासिल की जा सकती है, किंतु दूसरे देशों में मूल रूप से गणित, भाषाओं और विज्ञान पर अधिक

ध्यान देकर, मुख्य धारा की शिक्षा के साथ अनुपूरक विषयों की शिक्षा प्राप्त करना सर्वश्रेष्ठ निवेश माना जाता है।

प्राइवेट ट्यूशन पहले ही इतनी लोकप्रिय हो चुकी है कि इस पर सामान्य प्रतिबंध लगाना उचित और कारगर नहीं होगा। किसी भी स्थान पर पूर्ण प्रतिबंध सफल नहीं हुआ है, तथापि मुख्य धारा के शिक्षकों द्वारा अपने ही छात्रों को प्राइवेट ट्यूशन प्रदान करने पर प्रतिबंध लगाना उपयोगी हो सकता है। अधिकांश देशों में, निजी शिक्षा का अधिक सूक्ष्मता से और एक से अधिक तरीकों से मुकाबला करना होगा। प्राइवेट ट्यूशन के सबसे अधिक अनुचित और सामाजिक दृष्टि से अनौचित्यपूर्ण पहलुओं का विनियमों द्वारा मुकाबला करना होगा। इसके साथ-साथ, सरकार को स्वयं इस क्षेत्र में हस्तक्षेप करना होगा और कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को सहयोग देना होगा - किंतु इससे पहले इन सरकारों को स्कूली शिक्षा प्रणाली तथा अभिभावकों, शिक्षकों और अन्य लोगों पर पड़ने वाले व्यापक प्रभावों पर भी विचार करना होगा।

प्रतिच्छाया शिक्षा प्रणाली से सबक

नीति निर्माताओं और योजनाकारों को ट्यूशन को केवल नकारात्मक रूप में - सुंदर उद्यान को नष्ट करने वाली खरपतवार के रूप में ही नहीं देखना चाहिए। बल्कि उन्हें यह सवाल पूछना चाहिए कि माता-पिता मुख्य धारा से प्राप्त होने वाली शिक्षा के साथ-साथ अपना काफी धन अनुपूरक शिक्षा में खर्च करने के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं। कुछ माता-पिता अपने बच्चों को शिक्षक से अकेले क्यों पढ़ाना चाहते हैं; और कुछ दूसरे माता-पिता ऐसी प्राइवेट ट्यूशन के लिए धन खर्च करने के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं जिसमें 100 या कभी-कभी 1000 तक छात्र एकसाथ पढ़ते हैं? मुख्य धारा के स्कूल इससे क्या सबक ले सकते हैं कि कुछ महीनों में उनकी कक्षाएं बिल्कुल खाली रहती हैं, और छात्र स्कूल के स्थान पर ट्यूशन केंद्रों में जाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए रिश्वत तक देने के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं? और नीति निर्माता प्रौद्योगिकी में माहिर ट्यूटोरों से क्या सबक ले सकते हैं जो वीडियो पर ट्यूटोरियल बनाकर बेचते हैं जिन्हें कंप्यूटरों या मोबाइल, इत्यादि उपकरणों पर डाउनलोड किया जा सकता है और जिसे छात्र सबवे में, पार्क में, स्कूल में या घर पर आराम से बैठकर देख सकते हैं।

इन प्रश्नों का एक उत्तर यह है कि कम-से-कम कुछ संस्कृतियों में प्राइवेट ट्यूटर अधिक साहसी होते हैं और ग्राहक बनाने के लिए उत्सुक रहते हैं। ग्लासमैन (2007) का कहना है कि फ्रांस के निजी शिक्षक स्वयं को अधिक पारदर्शी मानते हैं, और स्कूल की तुलना में अधिक तत्परता से और अधिक व्याख्यात्मक उत्तर देते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य धारा की शिक्षा में कम अंक पाने वाले छात्रों से अगले साल भी दोबारा उसी कक्षा में बैठने के लिए कहा जाता है। इसके विपरीत, एक निजी शिक्षा कंपनी यह घोषित करती है कि यदि उनके छात्रों के अच्छे अंक नहीं आए तो माता-पिता अपनी धनराशि वापिस ले

सकते हैं अथवा उनके बच्चे को अगले वर्ष मुफ्त पढ़ाया जाएगा। किम ने देखा (2007, पृ. 12) कि कोरिया में, विशेष उच्चतर स्कूलों में आवेदन देने वाले:

... छात्रों को उनकी योग्यता पर ध्यान दिए बिना एक साथ पढ़ाने वाले स्कूलों की तुलना में, ऐसे प्राइवेट संस्थानों में शिक्षा दिलाना लाभदायक समझते हैं जहाँ छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार अलग समूहों में पढ़ाया जाता है और अलग पाठ्यक्रम का प्रयोग किया जाता है। माताएं चाहती हैं कि उनके बच्चे को व्यक्तिगत देखभाल मिले, जिसमें न केवल छात्र के व्यवहार का, अपितु उसकी शैक्षणिक उपलब्धियों का भी ध्यान रखा जाए। प्राइवेट संस्थानों में दी जाने वाली व्यक्तिगत देखभाल लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने और प्राइवेट संस्थानों पर उनका भरोसा बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण आधार है।

किम ने कहा कि आंशिक रूप से यह रुझान कोरियाई परिवारों की विचारधारा में हुए परिवर्तन से संबद्ध है। माता-पिता दोनों के काम पर चले जाने और भौगोलिक गतिशीलता में वृद्धि होने के कारण, जिसका तात्पर्य है कि दादा-दादी भी अपने नाती-पोतों के साथ नहीं रह पाएंगे, माता-पिता को लगता है कि प्राइवेट ट्यूशन केंद्रों में उनके बच्चों को व्यक्तिगत देखभाल मिलेगी जो अब उन्हें परिवार में नहीं मिल पाती और शायद स्कूलों में तो कभी नहीं मिलेगी।

यह तथ्य कि कोरिया में पाठों को डाउनलोड करने वाली ट्यूशन की प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध है, एक भिन्न दिशा की ओर संकेत करता है जो नीति निर्माताओं को उलझन में डाल सकता है। चो (2009, पृ. 14) ने बताया कि कोरिया में इंटरनेट को 10 गुना तीव्र बनाने के लिए लाखों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। यह सच्चाई कि अब डाउनलोड किए गए पाठ के किसी भाग को आवश्यकतानुसार छोड़ सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं और किसी भी भाग को कई बार दोबारा देख सकते हैं, छात्रों को ऐसी आरामदायक सुविधा दे दी है जो उन्हें आमने-सामने दी जाने वाली निजी शिक्षा में भी नहीं मिलती। शीघ्र ही ऑनलाइन या आमने-सामने दी जाने वाली शिक्षा के स्थान पर प्रयोग ऑफलाइन पाठों का प्रयोग होने लगेगा। निश्चित रूप से, ऐसे ऑफलाइन पाठ सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र भी उपलब्ध करा सकता है, किंतु इस समय निजी क्षेत्र इस दिशा में काफी आगे बढ़ चुका है। निजी शिक्षा का कारोबार करने वाली एक प्रमुख इंटरनेट कंपनी ने (चो, 2009, पृ. 4 पर उद्धृत) सुझाव दिया कि भविष्य में शायद छात्र केवल खेलकूद जैसी सामूहिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए ही, सप्ताह में (केवल) एक बार ही स्कूल जाएंगे।” सम्भवतया यह एक अतिशयोक्तिपूर्ण भविष्यवाणी है, किंतु निश्चित रूप से यह कुछ विशेष प्रकार के वातावरणों में रहने वाले विशेष छात्रों-विशेष रूप से परीक्षाओं के मौसम में अत्यधिक जोश दिखाने वाले छात्रों पर सही बैठती है।

तथापि, अन्य परिस्थितियों में निजी शिक्षा स्कूल, मानवीय सम्पर्क को घटाने के स्थान पर बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और एक भिन्न प्रकार की सेवा प्रदान कर रहे हैं। सोऊ (2007, पृ. 4) ने मकाओ के संदर्भ में परिवारों के बदलते स्वरूप का उल्लेख किया है जहाँ अधिक से अधिक निजी शिक्षा केंद्र “एक ही साथ” बच्चों की देखभाल या चाइल्ड-केयर की सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं।

स्कूल के बाद दोपहर के समय निजी शिक्षा केंद्र बच्चों स्कूल से निजी शिक्षा केंद्र ले जाने, और दोपहर का भोजन खिलाने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद दोपहर के शेष घंटों की पढ़ाई के लिए बच्चों को वापिस स्कूल ले जाया जाता है। स्कूल के बाद बच्चों को दोबारा निजी शिक्षा केंद्र लाया जाता है और जब तक उनके माता-पिता काम से लौटकर उन्हें घर ले जाने के लिए नहीं आते, उनके गृहकार्य में मदद की जाती है।

इसका कोई ठोस कारण नहीं है कि इन आवश्यकताओं को स्कूल स्वयं क्यों नहीं पूरा कर सकते। इंग्लैंड में सरकार स्कूल का समय प्रातःकाल 8.00 बजे से सायंकाल 6.00 बजे तक बढ़ाने का प्रयोग कर रही है, और कई स्कूलों में पहले ही दोपहर के भोजन के समय शिक्षक बच्चों का ध्यान रखते हैं। मकाओ में, सरकार ने 2002 में एक स्कूल कम्प्युनिकेशन योजना शुरू की थी जिसमें स्कूल ने समुदाय को कुछ अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान कीं। इसके अतिरिक्त, मकाओ में बड़े छात्रों के लिए अध्ययन कक्षों का आयोजन किया गया जिनके संचालन का काम नागरिक संगठनों को सौंपा गया; और 1997 से मकाओ सरकार गृहकार्य के बारे में निर्देश देने के लिए टेलीफोन सेवा का प्रयोग कर रही है (सोऊ, 2007, पृ. 9)

स्कूलों और निजी शिक्षा केंद्रों की अदला-बदली के संबंध में हार्टमैन ने मिस्र में किए गए अपने अध्ययन में एक छात्र की तीखी टिप्पणी का उल्लेख किया गया है (2008, पृ. 57) जिसका कहना था कि उसके अंक कम आने का कारण उसका नियमित रूप से स्कूल जाना था। “यदि मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया होता और केवल निजी शिक्षा लेता तो अधिक अच्छा रहता।” निश्चित रूप से यह छात्र इस मामले को केवल अपने संकीर्ण दृष्टिकोण से देख रहा था, किंतु स्कूली शिक्षा के बारे में सरकार के लक्ष्य अधिक व्यापक होते हैं जिनमें समाजीकरण, राष्ट्र-निर्माण और खेलकूद तथा शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ छात्र का संतुलित विकास भी शामिल होता है। तब भी, शिक्षा अधिकारी विवेकपूर्ण ढंग से बड़ी सार्वजनिक परीक्षाओं से पहले की तनावपूर्ण अवधि में छात्रों की चिंताएं कम करने के तरीके ढूंढ सकते हैं। शिक्षाविद् इत बात का रोना रोते हैं कि परीक्षा की अवधि में शिक्षा के व्यापक आयामों की उपेक्षा हो जाती है, किंतु छात्र और उनके परिवार भी समझते हैं कि शिक्षा प्रणाली के लिए क्या आवश्यक है। यदि ट्यूशन प्रणाली मुख्य धारा की शिक्षा को आड़ना दिखाकर यह बताने का प्रयास करती है कि उसमें क्या कमियां हैं, तो स्कूल उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कठोर परिश्रम कर सकते हैं।

व्यावहारिक रूप में, कम-से-कम कुछ समाजों में स्कूल वास्तव में अच्छी प्रतिक्रिया दर्शा रहे हैं। टैन (2007) ने सूचित किया कि सिंगापुर में ट्यूशन केंद्रों ने मुख्यधारा के स्कूलों से आगे बढ़कर पाठ्यक्रम को पहले ही पूरा करा देने के प्रयास किए। तत्पश्चात्, स्कूलों ने भी अपनी गति बढ़ाई और पाठ्यक्रम को, कम-से-कम कुछ छात्रों के लिए शीघ्र पूरा करना शुरू कर दिया जिसके परिणामस्वरूप ट्यूशन केंद्र और मुख्य धारा के स्कूल एक-दूसरे से मिलकर चलने लगे। कोरिया की हाई स्कूल समकरण नीति ने, सम्भवतया प्राइवेट ट्यूशन की मांग को कम करने के स्थान पर बढ़ाया है, और अधिक लचीलेपन की आवश्यकता ने कोरियाई प्राधिकारियों को समकरण नीति के स्वरूप और लक्ष्यों पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर कर दिया।

अतः, सरकारें अपने बचाव के लिए यदि अधिक रक्षात्मक रवैया न अपनाएं, तो वे प्रतिच्छाया शिक्षा प्रणाली से बहुत कुछ सीख सकती हैं। इसके लिए इस प्रणाली पर अधिक गहराई से ध्यान देना होगा। नीति निर्माताओं और योजनाकारों के लिए प्रतिच्छाया शिक्षा प्रणाली को अनदेखा करना सबसे कठिन है। अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए, नीति निर्माता और योजनाकार प्रतिच्छाया प्रणाली से सबक ले सकते हैं; सभी स्थानों पर उन्हें इसकी शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। इस पुस्तक ने यह जता दिया है कि विभिन्न देशों में होने वाले प्रयोगों के तुलनात्मक विश्लेषण से बहुत कुछ सीखा जा सकता है।

संदर्भ

- एडीईए, 2008. *बियौंड प्राइमरी एजुकेशन: चैलेजिज़ एंड अप्रोचिज़ टू एक्सपेंडिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़*, 2008. बाइनेल ऑन एजुकेशन इन एफ्रीका, 5-9 मई, मापुतो, मोज़ाम्बीक. पेरिस: एसोसिएशन फॉर द डेवेलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन एफ्रीका (एडीईए)।
- आंगलादे, आर. 2008. *सौतिओस्कॉलर: लनोवेलहोरिजोंदयूसिस्तेमएद्यूकातीफ?* 23 मई 2008 को www.temps-reels.net/imprimer.php3?idarticle=1778 से प्राप्त।
- एशर, सी. 2009. एनसीएलबी'ज़ सप्लिमेंटल एजुकेशन सविर्सिज़: इज़ दिस वॉट आवर स्टैंडैट्स नीड? *फि डेल्टा कम्पन* में, 88(2), 136-141.
- एशियावीक, 1997. *बैनिंग ट्यूटर्स: इन एजुकेशन आब्वैस्ड एशिया, द मूव इज़ बोथ राँग एंड फ्यूटाइल* (सम्पादकीय). 23(17), 2 मई, 2.
- बागडासरोवा, एन.; इवानोव, ए. 2009. *“प्राइवेट ट्यूटरिंग इन किर्गीस्तान”*: आई. सिलोवा (एड.), *प्राइवेट सप्लिमेंटरी ट्यूटरिंग इन सेंट्रल एशिया: न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड बर्डन्स* (पृ. 119-142) में प्रकाशित. पेरिस: आईआईईपी-यूनेस्को.
- बाह-लाल्या, आई. (एड.) 2006. *मॉरीशस: 2000-2005 एडुकेशनल रिफॉर्म्स*. पेरिस: आईआईईपी-यूनेस्को एवं एसोसिएशन फॉर द डेवेलपमेंट ऑफ एडुकेशन इन एफ्रीका (एडीईए) वर्किंग ग्रुप ऑन एडुकेशन सेक्टर एनालिसिस (डब्ल्यूजीईएसए).
- बाकर, डी.; अकीबा, एम.; ली तेद्रे, जी.के.; वाइज़मैन, ए. डब्ल्यू. 2001. “वर्ल्डवाइड शैडो एडुकेशन: आउटसाइड-स्कूल लर्निंग, इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग, एंड क्राम्स नेशनल मैथेमेटिक्स अचीवमेंट”. *एडुकेशनल इवैल्यूएशन एंड पॉलिसी एनालिसिस*, 23(1), 1-17.
- बाकर, डी.पी.; ली तेद्रे, जी.के. 2005. *नेशनल डिफ्रैन्सिज़, ग्लोबल सिमिलैरिटीज़: वर्ल्ड कल्चर एंड द फ्यूचर ऑफ स्कूलिंग*. स्टैनफोर्ड: स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस.
- बारोस, एस.ए.पी. 2008. अ बंका इ ए इंस्टीट्यूशनललिज़को डी एस्कोला: पॉसिबिलिडेडीज़ पारा ए हिस्टोरिया डी एडुककाओ डा बाहिया. डिपार्टमेंटो डी एडुककाओ डी यूनिवर्सिटीडेड डो एस्टाडो डा बाहिया.
- बासी ए.; दुपुइस, जे.; जेम्स, आर.; बेरार्ड, जे.; लोआरेर, सी.; मेनांत, जी. 2006. *ला'कॉम्पानेमेंत अ ला स्कोलारीते: पूर अं पोलितीक कूर्दोने एक्वीताब्ल ए आदोसे ऑ तैक्नोलॉजीज़ द लेन्फॉर्मातिसियों ए द ला कोम्यूनिकासियों*, पेरिस: मिनिस्तेर द लेद्यूकासियों नासियोनाले, द लेसेनमेंत सुपेरिय ए द ला रेशेश, 8 जून 2009 को <http://media.education.gouv.fr/file/06/7/6067.pdf> से प्राप्त।

- बेंदाल, एल.; तूर्ते, एल. (रिपोर्टर्स). 2009. ल सूतियों स्कूलर, रेयूसीत ऊ एशे? फ्रांस 2 चैनल ब्रॉडकास्ट, 22 जनवरी. 31 जनवरी 2009 को
http://envoye-special.france2.fr/index-fr.php?page=reportage-bonus&id_article=1205 से प्राप्त।
- बिस्वाल, बी.पी. 1999. “प्राइवेट ट्यूटिंग एंड पब्लिक करप्शन: अ कॉस्ट इफेक्टिव एडुकेशन सिस्टम फॉर डेवेलपिंग कंट्रीज़”. *द डेवेलपिंग इकोनॉमीज़ - XXXVII(2)*, 222-240 में प्रकाशित.
- ब्रे, एम. 1999ए. *द शैडो एडुकेशन सिस्टम: प्राइवेट ट्यूटिंग एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर प्लानर्स*. फंडामेंटल्स ऑफ एडुकेशनल प्लानिंग न. 61, पेरिस: आईआईपी-यूनेस्को. 1 अगस्त 2009 को
<http://unesdoc.unesco-org/images/0018/001802/180205e.pdf> से प्राप्त।
- ब्रे, एम. 1999बी. “द प्राइवेट कौट्स ऑफ पब्लिक स्कूलिंग: हाउसहोल्ड एंड कम्युनिटी फाइनेंसिंग ऑफ प्राइमरी एडुकेशन इन कम्बोडिया. पेरिस; आईआईपी-यूनेस्को. 1 अगस्त 2009 को
<http://unesdoc.unesco-org/images/0011/001176/117632E.pdf> से प्राप्त।
- ब्रे, एम. 2003. *एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ प्राइवेट सप्लीमेंटरी ट्यूटिंग : डाइमेंशन्स, इम्प्लीकेशंस, एंड गवर्नमेंट रिस्रॉन्स*. सीरीज़: एथिक्स एंड करप्शन इन एडुकेशन. पेरिस: आईआईपी-यूनेस्को. 1 अगस्त 2009 को
<http://unesdoc.unesco-org/images/0013/001330/133039e.pdf> से प्राप्त।
- ब्रे, एम. 2006. “प्राइवेट सप्लीमेंटरी ट्यूटिंग : कम्पैरेटिव पर्सपेक्टिव ऑन पैटर्न एंड इम्प्लीकेशंस”. *कम्पेयर: अ जरनल ऑफ कम्पैरेटिव एडुकेशन* 36(4), 515 – 530 में प्रकाशित.
- ब्रे, एम.; बनली, एस. 2005. *बैलेसिंग द बुक्स: हाउसहोल्ड फाइनेंसिंग ऑफ बेसिक एडुकेशन इन कम्बोडिया*. हाँगकाँग कम्पैरेटिव एडुकेशन रिसर्च सेंटर, द यूनिवर्सिटी ऑफ हाँगकाँग, एंड वाशिंगटन डीसी: ह्यूमन डेवेलपमेंट यूनिट, ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक रीजन, द वर्ल्ड बैंक, 7 जून 2009 को
www.hku.hk/cere/Publications/Mono4-ebook/Balancing-the-Books-To/C.pdf से प्राप्त।
- ब्रे, एम.; क्वोक, पी. 2003. “डिमांड फॉर प्राइवेट सप्लीमेंटरी ट्यूटिंग : कॉन्सैप्युअल कन्सीडरेशंस, एंड सोशियो- इकोनॉमिक पैटर्न्स इन हाँगकाँग”. *इकोनॉमिक ऑफ एडुकेशन रिव्यू*, 22(6), 611–620 में प्रकाशित.
- बकमैन, सी. 2002. “गैटिंग अहेड इन केन्या: सोशल कैपिटल, शैडो एडुकेशन, एंड अचीवमेंट”. बी. फुलर, ई. हानुम(एड्स), *स्कूलिंग एंड सोशल कैपिटल इन डाइवर्स कल्चर्स* (पृ. 133–159), एम्स्टर्डम: जेएआई प्रेस में प्रकाशित.

- बुडीन, वी.; ज़बुलिओनिस, ए. 2006. “लिथुआनिया”. आई. सिलोवा, वी. बुडीने, एम. ब्रे (एड्स.), *एजुकेशन इन अ हिडन मार्केट प्लेस: मॉनीटरिंग ऑफ प्राइवेट ट्यूटरिंग* (पृ. 211-235). न्यूयार्क: ओपन सोसायटी इंस्टीट्यूट. 7 जून 2009 को www.soros.org/initiatives/esp/articles_publications/publications/hidden_20070216 से प्राप्त।
- बर्च, पी.; डोनावान, जे.; स्टीनबर्ग, एम. 2006. “द न्यू लैंडस्केप ऑफ एजुकेशनल प्राइवेटाइजेशन इन द एरा आफ एनसीएलबी”. *फि डेल्टा कोप्पन*, 88(2), पृ. 129-135 में प्रकाशित.
- ब्यामुघिशा, ए.; सेनाबुलया, एफ. 2005. *द सैकमेम II प्रोजेक्ट इन यूगांडा: अ स्टडी ऑफ द कंडीशंस ऑफ स्कूलिंग एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन*. कम्पाला: मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, एंड हारारे: सदर्न एंड ईस्टर्न अफ्रीका कंसोर्टियम फॉर मॉनिटरिंग एजुकेशनल क्वालिटी (सैकमेक), 7 जून 2009 को www.sacmeq.org/downloads/sacmeqII/Uganda.zip से प्राप्त।
- ब्यून, एस. 2008. “असैसिंग द इफेक्ट्स ऑफ द हाई स्कूल इक्विवाइजेशन पॉलिसी ऑन शैडो एजुकेशन इन साउथ कोरिया: अ प्रोपेन्सिटी स्कोर मैचिंग अप्रोच”. *नाइंथ इंटरनेशनल काँफ्रेंस ऑन एजुकेशनल रिसर्च*, सिओल नेशनल यूनिवर्सिटी में प्रकाशित. 27-28 अक्टूबर में प्रस्तुत शोधपत्र पर आधारित.
- कैवेट, ए. 2006. ली सौतिंग स्कोलर: एंन एजुकेशन ऑन पॉपुलेर एत इंडस्ट्री डी सर्विस [इंग्लिश में भी उपलब्ध: *आफ्टर स्कूल ट्यूटरिंग : बिटवीन पॉपुलर एजुकेशन एंड अ सर्विस इंडस्ट्री, लेतरे डिइनफार्मेशन, लियोन: सेलुले वीले साइंटिफिक एत टैक्नोलॉजिक*, इंस्टीट्यूट नेशनल डी रेशेर्श पेदागोकीक. 6 जून 2009 को www.inrp.fr/vst/Lettre VST/english/december2006_en.htm से प्राप्त।
- शियो आर.; कुआह, ई. 2005. “मदर्स, मेइस एंड ट्यूटर्स: एन इम्पीरिकल इवैल्यूएशन ऑफ देर इफैक्ट्स ऑन चिल्ड्रेन्स अकेडमिक ग्रेड्स इन सिंगापुर”. *एजुकेशन इकोनॉमिक्स*, 13(3), 269-285 में प्रकाशित।
- शियो, एस.एच. 2009, “ऑनलाइन कोर्ज: इक्वेलाइज़र फॉर कोरियंस?” *इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून*, 2 जून, पृ. 14 में प्रकाशित।
- कोस्टा, जे.ए.; नेटो-मेंडीज़, ए.; वेंचुरा, ए. 2008. *एक्वेरितो आ कोदीसो दो रेकर्सो अ एक्सप्लीकासो*. फिफ्थ सिम्पोज़ियम ऑन ऑर्गनाइजेशन एंड स्कूल मैनेजमेंट में प्रस्तुतीकरण. यूनिवर्सिटी ऑफ अवीरो. पोर्तुगाल, 2-3 मई.
- डांग, एच. 2007. “द डिटर्मिनेंट्स एंड इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेट ट्यूटरिंग क्लासेज़ इन विएतनाम”. *इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन रिव्यू*, 26(6), 684-699 में प्रकाशित.

डांग, एच.; रोजर्स, एफ.एच. 2008. *हाउ टू इंटरप्रीट द ग्राइंग फिनोमेनन ऑफ प्राइवेट ट्यूटरिंग : ह्यूमन कैपिटल डीपनिंग, इनइक्वेलिटी इंक्रीजिंग, ऑर वेस्ट ऑफ रिसोर्सिज?* पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर 4530. वाशिंगटन डीसी: वर्ल्ड बैंक. 6 जून 2009 को

http://econ.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64165259&piPK=64165421&theSitePK=469372&menuPK=64166093&entityID=000158349_20080225153509 से प्राप्त.

डेवीस, एस.; ऑरिनी, जे. 2006. “द फ्रैंचाइजिंग ऑफ प्राइवेट ट्यूटरिंग : अ न्यू फ्रॉम कैनडा.” *फि डेल्टा कप्पन*, 88(2), 123-128 में प्रकाशित.

डॉसन, डब्ल्यू. 2009. “द ट्रिक्स ऑफ द टीचर: शैडो एडुकेशन एंड करप्शन इन कम्बोडिया”. एस.पी. हेनीमैन (एड.), *बाइंग योर वे इटू हैवन: एडुकेशन एंड करप्शन इन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव* (पृ. 51-74). रोटटरडैम: सेस पब्लिशर्स में प्रकाशित.

डियर्क्स, जे. 2008. “जैप्नीज़ शैडो एडुकेशन: द कॉन्सिक्वेंसिज़ ऑफ स्कूल चॉइस”. एम. फोरसे, एस. डेवीस, जी. वाल्फोर्ड (एड्स). *द ग्लोबलाइज़ेशन ऑफ स्कूल चॉइस?* (पृ. 231-248), ऑक्सफोर्ड: सिम्पोज़ियम बुक्स.

दीनदयाल, जे.; बेसूंदयाल, एच. 2007. “प्राइवेट ट्यूटरिंग इन मैथेमैटिक्स: द मॉरिशियन एक्सपीरिएंस”. *रिडिज़ानिंग पेडागोगी: कल्चर, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग* पर आयोजित संगोष्ठी में प्रस्तुत शोधपत्र. 1 अगस्त 2009 को

<http://conference.nie.edu.sg/2007/paper/papers/CUL394.pdf> से प्राप्त.

ऐलोर, जे. 2007. “इज़ कोचिंग अ चैलेंज टू यूगांडाज़ एडुकेशन सिस्टम?” *कन्फ्रंटिंग द शैडो एडुकेशन सिस्टम: वॉट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर वॉट प्राइवेट ट्यूटरिंग ?* पर आयोजित आईआईईपी पॉलिसी फोरम में प्रस्तुत शोधपत्र. पेरिस: आईआईईपी-यूनेस्को.

एल्बाडावी, ए.; अहलबर्ग, डी.; लेवीसन, डी.; अस्सद, आर. 2006. *प्राइवेट एंड गुप ट्यूटरिंग इन इजिप्ट: वेयर इज़ द जेडर इनइक्वेलिटी?* मिनीपोलिस: डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा. 30 जुलाई 2009 को

<http://iussp2009.princeton.edu/download.aspx?submissionId=91279> से प्राप्त.

इटीने, पी. 2007. “यूनेस्को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस: द गवर्नमेंट मस्ट केयर ‘द इविल’ ऑफ प्राइवेट ट्यूटरिंग”. *ल’एक्सप्रेस रूमॉरीशस*, 24 जुलाई में प्रकाशित.

फूंडुन, ए.आर. 1992. *प्राइवेट ट्यूटरिंग इन मॉरीशस: द मैड रेस फॉर अ प्लेस इन अ ‘फाइव स्टार’ सेकंडरी स्कूल*. पेरिस: आईआईईपी-यूनेस्को.

- फुंडुन, ए.आर. 2002. “द इश्यू ऑफ प्राइवेट ट्यूटरिंग : एन एनालिसिस ऑफ द प्रैक्टिस इन मॉरीशस एंड सिलेक्टिड साउथ-ईस्ट एशियन कंट्रीज़”. *इंटरनेशनल रिव्यू ऑफ एडुकेशन*, 48(6), 485 – 515 में प्रकाशित.
- फोरेस्टियर, सी. 2005. *आवी द्यू हॉ कोसेल आ लेवाल्यूएसिओं द लेकोल: ल त्रवेइ दे इलेवे पूर लेकोल ए देहोर्स द लेकोल*. पेरिस: हॉ कोसिएल आ लेवाल्यूएसिओं द लेकोल.
- जॉर्ज, सी. 1992. “टाइम टू कम आउट ऑफ द शैडो”. *स्ट्रेट्स टाइम्स*, 4 अप्रैल, पृ. 28 में प्रकाशित.
- ग्लासमैन डी. 2004. *ल ट्रवेई द एलेवे पूर लेकोल अं दिहोर द लेकोल*, सेवोई, फ्रांस: यूनिवर्सिटे द सेवोई फैकल्टे द लेतर्स, लांग्यूज ए सिएसेज़ ह्यूमेइन्ज़. 6 जून 2009 को www.ladocumentationfrancise.fr/rapports-publics/054000358/index.shtml से प्राप्त।
- ग्लासमैन डी. 2007. “ट्यूटरिंग फॉर द रिच, ट्यूटरिंग फॉर द पुअर? शॉर्ट नोट्स फ्रॉम फ्रांस”. *कन्फ्रंटिंग द शैडो एडुकेशन सिस्टम: वॉट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर वॉट प्राइवेट ट्यूटरिंग ?* पर आयोजित आईआईईपी पॉलिसी फोरम में प्रस्तुत शोधपत्र. पेरिस: आईआईईपी – यूनेस्को.
- ग्लासमैन डी., कोलोन्जे, जी. 1994. कूर्ज पार्तिकक्यूलिर्एस ए काँसत्रुसिओं सोसियेल द ला स्कोलारिते. पेरिस: सेंत्रनासियोनाल द डॉक्यूमेतेसियों पेदागोगीक.
- गोखूल, डी. 2006. वर्कशॉप ऑन इन्डक्शन प्रोग्राम फॉर सोशल वर्कर्स (एडुकेशन) एंड एडुकेशन साइकोलॉजिस्ट्स पर आयोजित कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर भाषण, मॉरीशस इंस्टीट्यूट ऑफ एडुकेशन, 13 नवंबर.
- गोंजेलीस, ई.जे.; स्मिथ, टी.ए.; 1997. *यूज़र गाइड फॉर द टिम्स इंटरनेशनल डाटाबेस: प्राइमरी एंड मिडल स्कूल इयर्स*. चेस्टनट हिल, एम.ए.; टिम्स इंटरनेशनल स्टडी सेंटर, बोस्टन कॉलेज. 10 अगस्त 2009 को http://timss.bc.edu/timss1995i/database/UG_1and2.pdf से प्राप्त.
- गोरगोज़े, एस. 2007. “करप्शन-फ्री बट इनइक्विटेबल: कैन प्राइवेट ट्यूटरिंग अंडरमाइन द इंटिग्रिटी ऑफ यूनिफाइड नेशनल एग्जामिनेशन?” *कन्फ्रंटिंग द शैडो एडुकेशन सिस्टम: वॉट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर वॉट प्राइवेट ट्यूटरिंग ?* पर आयोजित आईआईईपी पॉलिसी फोरम में प्रस्तुत शोधपत्र. पेरिस: आईआईईपी – यूनेस्को.
- गुबेर, के.एच. 2007. “फ्रॉम द शैडो इन्टू द लाइमलाइट: द इंक्रीजिंग विज़िबिलिटी ऑफ ट्यूटरिंग इन ऑस्ट्रेलिया”. *कन्फ्रंटिंग द शैडो एडुकेशन सिस्टम: वॉट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर वॉट प्राइवेट ट्यूटरिंग ?* पर आयोजित आईआईईपी पॉलिसी फोरम में प्रस्तुत शोधपत्र. पेरिस: आईआईईपी – यूनेस्को.

- गुबेर, के.एच. 2008. “डाई नेशिल्फे – इंडस्ट्री: जारलिश गेबेन एल्टर्न 140 मिलियनेन फुर प्राइवेट लर्नहिल्फे ऑस. इन डेन फेरीनमोनाटेन हर्श्ट होचकोन्जुंकटूर”. डाई ज़ीट, एनआर 27, 26 जून में प्रकाशित.
- हेगितेगास, जी. 2008ए. *द आइडेंटिटी ऑफ ओईएफई (हेलेनिक फेडरेशन ऑफ फ्रंटीस्टिरिया टीचर्स)*, एथेंस: हेलेनिक फेडरेशन ऑफ फ्रंटीस्टिरिया टीचर्स.
- हेगितेगास, जी. 2008बी. *द ओवरथ्रो ऑफ द ग्रीक मिथ*. एथेंस: लिवानिस. (ग्रीक में)
- हलाक जे.; पोइसन, एम. 2007. *करप्ट स्कूल्स, करप्ट यूनिवर्सिटीज़: वॉट कैन बी डन?* पेरिस: आईआईईपी – यूनेस्को.
www.iiep.unesco.org/information-service/publications/abstracts/2007/etico-corrupt-schools.html पर उपलब्ध.
- हार्टमैन, एस. 2008. *द इन्फॉर्मल मार्केट ऑफ एडुकेशन इन ईजिप्ट: प्राइवेट ट्यूटरिंग एंड इट्स इम्प्लीकेशंस*. वर्किंग पेपर्स नं. 88. मेन्ज़: इंस्टीट्यूट फुर एथनोलॉजी एंड एफ्रीकास्टुडिएन, जोहानीस गुटेनबर्ग – यूनिवर्सिटी. 7 जून 2009 को
www.ifeas.uni-mainz.de/workingpapers/AP88.pdf से प्राप्त।
- हेनरी, एम.; लिनगार्ड, बी.; रिज़वी, एफ.; टेलर, एस. 2001. *द ओईसीडी, ग्लोबलाइज़ेशन एंड एडुकेशन पॉलिसी*. ऑक्सफोर्ड: पर्गामोन प्रैस.
- हेररा, एल. 1992. *सीन्स ऑफ स्कूलिंग: इनसाइड अ गर्ल्स स्कूल इन कैरो, कैरो पेपर्स इन सोशल साइंस 15(1)*. कैरो: द अमेरिकन यूनिवर्सिटी इन कैरो प्रैस.
- हर्टफोर्डशायर लोकल अथॉरिटी. 2009. *मेकिंग गुड प्रोग्रेस: वन टू वन ट्यूटरिंग इन हर्टफोर्डशायर*. 1 अगस्त 2009 को
www.thegrid.org.uk/learning/mgp/hr/documents/hr_factsheet.pdf से प्राप्त।
- हिलबर्ट, पी. 2009. “ऐबोलिसियों दे लेसों एं स्तैदर्ड टः ला गुएरे ओवर्ते”. *ल’एक्सप्रैस (मॉरीशस)*, 26 मई में प्रकाशित.
- हो, एस.सी. 2008. *करंट सिचुएशन एंड इम्पैक्ट ऑफ ट्यूटोरियल क्लास/आफ्टर स्कूल स्टडी क्लास एंड इट्स रिलेटिव सर्विसेज़ इन मकाओ*. मकाओ: डिरेकाओ डोस सर्विकोस डी एडुककाओ ई जुवेन्ट्यूड (चीनी में).
- आयरसन, जे. 2004. “प्राइवेट ट्यूटरिंग : हाऊ प्रैवलेंट एंड इफेक्टिव इज़ इट?” *लंदन रिव्यू ऑफ एडुकेशन*, 2(2), 109–122 में प्रकाशित.
- आयरसन, जे. 2007ए. “मॉनीटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग प्राइवेट ट्यूटरिंग : हाउ एंड वाय बी शुड डू इट?” *कन्फ्रंटिंग द शैडो एडुकेशन सिस्टम: वॉट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर वॉट प्राइवेट ट्यूटरिंग ?* पर आयोजित आईआईईपी पॉलिसी फोरम में प्रस्तुत शोध पत्र. पेरिस: आईआईईपी – यूनेस्को.

- आयरसन, जे. 2007बी. *कन्फ्रंटिंग द शैडो एडुकेशन सिस्टम: वॉट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर वॉट प्राइवेट ट्यूटरिंग ?* पर आयोजित आईआईईपी पॉलिसी फोरम में प्रस्तुत टिप्पणी. पेरिस: आईआईईपी-यूनेस्को.
- आयरसन, जे.; रशफोर्थ के. 2005. *मैपिंग एंड इवैल्यूएटिंग शैडो एडुकेशन*, ईएसआरसी रिसर्च प्रोजेक्ट आरईएस-000-23-0117. लंदन: इंस्टीट्यूट ऑफ एडुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन.
- जलालुद्दीन, ए.के. 2007. “प्राइवेट ट्यूटरिंग इन एन ओपन नॉलेज इकोनॉमी एंड स्कूल-कम्युनिटी पार्टनरशिप”. *कन्फ्रंटिंग द शैडो एडुकेशन सिस्टम: वॉट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर वॉट प्राइवेट ट्यूटरिंग ?* पर आयोजित आईआईईपी पॉलिसी फोरम में प्रस्तुत शोधपत्र. पेरिस: आईआईईपी-यूनेस्को.
- जापान, मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन, साइंस, कल्चर एंड स्पोर्ट. 2008. *रिपोर्ट ऑन चिल्ड्रेन्स आउट-ऑफ-स्कूल लर्निंग एक्टिविटीज़*. टोक्यो: मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन, साइंस, कल्चर एंड स्पोर्ट (जापानी में).
- जॉनसन, ई.एम. 2008. *आउट ऑफ कंट्रोल? पैटर्न्स ऑफ टीचर करप्शन इन किर्गीस्तान एंड देयर इम्प्लीकेशन्स फॉर द स्टडी ऑफ स्ट्रीट-लेवल करप्शन कंट्रोल*. पीएचडी शोधपत्र. ग्रेजुएट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड साइंस. कोलम्बिया यूनिवर्सिटी.
- जॉयनाथसिंह, एम.; मंसूर, एम.; नबाबसिंह, वी.; पोचुन, एम.; सेल्विन, पी. 1988. *द प्राइवेट कॉस्ट्स ऑफ एडुकेशन इन मॉरीशस*. रेडूइट: स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरीशस.
- काज़िमज़ेड, ई. 2007. आईआईईपी पॉलिसी फोरम में *कन्फ्रंटिंग द शैडो एडुकेशन सिस्टम: वॉट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर वॉट प्राइवेट ट्यूटरिंग ?* के दौरान प्रस्तुत टिप्पणी. पेरिस: आईआईईपी-यूनेस्को.
- किम, एच. 2004. “एनालाइजिंग द इफेक्ट्स ऑफ द हाई स्कूल इक्विलाइजेशन पॉलिसी एंड द कॉलेज एण्ट्रेस सिस्टम ऑन प्राइवेट ट्यूटरिंग एक्सपेंडीचर इन कोरिया”. *केईडीआई जर्नल ऑफ एडुकेशन पॉलिसी*, ५(1) पृ. 5-24 में प्रकाशित.
- किम, एम. 2007. “स्कूल चॉइस एंड प्राइवेट सप्लीमेंटरी एडुकेशन इन साउथ कोरिया”. *कन्फ्रंटिंग द शैडो एडुकेशन सिस्टम: वॉट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर वॉट प्राइवेट ट्यूटरिंग ?* पर आयोजित आईआईईपी पॉलिसी फोरम में प्रस्तुत शोधपत्र. पेरिस: आईआईईपी-यूनेस्को.

- किम, एस.; ली, जे. 2008. *प्राइवेट ट्यूटरिंग एंड द डिमांड फॉर एडुकेशन इन साउथ कोरिया*. अप्रकाशित पांडुलिपि. मिलवाउकी: यूनिवर्सिटी ऑफ विन्सकोसिन. 7 जून 2009 को www.rrojasdatabank.info/devstate/southkorea1.pdf से प्राप्त.
- कितेव, आई. 2007. “प्राइवेट ट्यूटरिंग एंड फाइनेसिंग इशूज़”. *कन्फ्रंटिंग द शैडो एडुकेशन सिस्टम: वॉट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर वॉट प्राइवेट ट्यूटरिंग ?* पर आयोजित आईआईईपी पॉलिसी फोरम में प्रस्तुत पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन. पेरिस: आईआईईपी – यूनेस्को.
- क्लिटगार्ड, आर.ई. 1988. *कंट्रोलिंग करप्शन*. बर्कले: यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रैस.
- कोडिरोव, एस.; अमोनोव, एन. 2009. *प्राइवेट ट्यूटरिंग इन ताजिकिस्तान*. आई. सिलोवा (एड.), *प्राइवेट सप्लीमेंटरी ट्यूटरिंग इन सेंट्रल एशिया: न्यू अपॉर्चिनिटीज़ एंड बर्डन्स* (पृ. 143 – 165) में प्रकाशित, पेरिस: आईआईईपी – यूनेस्को.
- कुबानोवा, एम. 2006. *स्लोवाकिया, आई. सिलोवा, वी. बुडीन, एम. ब्रे (एड्स), एडुकेशन इन अ हिडन मार्केट प्लेस: मॉनिटरिंग ऑफ प्राइवेट ट्यूटरिंग* (पृ. 279 – 303), न्यूयॉर्क: ओपन सोसायटी इंस्टीट्यूट में प्रकाशित. 7 जून 2009 को www.soros.org/initiatives/esp/articles_publications/publications/hidden_20070216 से प्राप्त.
- कुमोन. 2008. *कुमोन इंस्टीट्यूट ऑफ एडुकेशन*. 28 जुलाई 2008 को www.kumon.ne.jp/english/index.html 2008 से प्राप्त.
- क्वाक, वाई.एस. 1999. “इनसफिशेंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एडुकेशन फियर्ड टू वीकन नेशनल कम्पटीटिवनेस”. *कोरिया हेराल्ड*, 24 जून, में प्रकाशित.
- क्वोक, पी. 2009. “अ कल्चरल एनालिसिस ऑफ क्रैम स्कूल्स इन हाँगकाँग: इम्पैक्ट ऑन यूथ वैल्यूज़ एंड इम्प्लीकेशंस”. *जरनल ऑफ यूथ स्टडीज़ (हाँगकाँग)*, 12(1), 104 – 114 में प्रकाशित.
- ली, सी.जे. 2005. “कोरियन एडुकेशन फीवर एंड प्राइवेट ट्यूटरिंग ’’. *केईडीआई जरनल ऑफ एडुकेशनल पॉलिसी*, 2(1), 99 – 107 में प्रकाशित. 8 जून 2009 को http://eng.kedi.re.kr/upload_data/kedi_irn/Journal-Chong%20Jae%20Lee से प्राप्त.
- ली, सी.जे.; जंग, एच. 2008. “हिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी टू शैडो एडुकेशन’’. *नाइंथ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एडुकेशनल रिसर्च*, सिओल यूनिवर्सिटी, 27 – 28 अक्टूबर में प्रस्तुत शोधपत्र.
- ली, सी.जे.; पार्क, एच.जे.; ली, एच.एस. 2009. “‘शैडो एडुकेशन सिस्टम्स’”. जी. साइक्स, बी.एल. शनीडर, डी.एन. प्लैक (एड्स), *हैंडबुक ऑफ एडुकेशनल पॉलिसी रिसर्च* (पृ. 901 – 919), न्यूयॉर्क: राउटलेज में प्रकाशित.

- ली, जे. 2007. “टू वर्ल्ड्स ऑफ प्राइवेट ट्यूटोरिंग : द प्रैक्लेस एंड कॉज़िज़ ऑफ आफ्टर-स्कूल मैथेमैटिक्स ट्यूटोरिंग इन कोरिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स”. *टीचर्स कॉलेज रिकॉर्ड*, 109 (5), 1207-1234 में प्रकाशित.
- ली, जे. 2009. “क्रैम स्कूलिंग इन ताइवान”. *जरनल ऑफ यूथ स्टडीज़ (हांगकाँग)*, 12(1), 129-136 में प्रकाशित.
- महादेव, एस.के. 2008. “मॉरीशस: अबॉलिशिंग द सीपीई एज़ इट इज़”. *ल’एक्सप्रेस (मॉरीशस)*, 3 मई में प्रकाशित. 5 अगस्त 2009 को <http://allafrica.cpm/stories/200805051582.html> से प्राप्त।
- मैकगोठी, ए. 2007. *कन्फ्रंटिंग द शैडो एडुकेशन सिस्टम: वॉट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर वॉट प्राइवेट ट्यूटोरिंग ?* पर आयोजित आईआईईपी पॉलिसी फोरम में प्रस्तुत शोध पत्र. पेरिस: आईआईईपी-यूनेस्को.
- मनराखन, आर.; वशिष्ठ, के.; वाडमूटू, वी. (1991). *डिटरमिनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस इन प्राइमरी स्कूल्स विद स्पेशल रेफरेंस टू फेलयर्स एट सीपीई लेवल*. रेडुइट: मॉरीशस एक्ज़ामिनेशन सिंडिकेट.
- मारिमुथु, टी.; सिंह, जे.एस.; अहमद, के.; लिम, एच.के.; मुखर्जी, एच.; उस्मान, एस.; चेल्लियाह, टी.; शर्मा, जे.आर.; सालेह, एन.एम.; योंग, एल.; लिम, टी.एल.; सुकुमारन, एस.; थोग, एल.के.; जमालुद्दीन, डब्ल्यू. 1991. *एक्स्ट्रा-स्कूल इंस्ट्रक्शन, सोशल इक्विटी एंड एडुकेशनल क्वालिटी (इन मलेशिया)*. सिंगापुर: इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर.
- मारलेंटीस, एल.; सुनोल, ई. 2006. “ऑनलाइन ट्यूटर्स: एडुकेशन अ क्लिक अवे-अमेरिकन स्टूडेंट्स टर्न टू इंडिया फॉर होमवर्क हैल्प”. *एबीसी वर्ल्ड न्यूज़*, 25 नवंबर में प्रकाशित. 30 अगस्त 2008 को <http://abcnews.go.com/WNT/Technology/story?id=2641669&page=1> से प्राप्त।
- मार्टिन, एम.ओ. 1996. “थर्ड इंटरनेशनल मैथेमैटिक्स एंड साइंस स्टडी: एन ओवरव्यू”. एम.ओ. मार्टिन एवं डी.एल. केली (एड्स), *थर्ड इंटरनेशनल मैथेमैटिक्स एंड साइंस स्टडी (टिम्स) टेक्नीकल रिपोर्ट, वॉल्यूम ५: डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट*. चेस्टनट हिल, एम.ए.: टिम्स इंटरनेशनल स्टडी सेंटर, बॉस्टन कॉलेज. 10 अगस्त 2009 को <http://timss.bc.edu/timss1995i/TIMSSPDF/TRCHP1.PDF> से प्राप्त।
- मट्टोस, एल.ओ.एन. 2007. “एक्सप्लीकेटोरेस डो रियो डी जनीरो: एनकंट्रोस ई डिसेन्कोन्ट्रोस एम ट्राजेक्टोरोआस प्रोफिश्नेस सिंगुलेरीज़”. *रेविस्टा ब्रासिलिएरा डी एस्टुडोस पेडागोगिकोस*, 88(218), 140-156 में प्रकाशित.
- मॉरीशस, मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन, आर्ट्स एंड कल्चर. 1984. *वाइट पेपर ऑन एडुकेशन*. पोर्ट लुई: मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन, आर्ट्स एंड कल्चर.

- मॉरीशस, मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवेलपमेंट. 1997. *वाइट पेपर ऑन ग्री प्राइमरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एडुकेशन*. पोर्ट लुई: मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवेलपमेंट
- मॉरीशस, मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन एंड साइंस. 1994. *यूज़ एंड एब्यूज़ ऑफ प्राइवेट ट्यूटरिंग*. पोर्ट लुई: मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन एंड साइंस.
- मॉरीशस, मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च. 2001. *एण्डिंग द रैट रेस इन प्राइमरी एडुकेशन एंड ब्रेकिंग द एडमिशन बॉटलनेक एट सेकेण्डरी लैवल*. पोर्ट लुई: मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च. 7 जून 2009 को www.gov.mu/portal/goc/educationsite/file/reforms.pdf से प्राप्त.
- मॉरीशस, मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन, कल्चर एंड ह्यूमन रिसोर्सिज़ 2008. *एडुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सिज़ स्ट्रैटेजी प्लान 2008-2020*. पोर्ट लुई: मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन, कल्चर एंड ह्यूमन रिसोर्सिज़. 7 जून 2009 को www.gov.mu/portal/site/Mainhomepage/menuitem.a42b24128104d9845dabddd154508a0c/?content_id=ca01e23ddbdbd110VgnVCM1000000a04a8c0RCRD से प्राप्त.
- मीतरभान, आर. 2009. “ली मॉवेइस रेमेडे”. *ल’एक्सप्रेस (मॉरीशस)*, 26 मई में प्रकाशित.
- मेलोत, एल. 2007. *ली मार्च दु सौतिएन स्कोलेयर*. पेरिस: प्रीसेप्ता. सारांश <http://www.xerfi.fr/etudes/7SME04.pdf> पर उपलब्ध.
- मेंडाकी. 2009. ययासन मेंडाकी एनुअल रिपोर्ट 2008. सिंगापुर काउंसिल ऑन एडुकेशन फॉर मलय/मुस्लिम चिल्ड्रेन (मेंडाकी). 8 अगस्त 2009 को <http://www.mendaki.org.sg/index.jsp> से प्राप्त.
- मोरी, आई. 2008. “द पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ प्राइवेट ट्यूटरिंग : अ कम्पैरिज़न ऑफ जापान एंड कोरिया”. *52वीं एनुअल काँफ्रेंस ऑफ द कम्पैरिटिव एंड इंटरनेशनल एडुकेशन सोसायटी, न्यूयार्क*, 17-21 मार्च में प्रस्तुत शोधपत्र.
- मोरी, आई. 2009. “बैकग्राउंड ऑफ प्राइवेट ट्यूटरिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स”. *53वीं एनुअल काँफ्रेंस ऑफ द कम्पैरिटिव एंड इंटरनेशनल एडुकेशन सोसायटी, चार्ल्सटन, साउथ कैरोलिना*, 22-26 मार्च में प्रस्तुत शोधपत्र.
- मुलिस, आई.; मार्टिन वी.एस.; माइकेल, ओ.; पीरेम, एफ. 2005. *आईईए’ज़ टिम्स 2003 इंटरनेशनल रिपोर्ट ऑन अचीवमेंट इन द मैथेमैटिक्स कॉग्नीटिव डोमेन : फाइंडिंग्स फ्रॉम अ डेवेलपमेंट प्रोजेक्ट*. बॉस्टन: टिम्स एंड पीआईआरएलएस इंटरनेशनल स्टडी सेंटर, लिंग स्कूल ऑफ एडुकेशन, बॉस्टन कॉलेज. 6 जून 2009 को http://timss.bc.edu/PDF/t03_download/t03cdrpt_frontmatter.pdf से प्राप्त.

- नंदा, पी.के. 2005. *आउटसोर्सिंग ऑफ एडुकेशन इज़ इंडिया 'ज़ न्यू कैच*. 26 जुलाई 2005 को www.newkerala.com/news.php?action=fullnews&id=7177 से प्राप्त.
- नाथ, एस.आर. 2008. “प्राइवेट सप्लीमेंटरी ट्यूटरिंग अमंग प्राइमरी स्टूडेंट्स इन बांग्लादेश”. *एडुकेशनल स्टडीज़*, 34(1), 55-72 में प्रकाशित.
- नेटो-मेडीज़, ए.; कोस्ता, जे.ए. 2007. “प्राइवेट सप्लीमेंटरी ट्यूटरिंग इन पुर्तगाल: अ कंट्रीब्यूशन टु अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी”. *कन्फ्रंटिंग द शैडो एडुकेशन सिस्टम: वॉट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर वॉट प्राइवेट ट्यूटरिंग ?* पर आयोजित आईआईईपी पॉलिसी फोरम में प्रस्तुत शोधपत्र. पेरिस: आईआईईपी-यूनेस्को.
- न्ग, वाई.एच. 2009. “ट्यूटर्स आर लाइक एक्टर्स”. *डेक्कन हेराल्ड*, 4 जून में प्रकाशित. 3 अगस्त 2009 को www.deccanherald.com/content/8619/tutors-like-actors.html से प्राप्त.
- न्गीनूनान्ये, जी.टी. 2007. “प्राइवेट ट्यूटरिंग इन नमीबिया: शॉर्ट नोट्स टुवर्ड्स पॉलिसी फोरम ऑन प्राइवेट ट्यूटरिंग , आईआईईपी, पेरिस”. *कन्फ्रंटिंग द शैडो एडुकेशन सिस्टम: वॉट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर वॉट प्राइवेट ट्यूटरिंग ?* पर आयोजित आईआईईपी पॉलिसी फोरम में प्रस्तुत शोधपत्र. पेरिस: आईआईईपी-यूनेस्को.
- ओबीगाडू, एस. 2007. *कन्फ्रंटिंग द शैडो एडुकेशन सिस्टम: वॉट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर वॉट प्राइवेट ट्यूटरिंग ?* पर आयोजित आईआईईपी पॉलिसी फोरम में प्रस्तुत टिप्पणियाँ. पेरिस: आईआईईपी-यूनेस्को.
- ओईसीडी. 2005. *स्टूडेंट क्वेश्चनेयर फॉर पीसा 2006: मेन स्टडी*. पेरिस: ऑर्गनाइज़ेशन फॉर इकोनॉमिक को-ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (ओईसीडी).
- ओईसीडी. 2006ए. *डिमांड-सेसेटिव स्कूलिंग: एविडेंस एंड इश्यूज़*. पेरिस: ऑर्गनाइज़ेशन फॉर इकोनॉमिक को-ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (ओईसीडी).
- ओईसीडी. 2006बी. *असैसिंग साइटिफिक, रीडिंग एंड मैथैमैटिकल लिटरेसी: अ फ्रेमवर्क फॉर पीसा 2006*. पेरिस: ऑर्गनाइज़ेशन फॉर इकोनॉमिक को-ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (ओईसीडी).
- ओपन सोसायटी इंस्टीट्यूट (ओएसआई) 2008. *ओपन सोसायटी एडुकेशन मॉनीटरिंग इनीशिएटिव*. 24 अगस्त 2008 को www.soros.org/initiatives/esp/focus_areas/emi से प्राप्त.
- परसुरामन, ए. 1997. *मास्टर प्लान फॉर एडुकेशन फॉर द इयर 2000: द मॉरिशियन एक्सपीरिएंस*. इशूज़ एंड मैथेडोलॉजीज़ इन एडुकेशनल डेवलपमेंट 14, पेरिस: आईआईईपी-यूनेस्को.

- परशुरामन, ए. 2007. *कन्फ्रंटिंग द शैडो एडुकेशन सिस्टम: वॉट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर वॉट प्राइवेट ट्यूटोरिंग ?* पर आयोजित आईआईईपी पॉलिसी फोरम में प्रस्तुत टिप्पणियां. पेरिस: आईआईईपी-यूनेस्को.
- पेवियट, एल. 2007. “द डिज़ाइन ऑफ प्युपिल क्वशचनेयर आइटम्स ऑन एक्स्ट्रा ट्यूटोरिंग फॉर द सैकमैक III प्रोजेक्ट डाटा कलेक्शन”. *कन्फ्रंटिंग द शैडो एडुकेशन सिस्टम: वॉट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर वॉट प्राइवेट ट्यूटोरिंग ?* पर आयोजित आईआईईपी पॉलिसी फोरम में प्रस्तुत शोधपत्र. पेरिस: आईआईईपी-यूनेस्को.
- पेवियट, एल. 2009. फाइनल सैकमेक प्रश्नावली पर लेखक को दी गई व्यक्तिगत सूचनाएं. पेरिस: आईआईईपी-यूनेस्को.
- पेवियट, एल. 2009. हीनसोन, एन.; कोर्कमैन, जे. 2008. “एक्स्ट्रा ट्यूटोरिंग इन सर्दन एंड ईस्टर्न एफ्रीका: कवरेज, ग्रोथ एंड लिंकेजिज़ विद प्युपिल अचीवमेंट”. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडुकेशनल डेवलपमेंट, 28(2)*, 149-160 में प्रकाशित.
- पेक, एम. 2008. “प्लू दं मिलियों देल्वे बेनेफिसियों दं सूतियों स्कोलर”. *ल फिगारो*, 29 अक्टूबर, 9 में प्रकाशित. 6 जून 2009 को www.udapel93.fr/IMG/pdf/2008_10_29_Le_Figaro.pdf से प्राप्त.
- पीटर्स, एम.; कारपेंटर, एच.; एडवर्ड्स, जी.; कोलमैन, एन. 2009. *प्राइवेट ट्यूटोरिंग : सर्वे ऑफ पेरेंट्स एंड केयरर्स*. रिसर्च ब्रीफ डीसीएसएफ-आरबीएक्स-09-01. लंदन: डिपार्टमेंट फॉर चिल्ड्रेन, स्कूल्स एंड फैमिलीज़. 5 अगस्त 2009 को www.dcsf.gov.uk/research/programmeofresearch/projectinformation.cfm?projectid=15666&resultspage=1 से प्राप्त.
- पोइसन, एम. 2007. “प्राइवेट ट्यूटोरिंग : असेट और थ्रैट फॉर मेनस्ट्रीम एडुकेशन? चैलेजिज़ एंड रिस्पांसिज़”. *कन्फ्रंटिंग द शैडो एडुकेशन सिस्टम: वॉट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर वॉट प्राइवेट ट्यूटोरिंग ?* पर आयोजित आईआईईपी पॉलिसी फोरम में प्रस्तुत शोधपत्र. पेरिस: आईआईईपी-यूनेस्को.
- प्राइसवॉटरहाउस कूपर्स. 2008. *इवेल्यूएशन ऑफ द मेकिंग गुड प्रोग्रेस पायलट: इटेरिम रिपोर्ट*. रिसर्च रिपोर्ट एससीएसएफ - आरआर065. लंदन: डिपार्टमेंट फॉर चिल्ड्रेन, स्कूल्स एंड फैमिलीज़. 4 अगस्त 2009 को <http://publications.dcsf.gov.uk/default.aspx?PageFunction=productdetails&PageMode=publications&productID=DCSF-RR065> से प्राप्त.
- साचारोपुलोस, जी.; पापॉकोस्टेनटिनाऊ, जी. 2005. “द रियल यूनिवर्सिटी कॉस्ट्स इन अ ‘फ्री’ हायर एडुकेशन कंट्री”. *इकॉनोमिक्स ऑफ एडुकेशन रिव्यू, 24(1)*, 103-108 में प्रकाशित..

- साचारोपुलोस,जी.; तासौलास, एस. 2004. “अचीवमेंट एट द हायर एजेकुशन एंट्री एक्जामिनेशन इन ग्रीस: अ प्रोक्रस्टियन अप्रोच”. *हायर एडुकेशन*, 47(2), 241-252 में प्रकाशित.
- रेड्डी, वी. 2007. “इवैल्यूएटिंग द शैडो: सप्लीमेंटरी ट्यूटरिंग टू अचीव इक्विटी एंड रिड्रेस इन साउथ एफ्रीका”. *कन्फ्रंटिंग द शैडो एडुकेशन सिस्टम: वॉट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर वॉट प्राइवेट ट्यूटरिंग ?* पर आयोजित आईआईपी पॉलिसी फोरम में प्रस्तुत शोधपत्र. पेरिस: आईआईपी-यूनेस्को.
- रोबिटेल्, डी.एफ.; बीटन, ए.ई. 2002. टिम्स: अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द स्टडी. डी.एफ. रोबिटेल् एवं ए.ई. बीटन (एड्स), *सेकेंडरी एनालिसिस ऑफ द टिम्स डाटा* (पृ. 11-18). डोरड्रेश: क्लूवर अकेडमिक पब्लिशर्स.
- रोसगार्ड, एम.एच. 2006. *जैपनीज़ एडुकेशन एंड द क्रैम स्कूल बिज़नेस: फंक्शंस, चैलेजिज़ एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ द जुकु.* कोपनहेगन: नॉर्डिक इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज़ प्रैस.
- समथ, एफ. 2007. *श्री लंका: प्राइमरी एडुकेशन इन क्राइसिस.* इंटर प्रैस सर्विस न्यूज़ एजेंसी. 31 जुलाई 2009 को www.ipsnews.net/print.asp?idnews=38219 से प्राप्त.
- सेठ, एम.जे. 2002. *एडुकेशन फीवर: सोसायटी, पॉलिटिक्स, एंड द परस्यूट ऑफ स्कूलिंग इन साउथ कोरिया.* होनोलुलु: यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई प्रैस.
- शर्मा, वाई. 2009. “ब्रिटेन ‘स स्ट्रगलिंग’”. *स्टूडेंट्स गैट एक्स्ट्रा ट्यूटरिंग* ’. *साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट*, 7 फरवरी, पृ. ई2 में प्रकाशित.
- सिलोवा आई. 2007. “प्राइवेट ट्यूटरिंग इन ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशिया: पॉलिसी चॉइसिज़ एंड इम्प्लीकेशंस”. *कन्फ्रंटिंग द शैडो एडुकेशन सिस्टम: वॉट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर वॉट प्राइवेट ट्यूशन?* पर आयोजित आईआईपी पॉलिसी फोरम में प्रस्तुत शोधपत्र. पेरिस: आईआईपी-यूनेस्को.
- सिलोवा, आई. (एड) 2009. *प्राइवेट सप्लीमेंटरी ट्यूटरिंग इन सेंट्रल एशिया: न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड बर्डन्स.* पेरिस- आईआईपी-यूनेस्को।
- सिलोवा, आई.; बुडीन, वी.; ब्रे, एम. (एड) 2006. *एडुकेशन इन अ हिडन मार्केट प्लेस: मॉनीटरिंग ऑफ प्राइवेट ट्यूटरिंग.* न्यूयॉर्क: ओपन सोसायटी इंस्टीट्यूट. 7 जून 2009 को www.soros.org/initiatives/esp/articles_publications/publications/hidden_20070216 से प्राप्त.

सिलोवा, आई.; काज़िमज़ेड, ई. 2006. “अज़रबेज़ान”. आई सिलोवा, वी. बुडीन. एंड एम. ब्रे (एड), *एडुकेशन इन अ हिडन मार्केट प्लेस: मॉनीटरिंग ऑफ प्राइवेट ट्यूटरिंग* (पृ. 113 - 141). न्यूयार्क: ओपन सोसयटी इंस्टीट्यूट.

7 जून 2009 को

www.soros.org/initiatives/esp/articles_publications/publications/hidden_20070216 से प्राप्त।

सिन्डा. 2009. *कमिंग टुगेदर: सिन्डा एनुअल रिपोर्ट 2008*. सिंगापुर: सिंगापुर इंडियन डेवेलपमेंट एसोसिएशन (सिन्डा). 8 अगस्त 2009 को http://www.sonda.org.sg/admin/userfiles/file/annialreport2008/SINDA2008_AR.pdf से प्राप्त।

स्मिथ, ई. 2009. “बाइंग योर वे इंटू कॉलेज? प्राइवेट ट्यूटरिंग एंड द ट्रांज़ीशन टफ हायर एडुकेशन इन आयरलैंड.” *ऑक्सफोर्ड रिव्यू ऑफ एडुकेशन*, 35(1), 1-22 में प्रकाशित.

सोऊ, सी. 2007. प्राइवेट ट्यूशन इन मकाओ’. *कन्फ्रंटिंग द शैडो एडुकेशन सिस्टम: वॉट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर वॉट प्राइवेट ट्यूटरिंग ?* पर आयोजित आईआईईपी पॉलिसी फोरम में प्रस्तुत शोधपत्र. पेरिस: आईआईईपी - यूनेस्को.

स्टीवेन्सन, डी.एल.; बेकर, डी.पी. (1992). “शैडो एडुकेशन एंड एलोकेशन इन फॉर्मल स्कूलिंग: ट्रांज़ीशन टू यूनिवर्सिटी इन जापान.” *अमेरिकन जरनल ऑफ सोशियोलॉजी*, 97(6), 1639-1657 में प्रकाशित.

सुजाथा, के. 2007. “प्राइवेट ट्यूटरिंग इन इंडिया: ट्रेड्स एंड पॉलिसी इम्प्लीकेशंस”. *कन्फ्रंटिंग द शैडो एडुकेशन सिस्टम: वॉट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर वॉट प्राइवेट ट्यूटरिंग ?* पर आयोजित आईआईईपी पॉलिसी फोरम में प्रस्तुत शोधपत्र. पेरिस: आईआईईपी - यूनेस्को.

सुंदरमन, जी.एल. 2006. “डू सप्लीमेंटल एडुकेशनल सर्विसेज़ इंक्रीज़ अपॉरचुनिटीज़ फॉर द माइनॉरिटी स्टूडेंट्स?” *फि डेल्टा कप्पन*, 88(2), 117-122 में प्रकाशित.

सुजुकी, एस. 2009. “प्राइवेट ट्यूटरिंग एज़; बिज़नेस.” अप्रकाशित पाण्डुलिपि. टोक्यो: वासेदा यूनिवर्सिटी.

टैन, जे. 2007. *कन्फ्रंटिंग द शैडो एडुकेशन सिस्टम: वॉट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर वॉट प्राइवेट ट्यूटरिंग ?* पर आयोजित आईआईईपी पॉलिसी फोरम में प्रस्तुत टिप्पणी. पेरिस: आईआईईपी - यूनेस्को.

टैन, जे. 2009. “प्राइवेट ट्यूटरिंग इन सिंगापुर: बस्टिंग आउट ऑफ द शैडो”. *जरनल ऑफ यूथ स्टडीज़ (हॉगकाँग)*, 12(1), 93-103 में प्रकाशित.

- टैनर, ई.; डे, एन.; टेनैन्ट, आर.; तर्कजुक, ओ.; आयरसन, जे.; रशफोर्थ, के.; स्मिथ, के. 2009. “*प्राइवेट ट्यूटरिंग इन इंग्लैंड* रिसर्च रिपोर्ट डीसीएसएफ – आरआर081. लंदन: डिपार्टमेंट फॉर चिल्ड्रेन, स्कूल एंड फैमिलीज़. 5 अगस्त 2009 को www.desf.gov.uk/research/data/uploadfiles/DCSF-RR081.pdf से प्राप्त.
- टनसेल, ए.; बिरकन, एफ. 2007. “*प्राइवेट सप्लीमेंटरी ट्यूटरिंग इन टर्की: रीसेंट एविडेंस ऑन इट्स वेरियस आस्पैक्ट्स*”. *कन्फ्रंटिंग द शैडो एडुकेशन सिस्टम: वॉट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर वॉट प्राइवेट ट्यूटरिंग ?* पर आयोजित आईआईईपी पॉलिसी फोरम में प्रस्तुत शोधपत्र. पेरिस: आईआईईपी – यूनेस्को.
- टेलर, डी. 2007. “*मेकिंग गुड प्रोग्रेस: द यूज़ ऑफ वन टु वन ट्यूटरिंग इन इम्प्रूविंग रेड्स ऑफ प्यूपिल प्रोग्रेशन*”. *कन्फ्रंटिंग द शैडो एडुकेशन सिस्टम: वॉट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर वॉट प्राइवेट ट्यूशन ?* पर आयोजित आईआईईपी पॉलिसी फोरम में प्रस्तुत शोधपत्र. पेरिस: आईआईईपी – यूनेस्को.
- टिम्स (थर्ड इंटरनेशनल मैथेमैटिक्स एंड साइंस स्टडी). 1998. *इंटरनेशनल वर्जन ऑफ द बैकग्राउंड क्वेश्चनेयर्स पॉपुलेशन 2*. चेस्टनट हिल, एमए: टिम्स इंटरनेशनल स्टडी सेंटर. बॉस्टन कॉलेज. 10 अगस्त 2009 को http://times.bc.edu/timss1995i/database/UGI_Sup2.pdf से प्राप्त.
- टिम्स (ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल मैथेमैटिक्स एंड साइंस स्टडी). 2003. *टिम्स 2003 स्टूडेंट क्वेश्चनेयर ग्रेड 8*. चेस्टनट हिल, एमए: टिम्स इंटरनेशनल स्टडी सेंटर. बॉस्टन कॉलेज. 10 अगस्त 2009 को http://times.bc.edu/timss2003i/PDF/T03_studentS_8.pdf से प्राप्त.
- ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2009. *करप्शन इन द एडुकेशन सेक्टर*. वर्किंग पेपर रु4ध2009. बर्लिन: ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल. 3 अगस्त 2009 को www.transparency.org/publications/publications/working_papers/working_paper_no_04_2007_education से प्राप्त.
- यूनेस्को. 2000. *द ईएफए 2000 असैसमेंट: कंट्री रिपोर्ट्स - रोमानिया*. पेरिस – यूनेस्को. 7 जून 2009 को www.unesco.org/education/wef/countryreports/romania/rapport_2_1.html से प्राप्त.
- यूनेस्को. 2004. *एडुकेशन फॉर ऑल: द क्वालिटी इम्पैरेटिव*. ईएफए ग्लोबल मॉर्निंग रिपोर्ट 2005. पेरिस: यूनेस्को. 7 जून 2009 को http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=35939&URL_DO=DO_TOPICS&URL_SECTION=201.html से प्राप्त.

- यूनेस्को. 2007. *एडुकेशन फॉर ऑल बाई 2015: विल वी मेक इट? ईएफए ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2008*. पेरिस-यूनेस्को. 7 जून 2009 को www.unesco.org/en/efareport/reports/2008-mid-term-review/ से प्राप्त.
- यूनेस्को. 2008. *ओवरकमिंग इनइक्वेलिटी: वाय गवर्ननेंस मैटर्स. ईएफए ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2009*. पेरिस: यूनेस्को.. 7 जून 2009 को www.unesco.org/en/efareport से प्राप्त.
- यूनिसेफ. 1994. *सिचुएशन एनालिसिस ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रेन इन मॉरीशस*. न्यूयार्क: यूनिसेफ.
- यूनिसेफ. 2007. *एडुकेशन फॉर सम मोर दैन अदर्स? अ रीजनल स्टडी ऑन एडुकेशन इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप एंड द कॉमनवैल्थ ऑफ इंडीपेंडेंट स्टेट्स (सीईई/सीआईएस)*. जेनेवा: यूनिसेफ रीजनल ऑफिस फॉर सीईई/सीआईएस. 7 जून 2009 को www.unisef.org/media/files/Regional_Education_Study_-.pdf से प्राप्त.
- वेंचुरा, ए. 2008ए. “एज़ एक्सप्लीकेकोस अत्रावेस दा इंटरनेट: ग्लोबेलाइजेकाओ ई ऑफशोरिंग”. जे.ए. कोस्टा, ए. नेटो-मेंडीज़, एवं ए. वेंचुरा (एड्स). *एक्सप्लिका: इन्वेस्टिगकाओ सोबरे अ मरकाडो दास एक्सप्लिकाकोस* (पृ. 69-84). अवीरो: यूनिवर्सिडैड डी अवीरो.
- वेंचुरा, ए. 2008बी. “प्राइवेट सप्लीमेंटरी ट्यूटरिंग इन यूरोप: एन ओवरव्यू”. *नाइथ इंटरनेशनल काँफ्रेंस ऑन एडुकेशनल रिसर्च*, सिओल नेशनल यूनिवर्सिटी, 27-28 अक्टूबर को प्रस्तुत शोधपत्र.
- वरगारी, एस. 2007. “फेडरलिज़्म एंड मार्केट-बेस्ड एडुकेशन पॉलिसी: द सप्लीमेंटल एडुकेशनल सर्विसेज़ मैडेट”. *अमेरिकन जरनल ऑफ एडुकेशन*, 113(2) 311-339 में प्रकाशित.
- वियेले-ग्रोसजीन, एच. 2009. *ली सौतिएन स्कोलेर: एन्ज्यूक्स एत इनइगेलिटीज़*. पेरिस: जेट्स डी'एन्करे.
- वाग्नेर, पी.; स्पील, सी.; त्रांकर, एम. 2003. *वेर निस्ट नैशिल्फे इन अंस्पुच? ईने एह् ऑस हॉपशुले अंड जिम्नाज़ियम*. *जीशरिफ़ फुर पडागोगिशे साइकोलॉजी*, 17(3-4). 233-234. 7 जून 2009 को www.stangl.eu/paedagogik/artikel/nachhilfe.shtml से प्राप्त.
- वनयामा, आई.; न्जेरू, ई. 2006. *द सोशियोलॉजी ऑफ प्राइवेट ट्यूटरिंग*. आईपीएआर पॉलिसी ब्रीफ 10(7) नैरोबी: इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी एनालिसिस एंड रिसर्च.

- वाटसन, एल. 2007. “प्राइवेट ट्यूटरिंग इन ऑस्ट्रेलिया: अ प्रिलिमिनरी एनालिसिस”. *कन्फ्रंटिंग द शैडो एडुकेशन सिस्टम: वॉट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर वॉट प्राइवेट ट्यूटरिंग ?* पर आयोजित आईआईईपी पॉलिसी फोरम में प्रस्तुत शोधपत्र. पेरिस: आईआईईपी – यूनेस्को.
- वाटसन, एल. 2008. “प्राइवेट एक्सपैक्टेड एंड पब्लिक स्कूलिंग: इ ग्रोथ ऑफ प्राइवेट ट्यूटरिंग इन ऑस्ट्रेलिया”. *नेशनल काँफ्रेंस ऑफ द ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन फॉर रिसर्च इन एडुकेशन (एएआरई)*, 30 नवंबर - 4 दिसंबर में प्रस्तुत शोधपत्र. 5 अगस्त 2009 को
http://ovcs.sfu.ca/aare/index.php/AARE_2008/AARE/paper/viewFile/692/170 से प्राप्त.
- वुल्फ, आर.एम. 2002. “एक्स्ट्रा-स्कूल इंजर्क्शन इन मैथेमैटिक्स एंड साइंस”. डी. एफ. रोबिटेल् एवं ई.बी. बीटन (एड्स), *सेकेंडरी एनालिसिस ऑफ द टिम्स डाटा* (पृ. 331-341), डोरड्रेष्ट: क्लूवर अकेडमिक पब्लिशर्स.
- वर्ल्ड बैंक. 2002. *अरब रिपब्लिक ऑफ इजीप्ट: एडुकेशन सेक्टर रिव्यू- प्रोग्रेस एंड प्रायोरिटीज़ फॉर द फ्यूचर*. वाशिंगटन डीसी: वर्ल्ड बैंक.
- वर्ल्ड बैंक. 2004. *विएतनाम: रीडिंग एंड मैथेमैटिक्स असेसमेंट स्टडी. वॉल. 2*. वाशिंगटन डीसी: ह्यूमन डेवलपमेंट सेक्टर यूनिट. ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक रीजन, वर्ल्ड बैंक.
- वर्ल्ड बैंक. 2005. *एक्सपैंडिंग ऑपोर्चुनिटीज़ एंड बिल्डिंग कम्पीटेन्सीज़ फॉर यंग पीपल: अ न्यू एजेंडा फॉर सेकेंडरी एडुकेशन*. वाशिंगटन डीसी: वर्ल्ड बैंक.
- वर्ल्ड बैंक. 2008. *द रोड नॉट ट्रेल्वलड: एडुकेशन रिफॉर्म इन द मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ एफ्रीका*. वाशिंगटन डीसी: वर्ल्ड बैंक. 7 जून 2009 को
<http://web.worldbank.org/wbsite/external/countries/menaext/0,,contentMDK:21617643~pagePK:146736~piPK:226340~thesitePK:256299,00.html> से प्राप्त.
- ज़्यू, एच.; डिंग, वाई. 2009. “अ पॉज़िटिविस्टिक स्टडी ऑन द प्राइवेट ट्यूटरिंग ऑफ स्टूडेंट्स इन अर्बन चाइना”. *जरनल ऑफ यूथ स्टडीज़* (हाँगकाँग), 12(1), 115-128 में प्रकाशित, (चीनी में)।
- यांग, एस. 2001. *ट्यूटरिंग पॉलिसी चेंज एंड रिफ्लेक्शन ऑन द रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट एडुकेशन*. सिओल: कोरियन एडुकेशन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (कोरियन में).
- यी, पी. 2002. “हाउसहोल्ड स्पैंडिंग ऑन प्राइवेट ट्यूटरिंग इन साउथ कोरिया”. 46 *एनुअल काँफ्रेंस ऑफ द कम्पैरेटिव एंड इंटरनेशनल एडुकेशन सोसायटी*, ओरलैंडो, फ्लोरिडा में प्रस्तुत शोधपत्र.

- यून, जे.आई.; हुह, टी.जे.; ली, बी.जी.; हाँग, एस.पी.; किम, जे.आर.; किम, डी.वाई.; कांग, टी.एच.; किम, ई.ओ. 1997. *रिसर्च ऑन द एक्चुअल कंडीशन ऑफ एक्स्ट्राकरीकुलर लैसन्स*. सियोल: कोरियन एडुकेशनल स्टाफ एसोसिएशन (कोरियन में).
- जंज़ीबार, रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ऑफ. (1998). *प्रोस्पैक्टिव स्टॉक-टेकिंग रिव्यू ऑफ एडुकेशन इन एफ्रीका: द जंज़ीबार .केस स्टडी*. पेरिस: एसोसिएशन फॉर द डेवेलपमेंट ऑफ एडुकेशन इन एफ्रीका (एडीईए), एंड जंज़ीबार: मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन.
- जेंग, के. 1999. *ड्रेगन गेट: कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसिस*, लंदन; कैसेल.
- ज़िंमर, आर.; गिल, बी.; रैज़क्विन, पी.; बूकर, के.; लॉकवुड, जे.आर. 2007. *स्टेट एंड लोकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नो चाइल्ड लैफ्ट बिहाइंड ऐक्ट: वॉल्यूम 1- टाइटल स्कूल चॉइस, सप्लीमेंटल एडुकेशनल सर्विसेज़, एंड स्टूडेंट अचीवमेंट*. वाशिंगटन डीसी: यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एडुकेशन. 7 जून 2009 को www.rand.org/pubs/reprints/RP1265/ से प्राप्त.

प्रतिच्छाया शिक्षा

अज़रबैज़न, 19-20, 37, 42, 79, 101
अनिवार्य शिक्षा, 49
अनौपचारिक शिक्षा, 87
अफ्रीका, 20, 21, 24, 27, 41
अभिभावक/संरक्षक/माता-पिता,
12, 13, 17, 22-24, 27, 29,
31-35, 39-41, 45, 47, 48,
50-52, 56, 57-67, 69, 75,
78, 80, 82-85, 88, 89, 91,
93-97, 100, 102, 104-106
असमानता देखें समानता, 13, 32, 35,
6, 38, 39, 42, 43, 46-48,
59, 60, 64, 66, 69, 71, 102
अवसर लागत, 31
आईआईपी पॉलिसी फोरम, 12, 24, 34,
36, 39, 41, 47, 54, 62, 63,
73, 89, 97, 101-103
आर्थिक, 11, 13-15, 17, 30-32, 34,
40, 47, 48, 51, 57, 58, 65,
66, 69-73, 76, 81, 90, 102,
107
प्रभाव, 11, 30, 63, 73
बोझ, 47, 48, 51, 58
एवं सामाजिक परिवर्तन का साधन,
47
सामाजिक और शैक्षणिक प्रभाव, 30
आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन
(ओईसीडी), 7, 11, 48, 64, 100
आमने-सामने बैठकर ट्यूशन देना, 14,
17, 22, 29, 39, 41, 72, 105

आयरलैण्ड, 23
ऑस्ट्रेलेशिया, 24, 101
ऑस्ट्रिया, 77, 89, 113
इंग्लैंड, 22, 339, 41, 8-75, 82, 91,
92, 95, 102, 103, 106
इंटरनेट, 14, 17, 27, 28, 29, 52,
53, 67, 72, 73, 79, 102,
105, 124
उच्च आय वाले देश, 17
उच्चतर/माध्यमिक स्कूल की परीक्षाएं,
49-50
उत्तरी अमेरिका, 24, 101
उपभोक्ता, 22, 80
उपभोक्तावाद, 102
एशिया, 19, 20, 24, 36-38, 52,
78, 79, 87, 101, 109, 110,
116, 121, 125
कंबोडिया, 17, 18, 35, 85, 101, 110,
112
कक्षा, 13, 15, 17-21, 25, 27, 32,
35, 38-60, 63-67, 72,
75-85, 88, 91, 93, 94,
97-100, 104
में अध्यापन, 56
कज़ाखिस्तान, 20, 36, 79, 87, 89
कनफ्यूशियन परंपरा, 24
कनफ्यूशियसवाद, 48

- कनाडा, 17, 18, 23, 29, 38, 68
टोरोन्टो, 38
वैनकोउवर, 38
- कम अंक पाने वाले छात्र, 38-40, 42, 43, 51, 72, 75, 103, 104
- कम आय,
वाले देश, 17
वाले परिवार, 32, 41, 57, 75, 86
- कर-निर्धारण, 32, 65-67, 69, 75, 89
में प्रोत्साहन, 75,
में छूट, 32, 65-67, 69, 75, 89
- किर्गीस्तान, 20, 34, 37, 79, 81, 82, 101
- किफायत, 40
- कुमोन, 28, 29
- केन्या, 17, 19, 21, 34, 35, 76
- कोरिया, 12, 24, 27, 30-32, 35, 43, 47, 48, 52-54, 56, 65, 69, 71, 72, 76, 77, 86, 89, 101, 103, 105, 107
- कॉकेशस, 79
- कॉलेज प्रवेश प्रणाली, 52, 53
- क्रैम स्कूल, 30, 50, 74, 95
- क्रोशिया, 19, 20, 37
- गुणवत्ता, 39, 52, 56, 59, 60, 69, 72, 79, 82-84, 86, 91, 95, 102
आश्वासन, 60, 82, 83,
शिक्षा की, 52, 56, 102
- गैर-सरकारी संगठन, 11, 86
- ग्रीस/यूनान, 22, 30, 85
- घरेलू/पारिवारिक सर्वेक्षण, 18-19, 35, 37, 94
- चीन, 18, 19, 26, 28, 38, 41, 48
की द्यूशन प्रणाली, 26, 37
- छात्र,
अल्पसंख्यक, 15, 38
उच्चतर/हाई स्कूलों के, 47, 51, 66, 105
कम अंक पाने वाले, 24, 38-40, 42, 43, 51, 72, 75, 103, 104
सर्वेक्षण, 93, 96
- जर्मनी, 68, 86
- जांजीबार, 21, 84, 85
- ज़ाबिया, 21
- जापान, 11, 17-19, 24, 28, 29, 48, 51, 72, 74, 89, 101
- जुकु (जापान) देखें द्यूटरिंग, 18, 29, 74, 75, 89
- जॉर्जिया, 19, 20, 37, 79, 101
- द्यूटर/निजी शिक्षक, 10, 12, 13, 14, 23, 27, 28, 30, 31, 36, 38, 40, 41, 43-45, 47, 50, 52, 58, 59, 61, 62, 66, 67, 69, 78, 79, 82-86, 88, 89, 91-93, 95, 96, 100, 104
- द्यूटरिंग (प्राइवेट)/द्यूशन,
की अवधि, 25, 59
का आकार और स्वरूप, 13, 14, 17, 41, 51, 58, 68, 74, 77, 97, 103
की आपूर्ति, 15, 36, 38, 64, 79

- आमने-सामने बैठकर, 14, 17,
22, 29, 39, 41, 72, 105
की आवर्ती, 16, 24, 92
इंटरनेट पर, 14, 17, 27, 28,
29, 52, 53, 67, 72, 73, 79,
102, 105, 124
ग्रामीण/शहरी क्षेत्र, 18, 19, 20,
23, 24, 28, 36-38, 72, 81
निगरानी एवं मूल्यांकन, 12, 15,
20, 45, 60, 93-100
पद्धति, 10, 24, 93, 103
पर पूर्ण प्रतिबंध, 76, 104
प्राइवेट/निजी संस्थान, 32, 43,
47, 51, 54, 79, 86, 105
जुकु (जापान), 18, 29, 74,
75, 89
हाकवोन (कोरिया), 47, 53,
56, 89
पाने वाले, देखें उपभोक्ता, 18, 21,
26, 35, 37, 40, 46, 53, 56
पर प्रतिबंध, 49-53, 57-60,
64, 76, 87-92, 94, 104
का प्रभाव, 11, 13, 29, 30, 39,
42-46, 66, 71
की मांग, 14, 15, 32, 35, 38,
43, 48, 53, 56, 57, 59, 62,
64, 71, 75-77, 102, 107
की मात्रा, 14, 20, 24, 30, 73,
90, 93, 94
स्कूल के बाद, 20, 22, 41, 52,
54, 67, 79, 100, 106
- तंज़ानिया, 21
ताईवान, 24, 38, 85
ताजीकिस्तान, 20, 31, 37, 79, 87-89,
- 101
तुर्की, 22, 30, 34, 42, 76
दक्षिण एशिया, 24, 38
दक्षिणी अफ्रीका, 20, 21, 27, 41
निःशुल्क शिक्षा, 102
निजीकरण, 69, 85, 101, 102
निजी शिक्षा, 11, 12, 88, 89, 101-106
नीति निर्माता और नियोजक/योजनाकार,
11, 12, 14, 15, 24, 29, 60,
64, 71-74, 76, 78, 81, 84,
93, 97, 101, 103-105, 107
नीतिगत प्रभाव, 14
नामांकन, 34, 49
नामीबिया, 21, 25, 90
नो चाइल्ड लैफ्ट बिहाइंड, 23, 29, 32,
38, 40, 43
पद्धति (ट्यूटिंग की) देखें ट्यूटिंग,
10, 24, 93, 103
परिवार द्वारा शिक्षा पर व्यय, 18, 21
परीक्षा/परीक्षाएं, 14, 19, 20, 25, 33,
38, 39, 41, 42, 46, 48-50,
53, 54, 56-61, 64, 72, 74,
75, 77, 81, 86, 96, 97, 103,
105, 106
बाहरी परीक्षा, 42
प्रवेश परीक्षा, 19, 25, 42, 48,
50, 54, 74, 75
सिविल सर्विस परीक्षा, 48
पश्चिमी यूरोप, 22-24, 101
पाठ्यक्रम, 13, 14, 17-20, 22, 26,
27, 29, 33, 38, 40, 43-46,
48, 49, 52, 59, 62-64, 66,

- 67, 74, 75, 79, 87, 88, 105, 107
- पाठ्येतर, 48, 49, 51-53
- पारगमन दरें, 77
- पारिवारिक व्यय, 18, 30, 47
- पुर्तगाल, 25, 90, 96
- पूर्वी यूरोप, 9, 19, 20, 24, 36, 37, 87, 101
- पोलैण्ड, 20, 37
- पॉलिसी फोरम (आईआईईपी) देखें
आईआईईपी पॉलिसी फोरम
- प्रजाति, 38, 72-73, 81
- प्रजातीयता देखें प्रजाति, 38
- प्रतिच्छाया शिक्षा (प्रणाली), 11, 13, 15, 34, 38, 71, 77, 86, 101, 107
- प्रतिबंध (ट्यूटिंग पर), 49-53, 57-60, 64, 76, 87-92, 94, 104
- प्रतिभाशाली छात्र, 14, 43, 46, 78
- प्रभाव (ट्यूटिंग/ट्यूशन का), 11, 13, 29, 30, 39, 42-46, 66, 71
- आर्थिक, 11, 30-36, 73
- सामाजिक, 30-36
- शैक्षिक/शैक्षणिक, 14, 30-36
- प्रसारण, 28
- प्राइवेट ट्यूशन/प्राइवेट ट्यूटिंग/निजी शिक्षा, 11-13, 17-39, 42-60, 62-95, 97-102, 104, 105, 107
- आकार और स्वरूप, 14, 17, 93
- प्रकृति और भूमिका, 65
- के प्रतिकूल प्रभाव, 87
- का प्रयोग, 37
- के माध्यम, 67
- के लिए राष्ट्रों के संकेतक, 18
- प्राथमिक स्कूल, 18, 21, 22, 25, 35, 38, 47, 49-53, 55-62, 64, 96, 100, 102
- प्रौद्योगिकी, 29, 102
- फ्रांस, 12, 22, 30, 33, 47, 65, 68, 69, 71, 75, 86, 92, 103, 104
- फ्रेंचाइजी प्रणाली, 29, 72, 74, 80
- बांग्लादेश, 18, 19, 35, 37, 86, 119
- बाजार आधारित ट्यूशन, 14, 42
- बेंचमार्क, 40, 97
- बोत्सवाना, 12, 97, 102
- बोसनिया तथा हेरजेगोविना, 19, 20, 37
- ब्रजील, 23
- भाषा, 15, 26, 28, 29, 31, 49, 51, 81, 88, 103
- भार/बोझ, 47, 49, 58, 65, 71, 82-84
- भारत, 21, 26, 28, 32, 34, 37, 41, 76, 90
- आंध्र प्रदेश, 21, 26, 37
- उत्तरप्रदेश, 21, 26, 37
- केरल, 21, 26, 37
- पश्चिम बंगाल, 21, 76
- महाराष्ट्र, 21, 26, 37, 90
- भारतीय ग्रामीण सर्वेक्षण, 36
- भ्रष्टाचार, 11, 14, 53, 80, 81, 92
- मंगोलिया, 19, 20, 79, 87, 89
- मकाओ, 26, 91, 97, 106
- मध्य एशिया, 79, 101
- मलावी, 21, 102
- मातृ भाषा, 26

माध्यमिक स्कूल, 15, 18-19, 22, 28, 29, 33, 34, 36, 41, 42, 49-51, 55, 56, 58, 59, 65, 72, 88, 96, 100

मानव पूंजी, 13, 31

मिस्र, 19, 31, 33, 35, 37, 42-44, 76, 78, 86, 106

मिस्र मजदूर बाजार सर्वेक्षण, 35, 37

मुख्य धारा, 13, 17, 29, 71, 72, 76-80, 85, 88-90, 92, 102-104, 106, 107

के अध्यापक, 80, 90, 92, 104, की शिक्षा, 71, 72, 76-79, 102-104, 106

के स्कूल, 88, 104, 107

मूल्यांकन, 81, 93, 95, 96

मॉरिशस, 21, 25, 42, 43, 47, 54-61, 63-65, 69, 71, 72, 76, 77, 80, 84, 97, 101, 103

मॉनीटर/मॉनीटरिंग

यूक्रेन, 20, 37, 87-89

यूगांडा, 20, 76, 91, 97, 102

राजस्व, 45, 90

लागत, 18, 22, 25, 27, 30, 31, 40, 41, 50, 65, 73, 94, 97, 127

लिंग/जेंडर, 34-36, 72, 73, 81

लिथुआनिया, 19, 20, 37, 87-89, 100

लैटिन अमरीका, 23, 24

विज्ञापन, 67, 74, 75, 79, 95

विनियम, 28, 50, 57-59, 71,

89-92, 94, 104

वियतनाम, 19, 25, 35, 38, 94

विषय देखें शैक्षणिक विषय, 15, 87-88, 99

शिकागो, 40

शिक्षा का बाजारीकरण और निजीकरण, 101

शिक्षा प्रणाली, 11, 13-15, 17, 23, 24, 28-30, 34-36, 38, 48, 52, 57, 59, 60, 62, 64, 69, 71, 77, 78, 80-82, 86, 87, 101, 102-104, 106, 107

शिक्षाविद, 105

शिशु देखभाल केन्द्र, 52

शैक्षिक/शैक्षणिक, 11, 12, 14, 30, 38, 52, 69, 75, 76, 89, 98, 99, 102, 106,

उपलब्धियां, 32, 76, 100, 105, 106

प्रभाव, 30

विषय, 15, 50

सामाजिक और आर्थिक विशेषताएं, 107

शोधकर्ता, 12, 17, 19, 21, 39, 97, 99

श्री लंका, 31, 101

संयुक्त राज्य अमरीका, 23, 28, 29, 32, 38, 39, 43, 68, 72, 75, 76, 102

संस्कृति, 15, 17, 19, 24, 30, 36, 47, 52, 53, 64, 85, 101-104

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), 18, 30, 31, 47

समानता, देखें भेदभाव, 34, 35, 52,
61, 72, 80
सरकारी,
नीतियां, 14, 24, 27, 29
व्यय, 30, 47
साइप्रस, 18
सामाजिक,
असमानताएं, 32, 36, 38, 46,
64, 66, 71, 102
और आर्थिक, 11, 13, 17, 57, 71,
102, 107
प्रभाव, 11, 13
एवं शैक्षिक प्रभाव
सामान्य सार्वजनिक आत्मविश्वास, 77-78
सिंगापुर, 25, 28, 41, 72, 75, 76, 91,
101, 107
सोवियत संघ, 19

स्कूल,
के बाद ट्यूटिंग देखें ट्यूटिंग,
20, 22, 41, 52, 54, 67, 79,
100, 106
निजी, 66
परिसर, 22, 58, 60, 63, 88
प्राथमिक/माध्यमिक, 18, 21, 22,
25, 35, 38, 47, 49-53,
55-62, 64, 96, 100, 102
के विषय, 15, 87-88, 99
सार्वजनिक, 41, 65, 70, 78, 102
स्तरीकरण, 77
स्लोवाकिया, 19, 20, 37, 87, 88, 100
हांगकांग, 18, 19, 24, 28, 38, 95,
97
हाकवोन (कोरिया) देखें ट्यूटिंग, 47,
53, 56, 89

आईआईईपी प्रकाशन एवं दस्तावेज

इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एडुकेशनल प्लानिंग द्वारा शिक्षा की योजनाओं के सभी पहलुओं पर 1,200 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। निम्नलिखित विषय-श्रेणियों पर एक विस्तृत कैटालॉग उपलब्ध है:

एडुकेशनल प्लानिंग एंड ग्लोबल इश्यूज़

सामान्य अध्ययन - वैश्विक/विकास संबंधी समस्याएं

एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एडुकेशन

विकेंद्रीकरण - सहभागिता - सुदूर शिक्षा - स्कूल का प्रतिचित्रण - शिक्षक

इकोनॉमिक्स ऑफ एडुकेशन

लागत एवं वित्त व्यवस्था - रोजगार - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

क्वालिटी ऑफ एडुकेशन

मूल्यांकन - नवप्रवर्तन - पर्यवेक्षण

डिफ्रेंट लेवल्स ऑफ फॉर्मल एडुकेशन

प्राथमिक से लेकर उच्चतर शिक्षा तक

आल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज़ फॉर एडुकेशन

जीवनपर्यंत शिक्षा - अनौपचारिक शिक्षा - कमजोर वर्ग - लैंगिक शिक्षा

कैटालॉग की प्रतियां निम्नलिखित पते से मंगाई जा सकती हैं:

आईआईईपी, पब्लिकेशंस एंड कम्युनिकेशंस यूनिट

info@iiep.unesco.org

नए प्रकाशनों और सारांश पत्रों को निम्नलिखित वेबसाइट पर देखा जा सकता है:

www.iiep.unesco.org

इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एडुकेशनल प्लानिंग

इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एडुकेशनल प्लानिंग (आईआईपी) शिक्षा नियोजन के क्षेत्र में उन्नत प्रशिक्षणों और अनुसंधानों के लिए स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। इसकी स्थापना यूनेस्को ने 1963 में की थी तथा इसका वित्त-पोषण यूनेस्को और सदस्य देशों से प्राप्त होने वाले स्वैच्छिक अंशदान द्वारा किया जाता है। हाल ही के वर्षों में, संस्थान को निम्नलिखित सदस्य देशों ने स्वैच्छिक अंशदान दिया: ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, भारत, आयरलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड।

संस्थान का उद्देश्य, विश्व भर में शिक्षा नियोजन के क्षेत्र में ज्ञान का विस्तार करके और योग्य व्यावसायियों की भर्ती करके शिक्षा के विकास में योगदान देना है। अपने इस प्रयास में संस्थान, सदस्य देशों में प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थानों को सहयोग प्रदान करता है। आईआईपी के शासी निकाय में अधिकतम आठ सदस्य निर्वाचित होते हैं, जो संस्थान के कार्यक्रमों और बजट को अनुमोदित करते हैं, और चार सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र संगठन तथा इसकी कुछ विशेष एजेंसियां और संस्थान मनोनीत करते हैं।

अध्यक्ष:

रेमंड ई. वानेर (यूएसए)

यूनेस्को मामलों के वरिष्ठ सलाहकार, यूनाइटेड नेशंस फाउंडेशन, वाशिंगटन डीसी, यूएसए.
मनोनीत सदस्य:

क्रिस्टाइन इवांस - क्लॉक

निदेशक, आईएलओ स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी डिपार्टमेंट, जेनेवा, स्विट्जरलैंड
कार्लोस लोपेज़:

सहायक महासचिव एवं कार्यकारी निदेशक

यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च (यूनिटार). यूनाइटेड नेशंस. न्यूयॉर्क, यूएसए
जामिल सल्मी

एडुकेशन सेक्टर मैनेजर, द वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूट, वाशिंगटन डीसी, यूएसए
डिएरी सेक

निदेशक, एफ्रीकन इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, डकार, सेनेगल.
निर्वाचित सदस्य:

अज़ीज़ा बेनानी (मोरक्को)

यूनेस्को में मोरक्को की राजदूत और स्थाई डेलीगेट

नीना येफुनोवना बोरेव्कार्या (रूस)

मुख्य अनुसंधानकर्ता एवं परियोजना अध्यक्ष, इंस्टीट्यूट ऑफ फार ईस्टर्न स्टडीज़, मॉस्को
बिरगेर फ्रेडरिकसन (नॉर्वे)

विश्व बैंक के शिक्षा विकास के सलाहकार

रिकार्डो हेनरीक (ब्राज़ील)

नेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के विशेष सलाहकार
टेकिट्वा मनूह (घाना)
निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ एफ्रीकन स्टडीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ घाना
फिलिप मेहॉत (फ्रांस)
एलईएसटी-सीएनआरएस, एक्स-एन-प्रोवेंस, फ्रांस.
ज़िनशेंग झांग (चीन)
वाइस-मिनिस्टर ऑफ एडुकेशन, चीन

संस्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सम्पर्क पता:
निदेशक कार्यालय, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एडुकेशनल प्लानिंग,
7-9, र्यू यूजीन देलाक्रोई, 75116, पेरिस, फ्रांस



इस पुस्तक में निजी अनुपूरक द्यूशन पद्धति की तथाकथित प्रतिच्छाया शिक्षा प्रणाली पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह द्यूशन पद्धति विशेष रूप से पूर्वी एशिया के भागों में बड़े पैमाने पर काफी समय से मौजूद है। अब इसका विस्तार एशिया के अन्य भागों और अफ्रीका, यूरोप, तथा उत्तरी अमरीका में भी बढ़ता जा रहा है। सामान्यतया, छात्रों को सार्वजनिक स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, किंतु वे स्कूल के बाद तथा/अथवा सप्ताहांत में या छुट्टियों के दौरान, फीस का भुगतान करके उन्हीं विषयों में अनुपूरक द्यूशन प्राप्त करते हैं।

अनुपूरक प्राइवेट द्यूशन के सकारात्मक पहलू भी होते हैं। इससे छात्रों को अपना पाठ्यक्रम पूरा करने में मदद मिलती है, स्कूल के समय के बाद युवाओं को एक बुनियादी व्यवसाय का अवसर मिलता है और निजी शिक्षकों को आय होती है। किंतु निजी शिक्षा के नकारात्मक पहलू भी हैं। यदि इसे बाजारी ताकतों के भरोसे छोड़ दिया जाए तो निजी शिक्षा से समाज में असमानताएं पनप और बढ़ सकती हैं; इससे उन युवा छात्रों में मानसिक तनाव बढ़ सकता है जिनके पास शिक्षा के अतिरिक्त किसी अन्य गतिविधियों के लिए समय ही नहीं बचता। यह स्थिति तब और भी गंभीर हो जाती है जब स्कूल के अध्यापक अपने ही छात्रों से फीस लेकर उन्हें अतिरिक्त कक्षाओं में पढ़ाते हैं, जिन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी उन पर पहले से ही होती है।

इस पुस्तक का आरंभ विभिन्न स्थानों पर प्रतिच्छाया शिक्षा प्रणाली के विस्तार, प्रकृति और प्रभावों के सर्वेक्षण से किया गया है। इसके पश्चात् इसमें प्राइवेट द्यूशन के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया का उल्लेख किया गया है। यह सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है जिसके द्वारा सरकारें यह तय करती हैं कि उन्हें किस प्रकार की द्यूशन की आवश्यकता है, और किस प्रकार की द्यूशन से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तत्पश्चात् उपयुक्त नीतियां तैयार की जाती हैं।

लेखक का परिचय

मार्क ब्रे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एडुकेशनल प्लानिंग (आईआईईपी) के निदेशक हैं। उनकी 1999 में प्रतिच्छाया शिक्षा प्रणाली पर लिखित पहली पुस्तक का प्रकाशन भी आईआईईपी ने ही किया था। यह अपनी तरह की अकेली पुस्तक थी जिसे व्यापक रूप से सराहा गया था। इस पुस्तक की पाठ्यसामग्री में, प्रमुख रूप से इसी विषय पर उनके बाद के अध्ययनों को शामिल किया गया है। मार्क ब्रे ने तुलनात्मक शिक्षा और शिक्षा के प्रशासन एवं वित्तीयकरण पर भी अनेक पुस्तकें लिखी हैं।



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



International Institute
for Educational Planning